

हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही
18 दिसम्बर, 2023
खण्ड-3, अंक- 2
अधिकृत विवरण



विषय सूची
सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर एवं चंडीगढ़ नगर निगम के

13 भूतपूर्व महापौरों का अभिनन्दन करना

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लोकरा, जिला गुरूग्राम के

विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

वॉक-आउट

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य मंत्री, हरियाणा तथा सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध

में सूचना देना

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में सूचना
 श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा जीन्द के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा
 स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर दिनांक 15.12.2023
 को सदन में उप मुख्यमंत्री और उनके बीच हुए विवाद का मामला उठाना
 हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन करना
 गवर्नमेंट कॉलेज पटौदी, जिला गुरूग्राम के विद्यार्थीगण तथा
 अध्यापकगण का अभिनन्दन करना
 श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा जीन्द के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा
 स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर दिनांक 15.12.2023
 को सदन में उप मुख्यमंत्री और उनके बीच हुए विवाद का मामला उठाना (पुनरारम्भ)
 बैठक का स्थगन
 शून्यकाल के सम्बन्ध में सूचना देना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा
 अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से सम्बन्धित

वक्तव्य-

गृहमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी
 पी.एम. श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी,
 जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना
 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)
 वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों
 और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान
 नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक
 अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना
 नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक
 अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना
 वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) की मांगों
 पर चर्चा तथा मतदान

डिमांड्स की हार्ड कॉपी सदस्यों को उपलब्ध करवाने के बारे में मामला उठाना
वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) की मांगों
पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

पी.एम. श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गंगवा, जिला हिसार के
विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना

वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) की मांगों
पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

विधायी कार्य-

(विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.12.2023 और 18.12.2023 को सदन
में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जवाब देना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन
विधेयक, 2023 को वापिस लेना।

3. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल
द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर हाई कोर्ट
के सिटिंग जज से इन्क्वायरी करवाने के मामले पर पुनर्विचार करने का मामला उठाना
शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना

श्री आफताब अहमद, विधायक द्वारा सदन की अधिकारी दीर्घा में

शून्य काल के दौरान किसी भी सीनियर अधिकारी के न बैठे

होने बारे मामला उठाना

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

आर्ट ऑफ लिविंग के सत्र में भाग लेने के सम्बन्ध में सूचना देना

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

शोक-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में शोक-प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, कल के दिन ही दो दुःखद घटनाएं हुई हैं।

जिसके सन्दर्भ में मैं सदन के सामने शोक-प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

श्री देवेन्द्र ढांडा

यह सदन राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे श्री देवेन्द्र ढांडा के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

वीर सैनिक

यह सदन लेफ्टिनेंट अक्षत जिला, हिसार के दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 को हुए दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव पढ़े हैं पूरा सदन इन दोनों परिवारों के प्रति दुःख की घड़ी में खड़ा हुआ है।

श्री वरुण चौधरी (मुलाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखे हैं मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे श्री देवेन्द्र ढांडा के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक

प्रकट करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से लेफ्टिनेंट अक्षत जिला, हिसार के दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 को हुए दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विपक्ष के माननीय सदस्य और आदरणीय उप मुख्य मंत्री ने जो अपनी संवेदना प्रकट की है मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। मैं भी अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर एक मिनट के लिए मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर एक मिनट के लिए मौन धारण किया गया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

सड़कों का निर्माण कार्य

***21. श्री प्रदीप चौधरी :-** क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) कालका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मौली से भूरेवाला सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाना था; तथा
- (ख) उपरोक्त सड़क को पूरा करने में देरी के कारण क्या है तथा इसके निर्माण के समय भी सड़क के टूटने के कारण क्या है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir,

- (a) The stipulated date of completion for the work was 24.11.2022.
- (b) The work was completed on the scheduled date. However, due to heavy flood in July/August, 2023 some patches developed. These have been repaired by the contractual agency and the road is in good condition now.

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो अगर कहीं पर कोई नई सड़क बनवानी होती है तो उसके लिए कई-कई साल तक अखबारों के माध्यम से बात उठानी पड़ती है कि सड़क टूटी पड़ी है और लोग परेशान हैं। उसके बाद जब साल दो साल के बाद किसी सड़क के बनने का नम्बर आता है तो सड़क बनते-बनते ही सड़क टूटनी शुरू हो जाती है। हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि बरसात के कारण कई जगह सड़क में गड्ढे पड़ गये जिनका पैच वर्क करवा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि यह सड़क तो बनते-बनते ही टूट गई थी। उस समय जब केशव कालोनी, रायपुररानी के कुछ दुकानदार आपके पास आये और उन्होंने यह कहा कि वहां पर जो नाला बन रहा है वह गलत बन रहा है उनके द्वारा उस नाले का बहुत विरोध किया गया लेकिन अधिकारियों द्वारा उनकी आवाज की सुनवाई नहीं की गई और आज भी उस नाले की स्थिति वैसी की वैसी है। बरसात के मौसम में उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर अब भी बरसात पड़ेगी तो अब भी पहले की ही तरह पानी भर जायेगा। चाहे केशव कालोनी हो, कशाल वाला मंदिर हो और चाहे आईडिया टॉवर कॉलोनी हो वहां के सभी लोग आज भी उस नाले से परेशान हैं। जब भी बरसात पड़ती है तो तहसील के सामने दो-दो फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। वहां पर डिवाइडर टूटे पड़े हैं। शुक्रवार को जब मेरा क्वेश्चन लगा तभी वीरवार को वहां पर पैच वर्क का काम किया गया। वहां पर अगर गांव गढ़ी से लेकर रायपुररानी तक देखा जाये तो कितने पैच वर्क उसमें हुए हैं। वहां पर नाले टूटे पड़े हैं। जो पांच-पांच फुट का फुटपाथ बनाया गया था वह भी टूटा पड़ा है। फुटपाथ तो कहीं-कहीं पर दब

भी गया है। फुटपाथ का कहीं पर भी पता नहीं चलता। पी.डब्ल्यू.डी. के स्तर पर उस सड़क में यूज किये गये मैटीरियल की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये। आज वहां पर लोग इस सड़क के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके डर से अकेली केशव कॉलोनी में से ही दो-तीन परिवार अपने मकान बेचकर पलायन करके चले गए हैं। मेरी बार-बार यही रिक्वेस्ट है कि इस सड़क में यूज किए गए मैटीरियल की पी.डब्ल्यू.डी. के स्तर पर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये। यह स्टेट हाईवे का मामला है। यह रोड बड़ी मुश्किल से बनी है। बनते-बनते ही यह सड़क टूटनी शुरू हो गई। वहां पर जगह-जगह नाले टूटे पड़े हैं। इसकी जांच करवाई जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस सड़क की बात कही थी वह मौली से भूरेवाला सड़क थी। इस सड़क की टोटल लम्बाई 13.4 किलोमीटर है। इस सड़क की date of completion 30.11.2022 थी और 24.11.2022 को इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। इस सड़क के निर्माण में कोई डिले नहीं हुआ है जैसा कि माननीय सदस्य ने बोला है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने कहा कि सड़क टूट गई। माननीय सदस्य की पूरी कांस्टीच्युएंसी में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां इस बार जुलाई में हैवी मानसून के कारण रोड डेमेज न हुई हो केवल पी.डब्ल्यू.डी. और स्टेट हाईवेज की बात ही नहीं है, शिमला जाने वाला नैशनल हाईवे जो इतने बड़े कंक्रीट वॉल के साथ गार्डिड था उसको भी पंचकूला और कालका के बीच में पानी का बहाव काटकर ले गया। जहां इस सड़क में पानी के बहाव से नुकसान हुआ था वह टोटल रिपेयर कर दिया गया था। यह सड़क डिफैक्ट लॉयबिलिटी पीरियड के अंदर होने के कारण किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं बल्कि उस कांट्रैक्टर ने ही इस सड़क की रिपेयर की है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक नहीं 1200 से ऊपर गांवों को जोड़ने या टच करने वाली छोटी-बड़ी सड़कों का नुकसान हुआ है और हमने प्रॉयरेटी के तौर पर उन सभी सड़कों को इमीडियेट रिपेयर में डाला ताकि संसाधनों की मूवमेंट में कोई कमी न आये। फिर भी माननीय सदस्य यदि कहते हैं कि कोई स्पैसिफिक

कॉलोनी का कोई स्पैसिफिक नाला बनाया जाना है तो इस बारे मेरा यही कहना है कि नाला बनवाना और नाला मेनटेन करना कई जगह एम.सी.जी. का काम है और कई जगह पंचायती राज का काम है। हमारी व्यवस्था सिर्फ इतनी होती है कि इनीशियली तौर पर जब सड़क बनती है तो वहां प्रॉविजन डाली जाये। लोग अपनी व्यवस्था के लिए भी मिलते हैं क्योंकि दुकान के पास नाला ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है। उसकी समयानुसार हम रिमॉडलिंग करते रहते हैं।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब नाला बनाया जा रहा था उस समय वहां के लोग पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों के पास मिलने के लिए गए उस समय अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया कि हम उसको ठीक कर देंगे लेकिन आज भी वह नाला ठीक नहीं हुआ है। आज भी वहां के लोग बरसात से डरते हैं कि पता नहीं कब बरसात हो जाये और उनके घरों और दुकानों में पानी भर जाये। इससे वहां पर एक बहुत बड़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहां पर नाले टूटे पड़े हैं। परसों ही वहां पैच वर्क का काम शुरू किया गया है। जब विधान सभा में मेरा सवाल लगा उसके बाद ही वहां पर काम शुरू किया गया। ये मेरे पास परसों की फोटोज हैं। मेरा बार-बार यही कहना है कि इस नाले को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये क्योंकि पिछली बार लोगों के घरों और दुकानों में पानी जाने के कारण फ्रिज खराब हो गये, गेहूं खराब हो गई और कपड़े खराब हो गये। मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल एक सड़क से शुरू हुआ था और अब नाला बनाने पर आ गया है। मैं इसकी इन्क्वायरी करवा लेता हूं और संबंधित विभाग चाहे वह रूरल डिवैल्पमेंट हो या अर्बन लोकल बॉडीज का एरिया पड़ता हो उनसे हम पानी की एक्सैस के लिए लैंड उपलब्ध करवाने के लिए कहेंगे। आपने स्वयं देखा है कि एन.एच.ए.आई. जैसी एजेन्सी को भी इसमें दिक्कत आती है क्योंकि रेन वाटर ड्रेन तो हाइवे के साथ-साथ बन

जाती है लेकिन उससे आगे एक्सेसिबिलिटी के लिए लैंड नहीं मिलती है जिसके कारण आगे पानी नहीं निकल पाता है। इसके बावजूद भी मैं इसकी इन्कवायरी करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: उप-मुख्यमंत्री जी, वहां पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आप एक नाला बनवा दीजिए यह समस्या समाप्त हो जायेगी। वह तो सड़क के साथ ही नाला बनना है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा।

अतिथि अध्यापकों को नियमित करना

***22. श्री सुरेन्द्र पंवार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएं कि :-

(क) क्या राज्य में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों की सेवाएं

नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अतिथि अध्यापकों की सेवाएं कब तक नियमित किए जाने की संभावना है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) श्रीमान जी, अतिथि अध्यापकों की सेवाएं हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम, 2019 के तहत कवर की गई है। अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत अतिथि अध्यापक सेवानिवृत्ति की आयु तक विभाग में कार्यरत रहेंगे, भले ही उनकी नियुक्ति का तरीका या सेवा की अवधि कुछ भी हो।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सुरेन्द्र पंवार: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश के राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए लगभग 20 हजार शिक्षक भर्ती किये थे। उस समय जल्दी में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी इसलिए अतिथि अध्यापकों की भर्ती की गई। वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में लगभग 12746 अतिथि अध्यापक कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी की

सरकार में 9 साल के कार्यकाल के बाद भी अतिथि अध्यापकों को नियमित नहीं किया गया। जहां तक मंत्री जी के जवाब की बात है तो उसमें यह लिखा हुआ है कि ये अतिथि अध्यापक 58 साल यानी सेवा निवृत्ति की तिथि तक कार्यरत रहेंगे। जहां तक अतिथि अध्यापकों और नियमित अध्यापकों की सैलरी की बात है तो जे.बी.टी. गैस्ट टीचर्स को 35400/- रुपये का स्लैब दिया जाता है जबकि नियमित जे.बी.टी. टीचर्स को 55 हजार रुपये का स्लैब मिलता है। इसी प्रकार से टी.जी.टी. की बात की जाये तो गैस्ट टीचर्स को 39900/- तथा नियमित टीचर्स को 65 हजार रुपये का स्लैब मिलता है। अगर पी.जी.टी. की बात की जाये तो इसमें भी गैस्ट टीचर्स को 47600/- रुपये तथा नियमित टीचर्स को 70 हजार रुपये का स्लैब मिलता है जबकि वे भी पूरे समय तक ड्यूटी देते हैं। उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जाता है? उनको सर्विस करते हुए 18 साल का समय हो गया है इसलिए उनको उनके सभी अधिकार मिलने चाहिए। जहां तक उनकी ट्रांसफर पॉलिसी की बात है तो इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। अध्यापकों के साथ ही अतिथि अध्यापकों की भी 5 साल के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें गैस्ट टीचर्स को भी ठहराव होना चाहिए तथा गैस्ट टीचर्स को भी यैस और नो का ऑप्शन होना चाहिए। जहां पर पति-पत्नी गैस्ट टीचर्स हैं उनको भी नियमित टीचर्स की तरह अतिरिक्त अंक मिलने चाहिए। मैं आपके माध्यम से इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में जब गैस्ट टीचर्स की भर्ती की गई थी तब वह पीरियड के हिसाब से भर्ती की गई थी लेकिन उसके बाद उनको रेगुलर तनख्वाह दी जाने लगी। उसके बाद 12.03.2019 को हरियाणा स्टेट गैस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट, 2019 लागू किया गया। यह उन्हीं की डिमांड थी और यह उनके साथ विचार-विमर्श करके लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत गैस्ट टीचर्स 58 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे यानी उनको बीच में हटाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही हम हटायेंगे। इस एक्ट में गैस्ट टीचर्स की सर्विस को रेगुलर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस एक्ट के तहत गैस्ट टीचर्स को दिये जाने वाले मासिक मानदेय पर रेगुलर टीचर्स को दिये जाने वाले डी.ए. के अनुरूप वर्ष में दो बार जनवरी तथा जुलाई में महंगाई भत्ता दिया जाता है। और यह बढौतरी तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैस्ट टीचर का मानदेय रेगुलर अध्यापक के एंट्री लैवल की न्यूनतम बेसिक पे के बराबर नहीं हो जाता तब तक गैस्ट

टीचर का यह मानदेय बढ़ता रहेगा लेकिन वह रेगुलर टीचर की बेसिक पे से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें यही प्रावधान है और इसके अनुसार ही हम उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं और दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2021 में गैस्ट टीचर्स के संबंध में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिये थे और वह कमेटी गठित भी हुई थी लेकिन अभी तक सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट का फैसला नहीं किया है। वह भी निर्धारित किया जाए और उसके बारे में भी बताया जाए कि उसके बारे में सरकार ने क्या किया है।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे ध्यान में नहीं है कि कौन सी कमेटी गठित की गई थी लेकिन यह बात उस समय की है जब एक्ट 2019 लागू किया गया था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि हम गैस्ट टीचर्स को 58 साल तक नहीं हटाएंगे। ये गैस्ट टीचर्स 58 साल तक सर्विस कर सकेंगे। वह प्रावधान तो इसमें है। जहां तक माननीय सदस्य ने ट्रांसफर की बात कही है तो वह कोर्ट का ही आदेश है कि पहले रेगुलर टीचर को स्थान दिया जाएगा उसके बाद गैस्ट टीचर को स्टेशन दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गैस्ट टीचर्स की सैलरी के बारे में तो बताया ही नहीं।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, सैलरी के बारे में हमने बता तो दिया है कि उस समय यह समझौता हुआ था कि गैस्ट टीचर की सैलरी रेगुलर टीचर की बेसिक पे से ज्यादा नहीं हो सकती है। वह चाहे टी.जी.टी. है या पी.जी.टी. है।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, यह काम तो एक्ट में प्रावधान करके भी किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : पंवार जी, यह आपकी मांग है उसको मंत्री जी देख लेंगे।

बाढ़ की रोकथाम

*23 श्री हरविंदर कल्याण : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:

- (क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2023 के दौरान यमुना नदी में बाढ़ के कारण करनाल जिले का यमुना बेल्ट क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था और बाढ़ का पानी उक्त क्षेत्र के खेतों और गांवों में घुस गया था; तथा
- (ख) यदि हाँ, तो भविष्य में इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या किए जाने की संभावना है?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) भविष्य में इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही का विवरण **Annexure-I** पर संलग्न है।

Annexure-I

भविष्य में करनाल जिले में इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई और की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है: –

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

- ❖ चरखी दादरी खदान से लाए गए पत्थर (बोल्डर) और एनएफएल पानीपत और थर्मल पावर प्लांट पानीपत से कोयला पत्थर (बोल्डर) को डंप करके लालूपुरा कॉम्प्लैक्स पर मौजूदा स्टड/संरचनाओं को मजबूत किया गया।
- ❖ नबियाबाद, खिराजपुर और कुंडाकलां कॉम्प्लैक्सों पर एनएफएल पानीपत से लाए गए कोयला पत्थर (बोल्डरों) को डंप करके मौजूदा स्टड/संरचनाओं को मजबूत किया गया।

.....

❖ @ उपरोक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा दिया गया ।

- ❖ कलसोरा, नबियाबाद, डबकोली, शेरगढ़ टापू, मोदीपुर, जरौली, नबीपुर, खिराजपुर, कुंडाकलां, ढाकवाला, सदरपुर, मुंडीगढ़ी और बल्हेरा कॉम्प्लैक्सों पर लकड़ी की बल्लियों के साथ झाड़ी लगाकर नदी के सक्रिय किनारे की सुरक्षा की गई।
- ❖ कलसोरा, नबियाबाद, खिराजपुर, ढाकवाला, लालुपुरा, सदरपुर परिसरों पर यमुना नदी के प्रवाह को मोड़ने के लिए मौजूदा स्टडों के बीच बल्ली स्पर बनाकर नदी के सक्रिय किनारे की सुरक्षा की गई।
- ❖ कलसोरा, नबियाबाद, डबकोली, शेरगढ़ टापू, मोदीपुर, जरौली, नबीपुर, खिराजपुर, कुंडाकलां, ढाकवाला, लालुपुरा, सदरपुर, मुंडीगढ़ी और बल्हेरा कॉम्प्लैक्सों पर मिट्टी से भरे ईसी बैगों को एमएस वायर क्रेटों के साथ-साथ कटाव की जगहों पर बिछाया गया।
- ❖ कलसोरा, नबियाबाद, डबकोली, शेरगढ़ टापू, मोदीपुर, जरौली, नबीपुर, खिराजपुर, कुंडाकलां, ढाकवाला, लालुपुरा, सदरपुर, मुंडीगढ़ी और बल्हेरा कॉम्प्लैक्सों पर आबादी क्षेत्र और कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए सक्रिय नदी किनारे, नदी तटबंध की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पॉकलेन/जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर, अन्य मशीनरी और मजदूरों की तैनाती की गई।
- ❖ उपरोक्त बाढ़ कार्य हेतु 506 फीट की लंबाई में तटबंध को भरने और 45700 फीट की लंबाई में कटाव वाले हिस्से को भरने के लिए 9,69,52,654/- रुपये खर्च किए गए हैं।

सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

दिनांक 30.10.2023 को आयोजित हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 55वीं बैठक में बाढ़, 2023 के बाद निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किए गए हैं:-

Sr. No.	Description of work	Estimated cost. in lakhs
1.	Providing protection to Dhanaura embankment of river Yamuna by providing brick pitching on inner side slope from RD 41300 to 41700 & 47290 to 47730 for protection of the village abadi and agriculture land .	22.00
2.	Providing protection to Kalsora Complex of River Yamuna by repairing 03 No. old damaged stone studs	400.00

Sr. No.	Description of work	Estimated cost. in lakhs
	and construction of 1500' new stone revetment to protect the agriculture land.	
3.	Providing protection to Nabiabad complex by repairing of 08 No. old damaged stone studs and construction of stone revetment of 600' to protect the agriculture land on river Yamuna.	300.00
4.	Providing protection to Jarauli complex by constructing 04 No. new stone stud to protect agricultural land.	125.00
5.	Providing protection to Khirajpur complex by constructing 490' Stone Revetment and repairing of 4 No. old Stone studs to protect river embankment and abadi area.	400.00
6.	Providing protection to Kundakalan Complex by constructing 03 No. new stone studs and 600' stone revetment and repair of 7 No. old damaged stone studs to protect abadi area.	450.00
7.	Providing protection to Dhakwala complex by constructing 02 No. new Stone Studs and 2139' Stone Revetment to protect the abadi area and agriculture land.	450.00
8.	The work of providing protection to Lalupura Complex of river Yamuna by repairing 07 No. old damaged stone studs and construction of 02 No. new stone studs(As per design adopted by Irrigation Deptt. of Uttar Pradesh state) and 3300' new stone revetment.	1200.00
9.	The work of providing protection to Sadarpur Complex of river Yamuna by repairing 02 No. old damaged stone studs and construction of 675' new stone revetment to protect abadi area and agriculture land.	130.00
	Total Estimated Amount	3477.00

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, उस समय जो बाढ़ की स्थिति बनी थी उस समय विभाग ने बहुत अच्छा काम किया था। अभी जवाब के अन्दर यह भी बताया गया है कि सरकार

ने ऐसे 9 खतरनाक प्वायंट्स को कवर किया है और उसके लिए लगभग पौने पैंतीस करोड़ रुपये के प्रस्ताव फ्लड कंट्रोल बोर्ड के पास भेजे गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो ये पौने पैंतीस करोड़ रुपये की लागत के प्रस्ताव आए हैं उनको मंजूर करवाया जाए। इसी के साथ मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा और मैं एक मांग भी करूंगा कि जब बरसात के दौरान ऐसी कोई एमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो यमुना नदी का बांध कच्चा होने के कारण वहां पर मैटिरियल पहुंचाने में बड़ी दिक्कत आती है तो ऐसे जो रिस्की प्वाइंट्स हैं उनको चिन्हित करके यमुना नदी के बांध के हिस्से को मोटेबल जरूर किया जाए ताकि एमरजेंसी में ट्रक के माध्यम से वहां मैटिरियल पहुंचाना आसान हो सके। ऐसा मैं सुझाव भी देता हूं और मांग भी करता हूं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात की है उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में पौने पैंतीस करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर कर दिये हैं। इनके एस्टीमेट बन गये हैं और विभाग द्वारा जल्दी ही ये कार्य कर दिये जाएंगे। माननीय सदस्य जो रास्ते की समस्या बता रहे हैं तो जैसे भी रास्ते होंगे 5 करम के, 6 करम के या 3 करम के उसमें हमारी नीति है कि हम उन विभागों को निर्देश दे देंगे कि वे उन रास्तों के बारे में विचार करके उनको बनाने की प्रक्रिया शुरू करें।

श्री हरविन्द्र कल्याण : स्पीकर सर, यह रेवैन्यू रिकॉर्ड के रास्ते के साथ-साथ यमुना नदी के बांध का जो ऊपर का हिस्सा होता है खास तौर पर उस रास्ते को मोटेबल करना जरूरी है क्योंकि उसी के माध्यम से ही साईट पर सामान जा सकता है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम विभाग को यह निर्देश देंगे कि जहां-जहां खतरनाक प्वाइंट्स हैं वहां तक गाड़ी सामान की भर कर चली जाए। ऐसी व्यवस्था हम करेंगे।

मुकंद लाल नागरिक अस्पताल में सुविधाएं

*24. श्री घनश्याम दास : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएं कि:—

- (क) क्या यमुनानगर में मुकंद लाल नागरिक अस्पताल के नवनिर्मित 200 बैड के भवन में कैथ लैब, आई.सी.यू. रेडियो थैरेपी तथा अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे कि एम.आर.आई. इत्यादि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा
- (ख) यदि हां, तो इसमें उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज):

- (क) श्रीमान जी, नव निर्मित अस्पताल में पी.पी.पी. मोड के तहत कैथ लैब तथा एम. आर.आई सेवाएं स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। परन्तु वर्तमान में, आई.सी.यू. स्थापित करने या रेडियोथेरेपी सेवाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

- (ख) कैथ लैब तथा एम.आर.आई सेवाएं के लिए निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगभग 6 महीने का समय अपेक्षित है।

श्री घनश्याम दास: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे यहां नए हस्पताल की बिल्डिंग बनी है और सरकार ने लगभग 100 करोड़ रूपया उस पर खर्च करने का काम किया है। हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट हैं अर्थात् कल्याणकारी राज्य हैं। लोगों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाना हमारा कर्तव्य है और जो यह चार सेवाओं की मैंने मांग की है ये मूलभूत सेवाओं में ही आती हैं। गरीब लोगों को इनके लिए बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि दो के बारे में तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि छः महीने में करेंगे और दो के बारे में कहा है कि विचाराधीन नहीं है। जो छः महीने में करने का प्रस्ताव इन्होंने रखा है उसकी समय सीमा कम की जाये और दूसरी दो सेवायें भी शीघ्रताशीघ्र जनहित में शुरू की जाये।

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि अत्याधुनिक सुविधायें सभी हस्पतालों को प्रदान की जायें। जहां तक कैथ-लैब की बात है, ये पी.पी.पी.मोड में अम्बाला, फरीदाबाद, गुरूग्राम और पंचकुला में चल रही हैं और सोनीपत, बहादुरगढ़, झज्जर और यमुनानगर में यह कैथ-लैब जल्दी ही लगाने के लिए निविदाएं दी जा चुकी हैं। उसी प्रकार एम.आर.आई. की जो सुविधायें हैं वे अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम और पंचकुला में पी.पी.पी. मोड पर चल रही हैं और पांच जिलों अर्थात् कुरूक्षेत्र, पानीपत, बहादुरगढ़, पलवल तथा चरखी दादरी में लगाने की हमारी योजना है। स्पीकर सर, हम इन्हें बाकी सभी हस्पतालों में लगाना चाहते हैं लेकिन कई जगह पर स्थान उपलब्ध नहीं हैं और बावजूद इसके हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी स्थान उपलब्ध हों और तुरंत प्रभाव से वहां पर भी ये सुविधायें प्रदान की जा सकें। स्पीकर सर, मैंने आदेश दिया था कि प्रदेश की जितनी भी टूटी-फूटी पी.एच.सीज. हैं, उन सभी को तोड़कर नया बनाया जाये। इनकी 162 की सूची मेरे हाथ में है अगर आप कहें तो मैं इनको पढ़कर भी सुना दूंगा। अगर पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि 162 जो पुरानी टूटी फूटी पी.एच.सीज. हैं, उनको तोड़कर बनाने का हमने टैंडर दे दिया है और कुछ जगह पर इनको तोड़ने का काम शुरू भी हो चुका है और बाकी जगह पर भी नई पी.एच.सीज. बनाकर देंगे। इसके अतिरिक्त जहां तक बात एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल की है तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि 134 सब हैल्थ सेंटर, 2 प्राइमरी हैल्थ सेंटर, 1 कम्युनिटी हैल्थ सेंटर और 37 पब्लिक हैल्थ सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी जा चुकी है।

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि रेडियोथैरेपी तथा आई.सी.यू. की सुविधा को भी प्रदान करने का समय बता दिया जाये कि कब तक ये सुविधायें शुरू हो जायेंगी और मंत्री जी इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख लेंगे तो लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी यह विचाराधीन नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हर जिले में एक आई.सी.यू. जरूर खोल सकें और उसके लिए हम प्रयत्न भी कर रहे हैं।

लघु सचिवालय के भवन का निर्माण करना

***25. श्री अमरजीत ढांडा :** क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) क्या यह तथ्य है कि जुलाना का उपमंडल के रूप में दर्जा बढ़ाया गया है परन्तु इसमें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है; तथा
- (ख) क्या जुलाना में लघु सचिवालय के भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त के कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):

- (a) Yes, Sir. Julana has been upgraded as Sub-Division vide notification dated 07-12-2023 and administrative officer will be posted soon.
- (b) At present there is no proposal under consideration of the Government to construct a building of Mini Secretariat in Julana.

श्री अमरजीत ढांडा: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जुलाना को सब डिवीजन बनाने की जो 30-35 सालों की मांग थी, उस मांग को सरकार ने पूरा करने का काम किया है। इसके साथ ही मैं डिप्टी सी.एम. साहब से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर लघु सचिवालय की जमीन का प्रावधान करके जल्द से जल्द लघु सचिवालय बनाने का काम किया जाये। अगर ऐसा होगा तो लोगों को बहुत सुविधा हो जायेगी।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7.12.2023 को जुलाना एक नई सब डिवीजन के तौर पर अनाउंस हुई है और जल्द ही सरकार वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसरज की नियुक्ति भी कर देगी और सब डिवीजन की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड की तलाश भी की जा रही है लेकिन साथ ही मैं यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि अगर माननीय विधायक साथी जी भी थोड़ी गति दिखाते हुए, कंसर्ड डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जितनी जल्दी एफ.सी.आर. आफिस में इसकी प्रपोजल भिजवायेंगे उतनी जल्दी हम वहां पर सब डिवीजन की इंफ्रास्ट्रक्चर

बिल्डिंग और अन्य फैसिलीटीज जो बननी हैं, उनको जल्द से जल्द सरकार बनवाने का काम करेगी।

श्री अमरजीत ढांडा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय डिप्टी सी.एम. साहब को बताना चाहता हूँ हमारे यहां पर चारों तरफ नगर पालिका की काफी जमीन है और लोग इस जमीन को देने के लिए तैयार भी हैं। यहीं नहीं यहां पर सरकारी जमीन भी अवेलेबल है। जहां पर तहसील बनी हुई है उसके चारों तरफ नगर पालिका की जमीन अवेलेबल है। अतः निवेदन है कि इस दिशा में जरूर ध्यान दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: ढांडा जी, आप माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को इसको लिखित रूप में भिजवा दें वे उस पर विचार कर लेंगे और उप-मुख्यमंत्री जी कह भी रहे हैं कि आप इसे लिखित रूप में भेज दें तो वे इस पर निश्चित रूप से विचार कर लेंगे।

श्री अमरजीत ढांडा:अध्यक्ष महोदय, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपका भी तथा उप मुख्यमंत्री जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा जो आपने मेरे विषय पर इतनी गंभीरता दिखने का काम किया।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जुलाना को सब डिवीजन बनाने की नोटिफिकेशन हुए मात्र 11 दिन हुए हैं। 11 दिन के अंदर इनका सवाल भी लग गया है। यह तो माननीय सदस्य की एफिशियेंसी ही है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को जो भी सरकारी जमीन वहां पर सब डिवीजन के लिए सूटेबल लगती है, उसका प्रपोजल वे जितना जल्दी भिजवायेंगे उतनी जल्दी हम इसको आगे टेकअप करेंगे।

श्री अध्यक्ष: डिप्टी सी.एम. साहब, माननीय सदस्य ने इसके लिए आपका धन्यवाद भी किया है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के धन्यवाद का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

**चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर एवं चंडीगढ़ नगर निगम के
13 भूतपूर्व महापौरों का अभिनन्दन करना ।**

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि श्री अनूप गुप्ता, महापौर, नगर निगम, चंडीगढ़ एवं अन्य 13 भूतपूर्व महापौर, नगर निगम, चंडीगढ़ आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

तारांकित प्रश्न संख्या 26

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राकेश दौलताबाद सदन में उपस्थित नहीं थे।)

फसल बीमा के खाते पर बकाया राशि

***27. डॉ. अभय सिंह यादव :** क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) रबी 2022 में सरसों की फसल के लिए महेन्द्रगढ़ जिले में फसल बीमा के खाते पर किसानों को दी जाने वाली कुल बकाया राशि कितनी है; तथा
- (ख) महेन्द्रगढ़ जिले में किसानों को कुल बकाया राशि का भुगतान किस तारीख तक किए जाने की संभावना है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई) के तहत रबी 2022-23 में सरसों की फसल के लिए सभी क्लेमों की एवज में महेन्द्रगढ़ के संबंधित किसानों को 6.75 करोड़ रुपये की पूर्ण राशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में जिले में किसी भी किसान का कोई क्लेम बकाया नहीं है।

डॉ. अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी या तो मेरे प्रश्न को प्रोपर समझ नहीं पाये हैं या फिर मैं माननीय मंत्री जी को प्रोपरली समझा नहीं पाया हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि रबी 2022 में सरसों की फसल के लिए महेन्द्रगढ़ जिले में फसल बीमा के

खाते पर किसानों को दी जाने वाली कुल बकाया राशि कितनी है। रबी 2023 की फसल तो अभी बोई ही जा रही है ?

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, रबी 2022 में सरसों की फसल के लिए महेन्द्रगढ़ जिले में फसल बीमा के खाते पर किसानों को दी जाने वाली कुल बकाया राशि कितनी है, के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि यह बकाया राशि कुछ नहीं है।

डॉ. अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, वे फार्मर्ज जिन्होंने बीमा करवा रखा है और जिनका पैसा भी कटा हुआ है वे फार्मर्ज अभी भी पेमेंट की इंतजार कर रहे हैं। आप इस बात का जवाब दें।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों से कुल 1943.34 करोड़ रुपये लिए गए हैं और इसमें स्टेट का शेयर 2575.10 करोड़ रुपये तथा सैंटर का शेयर 2295.42 करोड़ रुपये हैं अर्थात् कंपनियों को कुल 6813.87 करोड़ रुपये की राशि गई है। किसानों को हम कुल 7967.40 करोड़ रुपये दे चुके हैं। लगभग साढ़े ग्यारह सौ करोड़ रुपये की राशि से कंपनियां घाटे में हैं। अभी भी कुछ क्लेम डिस्प्यूटिड हैं जोकि 287 करोड़ रुपये की राशि है। इस तरह से यह राशि मिलाएं तो कंपनियों को 1400 करोड़ रुपये का लॉस हरियाणा में हुआ है। सरकार पूरी शिद्दत से किसानों का पक्ष रखती है और इस योजना में सुधार करने की कोशिश भी लगातार कर रही है। कई जगह ऐसा है कि पैसा कंपनी के पास नहीं पहुंचता और बैंक के पास ही रह जाता है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है कि बैंक के खिलाफ हम क्लेम डालते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस तरह के पैसों की पैडेंसी हो सकती है लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर इस क्षेत्र की सबसे ज्यादा अर्थात् मैक्सिमम पे-आउट हुई है।

डॉ. अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री जी से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि क्या शत-प्रतिशत किसानों को सरसों का पैसा मिल गया है ?

श्री अध्यक्ष: अभय जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया तो है कि 287 करोड़ रुपये की क्लेम की डिस्प्यूटिड राशि है ?

डॉ.अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने जब माननीय मंत्री जी से पूछा तो तब तो कह रहे थे कि कंपनी से डिस्प्यूट हो रहा है, इस वजह से यह काम नहीं हो रहा है। वैसे मैं एक डिटेल पता कर लेता हूँ।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, बीमा योजना की कुछ इस प्रकार की टर्म्ज एंड कंडीशंज हैं कि कोई कैलामिटी कैसे होती है। अगर ओलावृष्टि होती है तो हानि किसी इंडिविजुअल किसान की नहीं होती बल्कि जो गांव का कलस्टर होता है, उस पूरे कलस्टर की हानि होती है। नुकसान होगा तो ही बीमा मिलता है। यह नहीं कि हर कोई बीमा करवा ले उन सबको बीमा की राशि मिल जाये, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता लेकिन जिसका नुकसान का आंकलन होता है उसको बीमे की राशि मिलती है और हरियाणा का मैंने डाटा पेश भी कर दिया है कि हरियाणा जितना क्लेम, किसानों को पूरे देश में कहीं पर भी नहीं मिलता है।

डॉ. अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि किसानों की जो बकाया राशि है, वह लिस्ट मंत्री जी को भिजवा दूंगा।

एन.टी.पी.सी. पावर प्लांट से रिसाव की जाँच करना

28. श्री लक्ष्मण सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:

- (क) क्या एन.टी.पी.सी. पावर प्लांट, झाड़ली के जल रिसाव, जिसके कारण कोसली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, को रोकने/जांचने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा
- (ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) एन.टी.पी.सी. पावर प्लांट, झाड़ली में जल रिसाव के कारण जमा हुए पानी को बाहर निकालने की परियोजना 31.12.2024 तक पूरी हो जाएगी।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, झाड़ली का पावर प्लांट एन.टी.पी.सी. के द्वारा चलाया जा रहा है। वहां पर जल रिसाव होता था और कोयले को धोने का कार्य भी पानी से ही हो रहा था। इसकी वजह से किसानों की फसल निरंतर खराब होती रही। शुरूआत में एन.टी.पी.सी. ने किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया था। वर्ष 2012-13 में एन.टी.पी.सी. ने किसानों को 39 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान का मुआवजा दिया, वर्ष 2013-14 में किसानों को 49 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान का मुआवजा दिया गया और वर्ष 2014 तथा वर्ष 2016 में 25 हजार रुपये से 30 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया था। वर्ष 2016 के बाद एन.टी.पी.सी. ने किसानों को यह कहकर मुआवजा देना बंद कर दिया कि हमने आई.आई.टी. रूड़की हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट से इसकी जांच करवा ली है और वह पानी उनका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब वहां पर यह पावर प्लांट नहीं लगा था तो उस समय वहां का वाटर लैवल 25 फुट गहरा था लेकिन उस पावर प्लांट के लगने के बाद वहां का वाटर लैवल 1-2 फुट पर पहुंच चुका है। अतः मेरा कहना है कि एन.टी.पी.सी. का यह कहना कि वह पानी उनका नहीं है, सही नहीं है। इस पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लैबोरेट्रीज भी इस तरह का झूठा फरमान जारी कर सकती हैं? अगर वह पानी एन.टी.पी.सी. का नहीं है तो फिर उन्होंने उस समय किसानों को 3 साल तक मुआवजा क्यों दिया जिसे अब बंद कर दिया गया है? वह पानी उनका था और इसको उन्होंने माना भी था। इधर-उधर से जांच करवाकर आज किसानों के साथ सीधा-सीधा धोखा हो

.....

@ उपरोक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा दिया गया।

रहा है। पानी की निकासी के साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि वर्ष 2016 के बाद किसानों का जितना भी मुआवजा बनता है माननीय मंत्री जी वह उनको दिलवाने की कृपा करें।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, इसका आंकलन करना आसान नहीं है कि वहां पर सेम की समस्या किस वजह से आई है। हरियाणा के ऐसे बहुत-से क्षेत्र हैं जहां पर पहले पानी 100 फुट की गहराई पर था और आज 2 फुट की गहराई पर आ चुका है तथा वहां पर एन.टी.पी.सी. का प्लांट भी नहीं है। हम यह मानते हैं कि वहां पर किसानों की 300 एकड़ के आसपास जमीन खराब हुई है। पिछले दिनों बाढ़ के संबंध में हमने एक मीटिंग की थी। उसमें हमने निर्णय किया था कि हम शैलो ट्यूबवैल्वज लगाएंगे और वहां पर तालाब बनाकर वहां से पानी को अगले 2-3 गांवों में ले जाकर उससे सिंचाई करेंगे। हमने इसकी योजना बनाई है। इस एरिया में सेम की समस्या को खत्म करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बना दिया है और इसका पानी हम फसल की दूसरी सिंचाई के समय लेकर आयेंगे। हमने एन.टी.पी.सी. को भी लिखा है कि उनके जो पक्के टैंक हैं वे उनकी अच्छी व्यवस्था करें ताकि सीपेज बिल्कुल भी न हो।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वह रिसाव तो पानी का ही है। मेरा कहना है कि अब आप उसको लिफ्ट करेंगे लेकिन जो पांच साल का किसानों का नुकसान है उसको कौन पूरा करेगा ? उसका मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। दूसरी बात, आप यह कह रहे हो कि बाढ़ आती रहती है और वॉटर लेवल बदलता रहता है लेकिन वॉटर लेवल बाढ़ के एरिया में ही तो बदलता है। ऐसे अचानक कहां से पानी का लेवल बदल जायेगा ? यह तो छोटी-सी बात है और इस छोटी-सी बात को तो आम किसान भी जानता है। मुझे तो यही लगता है कि माननीय मंत्री जी जवाब देने से बचना चाह रहे हैं। किसान को न्याय जरूर मिलना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि उसकी जीवन रेखा तो खेत ही है। अगर खेत ही बंजर हो गया और बोने लायक नहीं रहा तो वो बेचारा क्या करेगा ? सरकारी एजेंसियां लेबोरेट्रीज का नाम लेकर बार-बार बहाने बनाती हैं। वे कभी कहती हैं कि इसमें लवण नहीं है, कभी कहती हैं कि इसकी वजह से नहीं है तो वह पहले कैसे ठीक था और आज कैसे गलत हो गया है ? मेरे क्षेत्र के चार-पांच गांव हैं जिन

में से तीन तो मेरे झज्जर के ही हैं जैसे गोरिया, मोहनबाड़ी और झाड़ली। लीलोढ़ मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है। उसमें निरंतर यही समस्या है। इससे पहले वहां कभी समस्या नहीं आई तो आज समस्या कैसे आ गई? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मुझे यह बता दें कि किसानों को पांच साल का मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन्होंने पहले भी विरोध-प्रदर्शन किया था, इसीलिए एन.टी.पी.सी. ने उन्हें मुआवजा दिया था। आज वे बेचारे किसान परेशान हैं और बार-बार धरने पर बैठते हैं। फिर भी हम उनको यह कहते हैं कि आप थोड़ी तसल्ली रखिये, हम सरकार से बात करेंगे। अतः उनको यह पांच साल का मुआवजा दिया जाए क्योंकि किसान का चूल्हा तो इसी से चलेगा। माननीय मंत्री जी मुझे बताएं कि अगर किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वही जलमग्न हो गई तो उसका गुजारा कैसे होगा?

श्री जय प्रकाश दलाल : महोदय, जो सेम की समस्या है उसके लिए हमने पहले स्कीम बनाई थी कि इस पानी को निकाल कर ड्रेन नम्बर 8 में डालेंगे। अब हमने उस स्कीम को चेंज कर दिया है और हम वहां पर शैलो ट्यूबवैल लगा देंगे तथा टैंक बनाकर पानी को सिंचाई के लिए लेकर जायेंगे। सेम की समस्या के लिए हरियाणा सरकार ने स्कीम बना दी है। इसके अलावा किसानों का पहले का कितना मुआवजा बकाया है, मैं इसका डाटा लेकर चैक करवा लूंगा। अगर किसानों का कुछ क्लेम/बकाया हुआ तो हम उस पर विचार कर लेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे पास संबंधित किसानों के डाटा हैं जिनको मुआवजा मिलना है।

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मण जी, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि इसमें डाटा चैक करवाकर मुआवजा दे देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि क्या किसानों को मुआवजा मिलेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मण जी, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि इसमें डाटा चैक करवाकर बता देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इनका डाटा तो चैक हो गया है। इसमें संबंधित किसानों को मुआवजा दे दें और डिस्पॉजल होता रहेगा। यह तो लम्बी प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मण जी, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि इसमें डाटा चैक करवाकर देख लेंगे। अगर होगा तो जरूर दे देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इसमें डाटा तो चैक गया है। यह कई लैबोरेट्रीज ने चैक कर दिया है और वे कभी कुछ कह रहे हैं और कभी कुछ कह रहे हैं।

मारूति कंपनी के लिए अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा

***29. श्री जयवीर सिंह:-** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि खरखोदा में मारूति कंपनी को सरकार द्वारा कितनी भूमि उपलब्ध कराई जा रही है तथा सरकार द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहण की गई है तथा अधिग्रहण कब की गई ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir,

- (i) Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation has allotted approximately 800 acres of land to M/s Maruti Suzuki India Ltd. (MSIL) under Ultra Mega Project.
- (ii) About 3200 acres of land was acquired in the year 2013 for a public purpose namely for the development of Industrial Model Township (IMT) at Kharkhoda. Another left out pocket measuring approximately 18 acres was acquired in the year of 2016.

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि वर्ष 2013 में 3200 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी थी। उन्होंने बताया कि छोटे-छोटे टुकड़ों में 18 एकड़ जमीन और एक्वायर की गयी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके मार्केट रेट क्या हैं और किसानों को क्या मुआवजा दिया गया है?

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल the extent of land acquired by the Government and the time of acquisition के बारे में था और मैंने

उसका जवाब दे दिया है। माननीय सदस्य मार्केट रेट और उस समय के मार्केट रेट की डिटेल्स चाहते हैं तो मैं अलग से दे सकता हूँ क्योंकि एट हैंड इस क्वेश्चन से मार्केट रेट/कलैक्टर रेट रिलेट नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष: जयवीर जी, अब आपने जो सप्लीमेंट्री पूछा है उसमें एट दा स्पॉट मार्केट रेट के बारे में पता नहीं है।

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री में मार्केट रेट के बारे में पूछ रहा हूँ कि मार्केट रेट क्या हैं और किसानों को क्या दिया गया है? यह तो सीधी सी बात है। इसके बारे में बताने से सरकार क्यों बच रही है?

श्री अध्यक्ष: जयवीर जी, सरकार मार्केट रेट के बारे में पता करेगी क्योंकि एट दा स्पॉट इसके बारे में पता नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम सवाल के जवाब से बच नहीं रहे हैं। मैंने खड़े होकर भी यही बात कही है कि माननीय सदस्य ने जो सप्लीमेंट्री पूछा है कि वह संबंधित प्रश्न से इमिडिएटली रिलेट नहीं करती। माननीय सदस्य वर्ष 2013, वर्ष 2016 और आज के कलैक्टर रेट पूछ रहे हैं। अगर माननीय सदस्य आज का कलैक्टर रेट पूछना चाहते हैं कि मारूती ने कितने रेट पर जमीन ली है तो मैं बता सकता हूँ कि इसको 7314.32 रूपये पर स्कवेयर मीटर के हिसाब से लैंड दी गयी है। मैं यह जवाब तो दे सकता है कि आज के समय में किस रेट पर जमीन दी गयी है। उस समय के पुराने कलैक्टर रेट आज के समय से बहुत पुराने हैं इसलिए मैं वह कलैक्टर रेट का डाटा शेयर करवा दूँगा।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लोकरा, जिला गुरुग्राम के विद्यार्थीगण तथा
अध्यापकगण का अभिनन्दन करना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लोकरा, जिला गुरुग्राम
के अध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं।
मैं अपनी तथा सदन की तरफ से इनका अभिनन्दन करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

यौन उत्पीड़न पंजीकृत मामलों की संख्या

*30. श्री अभय सिंह चौटाला: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) वर्ष 2019 से आज तक महिला खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के सामने आए/सरकार द्वारा पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या कितनी है; तथा
- (ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा उक्त मामलों पर कानूनी कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

Home Minister (Shri. Anil Vij): Sir, a statement is placed on the Table of the House.

statement

Statement of Sh. Anil Vij, Home Minister in reply to Starred Question No. 30.

Sir,

The requisite year wise number of cases from 1st January, 2019 till 11th December, 2023 are tabulated below:

Years	2019	2020	2021	2022	2023	Total cases Registered	No. of cases cancelled
No. of Cases registered	5	2	6	3	8	24	06

The names of the officers against whom legal action has been taken by the Government in these cases and the details of action taken are as below:-

Year 2019:-

S.N	Case FIR No., U/s and Date	Police Station	District	Brief Facts	Action Taken
1	FIR No. 383 dated 20.08.2019 u/s 323/ 341/ 354/ 354-A/ 354-D/ 506/ 509 IPC & 25-54-59 Arms Act.	PS Bilaspur	Gurugram	Case has been registered on the complaint of a Taekwondo player against Sombir a Wrestling Coach, R/o Dist. Jhajjar	The accused arrested in this case and charge sheet put in Court on 22.12.2020. The Hon'ble Court has Acquitted the accused on 10.10.2023. Reasons:- The eye witness (her father) has expired on 21.09.2019 and complainant has also expired on 12.11.2019. The prosecution has failed to connect the offence u/s 25 Arms Act. with the accused.



2	FIR No. 62 dated 19.07.2019 u/s 354, 376, 506, 511, 120B IPC	WPS Rohtak	Rohtak	Case has been registered on the complaint of Wrestling Player against Sombir and Satyawart S/o Satyawan a Coach, R/o Rohtak.	The case has been cancelled on 01.08.2019. Reasons:- The complainant got married to the accused. After some time, they had a dispute due to which, the said FIR was registered against the family of Satywan. Later, complainant has stated to the police that she did not want to take any action in this matter.
3	FIR No. 127 dated 15.06.2019 u/s 354D(2), 500, 504 IPC	PS Adampur	Hisar	Case has been registered on the complaint of a Football Player against Pardeep, Harpal, Ramesh, Sunil & Tannu R/o Hisar.	All accused arrested in this case and charge sheet put in Court on 15.05.2023 and one accused acquitted on 02.03.2023. Reason:- Tanu was acquitted of the charge framed against her by extending benefit of doubt by the Hon'ble Court
4	FIR No. 148 dated 03.07.2019 u/s 354, 354A, 354D IPC & 8/10 POCSO Act.	PS Adampur	Hisar	Case has been registered on the complaint of a Football Player against Vinod Loyal @ Bedu a Football Coach R/o Chuli Bagriyan, Hisar.	The case has been cancelled on 20.08.2019. Reason:- The charge framed by the complainant was found false.

5	FIR No. 149 dated 04.07.2019 u/s 354, 354A, 354D, 506 IPC & 8/10 POCSO Act.	PS Adampur	Hisar	Case has been registered on the complaint of a Football Player against Bhal Singh a Football Coach R/o Sadalpur, Hisar.	The case has been cancelled on 20.08.2019. Reason:- The charge framed by the complainant was found false.
---	---	------------	-------	---	--

Year 2020:-

S.N	Case FIR No., U/s and Date	Police Station	District	Brief Facts	Action Taken
1	FIR No. 25 dated 09.03.2020 u/s 323/ 452/ 120-B/ 384/ 506 IPC & 4/6 POCSO Act. & SC/ST Act.	WPS Kurukshetra	Kurukshetra	Case has been registered on the complaint of a Hockey player against Gurmail Singh a Hockey Coach R/o Kishangarh, Kurukshetra.	The accused arrested in this case and charge sheet put in Court on 08.05.2020. The case is under trial in the Hon'ble Court.
2	FIR No. 89 dated 04.10.2020 u/s 328/ 354-A/ 354-D/ 376/ 376(2)N/ 506/ 120-B IPC & 6/8/12 POCSO Act.	WPS Bhiwani	Bhiwani	Case has been registered on the complaint of a Volleyball player against Sonu Kumar R/o Budheri, Parvesh S/o Jaibir Singh R/o Miran.	All accused arrested in this case and charge sheet put in Court on 21.05.2021 and Acquitted on 05.12.2022. Reason:- During the trial, prosecution witness turned hostile from his prosecution version.

9

Year 2021 :-

S.N	Case FIR No., U/s and Date	Police Station	District	Brief Facts	Action Taken
1.	FIR No. 212 dated 16.07.2021 u/s 354-D/376/ 452/ 506 IPC	PS City Thanesar	Kurukshetra	Case has been registered on the complaint of a Swimming Trainer against Pardeep Kumar a Lawyer R/o Kurukshetra.	The accused arrested in this case and charge sheet put in Court on 23.01.2023. The case is under trial in the Hon'ble Court.
2.	FIR No. 74 dated 12.07.2021 u/s 354-A/294/506 IPC & 12 POCSO Act. & 3 SC/ST Act.	WPS Hisar	Hisar	Case has been registered on the complaint of a Shooting player against Subhash a Football Coach R/o Hisar.	The case has been cancelled on 10.08.2021. Reason:- The charge framed by the complainant was found false.
3.	FIR No. 131 dated 21.10.2021 u/s 3(2)(v)/3(2)(v)(a) SC/ST Act & 376(2)(n)/376 (3)/506 IPC & 6 POCSO Act.	WPS Kaithal	Kaithal	Case has been registered on the complaint of a Taekwondo player against Vikram Kadyan a Taekwondo Coach R/o Kaithal.	The case has been cancelled dated 29.10.2021. Reason:- The charge framed by the complainant was found false.
4.	FIR No. 36 dated 27.03.2021 u/s 376(3)/506 IPC & 3 (2) (v) SC/ST Act. & 6 POCSO Act.	WPS Jind	Jind	Case has been registered on the behalf of parents of Victim against Krishan a coach R/o Kinana, Hisar and Goldi R/o Hansi.	All accused arrested in this case and charge sheet put in Court on 11.06.2021 and Acquitted on 11.05.2023. Reason:- During the trial, prosecution witnesses (complainant and victim) turned hostile from their prosecution versions.

5.	FIR No. 391 dated 08.10.2021 u/s 323/34/354/354-A/ 506/ 509/ 379-B IPC	PS Civil Line	Sirsa	Case has been registered on the complaint of a Judo Coach against Akhilesh Dev a Govt. Employee A R/o Sonipat.	The accused arrested in this case and charge sheet put in Court on 02.01.2023. The case is under trial in the Hon'ble Court. A preliminary enquiry was entrusted to the District Attorney, Gurugram. District Attorney Gurugram has submitted the preliminary enquiry report which was examined by their department and observation made that the matter has not been examined properly and detailed facts have not been provided. Therefore, Director Prosecution, Haryana has directed District Attorney, Gurugram to re-enquire and the report is still awaited.
6.	FIR No. 726 dated 10.11.2021 u/s 148/149/ 302/ 307/ 354-D/ 506 IPC & 25/27-54-	PS Kharkhoda	Sonipat	Case has been registered on the complaint of a Wrestling player against Pawan a	The accused were arrested in this case and charge sheet put in Court on 21.01.2022.

6

	59 Arms Act.			Wrestling Coach R/o Rohtak.	The case is under trial in the Hon'ble Court.
--	--------------	--	--	-----------------------------	---

Year 2022:-

S.No.	Case FIR No., U/s and Date	Police Station	District	Brief Facts	Action Taken
1	FIR No. 599 dated 07.10.2022 u/s 10 POCSO Act. & 354-D/354-A(1)(i)/506 IPC	PS Civil Line	Hisar	Case has been registered on the complaint of a Boxing player against Harish a Boxing Coach R/o Hisar.	The accused arrested in this case and charge sheet put in court on 03.11.2022. The case is under trial in the Hon'ble Court.
2	FIR No. 12 dated 09.07.2022 u/s 323/354-A IPC & 8/10 POCSO Act.	WPS Dabwali	Police District Dabwali	Case has been registered on the complaint of a Basketball player against Parveen Kumar, DPE R/o Choutala.	The accused arrested in this case and charge sheet put in court on 06.06.2023. The case is under trial in the Hon'ble Court.
3	FIR No. 13 dated 09.08.2022 u/s 342, 376 (3), 376(2)F, 506 IPC & 6 POCSO Act.	WPS Dabwali	Police District Dabwali	Case has been registered on the complaint of a Athletics player against Parveen Kumar, DPE R/o Choutala.	The accused arrested in this case and charge sheet put in court on 03.07.2023. The case is under trial in the Hon'ble Court.

Year 2023 :-

S.No.	Case FIR No., U/s and Date	Police Station	District	Brief Facts	Action Taken
1.	FIR No. 61 dated 27.07.2023 u/s 328/354/354(a)/376/506 IPC	WPS Kaithal	Kaithal	Case has been registered on the complaint of a Taekwondo player against Deepak Kumar a Taekwondo Coach R/o Kaithal.	The charge sheet put in court on 17.10.2023. The case is under trial in the Hon'ble Court.

2.	FIR No. 62 dated 29.07.2023 u/s 354/354-A/354-D(2) IPC	WPS Kaithal	Kaithal	Case has been registered on the complaint of a Wushu Player against Deepak Kumar a Wushu Coach R/o Kaithal.	The charge sheet put in court on 23.11.2023. The case is under trial in the Hon'ble Court.
3.	FIR No. 17 dated 19.01.2023 u/s 354D(I)(i)/354-D(I)/506 IPC	PS Siwani	Bhiwani	Case has been registered on the complaint of a Athletic coach against Rajesh Athletic Coach R/o Bhiwani.	The case has been cancelled on 15.04.2023. Reasons:- No evidence found during the investigation, verified by DSP/ Loharu. As the case registered against him was cancelled by the police on 15.04.2023. Hence, no departmental action has been taken against him by the Sports Department, Haryana.
4.	FIR No. 108 dated 31.07.2023 u/s 363/366-A/342/376-D/506 IPC & 6 POCSO Act.	WPS Jind	Jind	Case has been registered on the behalf on parents of Victim against Krishan a Coach Gurukul Academy, Julani R/o Jind.	The accused arrested in this case and charge sheet put in Court on 26.09.2023. The case is under trial in the Hon'ble Court.
5.	FIR No. 360 dated 22.05.2023 u/s 306,395 IPC & 10 POCSO Act.	PS Chandni Bhag	Panipat	Case has been registered on the complaint of a Badminton player against Amit Malik a Badminton Coach R/o Panipat	The accused arrested in this case and charge sheet put in Court on 10.08.2023. The case is under trial in the Hon'ble Court.

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सारी रिपोर्ट लिखकर दे दी है, लेकिन मैंने प्रश्न में यह बात पूछी है कि आपके पास यौन शोषण के मामले में जितनी शिकायतें आयी हैं क्या उन सब पर कार्रवाई हुई है? दूसरी बात यह है कि पिछली बार वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ 16658 शिकायतें आयी थी जोकि वर्ष 2022 में बढ़ गयी हैं। उसके बाद पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें भी 57.2 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने केवल चार्जशीट दाखिल की है। जबकि अपराध की संख्या देखी जाए तो वह बहुत बड़ी है। इनमें बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिसने भी सरकार को शिकायत की उसमें बाकी सभी जगहों पर तो जहां भी शिकायत आयी, उस पर तुरंत एक्शन ले लिया गया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और दोषी को सस्पेंड भी कर दिया गया। उनके खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश कर दिये गये लेकिन एक महिला खिलाड़ी ने सरकार के मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और उस मंत्री के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उसका बचाव किया। जहां सरकार ने उसका बचाव किया वहीं चण्डीगढ़ प्रशासन की तरफ से जब मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई तो उसके बाद सरकार ने मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की? हमें इसके बारे में भी बताया जाये। सरकार ने बाकियों के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी लेकिन सरकार ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? हमें इसका कारण भी बताया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों के खिलाफ शोषण के केवल 24 केस आये हैं और 24 में से 17 केस कोर्ट में चल रहे हैं। 6 अभियोगों में जांच के दौरान कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। 4 अभियोगों में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित नहीं होने के कारण उनको छोड़ दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य ने मंत्री श्री संदीप सिंह के बारे में बताया है तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि इनके केस की jurisdiction चण्डीगढ़ प्रशासन में पड़ती है। इनका केस चण्डीगढ़ में दर्ज हुआ है। हमारे पास जो शिकायत आई है उसमें ममता सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी उसकी जो भी रिपोर्ट आई थी वह भी हमने चण्डीगढ़ प्रशासन को दे दी है। अब चण्डीगढ़ प्रशासन ने यह केस कोर्ट में डाल दिया है तो matter is sub-judices मैं सब-जुडिस मैटर पर और अधिक बात नहीं करना चाहता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कह दिया कि यह केस चण्डीगढ़ से जुड़ा हुआ है। यह मामला चण्डीगढ़ की कोर्ट में है लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार का यह मंत्री है। शिकायतकर्ता कोच भी हरियाणा प्रदेश की है, वह कोई दूसरी स्टेट की नहीं है। यह मामला हरियाणा प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ममता सिंह की जो रिपोर्ट आई है माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह रिपोर्ट चण्डीगढ़ प्रशासन को दे दी है तो फिर इन्होंने वह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की ? इन्होंने बाकी दोषियों के बारे में भी तो लिखकर दिया है तो फिर ये मंत्री के बारे भी लिखकर दे देते। मैंने तो पार्टिकुलर उस कोच के बारे में लिखा है। जिस कोच को सरकार ने प्रोटैक्शन देने की बजाए, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कोच पर बार-बार केस को वापिस लेने का दवाब बनाया गया कि किसी भी तरीके से वह केस को वापिस ले ले। इन्होंने अपने मंत्री का बचाव किया है। यह मुकद्दा चाहे चण्डीगढ़ में दर्ज हुआ हो या दिल्ली में दर्ज हुआ हो या फिर दूसरी स्टेट में दर्ज हुआ हो। अगर सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उस केस में शामिल पाया जाता है तो क्या सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी या फिर कोई दूसरे स्टेट की सरकार आकर कार्रवाई करेगी ? अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक दो बातें और भी पूछना चाहूंगा कि अगर इस मामले में मंत्री इन्वॉल्व है और वह किसी कोच और खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो क्या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ? आप यह मानकर चलो कि देश के अंदर हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी सबसे ज्यादा मैडल जीतने का काम करते हैं। हमारी बेटियां सबसे ज्यादा मैडल लेकर आती हैं। कल को कौन मां बाप अपने बच्चों को स्टेडियम में खेलने के लिए भेजेंगे क्योंकि खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से प्रोटैक्शन प्राप्त नहीं हो रही है। जब एक मंत्री होने के नाते उन खिलाड़ियों के साथ इस तरह की कार्रवाई करेगा तो आप ही बताएं कि बच्चों को किस प्रकार से मां बाप स्टेडियम में खेलने के लिए भेजेंगे और किस प्रकार से वे स्टेडियम में खेलने के लिए जायेंगे ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने कहीं भी किसी का बचाव नहीं किया है। यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट का जो निर्णय

आयेगा उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जब तक यह मामला कोर्ट में है आप भी इस बात को जानते हो कि इस मामले को हम यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष :मंत्री जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है हम कोर्ट के मामले को यहां डिस्कस नहीं कर सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम बात है। आप भी मंत्री को बचाने में लगे हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मैं मंत्री जी को बचाने में नहीं लगा हूं। यह प्रश्न काल है न कि चर्चा का विषय है। प्रश्न काल के दौरान एक विधायक दो सप्लीमेंट्री पूछ सकता है। उन्होंने आपके द्वारा पूछी गई 4 सप्लीमेंट्री का जवाब दे दिया है। अब आप प्लीज बैठ जायें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको पूरे प्रदेश की जनता देख रही है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, अब आप प्लीज बैठ जायें।

वॉक-आउट

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है, उसका मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं इसलिए मैं इसके विरोधस्वरूप सदन से वॉक-आउट कर रहा हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला उनके द्वारा दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 30 पर उनके द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण विरोधस्वरूप सदन से वॉक-आउट कर गये।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

मैटरनिटी अस्पताल स्थापित करना

***31. श्री लीला राम :** क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि कैथल शहर के पुराने अस्पताल में 100 बेड का मैटरनिटी अस्पताल कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान, कैथल शहर के पुराने नागरिक अस्पताल परिसर में 100 बिस्तरीय एम.सी.एच. (मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य) विंग स्थापित किया जाना विचाराधीन है। निर्माण कार्य आवश्यक स्वीकृतियां जारी होने के बाद 2 से 3 साल की अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री लीला राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने पहले भगवान परशुराम जी के नाम पर कैथल में एक मैडिकल कॉलेज मंजूर करने का काम किया था जिस पर एक हजार करोड़ रुपये के करीब खर्च आया। इस पर दिन-रात काम चला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे कैथल शहर में एक पुराना हॉस्पिटल है, वहां पर हमारे पास 12 से 14 एकड़ जमीन है। यह जमीन बिल्कुल शहर के बीच में बहुत अच्छी जगह पर है। सरकार ने यहां पर मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य हॉस्पिटल मंजूर किया है। इसके लिए मैं सरकार तथा माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं इसके साथ ही सरकार से यह निवेदन भी करता हूं कि इसको बनाने के लिए दो-तीन साल का समय काफी ज्यादा है। जिस प्रकार भगवान परशुराम मैडिकल कॉलेज पर काम चला हुआ है उसी प्रकार माननीय मंत्री जी इस हॉस्पिटल का काम भी जल्दी से शुरू करवाने का काम करें ताकि शहर तथा जिलावासियों को राहत मिल सके।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हम प्रदेश में 8 जगह एम.सी.एच. (मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य) हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये हॉस्पिटल पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, नलहड़-नूंह, सिरसा तथा कैथल जिले में बने रहे हैं। जैसा कि माननीय विधायक जी ने हमें कैथल जिले में इसके लिए साइट बताई, हम इन्हें यह हॉस्पिटल उसी जगह पर बनाकर देंगे। विधायक जी यह भी बता रहे हैं कि यह साइट ठीक है।

मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह साइट सिलैक्ट भी कर ली गई है और हम यहां पर जल्दी ही यह हॉस्पिटल बनाकर देंगे।

श्री लीला राम: ठीक है, मंत्री जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

गावों के विकास पर खर्च की गई राशि

***32. श्री नयन पाल रावत :** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएं:—

- (क) क्या यह तथ्य है कि पृथला विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के सात गांव अर्थात् नवादा, मुजेडी, मच्छगर, सोलई, साहुपुरा, मलेरना तथा चन्दावली को फरीदाबाद नगर निगम में शामिल किया गया है तथा चार गांव अर्थात् फिरोजपुर, अगवानपुर, आल्हापुर तथा नया गांव—फजलपुर को पलवल नगर परिषद में शामिल किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो उनकी पंचायत निधियों का ब्यौरा क्या है तथा जब इन गांवों को नगर निकायों में शामिल किया गया तब कितनी जमीन थी; तथा
- (ग) उपरोक्त निधि में से इन गांवों के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा० कमल गुप्ता) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) पंचायत निधियों एवम संबंधित नगर निकायों में शामिल भूमि का गांव वार विवरण इस प्रकार है:—

क्रमांक संख्या	नगर निकाय का नाम	गांव का नाम	प्राप्त धन (रूपये में)	भूमि का क्षेत्रफल
1	नगर निगम	साहुपुरा	2,74,90,307/-	246 क० - 4 म०
2	फरीदाबाद	सोलई	91,68,361/-	844 क० - 19 म०
3		नवादा	41,98,28,164/-	1300 क०- 12 म०
4		मुजेडी	1,35,46,05,470/-	795 क० - 8 म०
5		मच्छगर	66,52,12,128/-	492 क० - 10 म०
6		मलेरना	1,83,50,224/-	270 क० - 17 म०
7		चन्दावली	58,30,61,000/-	213 क० - 1 म०
		कुल		307,77,15,654/-
8	नगर परिषद	अगवानपुर	3,16,840/-	590 क० - 16 म०
9	पलवल	आल्हापुर	28,38,200/-	295 क० - 9 म०
10		फिरोजपुर	1,42,698/-	735 क० - 0 म०
11		नया गांव-फजलपुर	5,72,979/-	249 क० - 1 म०
	कुल		38,70,717/-	1870 क०- 6 म०

(ग) नगर निगम, फरीदाबाद और नगर परिषद, पलवल ने उपरोक्त गांवों के नगर निकायों में शामिल होने के बाद विकास कार्यों पर 3419.23 लाख रुपये खर्च किए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक संख्या	नगर निकाय का नाम	गांव का नाम	विकास कार्यों पर किया गया खर्च (रूपये में)
1	नगर निगम	साहुपुरा	89,37,000/-
2	फरीदाबाद	सोलई	1,11,95,000/-
3		नवादा	2,44,13,000/-
4		मुजेडी	84,43,000/-
5		मच्छगर	47,19,000/-
6		मलेरना	67,47,000/-
7		चन्दावली	31,30,000/-
8		इन गांवों के अंतर्गत विविध कार्य	75,04,000/-
	कुल(रूपये में)		7,50,88,000/-

क्रमांक संख्या	नगर निकाय का नाम	गांव का नाम	विकास कार्यों पर किया गया खर्च (रूपये में)
8	नगर परिषद	अगवानपुर	4,19,69,324/-
9	पलवल	आल्हापुर	2,94,63,712/-

10		फिरोजपुर	1,85,19,484/-
11		नया गांव-फजलपुर	3,68,82,530/-
12		अमृत योजना के तहत जल आपूर्ति लाइन, सीवरेज लाइन बिछाना और 2.5 एमएलडी एसटीपी की स्थापना	14,00,00,000/-
	कुल(रूपये मे)		27,10,38,050/-
	कुल योग(रूपये मे)		34,19,23,050/-

नगर निगम फरीदाबाद और नगर परिषद पलवल के विकास कार्यों का विवरण अनुलग्नक-क व अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

अनुलग्नक-क				
Expenditure made on development works by Municipal Corporation Faridabad				
Sr. No.	Village name	Name of work	Expenditure (in ₹)	Status
1	Chandawali	Repair of 150mm existing water supply PVC line in Village Chandawali Prathla Constituency	97000	Work Complete
2	Chandawali	Rough cost estimate for Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting hoisting, fixing in position on various drains of village Chandawali Faridabad.	492000	Work in progress
3	Chandawali	Hiring of tractor mounting pump set (Berma) for de-watering of over flooded water /rainy water from roads and low lying area of village Chandawali, Faridabad.	311000	Work in progress
4	Chandawali	Hiring of Gen set for MCF office in Chandawali village Recently transferred in MCF, Faridabad.	189000	Work in progress
5	Chandawali	Construction of 3 Nos. Rooms in Govt. School in Village Chandawali Faridabad.(D-Plan)	2041000	Under Tender Process
Total (in ₹)			3130000	
1	Machhgar	Completion of balance work of jaat chaupal in village machgar new added village in MCF Faridabad	1008000	Work Complete
2	Machhgar	Repair & Raising RMC of Phirni road Balram House to Gujjar Choupal in village Machhgar in newly added village in MCF.	2238000	Work Complete
3	Machhgar	Estimate of de watering of pond at Gujjar- Harijan wali Johar, Machgar. (Recently transferred in MCF	733000	Tender Re Called
4	Machhgar	Hiring of tractor mounting pump set (Berma) for de-watering of over flooded water /rainy water from roads and low lying area of village Machgar, Faridabad.	311000	Work in progress
5	Machhgar	Cleaning of pond in village Machhghar (Recently transferred in Municipal Corporation Faridabad	429000	Tender Re Called

Total (in ₹)			4719000	
1	Nawada	Estimate for Providing & Laying 80 mm thick interlocking paver block from Tej pal sarpanch to Mahesh house and up to Bir Singh House in village Nawada New Added village MCF	1045000	Work Complete
2	Nawada	Rough cost estimate for construction of Parks in village Nawada	2664000	Work Complete
3	Nawada	Re-Construction of drain type-II at Gram Sachivaly to Tigaon road, in village Nawada in MCF, Faridabad	3045000	Work in progress
4	Nawada	Providing and laying of RMC M-40 grade IMT road near Kanta to premchand house in villages Nawada, (Recenty transferred in Municipal Corporation Faridabad.)	3919000	Work in progress
5	Nawada	Rough cost estimate for Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting hoisting, fixing in position on various drains of village Nawada Faridabad.	462000	Work in progress
6	Nawada	Hiring of tractor mounting pump set (Berma) for de-watering of over flooded water /rainy water from roads and low lying area of village Nawada, Faridabad.	311000	Work in progress
7	Nawada	Estimate for providing and fixing of manholes & raising of manholes in village Nawada (Recently transferred village in Municipal Corporation Faridabad).	585000	Work in progress
8	Nawada	Estimate for Providing & Laying 80 mm thick interlocking paver block from Bhupgarh Mod (Tigaon Road) to Gram Sachivalya, Nawada in New Added village MCF.(Prithla Constitutency.	7800000	Under Technical Evaluation
9	Nawada	Repairing of Chaupal in various places in Nawada	1677000	Work in progress
10	Nawada	De-watering of Badi Johad in Village Nawada	2335000	Work in progress
11	Nawada	Construction of platform and SS railing work in prayer ground in Govt. Primary School at Village Nawada Faridabad. (D-Plan)	570000	Under Tender Process
Total (in ₹)			24413000	
1	Malerna	Cleaning of pond at Param Gada Malerna (Recently transferred in Municipal Corporation Faridabad).	1814000	Work in progress
2	Malerna	Cleaning of Balmiki wali Johad in village Malerna (Recently transferred in Municipal Corporation Faridabad).	1487000	Work in progress
3	Malerna	Cleaning of Peer Baba wali Johad in village Malerna (Recently transferred in Municipal Corporation Faridabad).	1831000	Work in progress
4	Malerna	Hiring of tractor mounting pump set (Berma) for de-watering of over flooded water /rainy water from	311000	Work in progress

		roads and low lying area of village Malerna, Faridabad.		
5	Malerna	Construction of RMC road from plot of manoj S/o Vishnu to Field of Raj Kumar S/o Raghbir in Village Malerna Faridabad. (D-Plan)	1304000	Under Tender Process
Total (in ₹)			6747000	
1	Mujeri	Cleaning /De-silting of Pond at Santa Mohalla Village Mujeri (Recently transferred in Municipal Corporation Faridabad).	4242000	Tender ReCalled
2	Mujeri	Cleaning /De-silting of Peer Baba Johad village Mujeri (Recently transferred in Municipal Corporation Faridabad).	2929000	Tender ReCalled
3	Mujeri	Hiring of tractor mounting pump set (Berma) for dewatering of over flooded water /rainy water from roads and low lying area of village Mujeri, Faridabad.	311000	Work in progress
4	Mujeri	Estimate of special repair & maintenance of Badi Choupal in village Mujeri MCF	961000	Tender ReCalled
Total (in ₹)			8443000	
1	Shahupura	Construction of RCC Nallah 2 feet wide and covering with precast slab in front of from Gambhira Public School up to plot of Randhir in village Sahupura new added village in MC Faridabad.	1257000	Work in progress
2	Shahupura	Cleaning of pond at village Sahupura Part No. 1 (Recently transferred in Municipal Corporation Faridabad).	1018000	Work in progress
3	Shahupura	Estimate for De-silting and dewatering of BPL wala pond in Village Sahupura (Recently transferred in Municipal Corporation Faridabad).	1047000	Work in progress
4	Shahupura	De- Silting and dewatering of pond at Peer Baba Mohalla in village Sahupura newly added village in MC Faridabad	3799000	Tender ReCalled
5	Shahupura	Hiring of tractor mounting pump set (Berma) for dewatering of over flooded water /rainy water from roads and low lying area of village Sahupura, Faridabad.	311000	Work in progress
6	Shahupura	Cleaning of Pond at Shaupura Part No. 2 & 3 (Recently transferred in Municipal Corporation Faridabad).	1505000	Work in progress
Total (in ₹)			8937000	
1	Sotai	Estimate for providing and fixing of manholes & raising of manholes in village Sotai in Municipal Corporation Faridabad	585000	Work in progress
2	Sotai	De- Silting and dewatering of pond at Jaat Mohalla village Sotai newly added village in MC Faridabad	866000	Work in progress
3	Sotai	Hiring of tractor mounting pump set (Berma) for dewatering of over flooded water /rainy water from roads and low lying area of village Sotai, Faridabad.	311000	Work in progress
4	Sotai	Providing & Laying 80 mm thick interlocking paver block and drain type-Ist various streets in village Sotai	5935000	Under Technical Evaluation

5	sotai	Desilting badly choked sewerline in village Sotai newly added villages in MCF.	2955000	Work in progress
6	sotai	Desilting of disposal Tank, Repair of 3 nos. leakage Pit-hole and provision interlocking tiles at disposal tank in village Sotai	316000	Tender ReCalled
7	Sotai	Repair & maintenance of 2 nos of 7.5 HP sewerage submersible pumps 1 no 15 HP Sewerage submersible pump and aluminium service cable 95 Sqm/ 4 core for replacement of service cable of satai disposal newly added village in MCF	227000	Tender ReCalled
Total (in ₹)			11195000	
1	various	Estimate for Installation of sewerage mono block with P.T.O. 150mm x 150mm heavy duty on Tractor with all accessories for dewatering of ponds/flooded water in Chnadawali, Machgar, Mujedi, Nawada, Sotai, Sahupura Malerna, MCF, Faridabad	85000	Work Complete
2	various	Estimate for Installation of sewerage mono block with P.T.O. 150mm x 150mm heavy duty on Tractor with all accessories for dewatering of ponds/flooded water in Pahaladpur,Kheri Khurd, Badoli,Bhatola, Faridpur, Neemka, Fajjupur, Mirjapur villages in MC, Faridabad	85000	Work Complete
3	various	Supply of Providing fixing of sign board SS pipe to aluminium sheet various points in new hand over villages Ballabgarh.	117000	Work Complete
4	various	Dismantling of existing RCC crossing slab/calvent relaying of RCC Slab as per requirement at various streets in New added villages in MCF villages Malerna, Sahupura, Sotai ,Chandawali Machgar, Mujeri, Nawada, Tigaon, Neemka, Mirzapur, Faizpur Neemka, Faridabad.	979000	Tender ReCalled
5	various	Day to day Repair and maintenance of water supply line in new added villages in MCF i.e. village Malerna, Sahupura, Sotai, Chandawali, Machgarh, Mujeri, Nawada, Tigaon, Neemka, Mirzapur, Faizpur Neemka, Faridabad.	1737000	Tender ReCalled
6	various	Repair & maintenance of damaged portion of interlocking paver block of various streets in new added villages in MCF i.e. village Malerna, Sahupura, Sotai, Chandawali, Machgar, Mujedi & Nawada. Tigaon Neemka, Mirzapur, Faizpur Neemka in MC, Faridabad	761000	Tender ReCalled
7	various	Repair & maintenance of damaged RMC in various streets by way of patch work in new added villages in MCF i.e. village in Malerna, Sahupura, Sotai, Chandawali, Machgar, Mujedi, Nawada, Neemka, Mirjapur , Fajjupur Neemka villages in MC, Faridabad	635000	Tender ReCalled
8	various	Day to day Repair and maintenance of existing open surface drain in new added villages in MCF i.e. village Malerna, Sahupura, Sotai, Chandawali, Machgarh, Mujeri, Nawada, Tigaon, Neemka, Mirzapur, Faizpur Neemka, Faridabad.	476000	Tender ReCalled

9	various	Running, Automation Operation, Repair & maintenance of water supply tubewells fo outsourcing in new added villages in MCF of Prithla Constituency Faridabad for one year period.	2314000	Work in progress
10	various	P/F of SS Sign Board of Hon'ble MLA Sh. Nayan Pal Rawat Ji Prithla Constituency	315000	Work in progress
Total (in ₹)			7504000	

Annexure-B/ अनुलग्नक-ख

Expenditure made on development works by Municipal Council Palwal

Sr. No.	Village name	Name of work	Expenditure In Rs.	Status
1	Ferozpur	Const. of Drain outer phirni	127067	Work Complete
2	Ferozpur	Const. of road & drain from H/o Bhim to H/o Kulwir	245424	Work Complete
3	Ferozpur	Const. of drain in outer phirni	400185	Work Complete
4	Ferozpur	Const. of road and drain	941986	Work Complete
5	Ferozpur	Const. of road & drain from various points	4342492	Work Complete
6	Ferozpur	Const. of road by interlocking tiles of M35 grade of various street & drain	571494	Work Complete
7	Ferozpur	Const. of road and drain from Nala to Kripal	633460	Work Complete
8	Ferozpur	Const. of road and drain from H/o Huka Chand to Kala Chand	484293	Work Complete
9	Ferozpur	Const. of road in village Firojpur	3090129	Work Complete
10	Ferozpur	Const. of road by IPB in Firojpur	949020	Work Complete
11	Ferozpur	Const. of road by interlocking tiles of various street & drain in village Firojpur	348079	Work Complete
12	Ferozpur	Repair of compost bit in MRF Centre of Patli Road	138855	Work Complete
13	Ferozpur	Const. of road from Chiranji lal bhagel to Govt. School in Firojpur ward No.1 MC Palwal	3945000	Work in progress
14	Ferozpur	Completion/Const. of shamshan Ghat in village Firojpur ward No.01 MC Palwal	2302000	Tender under process
Total (in ₹)			18519484	
1	Naya Goan-Fazalpur	Const. of street by earth filling from H/o Mahinder to H/o Balbir	653025	Work Complete
2	Naya Goan-Fazalpur	Repair of various street	303720	Work Complete

3	Naya Goan-Fazalpur	Const. of IPB road and from H/o Hansraj to H/o Prem Singh	762529	Work Complete
4	Naya Goan-Fazalpur	Repair of various streets	115953	Work Complete
5	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road and repair of Harijan Chaupal	939030	Work Complete
6	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road and drain from H/o hansraj to Prem Singh	128819	Work Complete
7	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road and drain by interlocking tiles M35 from SM Schhol to SM School	378315	Work Complete
8	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road from Vedpal to Laxman	1119712	Work Complete
9	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road and drain Babu to Gajender to Satish	486207	Work Complete
10	Naya Goan-Fazalpur	Repair of various streets	303720	Work Complete
11	Naya Goan-Fazalpur	Const. of Shed in Shamshan ghat	601440	Work Complete
12	Naya Goan-Fazalpur	Const. of street by E/filling with stone metal and drain ved Prakash wali gali	1100000	Work Complete
13	Naya Goan-Fazalpur	Const. of street by E/filling from h/o Mahinder to Balbir	555593	Work Complete
14	Naya Goan-Fazalpur	Repair or const. of road & drain	883040	Work Complete
15	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road from Babu to Gyander and Satish	486207	Work Complete
16	Naya Goan-Fazalpur	Const. of drain & interlocking tiles from H/o Raman ITI Boundary to Bahadur Singh	64342	Work Complete
17	Naya Goan-Fazalpur	Const. of Road & drain from Inder to Ravinder	299398	Work Complete
18	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road & drain from Ansar Singh thakur to Ram Kishan near Flyover	553528	Work Complete
19	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road & drain from Udayveer Fojuji to Deshraj	616217	Work Complete
20	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road in Ward No.2	495055	Work Complete
21	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road from Dr. Naresh to Lout Pachori	896264	Work Complete
22	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road & drain from Udayveer Fojuji to Deshraj	174400	Work Complete
23	Naya Goan-Fazalpur	Const. of Road & drain from Amar Singh Thakur to Ram kishan	471265	Work Complete
24	Naya Goan-Fazalpur	Const. of RMC road from Sukhdev to Mahender.	3189311	Work Complete
25	Naya Goan-Fazalpur	Const. of various road & drain in village fazalpur	6369087	Work Complete

26	Naya Goan-Fazalpur	Fabrication & Installation of Entry gate at Mahna road	271332	Work Complete
27	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road E/Fill with stone metal & drain from H/o Bhajan Aldoka to Suresh	737769	Work Complete
28	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road by E/filling & with stone metal with drain Hamlay to Jawahar	917336	Work Complete
29	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road & drain along with Alawalpur flyover to Hansraj Kapasiya main road	1272984	Work Complete
30	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road & drain from Sunder to Pujari house	1463263	Work Complete
31	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road from Pt. Dinesh to Mahesh Gurjar	1514913	Work Complete
32	Naya Goan-Fazalpur	Const. of satbir to Baagwale to Virender Ghodi Sarpanch	639447	Work Complete
33	Naya Goan-Fazalpur	Const. of road and drain from Sanjay Baghel to Mandir	1771309	Work Complete
34	Naya Goan-Fazalpur	Construction of IPB road and drain from hoti lal aaldyoka wale to h/o Mahesh Sholle tak in ward No.2 in MC Palwal	506000	Work in progress
35	Naya Goan-Fazalpur	Construction of IPB road and drain from H/o kishan fouji to h/o Nahar in Ward No.02 in MC Palwal	1785000	Work in progress
36	Naya Goan-Fazalpur	Construction of IPB road and drain from H/o Doctor vijay to h/o Dharampal in Ward No.02 in MC Palwal	1868000	Work in progress
37	Naya Goan-Fazalpur	Const. of IPB road and drain from H/o Deep Chand to Sanjay office in ward No.2 in MC Palwal	2189000	Tender under process
Total (in ₹)			36882530	
1	Alhapur	Completion of Ambedkar Bhawan	1144927	Work Complete
2	Alhapur	Completion of Brahman Chaupal	865711	Work Complete
3	Alhapur	Const. of road by 80mm thick & M35 grade interlocking tiles	825164	Work Complete
4	Alhapur	Repair of various street with 80mm interlocking tiles with drain	492407	Work Complete
5	Alhapur	Const. of road & drain from H/o Srichand to H/o Raju	325836	Work Complete
6	Alhapur	Const. of road and drain by 80mm thick interlocking tiles M-35 grade from H/o Kanhiyan to H/o Ratiram & H/o Sansu	980301	Work Complete
7	Alhapur	Const. of road & drain from GT road to H/o Mange	2106307	Work Complete
8	Alhapur	Const. of road and drain by IPB from Bulmini to Patli road	1095593	Work Complete
9	Alhapur	Const. of IPB road & drain from Ramchand to kishan to Gopal	238487	Work Complete
10	Alhapur	Const. of interlocking tiles road & drain udham to durga thakur & other side gali	403139	Work Complete

11	Alhapur	Const. of road & drain from H/o Dhanni to Durga Thakur	591948	Work Complete
12	Alhapur	Completion of Brahman chaupal	995393	Work Complete
13	Alhapur	Const. of road & drain Anil Nagar	838167	Work Complete
14	Alhapur	Const. of drain from H/o Tuliram to Mahar Chand	357150	Work Complete
15	Alhapur	Const. of MRF shed in village Allahpur	3195483	Work Complete
16	Alhapur	Const. of Community Centre	2353877	Work Complete
17	Alhapur	Const. of Dispensary	1342784	Work Complete
18	Alhapur	Const. of road & drain from Patli road to Harijan Basti	4202887	Work Complete
19	Alhapur	Development of Park	2547151	Work Complete
20	Alhapur	Completion of Balance work in Sant Ravidass Samudayik Kendra Alapur W.No.30	2464000	Work in progress
21	Alhapur	Construction of IPB street and drain from H/o Rampal to H/o Ex-Sarpanch Dalip Singh Ward No.30 MC Palwal	1293000	Work in progress
22	Alhapur	Completion of Balance work in Dispensary ward No.30 Allahapur in MC Palwal	804000	Tender under process
Total (in ₹)			29463712	
1	Agwanpur	Repair of various Streets	401807	Work Complete
2	Agwanpur	Const. of road and drain from H/o Giraj to Bahadur Singh	374697	Work Complete
3	Agwanpur	Const. of harijan Chaupal	1114300	Work Complete
4	Agwanpur	Const. of precast B/wall	2113880	Work Complete
5	Agwanpur	Const. of road by interlocking tiles of M35 grade	764934	Work Complete
6	Agwanpur	Const. of road and drain in Agwanpur	704900	Work Complete
7	Agwanpur	Const. of road and drain Yogesh wali gali	757918	Work Complete
8	Agwanpur	Providing & laying 250mm LdSW marked pipe for sewer line near Dharm Public School to Agwanpur Highway	1359985	Work Complete
9	Agwanpur	Const. of road & drain in various street in village Agwanpur	2273923	Work Complete
10	Agwanpur	Const. of Pre-cast B/wall in MC Land	999979	Work Complete

11	Agwanpur	Const. of community Centre at village Agwanpur	3356216	Work Complete
12	Agwanpur	Const. of community Centre at village Agwanpur	5269586	Work Complete
13	Agwanpur	Finishing of work in community centre in vill. Agwanpur at Harijan Chopal	959361	Work Complete
14	Agwanpur	Providing & laying of sewer line in Agwanpur Nangla	2028838	Work Complete
15	Agwanpur	Construction/ completion of community center in village agwanpur in ward no 01 in mc palwal.	9905000	Work in progress
16	Agwanpur	Construction of road and drain from H/o Sheetu to koau tak in ward No.1 MC Palwal	2057000	Work in progress
17	Agwanpur	Construction of road and drain from H/o Chiranji Namberdar to Sarkari School in ward No.1 MC Palwal	2072000	Work in progress
18	Agwanpur	Construction of road and drain from Shamshan ghat to koau tak in Ward No.1 MC Palwal	2073000	Tender under process
19	Agwanpur	Construction of IPB road and drain from H/o Rothan Sarpanch to Panchayati ghar in Ward No.01 MC Palwal	2291000	Work in progress
20	Agwanpur	Construction of road and drain from plot of Ram Gopal to Dheeraj (Master Narpat) in village Agwanpur Ward No.1 MC Palwal	1091000	Work in progress
Total (in ₹)			41969324	
1	Various	laying water supply line, sewerage line and installation of 2.5 MLD STP under AMRUT Scheme	140000000	Work Complete
Total (in ₹)			140000000	

श्री नयन पाल रावत: अध्यक्ष महोदय, लगभग दो साल पहले मेरी पृथला विधान सभा के सात गांव नवादा, मुजेड़ी, मच्छगर, सोलई, साहपुरा, मलेरना तथा चन्दावली को नगर निगम में शामिल किया गया और इनका लगभग 362 करोड़ रुपया, जो फिगर उत्तर में दी गई है मैच नहीं कर रही है। नगर निगम ने 362 करोड़ रुपये और इनकी जमीन भी टेक ओवर कर ली है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह पृथला विधानसभा के चार गांव पिछली योजना में पलवल नगर परिषद में शामिल हुए। इनके भी 35 करोड़ रुपये नगर निगम के पास हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन गांवों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। इन गांवों के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। इन गांवों का पैसा भी ले लिया गया और इनमें काम भी नहीं हुआ। जब ये गांव शामिल किये गये थे तब यह तय हुआ था कि इनका जो पैसा है, वह इन्हीं

गांवों पर खर्च होगा। जैसे पंचायत के माध्यम से खर्च होता था। यह पैसा उसी प्रकार से नगर परिषद या नगर निगम के माध्यम से इन गांवों पर खर्च होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि एक तो यह फिगर ठीक कर ली जाये और इन गांवों का जो काम है, वह समय सीमा से पूरा करवा दिया जाये। इसके अलावा इनमें जो नॉर्म्स हैं, वे अभी लागू नहीं हुए हैं इसलिए कम से कम जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं जिनका घर-परिवार अलग हो रहा है। उनको कंस्ट्रक्शन का कार्य करते वक्त तंग न किया जाये। धन्यवाद।

डॉ. कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सात गांव बताये इनके इन्होंने 362 करोड़ रुपये बताये जबकि ये 307 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा पलवल नगर परिषद में जो चार गांव लिये गये हैं। इन गांवों का जो धन इकट्ठा किया गया है वह 38 करोड़ रुपये हैं। इसके खर्चे का ब्यौरा भी हमने दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात मानता हूं कि पैसा कम खर्च हुआ है, पैसा काफी बचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी की जानकारी के लिए सदन में यह बताना चाहूंगा कि इनमें से 133.52 करोड़ रुपये का एस्टीमेट्स इन सातों गांवों में अमरूत-2 योजना के तहत सीवरेज तथा पानी सप्लाई का जो काम होने वाला है उसके लिए तैयार हो चुका है। इसलिए जैसे-जैसे इन 11 गांवों में काम आएंगे उनकी एडमिन अप्रूवल होगी, उनकी टैक्निकल अप्रूवल होगी तो उनकी उचित डिवायल्टमेंट के लिए यह पैसा खर्च किया जाएगा।

श्री नयनपाल रावत : अध्यक्ष महोदय, दो साल की समय सीमा बहुत ज्यादा होती है। मैं तो आपके माध्यम माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको टाइम बाउण्ड कर दें। आगे चुनाव आ रहा है। इसके लिए दो, तीन या चार महीने का समय तय कर दें। मुझे यह बता दिया जाये कि कब इसकी टैण्डर प्रोसेस पूरी होगी और कब यह काम कम्पलीट हो जायेगा?

डॉ. कमल गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 11 गांव हैं। अलग-अलग काम हैं तो उनके लिए एकदम से समय सीमा बताना सम्भव नहीं है लेकिन जल्द ही इसको संज्ञान में लेकर ये कार्य किये जायेंगे।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि ये जो 11 गांवों का पैसा आया है और जो नगर निगम में 626 करोड़ रुपये पड़े हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप फिर वहां नगर निगम पर पहुंच गये।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष जी, यह इसी गांव का है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : तो नगर निगम के 626 करोड़ रुपये से इसका क्या मतलब है? (विघ्न) 307 करोड़ रुपये तो उनको बताया है। (विघ्न)

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष जी, नगर निगम में पैसा है उसमें यह 307 भी शामिल है या नहीं है या यह 307 अलग है और इस पैसे का कोई कैप तो नहीं लगा रखा कि यह पैसा सिर्फ यहीं खर्च होगा या नगर निगम कहीं भी खर्च कर सकती है?

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष जी, यह पैसा उसमें इंकल्यूड है या नहीं ये मैं बाद में माननीय विधायक जी को जानकारी भिजवा दूंगा।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष जी, मैंने कैप के बारे में भी पूछा है।

श्री अध्यक्ष : 11 गांवों के लिए बता तो दिया है कि यह 11 गांवों के लिए पैसा है।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष जी, जो 11 गांवों से पैसा आया था माननीय विधायक श्री नयनपाल रावत को उसकी जानकारी दी गई है। इसका 626 करोड़ रुपये से क्या सम्बन्ध है मैं इसकी जानकारी माननीय विधायक श्री नीरज शर्मा जी को बाद में भिजवा दूंगा।

डबवाली के अस्पताल में सुविधाएं

*33. श्री अमित सिहाग : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएं कि :-

(क) डबवाली के नागरिक अस्पताल में एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है तथा नशा मुक्ति केंद्र के कब तक पुनः आरम्भ किए जाने की संभावना है; तथा

(ख) डबवाली के नागरिक अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड मशीन कब तक उपलब्ध किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

- (क) श्रीमान जी, उपमंडल नागरिक अस्पताल, डबवाली में पहले से ही एक मनोचिकित्सक तैनात है और नशा मुक्ति केंद्र कार्यरत है।
- (ख) श्रीमान जी, पी0पी0पी0 मोड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया में है और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना है, जिसमें आम तौर पर लगभग 6 महीने लगते हैं।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अल्ट्रासाउण्ड मशीन का सवाल है तो नवम्बर, 2020 में जब इस मशीन को डबवाली से अम्बाला ले गये थे उस समय मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में इसी विधान सभा पटल पर नवम्बर, 2020 को यह बात रखी थी और उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाऊस कहा था कि 6 महीने के अंदर-अंदर आपकी मशीन आपको दे दी जायेगी। उसके बाद मैं ए.सी.एस. महोदय से 6 महीने में कम से कम दो बार मिला। उनसे भी आश्वासन मिला। उसके बाद जब वो नहीं आई तो मैंने बजट सत्र 2022 में यह सवाल फिर से लगाया था और उस सत्र में जब सवाल लगा तो उस सत्र के शुरू होने से कुछ दिन पहले डी.जी., हेल्थ ने मुझे एक चिट्ठी जारी की कि पी.पी.पी. मोड के माध्यम से आपको यह मशीन और रेडियोलोजिस्ट 6 महीने के अंदर-अंदर दे दिया जायेगा। आज आ गया दिसम्बर, 2023 और आज भी यही जवाब दिया गया है कि पी.पी.पी. मोड के माध्यम से 6 महीने के अंदर दिया जायेगा। जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया था नवम्बर, 2020 में और आज दिसम्बर, 2023 है यानि तीन साल पूरे हो गये लेकिन आज भी वही आश्वासन है। मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या 14वीं विधान सभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले-पहले अपने स्वास्थ्य मंत्री जी इस आश्वासन को पूरा कर पायेंगे या तारीख पे तारीख देकर आने वाले बजट सत्र में भी इस मामले को ऐसे ही निपटा देंगे?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं इस बात का पता कराऊंगा कि अगर मैंने हाऊस में कहा था तो उतने समय में काम क्यों पूरा नहीं हुआ? और अगर किसी की उसमें कमी रही होगी तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही भी करूंगा। मैं विधायक महोदय को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह

अनिल विज की बात है कि 6 महीने के अंदर-अंदर और अगर हो सका तो उससे भी पहले इनके वहां पर यह मशीन लगा दी जायेगी।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री दूसरी चीज के बारे में है। स्वास्थ्य मंत्री जी के आश्वासन को देखकर ही मैंने माना था कि शायद हो जायेगा इसलिए मैंने यह मामला दोबारा से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाने का काम किया है। मेरी दूसरी बात नशा मुक्ति केन्द्र के बारे में है। इस बारे में मंत्री जी कह रहे हैं कि ये शुरू हो चुका है और वहां पर आज साईकैट्रिस्ट भी है। इसके बारे में भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अप्रैल, 2022 में मैंने कई बार शुरूआत से इसके ऊपर मुहिम छोड़ी थी कि हमें एक नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की जरूरत है। बल्कि स्टार्टिंग में शायद आपको याद होगा मेरा जो सवाल था उसके जवाब में डिएडीक्शन सेंटर की जगह उस समय एडीक्शन सेंटर भी लिखकर भेज दिया गया था। आखिरकार अप्रैल, 2022 में इसको शुरू किया गया। दो महीने वो चला। उसके बाद जो साईकैट्रिस्ट थे वे वहां से चले गए। अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए आज हो गया दिसम्बर, 2023 और किसी ने उसकी कोई सुध नहीं ली। अब जब मैंने सवाल फिर लगाया तो सेशन शुरू होने से दो दिन पहले हिसार से साईकैट्रिस्ट की डेप्यूटेशन पर दो महीने के लिए नियुक्ति की गई है। अगर अब कोई गम्भीर अवस्था में नशे के चंगुल में जो आज लोग हैं उनको देखते हुए क्या आपको लगता है कि क्या इसके लिए दो महीने पर्याप्त हैं? कम से कम जो डॉक्टर हिसार से डैप्यूटेशन पर भेजा गया है उसको 6 महीने के लिए तो रखना चाहिए तथा वहां पर एक डॉक्टर की स्थाई नियुक्ति का प्रावधान किया जाये। जो हमारा क्षेत्र है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस जिला भी इसलिए बनाया था क्योंकि यहां पर नशे की समस्या बहुत अधिक है। वहां पर नशे की समस्या को देखते हुए वहां पर जब डी-एडिक्शन सेंटर्स ही नहीं हैं तो जो लोग नशे के चंगुल में फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जा सकता है? इसलिए 2 महीने की डैप्यूटेशन पर्याप्त नहीं है उसको कम से कम 6 महीने की डैप्यूटेशन की जाये तथा साथ ही साथ स्थाई नियुक्ति का भी प्रावधान किया जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इसके लिए क्या प्रावधान करेंगे?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, साइकैट्रिस्ट की स्टेट में काफी कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए हमने 29 डॉक्टर्स को बेंगलोर के NIMHANS से डिप्लोमा करवाया है, वे डिप्लोमा करके आ गए हैं और 54 मेडिकल ऑफिसर्स को चण्डीगढ़ से कोर्स करवा रहे हैं। वे भी अपना कोर्स करके पहुंचेंगे। बिना साइकैट्रिस्ट के डी-एडिक्शन सैन्टर नहीं चल सकता है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा हिसार से 2 महीने की डेपुटेशन पर भेजे गए डॉक्टर की बात है तो मैं परमानेंट उसके ऑर्डर वहां पर कर देता हूं। जब दूसरे डॉक्टर्स आयेंगे तो बाकी जगहों पर हम उनको लगा देंगे।

श्री अमित सिहाग: धन्यवाद, सर।

विद्यालय दाखिलों का ब्यौरा

***34 श्री जगबीर सिंह मलिक :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएं कि :-

- (क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में पिछले वर्ष से राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले कम हुए हैं; यदि हां, तो उसके कारण क्या है तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-2023 के लिये कक्षा 1 से 12 तक दाखिलों का कक्षा-वार ब्यौरा क्या है; तथा
- (ख) अन्य राज्यों के राजकीय विद्यालयों की तुलना में राज्य के राजकीय विद्यालयों की स्थिति क्या है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

- (क) श्रीमान जी, हरियाणा राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के वार्षिक आंकड़े वर्ष 2019-20 से 2022-23 के निम्नानुसार तालिका में दिये गये हैं:-

कक्षाएं	छात्रों का वर्ष-वार नामांकन			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पहली	167591	162021	216614	159393
दूसरी	188624	185020	221398	222175
तीसरी	195067	198027	228701	218023
चौथी	179193	202468	233695	221532
पांचवीं	167521	187736	237759	229697
छहवीं	177285	176664	218786	226713
सातवीं	185657	182573	199972	210880
आठवीं	187586	188476	203816	191603
नौवीं	200894	232767	207700	204059
दसवीं	174649	170046	208370	183535
ग्याहरवीं	134172	156746	208267	161277
बाहरवीं	110626	129376	153881	182824
कुल	2068865	2171920	2538959	2411711

बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलवाना उनके माता-पिता की इच्छा पर आधारित होता है। वर्ष 2022-23 में राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों के नामांकन पूर्व महामारी वर्ष 2019-20 से 16.57% अधिक था। कोविड महामारी अवधि के दौरान सरकारी विद्यालयों में नामांकन में काफी वृद्धि हुई थी।

(ख) हरियाणा राज्य एवं अन्य राज्यों के सरकारी विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों सहित छात्रों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	राज्य	मौलिक (1 से 8)	माध्यमिक (9 से 10)	उच्च माध्यमिक (11 से 12)
2019-20	हरियाणा	1483287	385059	252868
2020-21		1518636	413111	295053

वर्ष	राज्य	मौलिक (1 से 8)	माध्यमिक (9 से 10)	उच्च माध्यमिक (11 से 12)
2021-22		1797737	426690	372063
*2022-23		1712804	397123	353043
2019-20		503178	165560	156630
2020-21	हिमाचल प्रदेश	500795	158203	160378
2021-22		532167	144961	180961
2022-23		आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं		
2019-20		पंजाब	1593060	451759
2020-21	1656904		478659	402716
2021-22	1814977		448594	441834
2022-23	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं			
2019-20	राजस्थान	6143364	1440407	933867
2020-21		6362918	1511418	1078541
2021-22		7079390	1474241	1354212
2022-23		आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं		
2019-20	उत्तराखण्ड	616343	181859	143049
2020-21		597400	174021	145030
2021-22		662555	160915	156949
2022-23		आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं		
*भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं किये गये हैं।				

नोट:— शेष आंकड़े भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए यू डार्ज+ (UDISE+) से लिये गये हैं। इन आंकड़ों में राज्यों के राजकीय विद्यालयों के अलावा केन्द्रीय विद्यालयों

और नवोदय विद्यालयों को भी शामिल किया गया है, तथा हरियाणा के आंकड़े तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से लिये गये हैं जोकि इस प्रश्न के लिए जरूरी है।

राज्य	छात्रों का वर्षानुसार नामांकन			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
हरियाणा	--	+4.98	+16.60	-5.14
हिमाचल प्रदेश	--	-0.73	+4.72	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
पंजाब	--	+6.67	+6.58	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
राजस्थान	--	+5.11	+10.67	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
उत्तराखंड	--	-2.63	+6.98	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या राज्य में पिछले वर्ष से राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले कम हुए हैं और पूछा है कि इसका कारण क्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 से कक्षा 9 तक हुए दाखिलों में पिछले वर्ष 2019-20 के मुकाबले 4.98 प्रतिशत दाखिले अधिक हुए हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2021-22 में कक्षा 1 से 12वीं के दाखिले वर्ष 2019-20 के मुकाबले 22.72 प्रतिशत बढ़े हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2022-23 में कक्षा 1 से 12वीं तक के दाखिले वर्ष 2019-20 के मुकाबले 16.57 प्रतिशत बढ़े हैं, वर्ष 2020-21 के मुकाबले में 11.4 प्रतिशत बढ़े हैं तथा वर्ष 2021-22 के मुकाबले में 5 प्रतिशत घटे हैं। अगर हम इसका टोटल लगाएं तो वर्ष 2019-20 में हमारे पास 20,68,865 विद्यार्थी थे, वर्ष 2020-21 में 21,71,920 विद्यार्थी, वर्ष 2021-22 में 25,38,959 विद्यार्थी तथा वर्ष 2022-23 में 24,11,711 विद्यार्थी थे। जो संख्या वर्ष 2021-22 में 5 प्रतिशत घटी है तो इसका कारण यही है कि यह संख्या लगातार एक जैसी नहीं रह सकती है क्योंकि इससे पहले कोविड-19 के कारण बच्चों की संख्या बढ़ी थी। लेकिन फिर भी हमने उसको काफी हद तक मेनटेन करके रखा है लेकिन थोड़ी सी संख्या घटी है। इसमें एक कारण यह भी है कि अब जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह पूछी है कि जो आसपास के स्टेट हैं उनके मुकाबले हमारी स्थिति क्या है तो इस बारे में मेरा कहना है कि तुलनात्मक अध्ययन

के आंकड़े भारत सरकार द्वारा यू-डाइज पर प्रकाशित किये गये हैं जो मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। हरियाणा व पड़ोसी राज्यों के आंकड़े राज्य के सरकारी स्कूल, राज्य के केन्द्रीय विद्यालय और राज्य के नवोदय विद्यालय से लिए गए हैं ताकि सभी राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। अगर हम पड़ोसी राज्यों से दाखिले की तुलना करें तो हरियाणा राज्य में पिछले साल 2021-22 के दौरान 16.60 प्रतिशत दाखिले अधिक हुए जो अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा हैं। वर्ष 2022-23 के आंकड़े भारत सरकार ने अभी प्रकाशित नहीं किए हैं। वर्ष 2020-21 में हमने 4.98 प्रतिशत अधिक दाखिले किये हैं जबकि हिमाचल प्रदेश में यह दर माइनस 0.73 प्रतिशत है यानी वहां पर संख्या घटी है, पंजाब में 6.67 प्रतिशत बढ़े हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में 5.11 प्रतिशत दाखिले बढ़े हैं तथा उत्तराखंड में 2.63 प्रतिशत घटे हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2021-22 में हरियाणा में 16.60 प्रतिशत दाखिले बढ़े हैं जबकि हिमाचल प्रदेश में 4.72 प्रतिशत बढ़े हैं। इसी तरह से पंजाब में 6.58 प्रतिशत बढ़े हैं, राजस्थान में 10.67 प्रतिशत बढ़े हैं तथा उत्तराखंड में 6.98 प्रतिशत दाखिले बढ़े हैं। यानि कि हमारे एडमिशन सबसे ज्यादा बढ़े हैं। वर्ष 2022-23 के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सदन को यह नहीं बताया कि इस वर्ष सरकारी स्कूलों में सवा लाख से ज्यादा विद्यार्थी घटे हैं। वे क्यों घटे हैं उसका कारण इन्होंने बताया है कि जनसंख्या घट रही है। अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या नहीं घटी है। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट क्या है और नैशनल लैवल के कम्पैरिजन में क्या रिजल्ट है ? मैं तो सोनीपत के एक गांव की बात कहता हूं कि उस गांव में सरकारी स्कूल में 58 बच्चे थे और वे 58 के 58 बच्चे फेल हैं। आज सरकारी स्कूलों का ये रिजल्ट है। मुझे यह भी बताया जाए कि हरियाणा को एजुकेशन का कौन सा ग्रेड मिला है। दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्कर्ष आदि 10 ग्रेड हैं। हरियाणा इनमें से कौन से ग्रेड में फाल करता है और उसमें एजुकेशन की क्या पोजिशन है। आज सरकारी स्कूलों में बच्चों का कान्फिडेंस क्यों नहीं है ? उसका कारण बताया जाए और रिजल्ट कम आने का कारण भी बताया जाए। अगर मंत्री जी नहीं बता सकते तो मैं बताऊं।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकारी स्कूलों के परिणाम अच्छे हैं तभी तो अभी मैंने बताया है कि हमारे स्कूलों में बच्चे बढ़ रहे हैं। अगर आप तुलना करेंगे तो वर्ष 2019 में हमारे स्कूलों में 20 लाख बच्चे थे और आज हमारे स्कूलों में 24 लाख बच्चे हैं। अब माननीय सदस्य तुलना कर रहे हैं कि वर्ष 2021-22 में सरकारी स्कूलों में जो 25 लाख बच्चे थे उसकी तुलना में हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे घटे हैं। यह मैं मान रहा हूँ क्योंकि कोविड के कारण हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे ज्यादा हो गये थे और उनमें से कुछ बच्चे हमारे वापिस भी चले गये हैं। यह बात भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़े हैं घटे नहीं है। अगर आप उस समय से भी तुलना करें तो भी हमारे सरकारी स्कूलों में 4 लाख 11 हजार बच्चे बढ़े हैं घटे नहीं हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सरकारी स्कूलों के दसवीं कक्षा के रिजल्ट की प्रतिशतता 21.28 है और पूरे देश की प्रतिशतता 44 है तथा यूपी के रिजल्ट की प्रतिशतता 63 है। यह दसवीं कक्षा का रिजल्ट है। अगर मैं 12 वीं कक्षा के रिजल्ट की बात करूँ तो वह टोटल कंट्री का 40.89 प्रतिशत है जिसमें हरियाणा का 25.58 प्रतिशत है। हरियाणा 12 वीं कक्षा के रिजल्ट में 12 वें नम्बर पर है और दसवीं कक्षा के रिजल्ट में हरियाणा 13 वें नम्बर पर है। ये हरियाणा की एजुकेशन की पोजिशन है। आज सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, फैसिलिटीज नहीं हैं, पांच-पांच लाख रुपये जुमाने लगने लग रहे हैं। मंत्री जी, आप इस एजुकेशन की स्थिति को सुधारो, यह सबसे जरूरी है।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न दूसरा पूछा था और ये बात दूसरी करने लगे। अगर ये यही प्रश्न पूछते तो मैं इसका जवाब और अच्छे तरीके से देता। अब इन्होंने प्रश्न दूसरा पूछा और अब बात कौन सी करने लगे।

सी.आर.एफ.योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण करना

*35. श्री ईश्वर सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि -

- (क) क्या यह तथ्य है कि कैथल जिले में सी.आर.एफ. योजना के अंतर्गत कैथल से चीका सड़क के निर्माण के संबंध में रुपये 129 करोड़ राशि की परियोजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है; यदि हां, तो क्या इस सड़क के निर्माण के लिए वन विभाग से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; तथा
- (ख) इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, a statement is placed on the table of the house.

Statement

The work of 4-laning from Kaithal to Cheeka (Except Kaithal City, Siwan Town & Cheeka) was approved under Central Road Infrastructure Fund (CRIF) amounting to Rs.129.40 Crore on 30.03.2023.

However, the work of special repair with the provision of 40mm bituminous concrete on Kaithal-Cheeka-Patiala road from km. 202.63 to 204.50, 205.80 to 209.00, 209.00 to 209.50, 209.50 to 211.27 and km. 211.27 to 227.44 in Kaithal Distt. had already been administratively approved amounting to Rs. 844.28 lacs vide dated 16.11.2022 under State Head.

Because of the bad condition of road and the significant public inconvenience being caused, improvement work on the existing carriageway was done with 40mm Bituminous Concrete with the Defect Liability Period of 3 years ending on 14.07.2026 under State Head. Widening work can be done only after clearance of Defect Liability Period and widening of road requires forest clearance and the utility shifting. Since this could take almost one year, the work approved in CRIF is not being taken up presently.

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि सी.आर.आई.एफ. की स्कीम के तहत इस सड़क के लिए 30.03.2023 को 129

करोड़ 40 लाख रूपये की लागत मंजूर हुई थी क्योंकि वह सड़क सारी खस्ता हालत में थी अर्थात् वह सड़क पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब सरकार कहती है कि हमने उस सड़क को ठीक करवा दिया है। पहली बात तो यह है कि मेरी समझ के अनुसार इस अवधि का सी.आर.आई.एफ. स्कीम से कोई मेल नहीं खाता है क्योंकि वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा होगा। दूसरा मंत्री जी इसके लिए एक साल का समय कह रहे हैं जबकि वन विभाग की मंजूरी लेने में भी टाईम लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमें यह स्पष्ट करें कि क्या सरकार एक साल में वन विभाग की मंजूरी ले लेगी? दूसरा मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि इस रोड को चौड़ा करने के टेंडर कब तक निकाल दिये जाएंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस सड़क के बारे में पूछा है उस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार ने 16.11.2022 को साठे आठ करोड़ रूपये की लागत से इस पूरी सड़क को रिपेयर करवाया है और मार्च, 2023 को सी.आर.आई.एफ. से इस सड़क की वाइडनिंग/स्ट्रेंथनिंग के लिए 129 करोड़ रूपया सैंशन हो गया है क्योंकि वाइडनिंग के लिए वहां पर दोनों तरफ पेड़ कटेंगे जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्लीयरेंस लेनी पड़ेगी। जब तक वह क्लीयरेंस नहीं आएगी। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। Central Road Infrastructure Fund आये हुए हैं। जैसे ही परमिशन आयेगी इसकी वाइडनिंग का काम भी हम आगे टेकअप कर लेंगे। आज के दिन वो सड़क मोटरेबल है उस पर रि-कारपेटिंग पूरी तौर पर हुई है। माननीय सदस्य ने स्वयं ही Central Road Infrastructure Fund आने से पहले इसकी वाइडनिंग ड्रॉप करवा कर केवल मात्र मोटरेबिलिटी बने और बेहतर सड़क कैथल और चीका के बीच में हो, इस बात को इसी सदन में दो बार रखी है और सरकार ने उस सड़क को दुरूस्त करवाया है। अब जब वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग की बात है जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से इसके लिये फॉरेस्ट क्लीयरेंस आ जाती है, हम कार्यवाही करेंगे। हम पूरे प्रदेश भर से 500 एकड़ लैंड चयनित कर रहे हैं जहां फॉरेस्ट लैंड को लेकर सड़क के प्रोजैक्ट्स डिले होते हैं ताकि भविष्य में कठिनाई ना आये। जल्दी ही हम वो लैंड भी एलोकेट कर लेंगे। माननीय सदस्य ने कहा है कि कब तक फॉरेस्ट क्लीयरेंस आयेगी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आगे ना

तो मेरा, न चेयर का और ना ही किसी अन्य माननीय सदस्य का बस चलता है। जैसे ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इसकी क्लीयरेंस आ जायेगी हम आगे की कार्यवाही कर देंगे।

श्री ईश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि Central Road Infrastructure Fund की मंजूरी आ गई है। प्रदेश सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी पूरी कर दी है। मैं तो एक बात क्लीयर करवाना चाहता हूं कि जब वह सड़क Central Road Infrastructure Fund के तहत करनाल से कैथल तक चौड़ी बनती आ गई तो आगे कैथल से चीका क्यों रोक दी गई है। इसमें ना तो इतना समय अवधि की जरूरत थी और ना ही Central Road Infrastructure Fund की जरूरत थी। यह बात हमारी समझ से बाहर है। यह सड़क आगे कैथल से चीका क्यों बननी बंद कर दी जबकि वह दो साल पहले कैथल से करनाल बननी शुरू हो चुकी थी। यह बात ठीक है कि इसके लिये 129 करोड़ रुपये आया है और राज्य सरकार ने भी इस सड़क को उसी समय मंजूर कर दिया था। यह सड़क तीन साल पहले बन चुकी होती, इसे क्यों बंद रख गया। यह बात सदन को बताई जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कैथल व करनाल रोड की बात कही है, मैं माननीय सदस्यों को तथ्य भी देना चाहता हूं कि Central Road Infrastructure Fund इस शासनकाल में नहीं आया बल्कि इसकी मंजूरी पिछले शासनकाल में हुई थी और उस मंजूरी के आने के बाद तीन साल तक फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं आई थी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 में जैसे ही इसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस आई इसका काम शुरू कर दिया गया और सड़क कम्पलीट करवा दी लेकिन कैथल से चीका सड़क का प्रपोज़ल वर्ष 2019 में भेजा था और वर्ष 2023 से Central Road Infrastructure Fund से उसकी मंजूरी आई थी। जब इस संबंध में फॉरेस्ट क्लीयरेंस आयेगी जितने समय में आयेगी इसके लिये भी आगे की कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये दोनों पैचिज ना तो सरकार द्वारा इक्वेटे भेजे गये थे और ना ही इक्वेटे एप्रूव होकर आये थे। दोनों अलग-अलग फेज हैं और दोनों की अलग-अलग फेजिज में मंजूरी होकर दोनों

की कार्यवाही अलग-अलग तरीके से चली है। माननीय सदस्य दोनों फेजिज को जोड़ने का काम ना करे। प्रोजेक्ट जिस फेज में एप्रूव होते हैं उसी फेज में कार्यवाही होती है।

श्री ईश्वर सिंह: धन्यवाद सर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

**नियम 45 1 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के
लिखित उत्तर**

रोजगारों की संख्या

*36. श्री बलराज कुंडू: क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि—

- (क) राज्य में आने वाले छः महीनों में ग्रुप—डी, क्लास—III, क्लास—II तथा क्लास—I श्रेणियों में सरकार द्वारा क्रमशः कितने रोजगार उपलब्ध कराये जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा
- (ख) क्या सरकार द्वारा ऐसी सभी रिक्तियों के विज्ञापन, परीक्षा, साक्षात्कार तथा नियुक्ति तक की अनुसूची जारी किये जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी,

- (क) राज्य में आने वाले छः महीने में सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले ग्रुप—डी, क्लास—III, क्लास—II तथा क्लास—I श्रेणियों के संभावित कुल रोजगारों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	समूह का नाम	पदों की संख्या
1.	ग्रुप—डी	13657
2.	क्लास— III	45873
3.	क्लास— II	3125
4.	क्लास— I	179
कुल		62,834

- (ख) हाँ, श्रीमान जी। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन सभी पदों की अनुसूची जारी कर दी गई है।

.....

चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण करना

* 37. श्री प्रवीण डागर : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) क्या यह तथ्य है कि बजट सत्र 2022 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पलवल में एक चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण करने की घोषणा की गई थी;
- (ख) क्या उक्त चिकित्सा संस्थान के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई स्थान निश्चित किया गया है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा
- (ग) उक्त चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए बजट कब तक जारी किए जाने की संभावना है तथा इसका निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री अनिल विज):

- (क) हाँ, श्रीमान जी।
- (ख) हाँ, श्रीमान जी। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पलवल की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत पेलक की 47 एकड़ 01 कनाल 01 मरला भूमि का चयन किया गया है।
- (ग) परियोजना के निष्पादन के लिए जल्द ही कार्यकारी एंजेसी नियुक्त की जाएगी और तदानुसार बजट प्रावधान किया जाएगा।

कच्ची सड़क को पक्का करना

*38. श्री शमशेर सिंह गोपी : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएं कि:

- (क) असंध विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली निम्नलिखित 14 कच्ची सड़कों को पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है:-

- (i) राहडा से डींग;
- (ii) जयसिंह पुरा से रंगरुटी खेड़ा;
- (iii) कोल खेर से गंगाटेहड़ी;
- (iv) असंध कैथल रोड से मर्दानहेड़ी;
- (v) डेरा गामा से ललैन पिंगहाला रतग;
- (vi) डेरा अर्धना से बंदराला;
- (vii) चौचड़ा से चोरकारसा;
- (viii) रुकसाना से हबरी वाया डींग;
- (ix) चौचड़ा से कुम्बर किला;
- (x) चौचड़ा से रुकसाना;
- (xi) रिसालवा से मलिकपुर;
- (xii) उपलाना-जलमाना सड़क से श्री लेखा सिंह सुपुत्र केसर सिंह उपलाना-जलमाना के खेत तक;
- (xiii) जुंडला से जैनी एक्स्टेंशन आगे स्टोन्डी (मुनक से करनाल सड़क) तक;
- (xiv) गंगा टेहड़ी से कोल खेडा;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों को कब तक पक्का किए जाने की संभावना है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो अब तक निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के कारण क्या हैं?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): क, ख तथा ग, महोदय, उपरोक्त 13 सड़कों में से क्योंकि क्रमांक (iii) की सड़क क्रमांक (xiv) पर दोहराई गई है, 03 सड़कें पहले से ही पक्की सड़कें हैं। इन शेष 10 कच्चे रास्तों को पक्का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डीपीआर की संख्या तथा होर्डिंग के लिए निर्धारित सरकारी स्थान

***39. श्री भारत भूषण बतरा :** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) राज्य में होर्डिंग, फ्लेक्स तथा पोस्टर इत्यादि लगाने के लिए डीपीआर स्थलों तथा सरकारी स्थलों की जिलेवार संख्या कितनी है;
- (ख) रोहतक जिले में डीपीआर स्थलों संख्या कितनी है तथा उनके स्थान का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह तथ्य है कि निजी व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत फ्लेक्स, होर्डिंग/पोस्टर डीपीआर साइट पर लगाए जा रहे हैं; यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; तथा
- (घ) सरकारी डीपीआर तथा स्थलों पर अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्स तथा पोस्टरों को लगाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी,

- (क) राज्य के सभी जिलों में सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के होर्डिंग्स की कुल संख्या 994 है। इनकी जिलावार संख्या का विवरण पताका 'A' पर रखा है।
- (ख) वर्तमान में जिला रोहतक में सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के होर्डिंग्स की संख्या 49 हैं। इनका विवरण पताका 'B' पर रखा है।
- (ग) कभी-कभी जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अनाधिकृत रूप से विभागीय होर्डिंग पर लगी प्रचार सामग्री को हटाने के संबंध में तुरंत कार्रवाई की जाती है।
- (घ) इस संबंध में सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के जिला नियुक्त फिल्ड अधिकारी (जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी) द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। यदि किसी विभागीय होर्डिंग पर निजी प्रचार सामग्री प्रदर्शित/चस्पा पाई जाती है तो उसे तत्काल हटा दिया जाता है।

1

DIPRO'S से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक जिला में विभागीय होर्डिंग्स की स्थिति

क्रमांक	जिला	होर्डिंग्स की संख्या
01.	पानीपत	46
02.	पंचकूला	46
03.	यमुनानगर	48
04.	अम्बाला	49
05.	कुरुक्षेत्र	46
06.	रोहतक	49
07.	कैथल	46
08.	जींद	44
09.	सिरसा	48
10.	फतेहाबाद	49
11.	हिसार	48
12.	भिवानी	40
13.	रेवाड़ी	48
14.	फरीदाबाद	49
15.	गुरुग्राम	46
16.	नारनौल	49
17.	झज्जर	46
18.	मेवात	48
19.	पलवल	44
20.	करनाल	49
21.	बखी दादरी	07
22.	सोनीपत	49
कुल		994

2

जिला रोहतक में विभिन्न स्थानों पर लगे विभागीय होर्डिंग्स की लोकेशन/सूची निम्नप्रकार से है।

रोहतक	विवरण	
1	डीईओ आफिस, नजदीक बाल भवन, रोहतक	1
2	अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय (पुराना) बीडीपीओ आफिस	1
3	तिलियार लेक, नजदीक चिड़ियाघर, रोहतक	1
4	होटल मैनेजमेंट संस्थान के अंदर, रोहतक	1
5	उपनिदेशक कृषि, रोहतक	1
6	खजाना कार्यालय, रोहतक	1
7	लघु सचिवालय में पार्क के अन्दर	1
8	कैनाल रैस्ट हाऊस	1
9	श्रीराम रंगशाला, रोहतक	1
10	राजीव गांधी खेल परिसर, रोहतक	1
11	आईटीआई रोहतक	1
12	न्यू बस स्टैंड चौकी के पास	3
13	न्यू बस स्टैंड, मुख्य द्वार रोहतक	
14	न्यू बस स्टैंड जीएम आफिस के पीछे	
15	फिल्म संस्थान के सामने, रोहतक	1
16	सुनारिया जेल परिसर (क्षतिग्रस्त)	1
17	मिल्क प्लांट, रोहतक	2
18	मिल्क प्लांट के अंदर	
19	छोटूराम स्टेडियम, सोनीपत रोड़	1
20	आईसी कॉलेज नजदीक कैन्टीन, रोहतक	1
21	सीएमओ आफिस, मैन गेट के आगे, रोहतक	1

Janfer
Dist. Information & Public Relations Officer
ROHTAK-1343

पृष्ठ नं० I

3

22	सिविल अस्पताल, रोहतक	2
23	सिविल अस्पताल, रोहतक	
24	अनाज मंडी रोहतक	2
25	अनाज मंडी रोहतक	
26	नई सब्जी मंडी रोहतक	1
27	नेकीराम कॉलेज, पार्क/साईकिल स्टैंड, रोहतक	1
28	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (क्षतिग्रस्त)	1
29	सर्किट हाऊस के अंदर, दिल्ली चौक	1
30	आईएमटी चौक, मुख्य द्वार रोहतक	3
31	आईएमटी चौक, पार्क की दीवार के साथ	
32	एशियन पेन्ट चौक (गोल चक्र)	
33	ओबीसी बैंक के सामने, हुडा आफिस रोहतक	1
34	एलएन हिन्दु कॉलेज ब्यायज भिवानी रोड़	1
	महम	6
35	ग्रेन मार्केट, महम	
36	एसडीएम आफिस, महम	
37	सिविल अस्पताल, महम	
38	महम चबूतरा	
39	बीडीपीओ आफिस, महम	
40	बस स्टैंड, महम	
	लाखनमाजरा	3
41	सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाखनमाजरा	
42	सिविल अस्पताल, लाखनमाजरा	


 Dist. Information & Public Relations Officer
 ROHTAK-1341

फैल नं० 2

	बीडीपीओ ब्लॉक के अन्दर लाखनमाजरा	
	सांपला	3
44	बीडीपीओ आफिस, सांपला	
45	सिविल अस्पताल के अन्दर, सांपला	
46	बाईपास सांपला	
	कलानौर	3
47	बस स्टैंड, कलानौर	
48	सीएचसी कलानौर -	
49	बीडीपीओ आफिस, कलानौर	
	कुल	49

प्र. नं. 3

Office
Dist. Information & Public Relation Officer
ROHTAK-13113

H

कुरुक्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी पार्क विकसित करना

*40. श्री सुभाष सुधा : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) क्या युवाओं के रोजगार के लिए कुरुक्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा
- (ख) यदि हां, तो कुरुक्षेत्र में इस पार्क के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): नहीं श्रीमान जी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर
फिरनियों को पक्का करना

41. श्री सीता राम यादव : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएं कि क्या अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पडने वाले उन गांवों के नाम क्या हैं जिनमें सरकार द्वारा फिरनियों को पक्का किया जाना है तथा उक्त फिरनियों को कब तक पक्का किये जाने की सम्भावना है ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान्, सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रथम चरण में 5000 से अधिक आबादी (पिछले वर्ष 31 दिसंबर के परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के अनुसार) वाली ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से पक्का बनाया जाएगा। अटेली विधानसभा क्षेत्र में 5000 से अधिक आबादी वाले केवल दो गांव ऐसे हैं जिनकी फिरनी का कुछ हिस्सा कच्चा है। इन 2 कार्यों का अनुमान पहले से ही सरकार के पास है और इन फिरनियों के 30.09.2024 तक पक्का होने की संभावना है।

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र का नाम	गांव का नाम	कार्य का नाम	लागत (लाख रूपये में)
1.	अटेली	धनौदा	इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से फिरनी का निर्माण	44.30
2.	अटेली	खेरी	इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से फिरनी का निर्माण	28.50

शिव धाम योजना के अंतर्गत कार्य पूरा करना

42. श्री सीता राम यादव : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएं कि :-

(क) अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पडने वाले उन गांवों के नाम क्या हैं जिनमें शिवधाम योजना के तहत चारदीवारी, रास्ते पक्के करना, टिन शेड तथा पानी की टंकी से संबंधित कार्य लंबित हैं; तथा

(ख) उक्त कार्यों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : श्रीमान्,

(क) सदन के पटल पर बयान रखा गया है।

(ख) विवरण में उल्लिखित गांवों के शमशान घाटों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के प्राकलन हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड में प्राप्त हो गये हैं। चयनित शिवधामों में सरकार की नीति के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

बयान

SR. NO.	Constituency	NAME OF VILLAGES	NAME OF FACILITIES NOT AVAILABLE IN CREMATION GROUNDS
1	2	3	4
1	Ateli	Nangal	Const. of B/Wall, Shed, W/Tanki, Rasta
2	Ateli	Nawadi	Const. of B/Wall, Shed, W/Tanki, Rasta
3	Ateli	Hasanpur	Const. of Rasta, B/wall, W/Tanki, Tin Shed
4	Ateli	Bhori	Const. of Rasta and B/Wall, W/Tanki, Tin Shed
5	Ateli	Bhilwara	Const. of B/wall, Shed, W/Tanki
6	Ateli	Khairani	Const. of B/wall, Shed, W/Tanki
7	Ateli	Neerpur	Const. of B/wall, Shed, W/Tanki
8	Ateli	Rajpura	Const. of B/wall, Shed, W/Tanki
9	Ateli	Tigra	Const. of B/wall, Shed, Rasta
10	Ateli	Tobra	Const. of B/wall, Shed, W/Tanki
11	Ateli	Rampura	Const. of B/Wall, Shed, W/Tanki
12	Ateli	Kanti	Const. of B/Wall, Shed, W/Tanki
13	Ateli	Sarai Bahadur Nagar	Const. of B/Wall, Shed, W/Tanki
14	Ateli	Saidpur	Const. of Tin Shed, B/Wall, W/Tanki

SR. NO.	Constituency	NAME OF VILLAGES	NAME OF FACILITIES NOT AVAILABLE IN CREMATION GROUNDS
1	2	3	4
15	Ateli	Bazad	Const. of Tin Shed, B/Wall, W/Tanki
16	Ateli	Kheri	Const. of B/Wall, Water Tanki, Tin Shed
17	Ateli	Ganiyar	Const. of B/wall, W/Tanki, Tin Shed
18	Ateli	Beghpur	Const. of B/wall, W/Tanki, Rasta
19	Ateli	Dhanunda	Const. of B/wall, W/Tanki, Tin Shed
20	Ateli	Chandpura	Const. of B/wall, Tin Shed, W/Tanki
21	Ateli	Ateli Rural	Const. of B/wall, W/Tanki, Tin Shed
22	Ateli	Kheri	Const. of B/wall, Tanki, Shed
23	Ateli	Syana	Const. of B/wall, Shed, W/Tanki
24	Ateli	Bharaf	Const. of B/Wall, Rasta, W/Tanki
25	Ateli	Gomli	Const. of B/Wall, W/Tanki
26	Ateli	Uninda	Const. of B/wall, W/Tanki, Tin Shed
27	Ateli	Bochariya	Const. of W/Tanki, Tin Shed
28	Ateli	Tajpur	Const. of Rasta and B/Wall
29	Ateli	Mahasar	Const. of B/wall, Tin Shed
30	Ateli	Chelawas	Const. of Shed, W/Tanki
31	Ateli	Kharkada Bass	Const. of Pathway, Shed
32	Ateli	Nautana	Const. of B/Wall, Shed
33	Ateli	Talwana	Const. of Shed, W/Tanki
34	Ateli	Unhani	Const. of W/Tanki, Shed
35	Ateli	Koka	Const. of B/Wall, Tanki
36	Ateli	Jhigawan	Const. of W/Tanki, Shed
37	Ateli	Atali	Const. of B/Wall, W/Tanki
38	Ateli	Kalwari	Const. of Rasta, B/wall
39	Ateli	Kotia	Const. of B/Wall, W/Tanki
40	Ateli	Uchhat	Const. of B/Wall, W/Tanki
41	Ateli	Jharli	Const. of B/Wall, W/Tanki

SR. NO.	Constituency	NAME OF VILLAGES	NAME OF FACILITIES NOT AVAILABLE IN CREMATION GROUNDS
1	2	3	4
42	Ateli	Karia	Const. of Shed, W/Tanki
43	Ateli	Bhori	Const. of W/Tanki
44	Ateli	Khariwara	Installation of Tin Shed
45	Ateli	Mohmmadpur	Installation of Tin Shed
46	Ateli	Fatehpur	Installation of Tin Shed
47	Ateli	Katkai	Installation of Tin Shed
48	Ateli	Rambass	Const. of Rasta
49	Ateli	Khairana	Const. of Rasta
50	Ateli	Bhalkhi	Const. of Rasta
51	Ateli	Silarpur	Const. of Rasta
52	Ateli	Mundia Khera	Const. of B/Wall
53	Ateli	Manpura	Const. of W/Tanki

पाकों तथा व्यायामशालाओं को विकसित करना

43. श्री सीता राम यादव : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पडने वाले उन गांवों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक पाकों एवं व्यायामशालाओं को विकसित नहीं किया गया है तथा ऐसे पाकों एवं व्यायामशालाओं को कब तक विकसित किये जाने की संभावना है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान्, अटेली विधानसभा क्षेत्र के 10 गांवों बाछौद, बिहाली, चांदपुरा, डोंगरा अहीर, गुढ़ा, ककराला, कटकई, खरखड़ा बास, मुंडिया खेड़ा व सेहलंग में पार्क-एवं-व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं।

4 गांवों छपरा सलीमपुर, दुलोठ जाट, अटाली और डोंगरा जाट में पार्क-एवं-व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पार्क-एवं-व्यायामशालाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के साथ निर्माण लागत का 20 प्रतिशत योगदान देने का प्रस्ताव पारित करने वाली पंचायतों को मंजूरी दी जाएगी।

अटेली विधानसभा क्षेत्र के 25 गांवों में ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

सरकार ने कनीना खंड के गांव गाहरा में इन्डोर जिम की स्थापना की मंजूरी दे दी है। जो ग्राम पंचायतें 1000 वर्गफुट से 1600 वर्गफुट क्षेत्रफल के मौजूदा भवन के साथ जिम उपकरणों की लागत का 20 प्रतिशत योगदान के लिए प्रस्ताव पारित करेंगी, उन ग्राम पंचायतों में इन्डोर जिम स्थापित करने हेतु विचार किया जाएगा। सदन के पटल पर बयान भी रखा गया है।

बयान

Statement on Unstarred Assembly Question No.43 regarding Gym/Vayayamshala					
Sr. No.	Name of village	Name of Block	Open Gym (available Yes/No)	Park-cum- Vyayamshala (available Yes/No)	Indoor Gym (available Yes/No)
1	Ateli	Ateli	No	No	No
2	Bachhod	Ateli	Yes	Yes	No
3	Bajar	Ateli	No	No	No
4	Begpur	Ateli	No	No	No
5	Bhilwara	Ateli	No	No	No
6	Bhori	Ateli	Yes	No	No
7	Bihali	Ateli	NO	Yes	No
8	Bocharia	Ateli	NO	No	No
9	Chandpura	Ateli	NO	Yes	No
10	Chhapra Salimpur	Ateli	NO	In Progress	No
11	Dhanaunda	Ateli	NO	No	No
12	Fatehpur	Ateli	Yes	No	No
13	Ganiyar	Ateli	NO	No	No
14	Garhi Ruthal	Ateli	Yes	No	No
15	Gujjarwas	Ateli	NO	No	No
16	Hasanpur Girdharpur	Ateli	Yes	No	No
17	Kanti	Ateli	NO	No	No
18	Kariya	Ateli	Yes	No	No
19	Katkai	Ateli	yes	Yes	No
20	Khalrani	Ateli	yes	No	No
21	Khariwara	Ateli	NO	No	No
22	Kheri	Ateli	NO	No	No
23	Khor	Ateli	NO	No	No
24	Kunjpura Shyampura	Ateli	NO	No	No
25	Mahasar	Ateli	NO	No	No
26	Mirjapur	Ateli	NO	No	No
27	Mohalra	Ateli	NO	No	No
28	Mohamadpur	Ateli	NO	No	No
29	Nangal	Ateli	NO	No	No
30	Nawadi	Ateli	NO	No	No
31	Neerpur	Ateli	NO	No	No
32	Prithivpura	Ateli	NO	No	No
33	Rajpura	Ateli	NO	No	No
34	Rampura	Ateli	NO	No	No
35	Rata Kalan	Ateli	Yes	No	No
36	Rata Khurd	Ateli	Yes	No	No
37	Saidpur	Ateli	NO	No	No
38	Salimpur Gokalpur	Ateli	NO	No	No
39	Sarai Bahadur Nagar	Ateli	NO	No	No
40	Sujapur	Ateli	NO	No	No
41	Surani	Ateli	NO	No	No
42	Tajpur	Ateli	NO	No	No
43	Tigra	Ateli	Yes	No	No
44	Tobra	Ateli	Yes	No	No
45	Uninda	Ateli	Yes	No	No
46	Agriyar	Kanina	NO	No	No
47	Baghot	Kanina	NO	No	No
48	Bewal	Kanina	NO	No	No

Sr. No.	Name of village	Name of Block	Open Gym (available Yes/No)	Park-cum- Vyayamshala (available Yes/No)	Indoor Gym (available Yes/No)
49	Bharaf	Kanina	NO	No	No
50	Bhojawas	Kanina	Yes	No	No
51	Chelawas	Kanina	Yes	No	No
52	Chhitroli	Kanina	Yes	No	No
53	Dhanaunda	Kanina	NO	No	No
54	Gahra	Kanina	NO	No	No
55	Gomia	Kanina	Yes	No	No
56	Gomli	Kanina	NO	No	No
57	Gudha	Kanina	NO	Yes	No
58	Israna	Kanina	NO	No	No
59	Jharli	Kanina	Yes	No	No
60	Jhigawan	Kanina	NO	No	No
61	Kaimia	Kanina	NO	No	No
62	Kakrala	Kanina	NO	Yes	No
63	Kapoori	Kanina	NO	No	No
64	Karira	Kanina	NO	No	No
65	Khalirana	Kanina	NO	No	No
66	Kharkhra Bas	Kanina	NO	Yes	No
67	Kheri	Kanina	NO	No	No
68	Koka	Kanina	NO	No	No
69	Kotia	Kanina	NO	No	No
70	Mānpura	Kanina	Yes	No	No
71	Mohanpur	Kanina	Yes	No	No
72	Mori	Kanina	NO	No	No
73	Nangal	Kanina	NO	No	No
74	Nautana	Kanina	NO	No	No
75	Partal	Kanina	NO	No	No
76	Pathera	Kanina	NO	No	No
77	Putra	Kanina	Yes	No	No
78	Rambas	Kanina	NO	No	No
79	Rasulpur	Kanina	NO	No	No
80	Sehlang	Kanina	Yes	Yes	No
81	Siana	Kanina	Yes	No	No
82	Sihore	Kanina	Yes	No	No
83	Sundrah	Kanina	NO	No	No
84	Talwana	Kanina	NO	No	No
85	Uchhat	Kanina	NO	No	No
86	Unahani	Kanina	Yes	No	No
87	Atali	Sihma	NO	In Progress	No
88	Dongra Ahir	Sihma	NO	Yes	No
89	Dongra Jat	Sihma	NO	In Progress	No
90	Duloth Jat	Sihma	NO	In Progress	No
91	Kalwari	Sihma	NO	No	No
92	Mundia Khara	Sihma	NO	Yes	No
93	Sagarpur	Sihma	NO	No	No
94	Silarpur	Sihma	NO	No	No

.....

ट्यूबवेलों के बकाया बिल

44. श्री सीता राम यादव : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

- क) क्या यह तथ्य है कि अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ट्यूबवेलों के बिल बकाया हैं, और
- ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, ब्यौरा दें ?

विकास एवं पंचायत मन्त्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) :

- क) हां श्रीमान, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
- ख) ग्राम पंचायतें ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन के बकाया बिलों का भुगतान अपने स्वयं के स्रोतों की आय एवं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान जोकि ग्राम निधि है, से कर सकती हैं ।

अनुसूचित प्रश्न-4 के संघर्ष में विवरण							
निर्वाचन क्षेत्र-अटली जिला-नारनौल							
क्र. सं.	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	ग्राम पंचायत में स्थापित दूरबीन की संख्या	बिजली कनेक्शन संख्या	दूरबीन का बिल भकाया है या नहीं	यदि हाँ तो दूरबीन का बिल भकाया कितने रुपये में	
			ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	हाँ / नहीं	ग्राम पंचायत	
1	अटली	बडोरा	00	1	3565971000	हाँ	5,720
2	अटली	बनवा	00	1	4327871000	हाँ	5,32,872
3	अटली	बाघोरा	00	1	7	हाँ	9,61,570
4	अटली	बागोरा	00	1	9	हाँ	5,07,073
5	अटली	दुलारपुर	00	1	7798112407	हाँ	91,248
6	अटली	बाडी	00	1	7	हाँ	11,85,065
7	अटली	बाडी	00	1	9	हाँ	9,51,817
8	अटली	बाडी	00	1	6	हाँ	7,43,433
9	अटली	भिरवपुर	00	1	9149871000	हाँ	52,61,630
10	अटली	बाडी	00	1	6181900000	हाँ	23,63,571
11	अटली	बुलवा	00	3	SR510173Y, SR51-0186W	हाँ	11,76,171
12	अटली	बनवा	00	3	NA/P4	हाँ	4,12,572
13	अटली	बनवा	00		NA/P7	हाँ	3,14,701
14	अटली	बनवा	00		7123002000	हाँ	4,77,830
15	अटली	बिहारी	00	1	2230002000	हाँ	2,60,267
16	अटली	बनवा	00	6	078612000	हाँ	1,22,279
17	अटली	अटली	00	10	DD/P7	हाँ	14,18,284
18	अटली	अटली	00		DD/P4	हाँ	10,70,260
19	अटली	अटली	00		DD/P8	हाँ	7,88,111
20	अटली	अटली	00		DD/P9	हाँ	6,43,879
21	अटली	अटली	00		DD/P8	हाँ	5,24,568
22	अटली	अटली	00		DD/P8	हाँ	3,55,987
23	अटली	अटली	00		DD/P11	हाँ	1,83,781
24	अटली	अटली	00		300691000	हाँ	21,25,841
25	अटली	अटली	00		86281000	हाँ	38,33,739
26	अटली	अटली	00		2 (पैर अटली)	113111	हाँ
27	अटली	अटली	00	3 (पैर अटली)	737991000	हाँ	5,843
28	अटली	अटली	00	7 (पैर अटली)	CD18	हाँ	49,650
29	अटली	अटली	00	7 (पैर अटली)	731400000	हाँ	34,38,703
30	अटली	अटली	00	1 (पैर अटली)	1875001000	हाँ	1,17,308
31	अटली	अटली	00	3 (पैर अटली)	346991000	हाँ	13,68,628
32	अटली	अटली	00	3 (पैर अटली)	NA3114	हाँ	3,39,457
33	अटली	अटली	00		907790000	हाँ	12,23,261
34	अटली	अटली	00		89681000	हाँ	11,15,615
35	अटली	अटली	00	1	10000000	हाँ	25,15,004
36	अटली	अटली	00	1	27181000	हाँ	39,298
37	अटली	अटली	00	4 (पैर अटली)	897901000	हाँ	8,183
38	अटली	अटली	00		NA3113	हाँ	1,27,857
39	अटली	अटली	00		83720	हाँ	5,621
40	अटली	अटली	00	NA2020	हाँ	781	
41	अटली	अटली	00	2	082842000	हाँ	6,818
42	अटली	अटली	00	1	412281000	हाँ	25,14,922
43	अटली	अटली	00	1	801691000	हाँ	22,46,429
44	अटली	अटली	00	1	N328	हाँ	23,000
45	अटली	अटली	00	3	N/A	हाँ	17,86,013
46	अटली	अटली	00	1	N/A	हाँ	7,00,000
47	अटली	अटली	00	2	N/A	हाँ	3,00,000
48	अटली	अटली	00	1	NA/P1	हाँ	11,32,663
49	अटली	अटली	00	2 (पैर अटली)	DD/P8	हाँ	4,62,387
50	अटली	अटली	00		DD/P11	हाँ	4,16,284
51	अटली	अटली	00	3 (पैर अटली)	NA336	हाँ	3,44,331
52	अटली	अटली	00	1	CD1412	हाँ	1,34,391
53	अटली	अटली	00	1 (पैर अटली)	NA3115	हाँ	82,474
कुल			81	87			4,95,18,138

राशन डिपो पर छापेमारी की संख्या

45. श्री नीरज शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) राज्य में जनवरी, 2019 से नवंबर, 2023 तक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कितने राशन डिपो पर छापेमारी की तथा उक्त छापेमारी के दौरान स्टॉक में पाई गई अनियमितताओं का जिलावार ब्यौरा क्या है; तथा
- (ख) छापे के दौरान कितने डिपो में स्टॉक में अनियमितताएं पाई गई तथा उसके बाद अधिकारियों ने रिकॉर्ड के अनुसार माल के स्टॉक पूरा होने से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा स्टॉक पूरा होने की उक्त रिपोर्ट को सौंपने वाले उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई, तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

- (क) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा जनवरी, 2019 से नवंबर, 2023 तक 2808 राशन डिपो में छापेमारी की गई। अनियमितताएं 310 डिपो में पाई गईं। उक्त छापे के दौरान स्टॉक में पाई गई अनियमितताओं का जिलेवार ब्यौरा अनुबंध-ए पर उपलब्ध है।
- (ख) ऐसे छापों के दौरान जिन मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, उनमें बाद में किसी भी अधिकारी ने स्टॉक पूरा होने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

.....

@ उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के जबाव के अनैक्चर्ज 30 पेजिज के होने के कारण चेयर के आदेशानुसार एवं पूर्व प्रथानुसार विधान सभा के पुस्तकालय में रखवाए गए!

आई.पी.एस. अधिकारियों के इज़राइल दौरे के संबंध में ब्यौरा

46. श्री नीरज शर्मा: क्या गृह मंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2018 में आई.पी.एस.अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इज़राइल दौरे पर गया था; तथा
- (ख) क्या अधिकारियों द्वारा उक्त दौरे की कोई रिपोर्ट तैयार की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

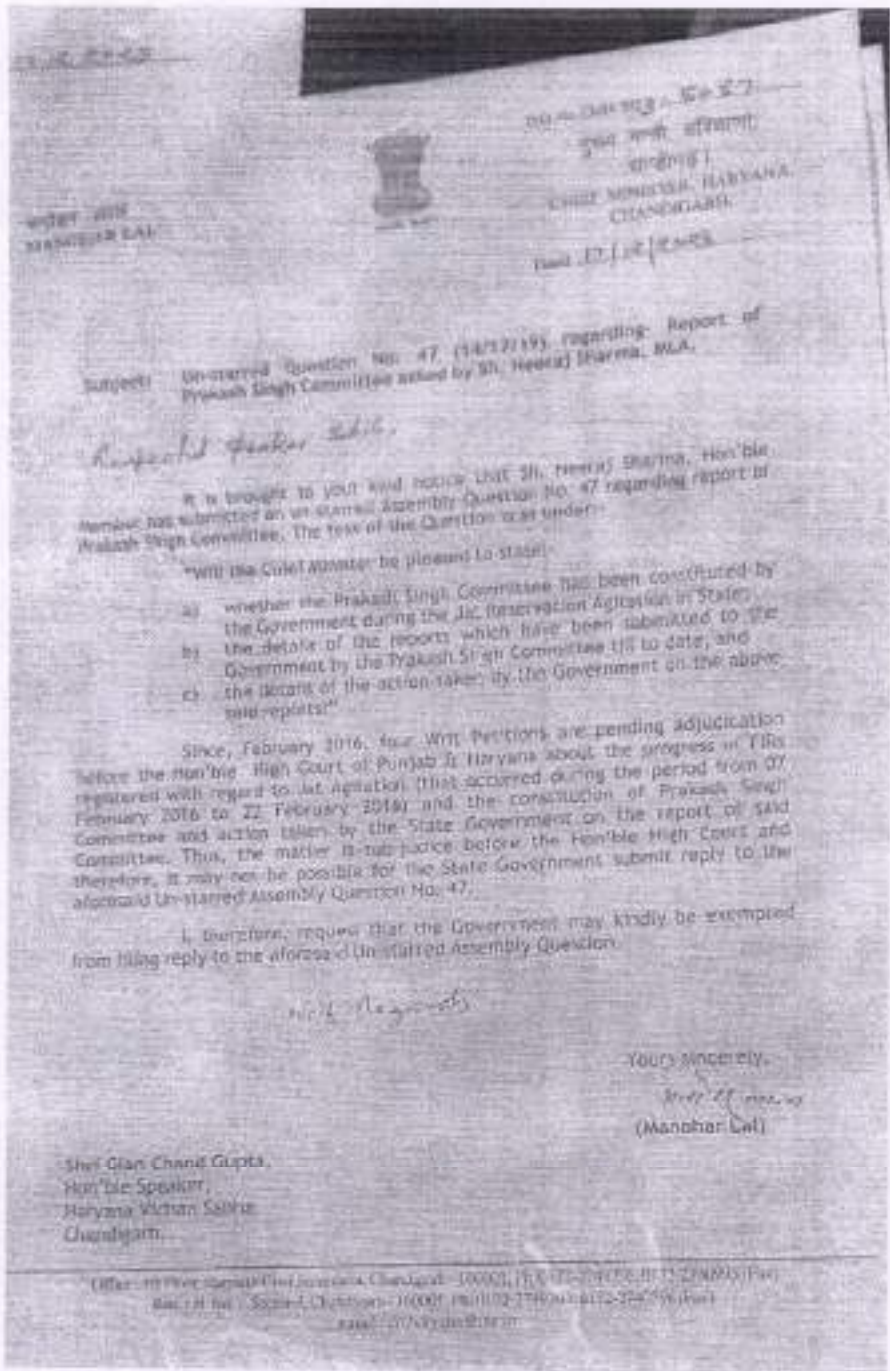
गृह मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय, बिंदुवार उत्तर इस प्रकार है:-

- (क) हाँ श्रीमान ।
- (ख) हाँ श्रीमान, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट हरियाणा पुलिस की कानून और व्यवस्था, अपराध, सुरक्षा और खुफिया कार्यों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए संभावित उपायों से संबंधित है और राज्य की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था के परिदृश्य में और सुधार के लिए हरियाणा में पेश की जा सकने वाली नवीनतम तकनीकों की उपलब्धता पर भी विचार करती है।

प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट

47. श्री नीरज शर्मा : क्या गृह मंत्री कृपया बताएं कि : -

- (क) क्या राज्य में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा प्रकाश सिंह कमेटी का गठन किया गया था;
- (ख) प्रकाश सिंह कमेटी द्वारा आज तक सरकार को सौंपी गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; तथा
- (ग) उपरोक्त रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?



अधिवक्ताओं को किया गया भुगतान की सीमा

48. श्री नीरज शर्मा: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि: -

- (क) निजी क्षेत्र में नौकरी में 75% आरक्षण के संबंध में 2021 के केस संख्या सी. डब्ल्यू.पी. 26573 के लिए माननीय उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई की संख्या कितनी है;
- (ख) उपरोक्त केस में माननीय उच्च न्यायालय में सरकार के पक्ष में महाधिवक्ता, श्री महाधिवक्ता श्री बलदेव राज महाजन व्यक्तिगत रूप से कितनी सुनवाईयों में उपस्थित हुए तथा श्री बलदेव राज महाजन को उनकी नियुक्ति से 30 नवंबर 2023 तक सरकार द्वारा कितना भुगतान किया गया; तथा
- (ग) क्या यह तथ्य है कि माननीय उच्च न्यायालय में अन्य मामलों/ केसों में सरकार द्वारा निजी अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है यदि हां, तो इस संबंध में 01 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023 तक सरकार द्वारा कितना भुगतान किया गया तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी,

- (क) प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका संख्या 26573 ऑफ 2021 और अन्य आठ संबद्ध मामलों के लिए माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई की कुल संख्या 30 है।
- (ख) श्री बलदेव राज महाजन, महाधिवक्ता हरियाणा रोक आदेश के विरुद्ध प्रथम सुनवाई पर मामले में उपस्थित हुए और उसके बाद, श्री तुषार मेहता, सालिसिटर-जनरल रोक मामले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक सुनवाई पर उपस्थित हुए और उसके बाद, श्री जगबीर मलिक, अपर महाधिवक्ता के साथ श्री पुनित बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, मामले में हरियाणा राज्य के लिए अधिनियम का बचाव करने हेतु 26 सुनवाईयों

पर उपस्थित हुए और श्री जगबीर मलिक, अपर महाधिवक्ता दो सुनवाईयों पर उपस्थित हुए थे।

इन मामलों में श्री बलदेव राज महाजन, महाधिवक्ता, हरियाणा को किसी काउंसेल फीस का भुगतान नहीं किया गया था, चूंकि महाधिवक्ता, हरियाणा किसी मामले में काउंसेल फीस का दावा नहीं करता है, किन्तु वह 10.11.2014 से 16.11.2021 तक प्रतिमास 2,50,000/- रूपए तथा दिनांक 17.11.2021 से अब तक 4,50,000/- रूपए की केवल मासिक प्रतिधारण फीस प्राप्त कर रहे हैं।

- (ग) सरकार ने सिविल न्यायाधीशों का अपर जिला न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति हेतु सिफारिशों को रद्द करने के सम्बन्ध में याचिकाओं के लिए अन्य बैंच में निजी काउंसेल नियोजित किए। श्री विक्रमजीत बैनर्जी, भारतीय अपर सालिसिटर-जनरल सिविल याचिका संख्या 19775 ऑफ 2023 तथा अन्य सम्बन्धित मामलों अर्थात् सिविल याचिका संख्या 22818 ऑफ 2023, सिविल याचिका संख्या 23804 ऑफ 2023 तथा सिविल याचिका संख्या 26217 ऑफ 2023 में प्रथम जनवरी, 2020 से 30.11.2023 के बीच उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए।

श्री तुषार मेहता, भारतीय सालिसिटर जनरल को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 4,40,000/-रूपए की काउंसेल फीस का भुगतान किया गया तथा श्री पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता को 75 प्रतिशत आरक्षण के नौ मामलों में 2,20,000/-रूपए प्रति सुनवाई की दर से काउंसेल फीस का भुगतान किया गया तथा कुल 55,44,000/-रूपए काउंसेल फीस का भुगतान किया गया। श्री विक्रमजीत बैनर्जी को अभी तक किसी भी काउंसेल फीस का भुगतान नहीं किया गया है, चूंकि उक्त मामले में निर्णय अभी लम्बित है।

.....

कीटनाशकों, बीजों तथा उर्वरकों के नमूने

49. श्री जगबीर सिंह मलिक: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या प्रत्येक जिले में लक्ष्य के अनुरूप सरकार द्वारा कीटनाशकों, बीजों तथा उर्वरकों आदि के नमूने एकत्रित किए गए हैं; यदि नहीं, तो 2019-20 से ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) क्या नमूनों की विफलता के मामलों में वर्ष 2015 से किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया/ सजा दी गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल):

(क) हाँ श्रीमान जी, प्रत्येक जिले में लक्ष्य के अनुसार कीटनाशकों, बीजों तथा उर्वरकों के नमूने एकत्रित करने का विवरण वर्ष 2019-20 से अनुलग्नक 'ए' 'बी' और 'सी' पर संलग्न है।

(ख) विवरण अनुलग्नक 'डी' पर संलग्न है।

अनुलग्नक 'ए'

क्र 0	जिला	कीटनाशक नमूनों का विवरण 2019-20 से 2022-23 तक							
		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अम्बाला	127	112	127	124	127	135	127	146
2	भिवानी	135	73	100	79	90	65	90	33
3	चरखी दादरी	0	0	35	0	45	2	45	7
4	फरीदाबाद	64	40	64	51	64	36	64	37
5	फतेहाबाद	194	142	194	165	194	131	194	156
6	गुड़गांव	31	29	31	29	31	30	31	25
7	हिसार	207	205	207	181	207	192	207	186
8	झज्जर	165	114	165	91	165	118	165	108
9	जींद	137	109	137	94	137	128	137	135
10	कैथल	165	130	165	105	165	149	165	147

11	करनाल	225	225	225	225	225	230	225	227
12	कुरुक्षेत्र	174	166	174	168	174	168	174	158
13	मेवात	32	36	32	30	32	37	32	32
14	महेन्द्रगढ़	32	33	32	28	32	31	32	34
15	पलवल	55	22	55	34	55	24	55	19
16	पंचकूला	40	44	40	35	40	34	40	35
17	पानीपत	186	142	186	128	186	129	186	107
18	रेवाड़ी	97	79	97	55	97	21	97	64
19	रोहतक	100	75	100	75	100	87	100	77
20	सिरसा	202	126	202	135	202	140	202	146
21	सोनीपत	129	128	129	121	129	124	129	130
22	यमुनानगर	128	114	128	126	128	128	128	88
	कुल	2625	2144	2625	2079	2625	2139	2625	2097

अनुलग्नक 'बी'

क्र०	जिला	बीज नमूनों का विवरण 2019-20 से 2022-23 तक							
		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अम्बाला	141	104	141	97	141	85	165	107
2	भिवानी	220	168	220	93	149	140	172	140
3	चरखी दादरी	0	0	0	0	73	18	91	48
4	फरीदाबाद	85	81	85	75	85	58	107	73
5	फतेहाबाद	264	137	264	162	264	239	294	165
6	गुड़गांव	79	78	79	78	79	77	100	96
7	हिसार	328	295	328	296	328	278	363	256
8	झज्जर	213	143	213	80	213	116	237	123
9	जींद	264	243	264	162	264	234	293	248
10	कैथल	197	52	197	128	197	183	222	193
11	करनाल	217	183	217	182	217	219	240	241
12	कुरुक्षेत्र	204	168	204	185	204	180	228	147
13	मेवात	90	87	90	90	90	90	107	98
14	महेन्द्रगढ़	158	159	158	154	158	144	178	143
15	पलवल	149	123	149	137	149	128	178	33

16	पंचकूला	38	30	38	28	38	46	53	44
17	पानीपत	167	125	167	147	167	140	187	98
18	रेवाड़ी	181	154	181	143	181	128	204	157
19	रोहतक	161	90	161	90	161	116	186	117
20	सिरसा	310	217	310	177	310	271	342	203
21	सोनीपत	170	103	170	158	170	189	196	202
22	यमुनानगर	172	152	172	124	172	172	196	108
	कुल	3808	2892	3808	2786	3810	3251	4339	3040

अनुलग्नक 'सी'

क्र०	जिला	उर्वरक नमूनों का विवरण 2019-20 से 2022-23 तक							
		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अम्बाला	157	67	157	66	157	79	157	106
2	भिवानी	171	39	120	97	115	93	115	67
3	चरखी दादरी	0	0	51	0	56	4	56	15
4	फरीदाबाद	48	37	48	40	48	34	48	30
5	फतेहाबाद	292	103	292	143	292	179	292	164
6	गुड़गांव	47	49	47	46	47	42	47	44
7	हिसार	305	251	305	266	305	241	305	263
8	झज्जर	69	62	69	23	69	44	69	64
9	जींद	277	132	277	124	277	210	277	262
10	कैथल	269	74	269	88	269	176	269	114
11	करनाल	318	303	318	277	318	252	318	153
12	कुरुक्षेत्र	271	252	271	226	271	176	271	229
13	मेवात	62	54	62	60	62	52	62	55
14	महेन्द्रगढ़	91	91	91	75	91	64	91	63
15	पलवल	165	62	165	55	165	36	165	36
16	पंचकूला	27	26	27	27	27	23	27	25
17	पानीपत	151	133	151	134	151	123	151	63
18	रेवाड़ी	126	73	126	62	126	20	126	75
19	रोहतक	158	83	158	60	158	110	158	102

20	सिरसा	404	206	404	203	404	238	404	214
21	सोनीपत	224	222	224	208	224	230	224	224
22	यमुनानगर	193	175	193	197	193	194	193	184
	कुल	3825	2494	3825	2477	3825	2620	3825	2552

अनुलग्नक 'डी'

नमूनों की विफलता के मामले में वर्ष 2015 से किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया/ सजा दी गई			
क्र०	वर्ष	वस्तु का नाम	दोषी ठहराया/ सजा दी
1	2015-2016	उर्वरक	9
		कीटनाशक	9
		बीज	9
2	2016-2017	उर्वरक	2
		कीटनाशक	10
		बीज	2
3	2017-2018	उर्वरक	3
		कीटनाशक	12
		बीज	8
4	2018-2019	उर्वरक	13
		कीटनाशक	17
		बीज	3
5	2019-2020	उर्वरक	25
		कीटनाशक	38
		बीज	11
6	2020-2021	उर्वरक	17
		कीटनाशक	22
		बीज	9
7	2021-2022	उर्वरक	25
		कीटनाशक	14
		बीज	2
8	2022-2023	उर्वरक	10
		कीटनाशक	10
		बीज	3
	कुल	उर्वरक	104
		कीटनाशक	94
		बीज	50

गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना

50. श्री प्रदीप चौधरी:- क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उन गांवों का ब्यौरा क्या है जो अब तक पक्की सड़कों से नहीं जोड़े गए हैं तथा उपरोक्त गांवों को कब तक पक्की सड़कों के साथ जोड़ दिए जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): महोदय, कालका विधानसभा क्षेत्र के 10 नंबर गांव ऐसे हैं जो पक्की पीडब्ल्यूडी सड़क से नहीं जुड़े हैं। इन 10 सड़कों में से 2 न. सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इन सड़कों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	टिप्पणियाँ
1	पोलिंग बूथ नालाघाट से ग्राम धारला।	3.25	मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) उपलब्ध नहीं है।
2	कंडेरन से ढाबसू स्कूल	3.00	
3	ग्राम भोज पोंटा से कटाली स्कूल	2.00	
4	पीडब्लूडी सड़क ग्राम थाना से मारोग स्कूल तक	3.50	
5	कांगर घाट सड़क से धरदा स्कूल तक	4.10	
6	टिक्कर ताल रोड से गज्जन स्कूल तक	2.00	
7	पीडब्लूडी रोड हरकाघाट से रज्जी टिकारी स्कूल तक	2.00	
8	पंचकुला जिले में उट्टॉन स्कूल तक खुडली लोक निर्माण विभाग सड़क का निर्माण।	2.50	

9	टिक्कर ताल से मीरापुर वाया ग्राम भोगपुर ढिंडान	3.96	इस सड़क की 637.81 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार से प्राप्त हो चुकी है। सड़क निर्माण का प्रस्ताव किमी 0 से 3.96 (गांव टिक्कर से धरवाला) प्रक्रियाधीन है और किमी 3.96 से 7.50 (गांव धरवाला से मीरापुर) तक कोई मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) उपलब्ध नहीं है।
10	जेबीटी स्कूल से गांव उतरौन	3.54	इस सड़क की 603.11 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार से प्राप्त हो चुकी है, इस सड़क की निविदा आमंत्रित कर ली गई है।

(iii) इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

जान-माल के नुकसान का ब्यौरा

51. श्री प्रदीप चौधरी : क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) कालका विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में हाल ही के मानसून के दौरान हुए जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है; तथा
- (ख) जान-माल के नुकसान के लिए प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

- (क) महोदय, कालका विधानसभा क्षेत्र में माह जुलाई 2023 के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त दावों अनुसार तथा जिला प्रशासन के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा सत्यापन उपरांत, 04 मानवीय मृत्यु, आवासीय नुकसान के 155 दावों, पशु हानि के 02 दावों के अतिरिक्त निजी संपत्ति (घरेलू सामान कपडे व बर्तन) के नुकसान के 03 दावें प्राप्त हुए थे।

(ख) सरकार द्वारा 04 मानवीय मृत्यु के लिए 16,00,000 /-रूपये (प्रति मृतक 4,00,000/- रूपये) अनुग्रहराशि, आवासीय नुकसान के 155 दावों के लिए 14,70,000 रूपये, पशु हानि के 02 दावों के लिए 1,44,500 रूपये तथा निजि संपत्ति (घरेलू सामान कपडे व बर्तन) के नुकसान के 03 दावों के लिए 7,500 रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है ।

कालका विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत दावों और अनुमोदित मुआवजा राशि का विवरण अनुलंगक 'क' पर है ।

अनुलंगक 'क'

आवासीय नुकसान विवरण					
जिला	विधान सभा क्षेत्र	गांव का नाम	स्वीकृत दावें	अनुमोदित राशि	मुआवजा रूपये में
पंचकूला	कालका	बागवाली	1	10,000	
		भैरों की सैर पार्ट	1	1,20,000	
		भोज बालीग	14	1,10,000	
		भोज दारडा	1	5,000	
		भोज धरती	14	90,000	
		भोज जबीयल	6	35,000	
		भोज कोठी	7	35,000	
		भोज कोटी	17	1,20,000	
		भोज कुदाना	20	1,10,000	
		भोज मटोर	7	35,000	
		भोज नायटा	16	1,30,000	
		भोज प्लासरा	4	25,000	
		भोज पौंटा	5	35,000	
		भोज टिपरा	8	50,000	
		चिक्कन	1	10,000	
		धराला 326	1	5,000	
		जैथल	2	10,000	
		कंडियाला	2	2,40,000	
		खोल फतेहसिंह	1	5,000	

		रहना	3	15,000
		रजी टिकरी	21	2,50,000
		थनडोग	3	25,000
		कुल	155	14,70,000
पशु हानि विवरण				
जिला	विधानसभा क्षेत्र	गांव का नाम	स्वीकृत दावें	अनुमोदित मुआवजा राशि रूपये में
पंचकूला	कालका	टिब्बी	1	32,000
		प्यारेवाला	1	1,12,500
		कुल	02	1,44,500
घरेलू सामान (कपडे व बर्तन) नुकसान विवरण				
जिला	विधानसभा क्षेत्र	गांव	स्वीकृत दावें	अनुमोदित मुआवजा राशि रूपये में
पंचकूला	कालका	टिब्बी	1	2,500
		बडौना कलां	2	5,000
		कुल	03	7,500/-

पुलों और सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करना

52. श्री प्रदीप चौधरी:- क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही के मानसून मौसम के दौरान क्षतिग्रस्त हुए छोटे पुलों/पुलियों तथा सड़कों का ब्यौरा क्या है; तथा
- (ख) उपरोक्त पुलों तथा सड़कों को पुनः निर्मित/मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): महोदय,

- (क) हाल के मानसून सीजन के दौरान कालका निर्वाचन क्षेत्र में कुल 76 नंबर सड़कें और 3 नंबर पुल क्षतिग्रस्त हुए थे जिनमें से 57 सड़कों को मामूली मरम्मत की आवश्यकता थी जो बारिश के बाद पहले ही कर दी गई और ये

सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं, 19 नं. सड़कें एवं 3 नं. पुलों को बड़ी मरम्मत की आवश्यकता थी जिन्हें यातायात योग्य स्थिति में भी बनाया गया और बड़ी मरम्मत के लिए अनुमान अनुमोदन की प्रक्रिया में है। सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद इन सड़कों/पुलों के जीर्णोद्धार से संबंधित प्रमुख कार्य हाथ में लिया जाएगा।

(ख) इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

सड़क का निर्माण कार्य आरंभ करना

53. श्री धर्म सिंह छोकर : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि सरकारी अस्पताल (जी.टी. रोड़-44) से समालखा सचिवालय तक सड़क का निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): महोदय, सरकारी अस्पताल से समालखा सचिवालय तक सीधी सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सब्जी मंडी स्थापित करना

54. श्री धर्मसिंह छोकर: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएं कि सरकार द्वारा ब्लॉक बापौली में प्रस्तावित सब्जी मंडी के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): बापौली ब्लॉक में नई अनाज मंडी बापौली के अन्दर 1.31 एकड़ भूमि पर सब्जी मंडी बनाने की योजना है। मंडी की अधिसूचना को संशोधित करने की प्रक्रिया जारी है। सब्जी मंडी के वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्थापित होने की संभावना है।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा सेक्टर विकसित करना

55. श्री धर्म सिंह छोकर: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा सेक्टर विकसित करने का कार्य सरकार द्वारा कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

1. तिथि तक एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने समालखा में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कोई भूमि अर्जित नहीं की है।
2. एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने बहुत पहले समालखा में लगभग 25 एकड़ के क्षेत्र पर औद्योगिक सम्पदा विकसित की थी। औद्योगिक सम्पदा समालखा में अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए कार्य दिसंबर, 2023 में दिया गया है। कार्य सितंबर, 2024 तक पूरा करवाया जाएगा।

सामुदायिक हाल की प्रशासनिक स्वीकृति

56. श्री अमरजीत ढाण्डा: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएं कि :-

- क) क्या यह तथ्य है कि जुलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के दो गांवों अर्थात् शामिलों कलां तथा खरेन्टी में सामुदायिक हाल का निर्माण करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है; तथा
- (ख) यदि हां, तो उपरोक्त सामुदायिक हाल की प्रशासनिक स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): (क) एवं (ख)]हां श्रीमान जी, जुलाना विधानसभा के शामिलों कलां और खरेन्टी गांव में सामुदायिक भवनों के निर्माण की लागत का अनुमान सरकार द्वारा प्राप्त हो चुका है। उन पर नीति के अनुसार

कार्यवाही की जा रही है। प्राशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में 28.02.2024 तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

अस्वीकृत कॉलोनियों को नियमित करना

57. श्री अमरजीत ढांडा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि जुलाना नगर पालिका में अस्वीकृत कॉलोनियां 70 % से ज्यादा विकसित हो चुकी है तथा जो कि सभी नियमों का पालन करती हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो इन कॉलोनियों को कब तक नियमित किए जाने की संभावना है ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा० कमल गुप्ता):

(क) नगर पालिका जुलाना की 5 अनधिकृत कॉलोनियों का प्रस्ताव जिला नगर आयुक्त, जींद से प्राप्त हुआ। प्रत्येक कॉलोनी का निर्मित क्षेत्र 40: से कम था। पत्र दिनांक 03.03.2023 द्वारा प्रसारित मानदंडों के अनुसार कॉलोनियों की जांच की गई और पाया गया कि 5 कॉलोनियों में से 4 कॉलोनियां आंतरिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई यानी 3 मीटर के मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इसलिए, आंतरिक सड़कों की चौड़ाई को पुनः सत्यापन के लिए इसे जिला नगर आयुक्त, जींद को वापस कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका समिति, जुलाना में 6.25 एकड़ क्षेत्रफल की एक कॉलोनी को दिनांक 06.10.2023 के द्वारा अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ख) निदेशालय द्वारा मांगी गई पुनः सत्यापन रिपोर्ट जिला नगर आयुक्त, जींद से प्राप्त होने के उपरान्त, मानदंडों के अनुसार पाए जाने वाली बची हुई कॉलोनियों को अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र घोषित करने पर विचार किया जाएगा।

.....

मास्टर प्लान को मंजूर करना

58. श्री अमरजीत ढांडा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएं कि क्या यह तथ्य है कि जुलाना कस्बे का मास्टर प्लान तैयार हो गया है तथा मंजूरी के लिए भेजा हुआ है; यदि हां, तो इसके कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, जुलाना की प्रारूप विकास योजना 2041 ई0 को शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छह महीने में प्रकाशित कर दिया जायेगा।

.....

मंत्री आवासों पर कुल खर्च राशि

59. श्री अभय सिंह चौटाला : क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि वर्ष 2019 से 2023 तक चंडीगढ़ तथा पंचकूला में स्थित मंत्रियों, बोर्ड अध्यक्षों तथा अधिकारियों को आवंटित सरकारी निवास स्थानों के जीर्णोद्धार तथा मरम्मत पर वर्ष-वार कुल कितना खर्च किया गया तथा उसका आवास-वार ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): महोदय, चंडीगढ़ और पंचकूला में मंत्रियों, बोर्ड अध्यक्षों तथा अधिकारियों को आवंटित सरकारी निवास स्थानों के जीर्णोद्धार तथा मरम्मत पर वर्ष-वार किये गये कुल व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

नवंबर, 2019 से मार्च 2020	:	245.23 लाख रुपये
अप्रैल, 2020 से मार्च 2021	:	1018.81 लाख रुपये
अप्रैल, 2021 से मार्च 2022	:	1776.79 लाख रुपये
अप्रैल, 2022 से मार्च 2023	:	693.72 लाख रुपये
अप्रैल, 2023 से नवंबर 2023	:	520.13 लाख रुपये

चंडीगढ़ और पंचकूला में हरियाणाके विभिन्न मंत्रियों/ ओ.एस.डी./ अधिकारियों के कुल 102 आवास (84+18) का रख रखाव देखा जा रहा है इन 102 आवासों में से, चंडीगढ़ में 84 आवास माननीय मंत्रियों/ओ.एस.डी. को आवंटित किये गए हैं और पंचकूला में 18 आवास विभिन्न बोर्डों/निगमों के अध्यक्षों और अधिकारियों को आवंटित किये गए हैं। इन घरों का जीर्णोद्धार तथा मरम्मत कार्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद और रहने वालों की माँग पर किया जाता है।

इन आवासों पर किये गए वार्षिक व्यय का आवास-वार विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:-

चंडीगढ़/पंचकूला में विभिन्न घरों के जीर्णोद्धार तथा मरम्मत पर किये गए व्यय का विवरण:

2019-20 (11/2019 से 3/2020)

क्रमांक नं.	अधिभोगी का नाम	कोठी नंबर	व्यय (रुपयों में)
1	श्री हरपाल सिंह गिल, चेयरपर्सन	737, सैक्टर 12/A, पंचकूला	594348.00
2	श्री रघुनाथ कश्यप, चेयरमैन, हरियाणा राज्य सहकारी संघ महासंघ	57, सैक्टर 7, चंडीगढ़	464000.00
3	श्री ज्ञान चंद गुप्ता, अध्यक्ष	49, सैक्टर 2, चंडीगढ़	473610.00
4	श्री कृष्ण कुमार बेदी, मंत्री	68, सैक्टर 7, चंडीगढ़	1339624.00
5	श्री संदीप सिंह, मंत्री	72, सैक्टर 7, चंडीगढ़	420625.00
6	श्री रणबीर सिंह गंगवा, डिप्टी स्पीकर	280, सैक्टर 16, चंडीगढ़	464000.00
7	श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष	70, सैक्टर 7, चंडीगढ़	34899.00
8	श्रीमती कमलेश ढांडा, मंत्री	73, सैक्टर 7, चंडीगढ़	795593.00
9	श्री बनवारी लाल, मंत्री	52, सैक्टर 5, चंडीगढ़	608531.00
10	श्री रामबिलास शर्मा, मंत्री	32, सैक्टर 3, चंडीगढ़	2381719.00
11	श्री बी.के. कुठियाला, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य शिक्षा परिषद	743, सैक्टर 12/A, पंचकूला	101650.00
12	श्री बी.आर. महाजन, महाधिवक्ता	78, सैक्टर 7, चंडीगढ़	339925.00
13	श्री मो. अकील, आईपीएस, अपर. पुलिस महानिदेशक	3019, सैक्टर 19, चंडीगढ़	4964704.00
14	श्री अमरजीत सिंह, ओएसडी, सीएम	56, सैक्टर 7, चंडीगढ़	833386.00
15	श्री बीरेंद्र सिंह, ईआईसी, सिंचाई विभाग	690, सैक्टर 7, चंडीगढ़	489915.00
16	श्री बृज किशोर कुठियाला, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद	म.नं. 743/12A, पंचकूला	1490375.00

17	श्री राजदीप फोगाट, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन	म.नं. 737/12A, पंचकूला	1804440.00
18	श्रीमती गीता भारती, आईएएस, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेक्टर 5	म.नं. 174/14, पंचकूला	133569.00
19	श्री राजीव अग्रवाल, चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर	म.नं. 619/6, पंचकूला	282565.00
20	श्री यशेन्द्र सिंह, एचसीएस	म.नं. 627 पंचकूला	2873795.00
21	श्रीमती रेखा, राज्य सूचना आयुक्त	म.नं. 632/6, पंचकूला	100000.00
22	डॉ. श्यामली वाष्णीय, एम.ओ., डी.जी.एच.एस., सेक्टर-6, पंचकूला	म.नं. 634/6, पंचकूला	477836.00
23	श्री केसी मीना, आईएफएस	म.नं. 639/6, पंचकूला	70822.00
24	श्री पंकज, आईएएस, एमडी हारट्रोन, पंचकूला	म.नं. 643/6, पंचकूला	139116.00
25	श्री चंद्र प्रकाश, आईएएस	म.नं. 646/6, पंचकूला	274463.00
26	श्रीमती आमना तस्लीम, आईएएस, एमडी, एचएससीएफएन और एचबीसीकेएन	म.नं. 647/6, पंचकूला	171179.00
27	कैप्टन निखिल नायडू, पायलट, नागरिक उड्डयन विभाग, सेक्टर-17, चंडीगढ़	म.नं. 656/6, पंचकूला	202064.00
28	श्री पंकज सेतिया, एचसीएस	म.नं. 664/6, पंचकूला	444372.00
29	श्रीमती हरप्रीत कौर, कार्यक्रम अधिकारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा	म.नं. 179/14, पंचकूला	249110.00
30	श्री सतबीर सिंह कादियान, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, सिंचाई भवन, सेक्टर-5, पंचकूला	म.नं. 642/6, पंचकूला	149174.00
31	श्री सुनील शर्मा, मुख्य समन्वयक, एचईडीसी	म.नं. 654/6, पंचकूला	853193.00
32	श्री श्रवण कुमार गर्ग, अध्यक्ष गो सेवा आयोग	म.नं. 738/12A, पंचकूला	499984.00
		कुल	24522586.00
			245.23 लाख रुपये

2020-21 (04/2020 से 03/2021)

क्रमांक नं.	अधिभोगी का नाम	कोठी नंबर	व्यय (रुपयों में)
1	श्री हरपाल सिंह गिल, चेयरपर्सन	737, सैक्टर 12/A, पंचकूला	34200.00
2	श्री रघुनाथ कश्यप, चेयरमैन, हरियाणा राज्य सहकारी संघ महासंघ	57, सैक्टर 7, चंडीगढ़	516938.00
3	श्री नीरज दफ्त्यार, प्रिंसिपल ओएसडी, सीएम	512, सैक्टर 18, चंडीगढ़	1201147.00
4	श्री मूलचंद शर्मा, मंत्री	75, सैक्टर 7, चंडीगढ़	5008263.00
5	श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री	48, सैक्टर 2, चंडीगढ़	18609227.00
6	श्री ज्ञान चंद गुप्ता, अध्यक्ष	49, सैक्टर 2, चंडीगढ़	8199789.00
7	श्री रणदीप सांघवान, प्रशासक आईएस हिसार	751, सैक्टर 12/A, चंडीगढ़	643840.00
8	श्री नैनपाल रावत, विधायक	747, सैक्टर 12/A, पंचकूला	599923.00
9	श्री डी.एस. ढेशी, चेयरमैन, एचईआरसी	79, सैक्टर 7, चंडीगढ़	3419084.00
10	श्री ओम प्रकाश यादव, मंत्री	68, सैक्टर 7, चंडीगढ़	7723284.00
11	श्री संदीप सिंह, मंत्री	72, सैक्टर 7, चंडीगढ़	9519964.00
12	श्री जय प्रकाश दलाल, मंत्री	239, सैक्टर 16, चंडीगढ़	2302870.00
13	श्री रणबीर सिंह गंगवा, डिप्टी स्पीकर	280, सैक्टर 16, चंडीगढ़	4455290.00
14	श्री कंवर पाल, मंत्री	4, सैक्टर 3, चंडीगढ़	1814210.00
15	श्री भूपेंदर सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष	70, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2888521.00
16	श्रीमती कमलेश ढांडा, मंत्री	73, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2015845.00
17	श्री अनूप धानक, मंत्री	76, सैक्टर 7, चंडीगढ़	6488703.00
18	श्री बनवारी लाल, मंत्री	52, सैक्टर 5, चंडीगढ़	4475898.00
19	श्री रणजीत सिंह चौटाला, मंत्री	32, सैक्टर 3, चंडीगढ़	10883289.00
20	श्री परविंद्र सिंह चौहान, सदस्य एचईआरसी	750, सैक्टर 12/A, पंचकूला	381955.00
21	श्री रणधीर सिंह गोलेन, चेयरमैन, हरियाणा पर्यटन	749, सैक्टर 12/A, पंचकूला	93601.00
22	श्री संदीप जोशी, चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड	746, सैक्टर 12/A, पंचकूला	417731.00
23	श्री बी.के. कुठियाला, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य शिक्षा परिषद	743, सैक्टर 12/A, पंचकूला	334847.00
24	श्री बी.आर. महाजन, महाधिवक्ता	78, सैक्टर 7, चंडीगढ़	1109997.00
25	श्री भूपेश्वर दयाल, सीएम के ओएसडी	762, सैक्टर 12, पंचकूला	86750.00
26	श्री भारत भूषण भारती, चेयरमैन, एचएसएससी	744, सैक्टर 12/A, पंचकूला	89000.00

27	श्रीमती आमना तस्नीम, आईएएस, एमडी एचएससीएफएन और एचबीसीकेएन पंचकूला	म.नं. 647/6, पंचकूला	699502.00
28	डॉ. प्रवीण गर्ग, निदेशक, डीजीएचएस, सेक्टर 6, पंचकूला	म.नं. 653/6, पंचकूला	281291.00
29	श्रीमती गीता भारती, आईएएस, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेक्टर 5	म.नं. 174/14, पंचकूला	469810.00
30	श्री ध्रुव मजूमदार, सी.एम. निवास, चंडीगढ़	म.नं. 619/6, पंचकूला	494245.00
31	श्री अंशज सिंह, आईएएस, सीए, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा	म.नं. 633/6, पंचकूला	55208.00
32	श्री सतपाल सिंह, न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता मंच	म.नं. 652/6, पंचकूला	499820.00
33	श्री जगदीप सिंह, जज, सीबीआई कोर्ट पंचकूला	म.नं. 660/6, पंचकूला	473064.00
34	श्री रणदीप सांगवान, विंग कमांडर (प्रशासक, आईएच, हिसार प्रोजेक्ट)	म.नं. 751/12A, पंचकूला	637471.00
35	श्री विनीत गर्ग, आईएएस, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सेक्टर-5, पंचकूला	म.नं. 620/6, पंचकूला	155801.00
36	श्री साकेत कुमार, आई.ए.एस., महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा, सेक्टर-4, देहरादून	म.नं. 650/6, पंचकूला	920777.00
37	डॉ. रेखा सिंह, उप निदेशक, डीजीएसएस, सेक्टर-6, हरियाणा	म.नं. 637/6, पंचकूला	499480.00
38	श्रीमती आमना तस्नीम, आईएएस, एमडी एचएससीएफएन और एचबीसीकेएन पंचकूला	म.नं. 647/6, पंचकूला	204273.00
39	श्री पंकज, आईएएस, एमडी हार्टोन पोर्टफोलियो	म.नं. 643/6, पंचकूला	454191.00
40	श्री बृज किशोर कुठियाला, अध्यक्ष उच्च शिक्षा परिषद	म.नं. 743/12A, पंचकूला	253110.00
41	श्री रणधीर सिंह गोलेन, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद	म.नं. 749/12A, पंचकूला	1802616.00
42	श्री मो. इमरान रज़ा, आईएएस, एडीसी कार्यालय	म.नं. 662/6, पंचकूला	450000.00
43	श्रीमती रेनू फूलिया, प्रबंध निदेशक	म.नं. 651/6, पंचकूला	216893.00
		कुल	101881718.00

1018.81 लाख रुपये

2021-22 (04/2021 से 03/2022)

क्रमांक नं.	अधिभोगी का नाम	कोठी नंबर	व्यय (रुपयों में)
1	श्री राजदीप फौगाट, चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड	737, सैक्टर 12/A, पंचकूला	933297.00
2	श्री योगेंद्र चौधरी, सलाहकार, आरएमसी	57, सैक्टर 7, चंडीगढ़	210704.00
3	श्री नीरज दफ्तौर, प्रिंसिपल ओएसडी, सीएम	512, सैक्टर 18, चंडीगढ़	1315664.00
4	श्री मूलचंद शर्मा, मंत्री	75, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2856357.00
5	श्री दुष्यंत चौटाला, उपप्रधान मुख्यमंत्री	48, सैक्टर 2, चंडीगढ़	8456668.00
6	श्री ज्ञान चंद गुप्ता, अध्यक्ष	49, सैक्टर 2, चंडीगढ़	4582584.00
7	विंग कमांडर रणदीप सांघवान, प्रशासक आईएस हिसार	751, सैक्टर 12/A, पंचकूला	3030994.00
8	श्री नैनपाल रावत, विधायक	747, सैक्टर 12/A, पंचकूला	509786.00
9	श्री डी.एस. देशी, चेयरमैन, एचईआरसी	79, सैक्टर 7, चंडीगढ़	3318713.00
10	श्री ओम प्रकाश यादव, मंत्री	68, सैक्टर 7, चंडीगढ़	4155926.00
11	श्री संदीप सिंह, मंत्री	72, सैक्टर 7, चंडीगढ़	9597910.00
12	श्री जय प्रकाश दलाल, मंत्री	239, सैक्टर 16, चंडीगढ़	3760167.00
13	श्री रणबीर सिंह गंगवा, डिप्टी स्पीकर	280, सैक्टर 16, चंडीगढ़	798034.00
14	श्री कंवर पाल, मंत्री	4, सैक्टर 3, चंडीगढ़	6166206.00
15	श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष	70, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2246251.00
16	श्रीमती कमलेश ढांडा, मंत्री	73, सैक्टर 7, चंडीगढ़	8121263.00
17	श्री अनूप धानक, मंत्री	76, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2015446.00
18	डॉ. बनवारी लाल, मंत्री	52, सैक्टर 5, चंडीगढ़	6617210.00
19	श्री रणजीत सिंह चौटाला, मंत्री	32, सैक्टर 3, चंडीगढ़	11571557.00
20	श्री परविंदर सिंह चौहान, सदस्य एचईआरसी	750, सैक्टर 12/A, पंचकूला	61714.00
21	श्री रणधीर सिंह गोलेन, चेयरमैन, हरियाणा पर्यटन	749, सैक्टर 12/A, पंचकूला	1854523.00
22	श्री बी.आर. महाजन, महाधिवक्ता	78, सैक्टर 7, चंडीगढ़	622904.00
23	श्री भूपेश्वर दयाल, सीएम के ओएसडी	762, सैक्टर 12, पंचकूला	1316001.00
24	श्री भारत भूषण भारती, चेयरमैन, एचएसएससी	744, सैक्टर 12/A, पंचकूला	68000.00
25	श्री वी. उमा शंकर, प्रमुख सचिव	283, सैक्टर 16, चंडीगढ़	2542116.00
26	श्री विजय वर्धन, आईएस	20, सैक्टर 7, चंडीगढ़	4866315.00
27	श्री मोहित सोनी, मुख्य फीडबैक अधिकारी सीएम	649, सैक्टर 6, पंचकूला	208860.00

28	श्री अमित झा, आईएएस	18, सैक्टर 7, चंडीगढ़	1594018.00
29	श्री संजीव कौशल, एसीएस (आर) अब मुख्य सचिव	39, सैक्टर 4, चंडीगढ़	721782.00
30	श्री आलोक निगम, एसीएस	82, सैक्टर 7, चंडीगढ़	1910883.00
31	श्रीमती ज्योति बेदा, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग	1185, सैक्टर 8, चंडीगढ़	2422186.00
32	श्री राजीव अरोड़ा, एसीएस (गृह)	13, सैक्टर 7, चंडीगढ़	1532646.00
33	श्री टीवीएसएन प्रसाद, आईएएस (एसीएस वित्त)	284, सैक्टर 16, चंडीगढ़	1399560.00
34	श्री अमित कुमार अग्रवाल, आईएएस, एपीएससीएम	5, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2002860.00
35	श्रीमती जी अनुपमा, राज्यपाल सचिव	6, सैक्टर 7, चंडीगढ़	1933732.00
36	श्री वी.एस. कुंडू, आईएएस, अतिरिक्त सरकार के मुख्य सचिव. हरियाणा	522, सैक्टर 16, चंडीगढ़	49441.00
37	श्री जयसिंह बिश्रोई, आरटीआई आयुक्त	745, सैक्टर 12/A, पंचकूला	452448.00
38	श्री अजय गौड़, राजनीतिक सचिव, मुख्यमंत्री	74, सैक्टर 7, चंडीगढ़	1450554.00
39	श्री सतीश कुमार, ओएसडी, सीएम हरियाणा	56, सैक्टर 7, चंडीगढ़	492650.00
40	विंग कमांडर डी.एस.नेहरा	734, सैक्टर 12/A, पंचकूला	454164.00
41	श्री सोमबीर सांगवान, चेयरमैन, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	736, सैक्टर 12/A, पंचकूला	585930.00
42	विंग कमांडर प्रवीण कुमार डीडू, वरिष्ठ कार्यकारी पायलट	1520, सैक्टर 18, चंडीगढ़	1479440.00
43	श्री नयनपाल रावत, चेयरमैन, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन	म.नं. 747/12A, पंचकूला	1631583.00
44	श्री शक्ति सिंह, आईएएस, एमडी हैफेड शुगर मिल लिमिटेड	म.नं. 644/6, पंचकूला	281836.00
45	श्री शक्ति सिंह, आईएएस, एमडी एफईडी शुगर मिल लिमिटेड	म.नं. 644/6, पंचकूला	635248.00
46	श्री मनिता मलिक, एचसीएस, एडीसी, पंचकूला	म.नं. 640/6, पंचकूला	652000.00
47	श्री विकास गुप्ता, आईएएस, डी.आई और सी.एम. एवं भूविज्ञान हरियाणा	म.नं. 636/6, पंचकूला	933868.00
48	श्री मोहित सोनी, मुख्य फीडबैक अधिकारी सीएम	म.नं. 649/6, पंचकूला	3598821.00
49	श्री के. मकरंद पांडुरंग, आई.ए.एस., निदेशक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग चंडीगढ़, हरियाणा	म.नं. 645/6, पंचकूला	482033.00
50	डॉ. शालीन, ऐड. वित्त विभाग एवं एमडी, हरको, एमडी, एससी वित्त एवं विकास निगम	म.नं. 624/6, पंचकूला	2151552.00

51	श्री पंकज, आईएएस, एमडी हारट्रोन पंचकूला	म.नं. 643/6, पंचकूला	1730000.00
52	डॉ. शालीन, ऐड. वित्त विभाग एवं एमडी, हरको, एमडी, एससी वित्त एवं विकास निगम	म.नं. 624/6, पंचकूला	855000.00
53	श्री के. मकरंद पांडुरंग, आई.ए.एस., निदेशक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग चंडीगढ़, हरियाणा	म.नं. 645/6, पंचकूला	1417661.00
54	श्री पंकज, आईएएस, एमडी हारट्रोन पंचकूला	म.नं. 643/6, पंचकूला	840000.00
55	डॉ. प्रवीण गर्ग, निदेशक, डीजीएचएस, सैक्टर 6, पंचकूला	म.नं. 653/6, पंचकूला	884858.00
56	श्री जय सिंह बिश्रोई, एसआईसी कमिश्नर	म.नं. 745/12A पंचकूला	1935103.00
57	श्री अरुण सांगवान, सदस्य, राज्य सूचना आयुक्त, एससीओ 71-72, सेक्टर-8, चंडीगढ़	म.नं. 661/6, पंचकूला	360367.00
58	श्री सुरिंदर सिंह, सदस्य एचपीएससी	म.नं. 740/12A, पंचकूला	951205.00
59	श्री परविंदर सिंह चौहान, सदस्य, एचईआरसी	म.नं. 750/12A, पंचकूला	908728.00
60	श्री नरेंद्र सिंह मलिक, सीनियर डेंटल सर्जन, आयुष्मान भवन, सेक्टर। 12, पंचकूला	म.नं. 175/14, पंचकूला	640000.00
61	श्री शक्ति सिंह, आईएएस, एमडी एफईडी शुगर मिल लिमिटेड	म.नं. 644/6, पंचकूला	738920.00
62	श्री कैलाश भगत, हैफेड के चेयरमैन	म.नं. 746/12A, पंचकूला	184777.00
63	श्री मो. इमरान रजा, आईएएस, एडीसी कार्यालय पंचकूला	म.नं. 662/6, पंचकूला	1431483.00
64	श्री अनिल कुमार भारद्वाज, डीए, मुख्य सचिव	म.नं. 665/6, पंचकूला	1509222.00
65	श्रीमती रेनू फूलिया, प्रबंध निदेशक	म.नं. 651/6, पंचकूला	668829.00
66	श्री सतबीर सिंह कादियान, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, सिंचाई भवन, सेक्टर-5, पंचकूला	म.नं. 642/6, पंचकूला	200000.00
67	श्रीमती रजनी खोखर, व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विभाग सैक्टर 2 पंचकूला	म.नं. 660/6, पंचकूला	225000.00
68	श्री विनीत गर्ग, आईएएस, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सेक्टर-5, पंचकूला	म.नं. 620/6, पंचकूला	511135.00
69	कैप्टन निखिल नायडू, पायलट, नागरिक उड्डयन विभाग, सेक्टर-17, चंडीगढ़	म.नं. 656/6, पंचकूला	1902197.00
70	श्री बीरेंद्र सिंह लौरा, निदेशक पशुपालन पंचकूला	म.नं. 626/6, पंचकूला	1434787.00
71	श्री रजनीश गर्ग, एडीसी टू सीएम, सिविल सचिवालय, चंडीगढ़	म.नं. 638/6, पंचकूला	733921.00

72	श्री श्रवण कुमार गर्ग, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग	म.नं. 738/12A, पंचकूला	269539.00
73	श्रीमती पूनम, व्याख्याता, शासकीय कॉलेज सेक्टर 8 पंचकूला	म.नं. 182/14, पंचकूला	764121.00
74	श्री कैलाश भगत, हैफेड के चेयरमैन	म.नं. 746/12A, पंचकूला	1409531.00
75	श्री रणधीर सिंह गोलेन, चेयरमैन, हरियाणा पर्यटन निगम	म.नं. 749/12A, पंचकूला	1767131.00
76	श्री अजय गौड़, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव (सीएम गेस्ट हाउस)	म.नं. 739/12A, पंचकूला	1511851.00
77	श्रीमती सिमरनजीत कौर, सीजेएम, डी.सी. कार्यालय, पंचकूला	म.नं. 176/14, पंचकूला	485000.00
78	श्री भारत भूषण भारती, चेयरमैन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग	म.नं. 744/12A, पंचकूला	28956.00
79	श्री परविंदर सिंह चौहान, सदस्य, एचईआरसी	म.नं. 750/12A, पंचकूला	1836418.00
80	श्री विकास गुप्ता, आईएएस, डी.आई और सी.एम. एवं भूविज्ञान हरियाणा	म.नं. 636/6, पंचकूला	933868.00
81	श्री संजय वर्मा, संयुक्त निदेशक, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, सेक्टर-5, पंचकूला	म.नं. 648/6, पंचकूला	99387.00
82	श्रीमती रेनू फूलिया, प्रबंध निदेशक	म.नं. 651/6, पंचकूला	5000.00
83	श्री जगदीप सिंह, जज, सीबीआई कोर्ट पंचकूला	म.नं. 660/6, पंचकूला	679147.00
84	डॉ. प्रवीण गर्ग, निदेशक, डीजीएचएस, सेक्टर 6, पंचकूला	म.नं. 653/6, पंचकूला	701485.00
85	श्री डी.एस.नेहरा, विंग. सीएम को सीडीआर	म.नं. 734/6, पंचकूला	1767599.00
86	डॉ. रेखा सिंह, उपनिदेशक, डीजीएसएस, सेक्टर-6, पंचकूला, हरियाणा	म.नं. 637/6, पंचकूला	200000.00
87	श्री पंकज, आईएएस, एमडी हारट्रोन पंचकूला	म.नं. 643/6, पंचकूला	271000.00
88	श्री राजदीप फोगाट, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन	म.नं. 737/12A, पंचकूला	1467101.00
89	श्री रणदीप सांगवान, विंग कमांडर (प्रशासक, आईएच, हिसार प्रोजेक्ट)	म.नं. 751/12A, पंचकूला	2265286.00
90	श्री रणदीप सांगवान, विंग कमांडर (प्रशासक, आईएच, हिसार प्रोजेक्ट)	म.नं. 751/12A, पंचकूला	902634.00
91	श्री राजदीप फोगाट, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन	म.नं. 737/12A, पंचकूला	1996536.00
92	श्री सोमबीर सांगवान, चेयरमैन, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, पंचकूला	म.नं. 736/12A, पंचकूला	1463622.00
93	श्री श्रवण कुमार गर्ग, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग	म.नं. 738/12A, पंचकूला	1774181.00

94	श्री भारत भूषण भारती, चेयरमैन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग	म.नं. 744/12A, पंचकूला	1319611.00
95	श्रीमती रजनी खोखर, व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विभाग सेक्टर 2 पंचकूला	म.नं. 660/6, पंचकूला	326128.00
96	श्री सीमा खंगवाल, डीईटीसी अधिकारी, पंचकूला	म.नं. 178/14, पंचकूला	544461.00
97	श्री अंशज सिंह, आईएएस, सीए, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा	म.नं. 633/6, पंचकूला	1466259.00
98	श्रीमती गीता भारती, आईएएस, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेक्टर 5	म.नं. 174/14, पंचकूला	1116251.00
99	श्री अंशज सिंह, आईएएस, सीए, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा	म.नं. 633/6, पंचकूला	475036.00
100	श्रीमती अमृता, एचसीएस	म.नं. 615/6, पंचकूला	978531.00
101	श्री पवन कुमार, सलाहकार, विदेश सहयोग विभाग	म.नं. 631/6, पंचकूला	1665724.00
102	श्रीमती नूपुर बिश्रोई, एसपी	म.नं. 181G/14, पंचकूला	199979.00

103	श्री राजीव रतन, आईएएस, निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हरियाणा	म.नं. 635/6, पंचकूला	450611.00
104	श्री पवन कुमार, सलाहकार, विदेश सहयोग विभाग।	म.नं. 173/14, पंचकूला	480000.00
105	श्री सतपाल सिंह, न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता मंच	म.नं. 652/6, पंचकूला	494700.00
106	श्रीमती सिमरनजीत कौर, सीजेएम, डी.सी. कार्यालय, पंचकूला	म.नं. 176G/14, पंचकूला	498908.00
107	डॉ. शिल्पी पैटर दत्त, एचसीएस, संयुक्त निदेशक आयुष हरियाणा	म.नं. 621/6, पंचकूला	469596.00
108	श्री अतुल द्विवेदी, आईएएस, निदेशक आयुष विभाग, हरियाणा	म.नं. 632/6, पंचकूला	1486506.00
109	श्री साकेत कुमार, आई.ए.एस., महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा, सेक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा	म.नं. 650/6, पंचकूला	198359.00
110	कैप्टन निखिल नायडू, पायलट, नागरिक उड्डयन विभाग, सेक्टर-17, चंडीगढ़	म.नं. 656/6, पंचकूला	1207008.00
111	श्रीमती आमना तस्नीम, आईएएस, एमडी एचएससीएफएन और एचबीसीकेएन पंचकूला	म.नं. 647/6, पंचकूला	499000.00
112	डॉ. सुवीर सक्सेना, पीएमओ पंचकूला	म.नं. 657/6, पंचकूला	485000.00
		कुल	177678659.00

1776.79 लाख रुपये

2022-23 (04/2022 से 03/2023)

क्रमांक नं.	अधिभोगी का नाम	कोठी नंबर	व्यय (रुपयों में)
1	श्री मूलचंद शर्मा, मंत्री	75, सैक्टर 7, चंडीगढ़	902133.00
2	श्री दुष्यंत चौटाला, उपप्रधान मुख्यमंत्री	48, सैक्टर 2, चंडीगढ़	6104499.00
3	श्री ज्ञान चंद गुप्ता, अध्यक्ष	49, सैक्टर 2, चंडीगढ़	178180.00
4	विंग कमांडर रणदीप सांघवान, प्रशासक आईएएस हिसार	751, सैक्टर 12/A, चंडीगढ़	15990.00
5	श्री नैनपाल रावत, विधायक	747, सैक्टर 12/A, चंडीगढ़	1038993.00
6	श्री डी.एस. देशी, आईएएस, अध्यक्ष, एचईआरसी	79, सैक्टर 7, चंडीगढ़	545663.00
7	श्री ओम प्रकाश यादव, मंत्री	68, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2736822.00
8	श्री संदीप सिंह, मंत्री	72, सैक्टर 7, चंडीगढ़	4576834.00
9	श्री जय प्रकाश दलाल, मंत्री	239, सैक्टर 16, चंडीगढ़	6053988.00
10	श्री रणबीर सिंह गंगवा, डिप्टी स्पीकर	280, सैक्टर 16, चंडीगढ़	1125257.00
11	श्री कंवर पाल, मंत्री	4, सैक्टर 3, चंडीगढ़	85425.00
12	श्री भूपेंदर सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष	70, सैक्टर 7, चंडीगढ़	299445.00
13	श्रीमती कमलेश ढांडा, मंत्री	73, सैक्टर 7, चंडीगढ़	514835.00
14	श्री अनूप धानक, मंत्री	76, सैक्टर 7, चंडीगढ़	12159.00
15	डॉ. बनवारी लाल, मंत्री	52, सैक्टर 5, चंडीगढ़	493792.00
16	श्री रणजीत सिंह चौटाला, मंत्री	32, सैक्टर 3, चंडीगढ़	3342003.00
17	श्री रणधीर सिंह गोलेन, चेयरमैन, हरियाणा पर्यटन	749, सैक्टर 12/A, पंचकूला	53280.00
18	श्री संदीप जोशी, चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड	746, सैक्टर 12/A, पंचकूला	75900.00
19	श्री बी.आर. महाजन, महाधिवक्ता	78, सैक्टर 7, चंडीगढ़	757315.00
20	श्री वी. उमा शंकर, प्रमुख सचिव	283, सैक्टर 16, चंडीगढ़	1833856.00
21	श्री विजय वर्धन, आईएएस	20, सैक्टर 7, चंडीगढ़	840875.00
22	श्री मोहित सोनी, मुख्य फीडबैक अधिकारी सीएम	649, सैक्टर 6, पंचकूला	482620.00

23	श्री संजीव कौशल, एसीएस (आर) अब मुख्य सचिव	39, सैक्टर 4, चंडीगढ़	394998.00
24	श्री आलोक निगम, एसीएस	82, सैक्टर 7, चंडीगढ़	621970.00
25	श्री अजय गौड़, राजनीतिक सचिव, मुख्यमंत्री	74, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2148792.00
26	श्री सतीश कुमार, ओएसडी, सीएम हरियाणा	56, सैक्टर 7, चंडीगढ़	3422124.00
27	श्री कंवलजीत सिंह, सदस्य एचएसएससी	736, सैक्टर 12/A, पंचकूला	46725.00
28	विंग कमांडर प्रवीण कुमार डीडी, वरिष्ठ कार्यकारी पायलट	1520, सैक्टर 18, चंडीगढ़	2566394.00
29	श्री श्रवण कुमार गर्ग, चेयरमैन, हरियाणा गौ सेवा आयोग	738, सैक्टर 12/A, पंचकूला	75850.00
30	श्रीमती ज्योति बैदा, अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग	741, सैक्टर 12/A, पंचकूला	3590609.00
31	श्री सुभाष बराला, चेयरमैन	24, सैक्टर 7, चंडीगढ़	4719033.00
32	श्री देवेन्द्र सिंह बबली, मंत्री	82, सैक्टर 7, चंडीगढ़	6854073.00
33	श्रीमती गीता भारती, आईएएस, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेक्टर 5	म.नं. 174G/14, पंचकूला	277855.00
34	श्री साकेत कुमार, आई.ए.एस., महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा, सेक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा	म.नं. 650/6, पंचकूला	594522.00
35	डॉ. डी. सुरेश, आईएएस, पी.एस. सरकार, हरियाणा	म.नं. 623/6, पंचकूला	1700018.00
36	श्री कुलदीप सिंह, तहसीलदार, कालका	म.नं. 180G/14, पंचकूला	648097.00
37	डॉ. सुवीर सक्सेना, पीएमओ पंचकूला	म.नं. 657/6, पंचकूला	254923.00
38	श्री पवन कुमार, सलाहकार, विदेश सहयोग विभाग	म.नं. 631/6, पंचकूला	847980.00
39	श्री पवन कुमार, सलाहकार, विदेश सहयोग विभाग	म.नं. 173G/14, पंचकूला	1948581.00
40	डॉ. श्यामली वाष्णीय, एम.ओ., डी.जी.एच.एस., सेक्टर-6, पंचकूला	म.नं. 634/6, पंचकूला	2091517.00
41	श्रीमती गीता भारती, आईएएस, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेक्टर 5	म.नं. 174G/14, पंचकूला	570642.00
42	श्रीमती आमना तस्लीम, आईएएस, एमडी एचएससीएफएन और एचबीसीकेएन पंचकूला	म.नं. 647/6, पंचकूला	262928.00
43	श्री सतपाल सिंह, न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता मंच	म.नं. 652/6, पंचकूला	99983.00
44	श्री सतपाल सिंह, न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता मंच	म.नं. 652/6, पंचकूला	99633.00
45	श्री साकेत कुमार, आई.ए.एस., महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा, सेक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा	म.नं. 650/6, पंचकूला	140871.00

46	श्रीमती रजनी खोखर, व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विभाग सैक्टर 2 पंचकूला	म.नं. 660/6, पंचकूला	169504.00
47	श्री मो. इमरान रजा, आईएएस, एडीसी कार्यालय पंचकूला	म.नं. 662/6, पंचकूला	118926.00
48	श्री शक्ति सिंह, आईएएस, एमडी एफईडी शुगर मिल लिमिटेड	म.नं. 644/6, पंचकूला	111636.00
49	डॉ. प्रवीण गर्ग, निदेशक, डीजीएचएस, सैक्टर 6, पंचकूला	म.नं. 653/6, पंचकूला	86875.00
50	कैप्टन अमन चहल, कार्यकारी पायलट नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा	म.नं. 625/6, पंचकूला	2388222.00
51	श्रीमती नूपुर बिश्रोई, एएसपी	म.नं. 181G/14, पंचकूला	448647.00
		कुल	69371792.00
			693.72 लाख रुपये

2023-24 (11/2023 तक)

क्रमांक नं.	अधिभोगी का नाम	कोठी नंबर	व्यय (रुपयों में)
1	श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री	48, सैक्टर 2, चंडीगढ़	2050219.00
2	श्री ज्ञान चंद गुप्ता, अध्यक्ष	49, सैक्टर 2, चंडीगढ़	1595705.00
3	श्री डी.एस. देशी, आईएएस, अध्यक्ष, एचईआरसी	79, सैक्टर 7, चंडीगढ़	1576277.00
4	श्री ओम प्रकाश यादव, मंत्री	68, सैक्टर 7, चंडीगढ़	1455229.00
5	श्री संदीप सिंह, मंत्री	72, सैक्टर 7, चंडीगढ़	919810.00
6	श्री जय प्रकाश दलाल, मंत्री	239, सैक्टर 16, चंडीगढ़	1961750.00
7	श्री रणबीर सिंह गंगवा, डिप्टी स्पीकर	280, सैक्टर 16, चंडीगढ़	354652.00
8	श्री कंवर पाल, मंत्री	4, सैक्टर 3, चंडीगढ़	1716667.00
9	श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष	70, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2016411.00
10	श्रीमती कमलेश ढांडा, मंत्री	73, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2224869.00
11	श्री रणजीत सिंह चौटाला, मंत्री	32, सैक्टर 3, चंडीगढ़	1884387.00
12	श्री संजीव कौशल, मुख्य सचिव	39, सैक्टर 4, चंडीगढ़	642998.00
13	डॉ. कमल गुप्ता, मंत्री	74, सैक्टर 7, चंडीगढ़	3044901.00
14	विंग कमांडर प्रवीण कुमार डीडी,, वरिष्ठ कार्यकारी पायलट	1520, सैक्टर 18, चंडीगढ़	1050107.00

15	डॉ. श्रवण कुमार गर्ग, चेयरमैन, हरियाणा गौ सेवा आयोग	738, सैक्टर 12/A, पंचकूला	299814.00
16	श्रीमती ज्योति बैदा, अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग	741, सैक्टर 12/A, पंचकूला	1240245.00
17	श्री सुभाष बराला, चेयरमैन	24, सैक्टर 7, चंडीगढ़	2976973.00
18	श्री देवेन्द्र सिंह बबली, मंत्री	82, सैक्टर 7, चंडीगढ़	7332885.00
19	श्री बीबी भारती, सीएम के राजनीतिक सलाहकार	744, सैक्टर 12/A, पंचकूला	2797314.00
20	डॉ. सोनिया त्रिखा, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	735, सैक्टर 12/A, पंचकूला	2204163.00
21	श्री अनुराग रस्तोगी, अपर. मुख्य सचिव (वित्त)	54, सैक्टर 5, चंडीगढ़	391670.00
22	श्री देवेन्द्र सिंह, सलाहकार, माननीय मुख्यमंत्री	740, सैक्टर 12/A, पंचकूला	2896865.00
23	श्री पवन कुमार, सदस्य, एचपीएससी	742, सैक्टर 12/A, पंचकूला	1347144.00
24	श्री अमित कुमार अग्रवाल, आईएस, एपीएससीएम	5, सैक्टर 7, चंडीगढ़	180884.00
25	श्रीमती नूपुर बिश्रोई, एसपी	म.नं. 181G/14, पंचकूला	1719386.00
26	श्री एमएल राणा, मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग	म.नं. 628/6, पंचकूला	267264.00
27	श्री राजेश कालिया, एचपीएस, एसपी (सीआईडी) सुरक्षा, पंचकुला	म.नं. 630/6, पंचकूला	1222138.00
28	श्री संजीव वर्मा, आईएस, अतिरिक्त सचिव, हरियाणा सरकार, सहयोग विभाग	म.नं. 663/6, पंचकूला	1446642.00
29	श्री ध्रुव मजूमदार, सी.एम. निवास, चंडीगढ़	म.नं. 619/6, पंचकूला	306698.00
30	डॉ. एस.एस. फुलिया, आईएस सेवानिवृत्त, एस.आई. आयुक्त कार्यालय एससीओ 114-115 चंडीगढ़	म.नं. 651/6, पंचकूला	824492.00
31	कैप्टन अमन चहल, कार्यकारी पायलट नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा	म.नं. 625/6, पंचकूला	175185.00
32	कैप्टन दिनेश बंसल, जूनियर पायलट नागरिक उड्डयन विभाग	म.नं. 627/6, पंचकूला	389997.00
33	श्री वाई.एस. गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक यूएलबी	म.नं. 658/6, पंचकूला	1499602.00
		कुल	52013343.00
			520.13 लाख रुपये

हेलीकाप्टर/हवाई जहाज पर कुल खर्च राशि

60. श्री अभय सिंह चौटाला: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि वर्ष 2019 से नवम्बर, 2023 तक सरकार द्वारा किराए पर लिए गए हेलीकाप्टर/हवाई जहाज किराये पर सरकार द्वारा कुल कितना खर्च किया गया तथा उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक उड्डयन मंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): महोदय, वर्ष 2019 से नवंबर, 2023 तक किराये/चार्टर्ड हेलीकॉप्टर/हवाई जहाज पर खर्च की गई कुल राशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यय रुपये में
2019	47,34,030/-
2020	Nil
2021	Nil
2022	12,00,000/-
नवंबर, 2023	Nil

कुल रु. 59,34,030/(रूपए उनसठ लाख चौतीस हजार तीस मात्र) वर्ष 2019 से नवंबर, 2023 तक किराए/ चार्टर्ड हेलीकॉप्टर/हवाई जहाज पर खर्च आया है।

पंजीकृत अपराधिक मामलों की संख्या

61. श्री अभय सिंह चौटाला : क्या गृह मन्त्री कृपया बताएं कि वर्ष 2022 से नवंबर 2023 तक राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूटपाट, महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा अनुसूचित जाति वर्गों के लोगों के विरुद्ध अपराध के लिए सरकार द्वारा पंजीकृत मामलों की संख्या कितनी है तथा उनका जिलेवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री अनिल विज): महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

1

वर्ष 2022 में संशुद्ध आयातक मामलों का विवरण (एम.डी.आर.डी. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'अंतिम रूप' इंडिया 2022 के अनुसार)

क्र.सं.	देश	एन.डी.ए. (म.रु.प.)	एन.डी.ए. (म.रु.प.)	संशुद्ध आयातक (17% के म.रु.प.)	कुल आयातक और आयातक (एम.डी.आर.डी.)	एन.डी.आर.डी. (7 म.रु.प.)	एन.डी.आर.डी. (म.रु.प.)	अंतिम रूप में विवरण कुल आयातक (एम.डी.आर.डी. 17% और 7 म.रु.प.)	देश	म.रु.प.	एन.डी.आर.डी.
1	अमेरिका	28	80	7	168	14	14	817	2	43	81
2	भारत	51	57	12	72	20	28	771	1	71	72
3	चीन	70	159	8	471	17	17	1317	2	72	74
4	रूस	14	43	8	68	8	8	388	5	74	80
5	जर्मनी	22	0	0	0	2	2	28	5	8	5
6	रूस	80	191	13	298	88	88	1360	8	67	85

3

7	जापान	37	100	13	118	28	29	435	31	288	318
8	फ्रांस	81	56	8	188	72	72	680	8	55	60
9	ईरान	28	47	7	111	31	31	551	7	43	46
10	रूस	33	44	2	175	27	27	484	3	40	52
11	दक्षिण कोरिया	85	124	0	190	11	11	1061	3	81	83
12	जर्मनी	27	68	8	185	24	24	853	13	66	79
13	दक्षिण कोरिया	33	38	8	85	5	3	318	7	58	67
14	ईरान	22	71	12	108	15	15	428	8	23	23
15	जापान	58	64	17	117	3	2	783	2	104	103
16	दक्षिण कोरिया	12	40	2	111	12	12	338	8	20	20
17	रूस	72	100	10	268	12	12	1271	4	65	67
18	ईरान	47	48	8	88	12	12	604	0	81	81
19	जापान	62	78	7	183	68	68	758	1	57	58
20	जापान	37	84	5	127	24	24	544	2	51	53
21	दक्षिण कोरिया	78	120	13	325	118	118	1117	3	48	51
22	दक्षिण कोरिया	30	105	9	207	10	10	875	4	58	62
23	दक्षिण कोरिया	17	18	1	25	4	4	202	0	34	34
24	ईरान	12	22	1	29	8	8	285	5	59	59
कुल		1,020	1,787	180	3,691	817	817	16,740	88	1,558	1,633

4
आयुक्त एवं विभिन्न दृष्टिकोणों में विवरण, पंचसौर, हरियाणा के अनुसार 1 जनवरी से 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न प्रकार के सड़कों में दूरी सुधारों की संख्या।

क्र.सं.	विवरण	कुल (मै.मी.)	सड़क (मै.मी.)	सड़क (मै.मी.)	अन्य (मै.मी.)	कुल (मै.मी.)	कुल (मै.मी.)	सड़क (मै.मी.)	अन्य (मै.मी.)	कुल (मै.मी.)	सड़क (मै.मी.)	अन्य (मै.मी.)
1	असतत	25	18	2	182	9	9	548	1	17	33	
2	सिमेंट	18	47	3	55	0	0	630	1	48	49	
3	बालू की सड़कें	13	20	2	79	1	3	160	2	32	34	
4	कंकरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	पट्टीदार	91	175	6	443	11	11	821	3	16	74	
6	पट्टीदार	22	33	4	77	2	1	228	7	11	78	
7	कंकरी	13	2	0	3	2	2	11	0	4	4	
8	सुरक्षा	35	174	0	33	0	0	925	1	42	43	
9	सड़क	08	21	1	25	8	8	193	1	48	49	
10	सिमेंट	52	109	1	132	13	11	847	4	224	230	
11	सुरक्षा	38	42	0	132	13	11	318	2	43	45	
12	कंकरी	43	42	0	89	0	0	482	1	42	43	
13	कंकरी	25	48	2	162	11	11	387	0	16	34	

14	सुरक्षा	33	716	1	272	5	5	727	3	80	83	
15	कंकरी	23	64	5	155	2	2	538	1	68	71	
16	पट्टीदार	27	35	3	68	4	4	284	8	16	35	
17	सुरक्षा	31	74	18	72	6	6	277	8	19	79	
18	सुरक्षा	48	77	17	108	3	3	419	0	72	72	
19	सुरक्षा	7	37	1	104	4	4	280	6	8	14	
20	सुरक्षा	61	96	6	185	10	18	627	1	47	48	
21	कंकरी	31	77	1	162	18	10	487	1	73	74	
22	सिमेंट	30	86	8	185	22	22	594	8	46	46	
23	सिमेंट	14	49	1	155	29	29	461	1	44	45	
24	कंकरी	96	115	8	277	11	13	961	0	67	67	
25	कंकरी	15	87	4	187	12	12	559	1	41	48	
कुल		914	1,781	139	5,871	271	271	18,946	40	1,338	1,378	

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सूची

62. श्री राकेश दौलताबाद: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएं:-

- (क) कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में खोले गये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की जिलावार सूची क्या है;
- (ख) इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रों की संचालन स्थिति क्या है; तथा
- (ग) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित यूथ की सूची का ब्यौरा क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी,

- (क) कौशल विकास कार्यक्रम की शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत राज्य में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे 36 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की जिला-वार सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।
- (ख) ये सभी 36 आई0टी0आई0 केन्द्र/संस्थान प्रचालन स्थिति में है।
- (ग) इन संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों की विस्तृत सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

Annexure-A

List of Govt. ITIs exclusively for women (session 2023-24)		
District	Sr. No.	ITI Name
Ambala	1	GITI Ambala City (W)
	2	GITI Naraingarh (W)
Bhiwani	3	GITI Bhiwani (W)
	4	GITI Tosham (W)
Charkhi Dadri	5	GITI Charkhi Dadri (W)
Faridabad	6	GITI Faridabad (W)
	7	GITI Uncha Gaon (W)
Fatehabad	8	GITI Tohana (W)
Gurugram	9	GITI Gurugram (W)

Hisar	10	GITI Adampur (W)
	11	GITI Hansi (W)
	12	GITI Hisar (W)
Jhajjar	13	GITI Bahadurgarh (W)
	14	GITI Jhajjar (W)
Jind	15	GITI DumerKhan (W)
	16	GITI Jind (W)
Kaithal	17	GITI Kaithal (W)
	18	GITI Pundri (W)
Karnal	19	GITI Karnal (W)
Kurukshetra	20	GITI Kurukshetra (W)
	21	GITI Shahabad (W)
Mahendergarh	22	GITI Mahendergarh (W)
	23	GITI Narnaul (W)
Nuh	24	GITI Ferozpur Jhirka(W)
	25	GITI Nuh(W)
	26	GITI Pinagwa (W)
	27	GITI Punhana (W)
	28	GITI Ujjina (W)
Panchkula	29	GITI Kalka at Bitna(W)
Panipat	30	GITI Panipat (W)
	31	GITI Samalkha (W)
Rewari	32	GITI Rewari (W)
Rohtak	33	GITI Rohtak (W)
Sirsa	34	GITI Sirsa (W)
Sonipat	35	GITI Sonipat (W)
Yamunanagar	36	GITI Chhachrauli (W)

Annexure-B

Details of trainees enrolled in Govt. ITIs women (session 2023-24)

District	Sr. No.	ITI Name	Total Sanctioned Seats	Total Trainees enrolled
Ambala	1	GITI Ambala City (W)	620	513
	2	GITI Naraingarh (W)	60	55
Bhiwani	3	GITI Bhiwani (W)	300	266
	4	GITI Tosham (W)	180	167
Charkhi Dadri	5	GITI Charkhi Dadri (W)	160	122
Faridabad	6	GITI Faridabad (W)	228	183
	7	GITI Uncha Gaon (W)	212	132
Fatehabad	8	GITI Tohana (W)	184	147
Gurugram	9	GITI Gurugram (W)	272	233
Hisar	10	GITI Adampur (W)	304	242
	11	GITI Hansi (W)	160	114
	12	GITI Hisar (W)	284	284
Jhajjar	13	GITI Bahadurgarh (W)	200	168
	14	GITI Jhajjar (W)	132	129
Jind	15	GITI DumerKhan (W)	208	195
	16	GITI Jind (W)	320	304
Kaithal	17	GITI Kaithal (W)	324	277
	18	GITI Pundri (W)	232	192
Karnal	19	GITI Karnal (W)	388	352
Kurukshetra	20	GITI Kurukshetra (W)	224	188
	21	GITI Shahabad (W)	60	55
Mahendergarh	22	GITI Mahendergarh (W)	204	202
	23	GITI Narnaul (W)	308	274
Nuh	24	GITI Ferozpur Jhirka(W)	92	92
	25	GITI Nuh(W)	24	24
	26	GITI Pinagwa (W)	44	0

	27	GITI Punhana (W)	40	0
	28	GITI Ujjina (W)	44	0
Panchkula	29	GITI Kalka at Bitna(W)	128	117
Panipat	30	GITI Panipat (W)	128	106
	31	GITI Samalkha (W)	84	84
Rewari	32	GITI Rewari (W)	308	250
Rohtak	33	GITI Rohtak (W)	248	209
Sirsa	34	GITI Sirsa (W)	380	340
Sonipat	35	GITI Sonipat (W)	204	143
Yamunanagar	36	GITI Chhachrauli (W)	40	38
Total			7328	6197

.....

उद्यम पूंजी निवेश की स्थिति

63. श्री राकेश दौलताबाद : क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएं कि:

- (क) हरियाणा बजट, 2023 में प्रस्तावित ₹ 2000 करोड़ उद्यम पूंजी निवेश (वेंचर कैपिटल फंड) की स्थिति क्या है;
- (ख) उपयोग किए गए 2000 करोड़ के बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है; तथा
- (ग) उन उद्यमियों की सूची का ब्यौरा क्या है जिन्हें उद्यम पूंजी निवेश (वेंचर कैपिटल फंड) के अंतर्गत राशि से लाभान्वित किया गया है ?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : हां, श्रीमान् जी।

- (क) राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा बजट भाषण 2023 के दौरान ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर एक उद्यम पूंजी निवेश (वीसीएफ) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। यह निवेश स्टार्ट अप उद्यमियों, जो महिलाएं हैं या जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है या जो अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, को वितरित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उद्यम पूंजी निवेश में 200 करोड़ रुपये का कोष होगा।

उद्यम पूंजी निवेश (वेंचर कैपिटल फंड) की नवीनतम स्थिति नीचे दी गई है:-

- हितधारकों के साथ संभावित सहयोग की जांच के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ परामर्श किया गया है।
 - एसवीसीएल (सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड) और आईएफसीआई (इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) जैसे प्रमुख हितधारकों द्वारा विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी अभी गहन अध्ययन या जांच चल रही है।
 - इसके अतिरिक्त, महिलाओं और अनुसूचित जाति उद्यमियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया ताकि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके, जिसका उद्देश्य एक ऐसी नीति तैयार करना है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करती हो।
- (ख) प्रस्तावित उद्यम पूंजी निवेश (वेंचर कैपिटल फंड) 200 करोड़ रुपये का है और अभी तक आवंटित नहीं किया गया है; और
- (ग) चूंकि निधि अभी तक आवंटित नहीं की गई है, इस उद्यम पूंजी निवेश (वेंचर कैपिटल फंड)के तहत राशि से लाभान्वित होने वाले उद्यमियों की विस्तृत सूची को शून्य माना जा सकता है।

.....

सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची

64. श्री राकेश दौलताबाद : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की जिलावार सूची क्या है तथा वे किस किस उपचार के लिए सूचीबद्ध हैं।
- (ख) उन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (मेडीकल रिम्बर्समेंट) का ब्यौरा क्या है जो कि उक्त सूचीबद्ध अस्पतालों में बहुत समय से लंबित हैं; तथा
- (ग) उन उपचारों की सूची का ब्यौरा क्या है जिनमें आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत केवल आंशिक रूप से कवर होने वाले उपचार या न कवर होने वाले उपचार के कारण होने वाले खर्च को लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाता है ?

@स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : महोदय, प्रश्न का एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

- (क) राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेषज्ञता के साथ सूचीबद्ध अस्पतालों की जिलेवार सूची (**Flag-A**) पर सलंगन है। उपलब्ध विशिष्टताओं के साथ सूचीबद्ध अस्पतालों (सार्वजनिक और निजी) की जिलेवार सूची <https://ayushmanbharat.haryana.gov.in/> पर उपलब्ध है।
- (ख) सूचीबद्ध अस्पतालों में कोई भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा लंबित नहीं है।
- (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को उपचार स्वास्थ्य लाभ पैकेज मास्टर के अनुसार प्रदान किया जाता है, जिसमें 2200 प्रक्रियाएं (**Flag-B**) पर सलंगन है। पैकेज मास्टर में ऑपरेशन से पहले 3 दिन और ऑपरेशन के बाद के 15 दिन, जिसमें रहना, डॉक्टर की फीस, दवाएं, जांच प्रक्रिया लागत आदि शामिल है। लाभार्थियों को अस्पतालों द्वारा कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। उपचार प्रदान करने के बाद, अस्पताल लेनदेन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर उक्त उपचार के लिए दावा करता है। अस्पतालों को भुगतान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण हरियाणा द्वारा फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) मोड में किया जाता है। यदि प्रक्रिया पैकेज मास्टर में उपलब्ध नहीं है, तो अस्पताल अनिर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत विशेष अनुमोदन के लिए अनुरोध कर सकता है। वित्तीय वर्ष 01.04.2023 से अब तक 36 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। अब तक कुल 67 मामलों को अनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के तहत मंजूरी दी गई है। (**Flag-C**) @

.....

@ उपरोक्त प्रश्न के अनैक्चर्ज 182 पेजिज के होने के कारण चेयर के आदेशानुसार और पूर्व प्रथानुसार विधान सभा के पुस्तकालय में रखवाए गए ।

अनुपचारित पानी की पंपिंग को रोकना

65. श्री चिरंजीव राव : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) क्या यह तथ्य है कि मसानी बैराज में सीवरेज का उपचारित या अनुपचारित पानी छोड़ा जा रहा है;
- (ख) गांव खरखड़ा, निखरी खलियावास तथा आस-पास के अन्य गांवों के समीप का भूमिगत जल प्रदूषित होने के कारण क्या हैं; तथा
- (ग) मसानी बैराज में अनुपचारित पानी की पंपिंग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

- (क) श्रीमान्, आज तक, मसानी बैराज में केवल रेवाड़ी शहर का उपचारित अपशिष्ट जल ही छोड़ा जा रहा है।
- (ख) ग्राम खरखड़ा, निखरी खलियावास और आस-पास के अन्य गांवों में भूमिगत जल प्रदूषित नहीं है, जोकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 24-04-2023 की अनुपालना में गठित संयुक्त समिति के द्वारा दिनांक 26-08-2023 व 13-09-2023 को विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए भूमिगत जल के नमूनों की रिपोर्ट (अनुलग्नक 1 और 2) से स्पष्ट है।
- (ग) उपरोक्त 'क' को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं है।

Test Report

अनुसूची-1

In compliance of order passed by Hon'ble WGT on dated 24.04.2023 in O.A.No. 4777/022 case titled as Prakash Yadav Vs. State of Haryana. A committee is hereby constituted of PHED officers / officials vide memo No. 6882 dated 25/06/2021, O/o the Executive Engineer F.H.E. Division No. 1 Roara for water sampling of various villages i.e., Khokhara, Dhuliyawa, Raigarh, Bhalsawa, Talsana, Nihari, Misari, Durgawala, Tarsapur, Akalpur on 26/08/2023 for compliance of order passed by Hon'ble WGT.

I Certify that I have analyzed the above-mentioned sample collected on dated 26/08/2023 and declare the result of analysis to be as follow:-

S. No.	Name of Village	Name of location	Turbidity (NTU) ± 0.05	Taste (Appreciable)	Odour (Appreciable)	Color (PCU ± 20%)	TDS (mg/l) (100-2000)	TH (mg/l) (100-2000)	Calcium (mg/l) (10-200)	Magnesium (mg/l) (10-200)	Total Alkalinity (mg/l) (100-500)	Chloride (mg/l) (20-400)	Sulphate (mg/l) (100-400)	Fluoride (mg/l) (0.1-1.5)	Iron (mg/l) (0.2)	Manganese (mg/l) (0.05)	pH (6.5-8.5)
1	Khadwara	TW-001 (Khadwara-1)	0.57	Appreciable	Appreciable	1	195	365	2425	2754	400	53.3	21	1.05	0.04	25.1	7.7
		TW-002 (Khadwara-2)	0.41	Appreciable	Appreciable	1	438	233	3000	3716	280	51.4	11	0.26	0.19	38.2	7.5
		TW-003 (Khadwara-3)	0.35	Appreciable	Appreciable	1	321	131	4625	6138	400	36.4	9	0.88	0.15	7.1	7.4
		Pt. DW-04 (Khadwara-4)	0.30	Appreciable	Appreciable	1	229	22	4108	2553	390	80.1	17	0.89	0.11	34.4	7.8
		Pt. DW-05 (Khadwara-5)	0.23	Appreciable	Appreciable	1	421	491	3410	6825	340	109.4	36	0.82	0.19	32.2	7.3
		Pt. DW-06 (Khadwara-6)	0.31	Appreciable	Appreciable	1	405	388	3307	2551	390	8	8	0.73	0.11	7.4	7.6
		Hand Pump (Khadwara-7)	0.57	Appreciable	Appreciable	1	1051	323	1542	8039	800	111.4	18	0.74	0.16	10.1	8.9
2	Khadwara	TW-004 (Khadwara-1)	0.60	Appreciable	Appreciable	1	2890	325	4826	4738	415	60	180	1.25	0.26	7.7	7.4
3	Bhalsawa	TW-005 (Bhalsawa-1)	0.28	Appreciable	Appreciable	1	331	180	2208	3827	390	92.7	20	1.12	0.03	15.6	7.7
		Pt. DW-07 (Bhalsawa-2)	0.50	Appreciable	Appreciable	1	721	380	4108	6131	130	111.2	30	0.84	0.03	30.3	7.4
4	Talsana	TW-006 (Talsana-1)	0.38	Appreciable	Appreciable	1	656	211	2825	2578	405	66.3	42	1.28	0.28	4.6	7.6
		TW-007 (Talsana-2)	0.38	Appreciable	Appreciable	1	488	220	2208	3892	340	11.8	11	1.28	0.03	9.3	7.8
		Pt. DW-08 (Talsana-3)	0.23	Appreciable	Appreciable	1	489	30	521	149	180	17.8	15	1.01	0.03	4.5	8.1
5	Misari	TW-008 (Misari-1)	0.27	Appreciable	Appreciable	1	620	335	4629	4617	190	119.4	54	0.86	0.07	11.9	7.4
		Pt. DW-09 (Misari-2)	0.53	Appreciable	Appreciable	1	177	191	1438	2111	390	36.4	42	1.08	0.05	5.8	7.5
6	Durgawala	TW-009 (Durgawala-1)	0.47	Appreciable	Appreciable	1	1108	200	4208	2108	400	118.2	170	0.84	0.03	12.6	7.6
		TW-010 (Durgawala-2)	0.51	Appreciable	Appreciable	1	628	180	1802	2108	385	81	37	0.27	0.03	4.3	7.8
		TW-011 (Durgawala-3)	0.23	Appreciable	Appreciable	1	818	179	3816	2108	448	118.4	16	1.25	0.03	9.2	7.7
		TW-012 (Durgawala-4)	0.23	Appreciable	Appreciable	1	794	229	1402	4405	305	11.8	38	1.01	0.03	12.4	8.0
		TW-013 (Durgawala-5)	0.23	Appreciable	Appreciable	1	1588	75	2805	1111	420	185.4	67	1.08	0.03	11.2	7.7
		TW-014 (Durgawala-6)	0.34	Appreciable	Appreciable	1	1121	115	2805	1101	448	182.4	138	0.81	0.03	8	7.4
		TW-015 (Durgawala-7)	0.23	Appreciable	Appreciable	1	1223	80	3108	384	408	218.8	178	0.84	0.04	8.8	7.7
7	Durgawala	TW-016 (Durgawala-1)	0.64	Appreciable	Appreciable	1	488	252	3817	2716	385	147.6	55	1.25	0.05	5.8	8.0
		TW-017 (Durgawala-2)	0.58	Appreciable	Appreciable	1	380	19	2402	1575	388	147.6	62	1.05	0.08	7.8	7.8
8	ROGAH	if Village RogaH there was no power supply at the time of sampling.															
9	Talsana	Water supply of Village Talsana commencing from Talsana No. 1, 2, 3 & 4 for Manual group of tube wells.															
10	Akalpur	Pt. TW-018 (Akalpur-1)	0.27	Appreciable	Appreciable	1	489	181	3801	1336	335	24.8	2	1.17	0.03	6.2	7.8
		Pt. TW-019 (Akalpur-2)	0.47	Appreciable	Appreciable	1	434	88	2102	1858	375	26.8	6	1.01	0.02	4.3	7.7

Note-The drinking water supplied by the Public Health Engineering Department is potable and suitable for drinking. As per opinion of the Chemist "There is no effect/ influence of water accumulated at Mussari barrage on these water sources".

Chemist 31/08/2023
District Water Testing Lab
PHED, Roara, Haryana

Test Report

प्रमाणपत्र-१

In compliance of order passed by Hon'ble MGT on dated 24/04/2023 in DA No. 6211/2022 case titled as Prakash Yadav vs. State of Haryana. A committee consisting of PHED officers / officials vide memo No. 7281 dated 12/01/2023. On the Executive Engineer P.H.E. Division No. 1 Rewari for water sampling of various villages i.e., Narthara, Bhalgana, Ragan, Bharsana, Dargapur, Nihari, Masan, Dargawan, Tisappa, Alwalpur on 11/01/2023 for compliance of order passed by Hon'ble MGT.

(Certify that I have analyzed the above mentioned sample collected on dated 11/01/2023 and declare the result of analysis to be as follow:-)

Sr. No.	Name of Village	Name of Installation	Turbidity (NTU) (1:100)	Taste (Aptitude)	Odour (Aptitude)	Color (PCU) (1:100)	TDS (mg/l) (1:100)	TSS (mg/l) (1:100)	Calcium (mg/l) (1:100)	Magnesium (mg/l) (1:100)	Total Alkalinity (mg/l) (1:100)	Chloride (mg/l) (1:100)	Sulphate (mg/l) (1:100)	Fluoride (mg/l) (1:100)	Iron (mg/l) (1:100)	Alumina (mg/l) (1:100)	pH
1	GADWARI	PHEDWATERGADWARI1	0.11	Aptitude	Aptitude	1	121	81	44.01	21.21	30	42	21	0.05	0.04	21.8	7.8
		PHEDWATERGADWARI2	0.04	Aptitude	Aptitude	1	93	26	32.07	14.1	33	35.6	21	0.02	0.01	26.9	7.8
		PHEDWATERGADWARI3	0.04	Aptitude	Aptitude	1	120	30	34.06	25.36	30	22.4	21	0.01	0.03	14.0	7.4
		Private Water Supply to Karam Bhandi	1.28	Aptitude	Aptitude	1	114	21	42.08	41.21	20	38.4	11	1.06	1.28	6.1	7.4
		Private Water Supply to Karam Bhandi	4.46	Aptitude	Aptitude	1	107	12	32.14	46.31	42	41	41	0.75	0.17	31.3	6.8
		Private Water Supply to Karam Bhandi	0.11	Aptitude	Aptitude	1	147	20	32.06	26.31	34.5	41	8	0.16	0.14	38.2	7.7
2	OKHARWARI	PHEDWATEROKHARWARI1	0.11	Aptitude	Aptitude	1	120	25	34.36	11.01	42	33.1	30	1.08	0.08	11.8	7.1
		PHEDWATEROKHARWARI2	0.27	Aptitude	Aptitude	1	52	10	22.04	11.71	30	26.6	31	1.13	0.04	31.1	7.7
3	BHALGANA	Private Water Supply to Bhalgana	0.14	Aptitude	Aptitude	1	77	14	24.17	11.11	34	17.4	14	0.09	0.07	44.1	7.5
		Private Water Supply to Bhalgana	0.11	Aptitude	Aptitude	1	118	11	26.04	11.01	30	16.4	11	1.02	0.07	6.0	7.8
4	NARTHARA	PHEDWATERNARTHARA1	0.21	Aptitude	Aptitude	1	100	14	30.36	11.71	44.5	11.4	11	0.09	0.03	7.1	7.5
		PHEDWATERNARTHARA2	0.11	Aptitude	Aptitude	1	101	11	24.34	11	10	16.4	11	1.22	0.24	11.1	7.9
		Private Water Supply to Narthara	0.21	Aptitude	Aptitude	1	148	10	24.34	11.81	10	41	11	1.16	0.05	22.1	7.8
5	DARGAWAN	PHEDWATERDARGAWAN1	0.11	Aptitude	Aptitude	1	111	11	22.34	14.1	10	10.4	11	1.18	0.08	6.1	8.0
		Private Water Supply to Dargawan	0.11	Aptitude	Aptitude	1	121	11	44.36	40.36	28	22.4	11	0.08	0.07	14.8	7.2
		Private Water Supply to Dargawan	0.11	Aptitude	Aptitude	1	107	10	10.21	7.21	30	17.2	11	0.08	0.05	34.1	7.2
6	MASAN	PHEDWATERMASAN1	0.11	Aptitude	Aptitude	1	121	21	34.31	21.11	17	40.1	11	0.08	0.01	12.1	7.8
		PHEDWATERMASAN2	0.11	Aptitude	Aptitude	1	117	11	22.34	11.11	15	30.4	11	0.11	0.01	8.1	7.9
		PHEDWATERMASAN3	0.11	Aptitude	Aptitude	1	111	21	24.34	11.71	42	11.1	11	1.01	0.04	14.1	7.8
		PHEDWATERMASAN4	0.11	Aptitude	Aptitude	1	114	11	11.11	11.71	41	41	11	1.01	0.01	11.1	7.5
		PHEDWATERMASAN5	0.11	Aptitude	Aptitude	1	111	11	11.11	11.71	41	41	11	1.01	0.01	11.1	7.6
		PHEDWATERMASAN6	0.11	Aptitude	Aptitude	1	111	11	14.01	11.44	44	24.1	11	0.01	0.01	11.1	7.8
		PHEDWATERMASAN7	0.11	Aptitude	Aptitude	1	111	11	11.11	11.11	11	11	11	0.01	0.01	11.1	7.5
7	DARGAPUR	PHEDWATERDARGAPUR1	0.11	Aptitude	Aptitude	1	70	11	14.01	11.11	11	14.1	11	1.01	0.01	6.1	7.8
		PHEDWATERDARGAPUR2	0.11	Aptitude	Aptitude	1	112	11	11.01	11.11	11	11.1	11	1.01	0.01	6.1	7.8
		Private Water Supply to Dargapur	0.11	Aptitude	Aptitude	1	91	11	20.4	11.01	41	11.1	11	1.01	0.01	6.1	8.1
		Private Water Supply to Dargapur	0.11	Aptitude	Aptitude	1	75	11	21.01	11.01	41	11.1	11	1.01	0.01	6.1	7.9
8	RAGAN	PHEDWATERRAGAN1	0.11	Aptitude	Aptitude	1	111	11	11.01	11.11	11	11.1	11	1.01	0.01	6.1	7.7
		Private Water Supply to Ragan	0.11	Aptitude	Aptitude	1	78	11	11.01	11.44	41	11	11	1.01	0.01	6.1	7.8
		Private Water Supply to Ragan	0.11	Aptitude	Aptitude	1	111	11	21.01	11.71	41	11.1	11	1.01	0.01	6.1	7.7
9	REWARI	Private Water Supply to Rewari	0.11	Aptitude	Aptitude	1	120	11	11.11	11.01	11	11.1	11	1.01	0.01	6.1	7.1
		Water supply of Village Dargapur a monitoring from Talsar No. 1, 1.1 & 1.2 from Masan ground water well.															
10	ALWALPUR	Private Water Supply to Alwalpur	0.11	Aptitude	Aptitude	1	120	11	21.01	11.11	11	11.1	11	1.01	0.01	6.1	7.4
		Private Water Supply to Alwalpur	0.11	Aptitude	Aptitude	1	111	11	11.01	11.11	11	11.1	11	1.01	0.01	6.1	8.1

Note: The drinking water supplied by the Public Health Engineering Department is potable and suitable for drinking. As per opinion of the Chemist (free to effect) influence of water accumulated at Masan Bhandi on their water supply.

Chemist 18/01/23
District Water Testing Lab
PHED, Rewari, Haryana

विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा करना

66. श्री घनश्याम दास : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कैप (कोड नंबर 0177) के नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त भवन के निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): श्रीमान जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कैप, यमुनानगर अब राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कैप, यमुनानगर (कोड नंबर 0177) है। इसके भवन निर्माण कार्य का विस्तृत अनुमान/निविदा आमंत्रण नोटिस (डी0एन0आई0टी0) प्रक्रियाधीन है। निविदा दिनांक 31.12.2023 तक आमंत्रित की जाएगी तथा मार्च, 2024 तक कार्य शुरू होने की संभावना है। निर्माण कार्य सितम्बर, 2025 तक पूर्ण करवा लिया जाएगा।

.....

चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य को पूरा करना

67. श्री घनश्याम दास : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि यमुनानगर में प्रस्तावित श्री गुरु तेग बहादुर साहिब चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य गांव पंजूपुरा जिला यमुनानगर में कार्यकारी एजेंसी यानी ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिया गया है और इसे अनुबंध के अनुसार 30 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

66 के. वी. ट्यूबलर/चाइना पोल (खम्बे) लगाना

68. श्री घनश्याम दास : क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएं कि:

- (क) क्या यह तथ्य है कि यमुनानगर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बहुत कम ऊंचाई से 66 के. वी. की एक्स्ट्रा हाई-टेंशन तार गुजर रही है जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है; तथा
- (ख) यदि हां, तो क्या लोगों के जान-माल को बचाने के लिए 66 के.वी. ट्यूबलर/चाइना पोल लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह):

- (क) हाँ श्रीमान, यमुनानगर की घनी आबादी वाले क्षेत्र के ऊपर से ओवरहेड 66 के.वी. एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनें गुजर रही हैं। काफी समय पहले 1980 के दशक में बनाई गई लाइनों के नीचे बाद में अनधिकृत आवासीय निर्माण किए गए हैं।
- (ख) नहीं श्रीमान, वर्तमान में 66 केवी ट्यूबलर/चाइना पोल लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यहां तक कि, ट्यूबलर/चाइना पोल पर इन लाइनों को दोबारा बिछाने, जो कि तकनीकी फिजीबिलिटी के अधीन है, से भी मामले का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइनें अनधिकृत आवासीय निर्माण के ऊपर से गुजरती रहेंगी।

पेयजल के लिए क्लस्टर परियोजना बनाना

69. डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि :-

- (क) क्या जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गावों अर्थात् अहिरका, कैरखेडी, रूपगढ़, झांझ कलां, झांझ खुर्द तथा जुलानी में पेयजल के लिए क्लस्टर परियोजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

जन स्वास्थ्य अभियान्तिकी विभाग मंत्री (डा. बनवारी लाल):

(क) गांव रूपगढ़ को छोड़कर (जिसे पहले से ही एक स्वतंत्र नहर आधारित जलघर द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है) पांच गांवों नामतः अहिरका, कैरखेड़ी, झांझ कलां, झांझ खुर्द और जुलानी को नहर आधारित पेयजल प्रदान करने के लिए परियोजना बनाने का कार्य पंचायती भूमि उपलब्ध ना होने के कारण रूका हुआ है जिसे अब ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है।

(ख) भूमि की खरीद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जिस के पश्चात (बाद) जलघर के निर्माण का कार्य 18 से 24 महीने के अंतर्गत पूरा कर लिया जाएगा।

पेयजल के लिए क्लस्टर परियोजना बनाना

70. डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि :

(क) क्या जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों अर्थात् ईक्कस, जलालपुर खुर्द, जलालपुर कलां, इंटल कलां, संगतपुरा, इंटल खुर्द, जाजवान, ढाण्डा खेडी तथा दरियावाला में पेयजल के लिए क्लस्टर परियोजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) क्या उपरोक्त गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं तथा क्या उक्त पानी पीने योग्य है ?

जन स्वास्थ्य अभियान्तिकी विभाग मंत्री (डा. बनवारी लाल):

(क) स्थिति का विस्तृत विवरण इस प्रकार है—

i) संगतपुरा, जाजवान, दरियावाला गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति स्वतंत्र नहर आधारित जल घर से की जा रही है।

- ii) ईक्कस और जलालपुर खुर्द गांव के लिए नहर आधारित जल घर के निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिस की अनुमानित लागत 477.65 लाख रूपये है।
- iii) स्वतंत्र नहर आधारित जल घर के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत इंटल खुर्द और ढांडा खेड़ी के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और परियोजना तैयार की जा रही है। 15 महीने के अंदर काम पूर्ण कर लिया जायेगा।
- IV) इस के अतिरिक्त इंटल कंला और जलालपुर कलां ग्राम पंचायत से स्वतंत्र जल घर बनाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत से भूमि लेने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।
- (ख) वर्तमान में इन सभी 9 गांवों में ट्यूबवैल और नहर आधारित जल घरों के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है, जैसा कि नीचे बताया गया है और प्रत्येक गांव में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से आपूर्ति की जा रही है।

क्रम संख्या	पेयजल आपूर्ति योजना का नाम	शामिल हुए गांवों के नाम	पेयजल आपूर्ति योजना का प्रकार (आधार)	वर्तमान पेयजल आपूर्ति स्थिति (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर में)
1	2	3	4	5
1	ईक्कस	ईक्कस	नलकूप आधारित	55
2		जलालपुर खुर्द		
3	जलालपुर कलां	जलालपुर कलां	नलकूप आधारित	55
4	इंटल कलां	इंटल कलां	नलकूप आधारित	55
5	संगतपुरा	संगतपुरा	नहर आधारित	55
6	इंटल खुर्द	इंटल खुर्द	नलकूप आधारित	55
7	जाजवान	जाजवान	नहर आधारित	55
8	ढाण्डा खेड़ी	ढाण्डा खेड़ी	नलकूप आधारित	55
9	दरियावाला	दरियावाला	नहर आधारित	55

सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा करना

71. डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री कृपया बताएंगे कि :-

- (क) जींद शहर में मां जयंती देवी मन्दिर के सामने से अस्थाई नन्दीशाला को कब तक स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है; तथा
- (ख) उपरोक्त भूमि पर प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र के निर्माण कार्य के पूरे हो चुके चरणों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (डॉ. कमल गुप्ता):

- (क) जींद शहर में मां जयंती देवी मन्दिर के सामने से अस्थाई नन्दीशाला को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- (ख) बागवानी विभाग की 5 एकड़ भूमि नगर परिषद्, जींद को स्थानान्तरित होने के पश्चात सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य किया जाएगा। कथित भूमि को लेने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

.....

कार्यरत एफेरसिस मशीन की संख्या

72. श्री वरुण चौधरी : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

- (क) राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत एफेरसिस मशीनों (प्लेटलेट्स मशीन) की जिले-वार संख्या कितनी है; तथा
- (ख) क्या राज्य में हाल ही में प्लेटलेट्स की कमी के कारण हुई मौतों के मद्देनजर मशीनों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज):

- (क) राज्य में 04 एफेरसिस मशीनें (प्लेटलेट्स मशीन) सरकारी जिला नागरिक अस्पतालों में, 06 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में तथा 01 रेड क्रॉस ब्लड सेंटर में कार्यरत हैं। विवरण इस प्रकार है:-

रक्त केंद्र का नाम		कार्यरत एफेरसिस मशीन की संख्या
जिला नागरिक अस्पताल		
1	फरीदाबाद	1
2	गुरुग्राम	1
3	हिसार	1
4	पंचकुला	1
सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज		
1	पीजीआईएमएस, रोहतक	1
2	बीपीएस सरकारी, मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां, सोनीपत	1
3	कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज, करनाल	1
4	राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर	1
5	ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद	1
6	एमएमसी, अग्रोहा, हिसार	1
अन्य		
1	रेडक्रॉस ब्लड सेंटर, पानीपत	1
कुल		11

(ख) हाँ श्रीमान जी, शेष जिला नागरिक अस्पतालों के लिए 18 अतिरिक्त एफेरसिस मशीनें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पहले से ही सरकार के विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का डाटा

73. श्री वरुण चौधरी : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- (क) मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों का डाटा एकत्रित न करने के कारण क्या हैं जिनकी आय दोगुनी हो गई है;
- (ख) उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है जो अपनी मासिक किस्तों को भरने में असमर्थ हैं; तथा
- (ग) हाल ही में एकत्रित किए गए डाटा के संबंध में विभिन्न ऋणों के अंतर्गत ब्याज छूट की राशि (प्रतिशत में) कितनी है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, उत्तर इस प्रकार से है:-

- (क) मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक पहल है जो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें कौशल विकास, वेतन रोजगार और स्वरोजगार इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी पारिवारिक आय को कम से कम 1.80 लाख प्रति वर्ष तक पहुँचाना है। मिशन वर्तमान में उन लाभार्थियों की संख्या का रखरखाव/संग्रह नहीं कर रहा है जिनकी आय दोगुनी हो गई है।
- (ख) ऋण मंजूरी और वितरण करने वाले बैंकों से जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस जानकारी का संग्रहण होने पर, इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।
- (ग) ब्याज सहायता प्रदान करने वाली सरकारी एजेंसियों से जानकारी एकत्र की जा रही है, इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

.....

मुख्यमंत्री घोषणाओं के अन्तर्गत विकास कार्य

74. श्री वरुण चौधरी : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि मुलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ की राशि के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 25284 की स्थिति क्या है तथा कार्यों के शुरू करने/पूरा करने के लिए शिलान्यास/उद्घाटन न करने के कारण क्या हैं जैसे कि अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान् जी, मुख्यमंत्री घोषणा 25284 के अन्तर्गत मुलाना विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि लाख रू० में)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	वित्तीय स्थिति			भौतिक स्थिति		
	स्वीकृति राशि	जारी राशि	खर्च की गई राशि	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगतिधीन कार्यों की संख्या
मुलाना	359.23	354.23	305.30	76	64	12

राज्य सरकार की नीति के अनुरूप विकास कार्यों के शिलान्यास/ उद्घाटन की कार्यवाही की जा रही है।

एक विश्वविद्यालय खोलना

75. श्री आफताब अहमद : क्या उच्चतर शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि नूह जिले में राज्य विश्वविद्यालय को स्थापित करने की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

उच्चतर शिक्षा मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

A proposal for establishing a State University in District Nuh is under consideration of the Government. Land for the said University is being located and Haryana State Higher Education Council is examining its feasibility. It will be possible to provide the time only after the feasibility is ascertained.

At present the 22 State Universities and 01 Central University are established in the State of Haryana. The district-wise details thereof are as under:-

Sr. No.	District	Name of the University
1	Mahendergarh	Central University, Jant-Pali, Mahendergarh
2	Bhiwani	Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani
3	Gurugram	Gurugram University, Gurugram
4	Jind	Chaudhary Ranbir Singh University, Jind
5	Kurukshetra	Kurukshetra University, Kurukshetra
6		Shri Krishna Ayush University, Kurukshetra
7	Kaithal	Maharshi Valmiki Sanskrit University, Kaithal
8	Rewari	Indira Gandhi University, Meerpur, Rewari
9	Rohtak	Maharshi Dayanand University, Rohtak

10		Pt. B.D. Sharma University of Health Science, Rohtak.
11		Pt. Lakhmi Chand State University of Performing & Visual Arts, Rohtak.
12	Sirsa	Chaudhary Devi Lal University, Sirsa.
13	Sonapat	Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonapat.
14		Dr. B.R. Ambedkar National Law University, Rai, Sonapat
15		Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal, Sonapat
16		Sport University of Haryana, Rai, Sonapat
17	Hisar	Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar
18		Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University, Hisar
19		Lala Lajpat Rai Veterinary University, Hisar
20	Faridabad	J.C. Bose University of Science & Technology, Faridabad.
21	Palwal	Shri Vishwakarma Skill University, Palwal.
22	Karnal	Pt. Deen Dayal Upadhyay University of Health Science, Karnal
23		Maharana Paratap Horticulture University, Anjanthali, Karnal.

Apart from the above, following 25 Private Universities are also established in the State of Haryana:-

Sr. No.	District	Name of the University
1	Ambala	Maharishi Markandeshwar University, Sadopur, Ambala
2	Faridabad	Al-Falah University, Faridabad
3		Manav Rachna University, Faridabad
4	Gurugram	Northcap University, Gurugram
5		Amity University, Gurugram
6		Apeejay Stya University, Gurugram
7		Sushant University, Gurugram

8		Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University, Gurugram
9		G.D. Goenka University, Gurugram
10		K.R. Mangalam University, Gurugram
11		BML Munjal University, Gurugram
12		Starex University, Gurugram
13		IILM University, Gurugram
14	Hisar	OM Sterling Global University, Hisar.
15	Jhajjar	PDM University, Bahadurgarh, Jhajjar
16		Jagan Nath University, Bahadurgarh, Jhajjar
17	Kaithal	NIILM University, Kaithal
18	Palwal	MVN University, Palwal
19	Rohtak	Baba Mast Nath University, Rohtak
20	Sonepat	O.P. Jindal Global University, Sonepat (now Deemed University under UGC)
21		SRM University, Sonepat
22		Ashoka University, Sonepat
23		Rishihood University, Sonepat
24		World University of Design, Sonepat
25	Panipat	Geeta University, Panipat

This matter was taken up during the Haryana Vidhan Sabha session held in February, 2019. The Minister gave an assurance bearing No. 60 on the floor of the house to open an academic university in District Nuh.

Later, the Deputy Commissioner, Nuh was requested to send a feasibility report and availability of land and the same has been received on 15.02.2023.

In the said report dated 15.02.2023, the Deputy Commissioner, Mewat has informed that 110 acres of land is available with the Gram Panchayat Nangal Mubarikpur, Sub Tehsil Nagina, if the same is transferred in the name of State Government, the proposal for establishing a University will be considered by the Government.

It is further stated that the State Government was constituted a Committee on 11.4.2023 comprising of the following officers/authorities to examine the feasibility of proposed land measuring 110 acres situated at Nangal Mubarikpur, Sub Tehsil Nagina for opening of a State University in District Nuh (Mewat) :-

1. Superintendent Engineer of Panchayat and Development Department, Nuh.
2. Superintendent Engineer of PWD B&R, Nuh.
3. Deputy Director (Works) Higher Education Department.
4. Tehsildar of Revenue Department, Nuh.
5. Nominee of Deputy Commission Nuh.

The committee has submitted its report on 09.12.2023 and the same is being submitted to the State Government for decision.

छात्रों तथा अध्यापकों की कुल संख्या

76. श्री आफताब अहमद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

- (क) राज्य में राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) मेवात में राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या कितनी है;
- (ग) राज्य के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है; तथा
- (घ) नूह जिले में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

- (क) राज्य में राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या 22,31,282 है।
- (ख) मेवात में राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या 2,53,247 है।
- (ग) राज्य के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 88,525 है; तथा
- (घ) नूह जिले में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की कुल संख्या 4,216 है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

जिला नूंह में कार्यरत अध्यापक		
क्रमांक	पद का नाम	कार्यरत संख्या
1.	प्रधानाचार्य	108
2.	स्नातकोत्तर प्राध्यापक (पी0जी0टी0)	658
3.	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टी0जी0टी0)	1050
4.	मुख्य शिक्षक	202
5.	पी0आर0टी0 / जे0बी0टी0	2198
कुल		4216

छात्रों को छात्रवृत्ति

77. श्री आफताब अहमद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएं कि :-

- (क) राज्य में वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में सरकार द्वारा कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई; तथा
- (ख) उपरोक्त अवधि के दौरान नूंह जिले में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा उनकी सूची क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

- (क) राज्य के राजकीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में 10,94,951 (दस लाख चौरानवें हजार नौ सौ इक्यावन) तथा वर्ष 2023-24 में 8,83,120 (आठ लाख तिरयासी हजार एक सौ बीस) छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी।
- (ख) वर्ष 2022-23 में जिला नूंह के राजकीय विद्यालयों में 49,745 (उन्चास हजार सात सौ पैतालिस) तथा वर्ष 2023-24 में 40,246 (चालीस हजार दौ सौ छियालिस) छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। राज्य के नूंह जिला के वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, उनकी सूची संलग्न है।

सूची

Total Students Class 9TH TO 12TH for FY 2022-23 (District Nuh, Haryana)			
Sr.no.	Credit Amount	Full Name in English	Address Line2
1	750	VISHAL	Government Senior Secondary School Lohringa Kalan
2	750	MOHIT	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
3	750	MAHESH KUMAR	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
4	750	ATENDER	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
5	1200	KAMINI	Government Senior Secondary School Adbar
6	750	PANKAJ	Government Senior Secondary School Purnana
7	750	AMAN	Government Senior Secondary School Purnana
8	750	PAWAN	Government Senior Secondary School Purnana
9	750	JEETAN	Government Senior Secondary School Purnana
10	750	SAANVI	Government Senior Secondary School Purnana , Nuh Mewat
11	750	SAHWAG	Government Senior Secondary School Purnana
12	1200	SHANKAR	Government Senior Secondary School Purnana
13	750	ANUJI	Government Senior Secondary School Pirangwan
14	750	KAPIL	Government Senior Secondary School Pirangwan
15	750	AJAY KUMAR	Government Senior Secondary School Pirangwan
16	750	PRINCE KUMAR	Government Senior Secondary School Pirangwan
17	1200	DEEPMALA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
18	1200	AARTI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
19	1200	ANALI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
20	1200	SOMAM	Government Girls Senior Secondary School Purnana
21	1200	INDUBALA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
22	1200	PIRACHI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
23	1200	SHASHI BALA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
24	1200	MEERA RANI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
25	1200	KAMINI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
26	1200	RASHI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
27	1200	NANCI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
28	1200	PNKI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
29	1200	ANJALI	Government Girls Senior Secondary School Purnana , Purnana
30	1200	GUDIYA	Government Girls Senior Secondary School Purnana , Purnana
31	1200	RACHNA	Government Girls Senior Secondary School Purnana , Nuh Mewat
32	1200	SONIA	Government Senior Secondary School Niwana
33	1200	SOMYA	Government Senior Secondary School Niwana , Purnana
34	1200	HIMANSHI	Government Senior Secondary School Niwana , Nuh Mewat
35	750	AJIT	Government Senior Secondary School Padheni , Taoru
36	750	PARVEEN	Government Senior Secondary School Mohd.Pur Ahr
37	750	JATIN	Government Senior Secondary School Basaikhazada
38	750	AMIT	Government Senior Secondary School Basaikhazada , Nagina
39	750	KHEM CHAND	Government Senior Secondary School Pachgaon
40	750	MANISH	Government Senior Secondary School Pachgaon
41	750	BANUJAY	Government Senior Secondary School Pachgaon
42	1200	KIRAN	Government Senior Secondary School Tapkan
43	1200	RAJNI	Government Senior Secondary School Tapkan
44	750	PARVESH	Government Senior Secondary School Tapkan
45	750	SANDEEP KUMAR	Government Senior Secondary School Tapkan
46	750	SUMIT KUMAR	Government Senior Secondary School Tapkan
47	750	ARVIND KUMAR	Government Senior Secondary School Tapkan
48	750	SAGAR	Government Senior Secondary School Tapkan
49	750	BHARAT RAM	Government Senior Secondary School Niwana
50	750	BHUDEV	Government Senior Secondary School Niwana
51	750	AKLAVYA	Government High School Gangwari
52	1200	MUSKAN	Government Senior Secondary School Mandi Kheta
53	1200	TANISHA	Government Girls Senior Secondary School Taoru , Taoru
54	1200	SAKSHI	Government Girls Senior Secondary School Taoru
55	1200	SANDHYA	Government Girls Senior Secondary School Taoru
56	1200	SHASHIKA	Government Girls Senior Secondary School Taoru
57	1200	NEHA	Government Girls Senior Secondary School Taoru
58	1200	SHIVANI	Government Girls Senior Secondary School Taoru
59	1200	KOMAL	Government Girls Senior Secondary School Taoru
60	1200	SIMRAN	Government Girls Senior Secondary School Taoru
61	750	TULSI	Government Girls Senior Secondary School Taoru
62	1200	KARISHMA	Government Girls Senior Secondary School Taoru
63	1200	KHUSHBU	Government Girls Senior Secondary School Taoru
64	1200	VASUMDHARA	Government Girls Senior Secondary School Taoru
65	1200	KOMAL	Government Girls Senior Secondary School Taoru
66	1200	KAJAL	Government Senior Secondary School Feroz Pur Namak
67	1200	ANSHU BALA	Government Senior Secondary School Feroz Pur Namak
68	750	MICRU	Government Senior Secondary School Feroz Pur Namak
69	1200	DEEPIKA	Government Senior Secondary School Raheri

70	750	LOKESH	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nuh
71	750	HEMANT	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nuh
72	750	ROBI	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nuh
73	750	DEEPAK	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nuh
74	750	ROHIT	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nuh
75	750	SAMEER	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nuh
76	750	ROHIT	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nuh
77	750	SONU SINGH	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nuh , Nuh
78	750	ANIL	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nuh , Nuh
79	1200	MANISHA	Government Girls Senior Secondary School Ujina
80	1200	PRINYANKA	Government Girls Senior Secondary School Ujina
81	1200	ANJU	Government Girls Senior Secondary School Nuh
82	1200	POOJA	Government Girls Senior Secondary School Nuh
83	1200	RIYA	Government Girls Senior Secondary School Nuh
84	1200	GURJAN	Government Girls Senior Secondary School Nuh
85	1200	ISHKA	Government Girls Senior Secondary School Nuh
86	1200	LUCKY	Government Girls Senior Secondary School Nuh
87	1200	MANSHI	Government Girls Senior Secondary School Nuh
88	1200	POOJA	Government Girls Senior Secondary School Nuh
89	1200	RAJNI	Government Girls Senior Secondary School Nuh
90	1200	SEEMA	Government Girls Senior Secondary School Nuh
91	1200	MINAKSHI	Government Girls Senior Secondary School Nuh
92	1200	SHEETAL	Government Girls Senior Secondary School Nuh
93	1200	KOMAL	Government Girls Senior Secondary School Nuh
94	1200	MONIKA	Government Girls Senior Secondary School Nuh
95	1200	SONYA	Government Girls Senior Secondary School Nuh
96	1200	YOGITA	Government Girls Senior Secondary School Nuh
97	1200	MANGLESH	Government Girls Senior Secondary School Nuh
98	1200	DEEPA	Government Girls Senior Secondary School Nuh
99	1200	NEHA	Government Girls Senior Secondary School Nuh , Nuh
100	1200	MAHI	Government Girls Senior Secondary School Nuh , Nuh
101	1200	MANISHA	Government Girls Senior Secondary School Nuh , Nuh
102	750	SAGAR	Government Senior Secondary School Malab
103	750	NARESH	Government Senior Secondary School Malab
104	1200	BUNTY	Government Senior Secondary School Chharara
105	1200	NEHA	Government Senior Secondary School Chharara
106	750	SAPAL	Government Senior Secondary School Chharara
107	750	KANWARPAL	Government Senior Secondary School Khor Basai
108	750	KARAMBIR	Government Senior Secondary School Khor Basai
109	750	VIRENDER	Government Senior Secondary School Khor Basai
110	750	MANJIT	Government Senior Secondary School Khor Basai , Nuh
111	1200	MUSKAN	Government Senior Secondary School Rawatan
112	750	DHEERAJ	Government Senior Secondary School Durdoh
113	1200	PRIYA	Government Senior Secondary School Durdoh
114	750	UMESH	Government Senior Secondary School Chhapara
115	750	KAMAL	Government Senior Secondary School Sakas
116	1200	POOJA	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Saroli
117	1200	NITESH RAMI	Government Girls Senior Secondary School Fhangwan , Punhana
118	1200	SOMIA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
119	750	BIPASHA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
120	1200	NISHA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
121	1200	AMAN	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
122	1200	KIRTI	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
123	1200	MELINA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
124	800	POONAM	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
125	750	RAMAL	Government Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
126	750	SANMAY SINGH	Government Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
127	750	RAVI	Government Senior Secondary School Ferozpur Jhirka
128	750	MOHIT	Government Senior Secondary School Ferozpur Jhirka , Ferozpur Jhirka
129	1800	GURAGUN	Government Girls Senior Secondary School Punhana
130	1800	SALONI BALA	Government Girls Senior Secondary School Punhana , Punhana
131	750	PRITAM SINGH	Government Senior Secondary School Bissar Akbarpur
132	1200	ANJALI KUMARI	Government Senior Secondary School Kamar Sika
133	1200	DURGESH MANDW	Government Senior Secondary School Kamar Sika
134	750	KULDEEP	Government Senior Secondary School Kamar Sika
135	750	ROHIT	Government Senior Secondary School Kamar Sika
136	1200	SINDHU KUMARI	Government Senior Secondary School Kamar Sika
137	750	HITESH	Government Senior Secondary School Kamar Sika
138	1200	PRINYANKA	Government Senior Secondary School Kamar Sika
139	750	YAS MAJORA	Government Senior Secondary School Kamar Sika
140	1200	KUMRUM	Government Senior Secondary School Kamar Sika

49656	750	SAHID	Government Middle School Kalabari, Nuh Mawat
49657	750	GAGAN BY FNO MUKESH	Government Middle School Sonkh, Nuh Mawat
49658	750	SAHEL	Government Girl Middle School Kangarka Nuh, Nuh Mawat
49659	750	WASEEM	Government Girl Middle School Kangarka Nuh, Nuh Mawat
49660	750	SAIF	Government Middle School Satputhyaka, Nuh Mawat
49661	750	ARMANSORSAD	Government Middle School Ibrahim Bas, Nuh Mawat
49662	750	ARRAF	Government Senior Secondary School Mahun
49663	750	MAHIFAL	Government Senior Secondary School Ferozpur Birka, Nuh Mawat
49664	750	AADI HUSSAIN	Government Middle School B.A. Pur, Nuh Mawat
49665	750	MR FIROZ KHAN	GMS Hanja Pur, Nuh Mawat
49666	750	WASEEM SO RASDAN WO BEJMAN	Government Middle School Shekhpur
49667	750	SAHIBSO MAKSUDFAIEDA	Government Girls Middle School Dorakhi, Nuh Mawat
49668	750	KUNAL	Government Senior Secondary School Atta Barota
49669	750	PREETIMNDOKAVITA	Government Senior Secondary School Atta Barota
49670	750	LUMTADOSANTRAM	Government Senior Secondary School Atta Barota
49671	750	SUMAIYAHANDOSHAMSHE DAI	Government Senior Secondary School Path Khori
49672	750	TAJIMADHUSAIN	Government Senior Secondary School Bhakdolli, Nuh Mawat
49673	750	TARFU MG MUNESH	Government Girl Middle School Kangarka Nuh
49674	750	FARIN	Government Girl Middle School Kangarka Nuh, Nuh Mawat
49675	750	SABIRNAGOMOSAM	Government Senior Secondary School Path Khori, Nuh Mawat
49676	750	KASHIFA NAJ	Government Girls Middle School Khori Kalan, Nuh Mawat
49677	750	AHSANA UG SAQR	Government Girls Middle School Salahan, Nuh Mawat
49678	750	JAIFADASRU	Government Middle School Ibrahim Bas, Nuh Mawat
49679	750	ANASTADOWAHD	Government Middle School Ibrahim Bas
49680	750	SAHWANA MG MUBINA	Government Middle School Satputhyaka
49681	750	AMRITA DO NARENDER	Government Girl Middle School Kita Khandwala
49681	750	CHANCHAL D/O RAMESH D/O BY MOTHER PUSHPA	Government Middle School Hanmuwas
49682	750	SUMAIYA	Government Senior Secondary School Mahun
49684	750	NIRENDRA SO KESAR WD BOHITASH	Government Senior Secondary School Mahun
49685	750	SAHRUNA	Government Senior Secondary School Mahun, Nuh Mawat
49686	750	SANIADOSHAMUDEEN	Government Middle School Champun Nuh Mawat, Nuh Mawat
49687	750	RABBIYASDABBAR	Government Middle School Champun Nuh Mawat, Nuh Mawat
49688	750	RIZA	Government Senior Secondary School Baded, Nuh Mawat
49689	750	BAJAI SO FOOL CHAND	Government Senior Secondary School Baded
49690	750	GIRRAJ MD MANU VILL BADED	Government Senior Secondary School Baded
49691	750	MRS SUWALIYA SUWALIYA	Kasturba Gandhi Bahi Vidyalya Ferozpur Birka
49692	750	MISS SHAHISTA SHAHISTA	Government Middle School Bhand, Nuh Mawat
49693	750	SOPIYA UG SAHIDA	Government Middle School Bhand, Nuh Mawat
49694	750	AAMADODEENU	Government Senior Secondary School Bhakdolli, Nuh Mawat
49695	750	GAURAV	Government Senior Secondary School Doha
49696	750	PASRAT D/O SHANAI W/D WAZID	Government Middle School Rithala, Nuh Mawat
49697	750	SADIA KHATUN D/O MOHD ZAHID	Government Girls Senior Secondary School Ghatera
49698	750	RIHAW S/O BASSI W/O SHARRIF	Government Middle School B.A. Pur
49699	750	KUNAL D/O RULENDER	Government Middle School B.A. Pur
49700	750	SONAM U/Y KLINTI	Government Girls Middle School Doha, Nuh Mawat
49701	750	MONIKA U/Y RAJINI DEVI	Government Girls Middle School Doha, Nuh Mawat
49702	750	MISS MANSAR MANSAR	Government Girl Middle School Habibka Nuh Mawat, Nuh Mawat
49703	750	MRS RUKSAR RUKSAR	GMS Hanja Pur, Nuh Mawat
49704	750	MRS MRS RUKSAR	GMS Hanja Pur, Nuh Mawat
49705	750	SAKILA	Government Middle School Sakras, Nuh Mawat
49706	750	SAFIYADASRU	Government Girls Middle School Dorakhi, Nuh Mawat
49707	750	FAINA U/G ARIFA W/O IMBAN	Government Girls Middle School Salahan
49708	750	MISS SOYIBA SOYIBA	Government Girl Middle School Habibka Nuh Mawat, Nuh Mawat
49709	750	PRITI DO VIKAL	Government Senior Secondary School Bazar Abdargur, Nuh Mawat
49710	750	ARCHANA	Government Senior Secondary School Bazar Abdargur, Nuh Mawat
49711	750	SADIA UG MUBARRE	Government Middle School Sonkh, Nuh Mawat
49712	750	NIHAL	Government Middle School Shekhpur
49713	750	RONAR	Government Middle School Shekhpur
49714	750	NEHA DO SABITA WO DHAN SINGH	Government Middle School Shekhpur
49715	750	AITSRIGHCHANDERBHAN	Government Senior Secondary School Bwan
49716	750	TOSMASONAWAB	Government Middle School Ibrahim Bas
49717	750	NOLLI	Government Senior Secondary School Baded, Nuh Mawat
49718	750	NAFISH	Government Middle School B.A. Pur, Nuh Mawat
49719	750	AYANDINSORUPI	Government Middle School Tigam

49720	750	RIFANSOMJIBREEN	Government Middle School Chainguri Nuh Mewat , Nuh Mewat
49721	750	MOHD ZAID	Government Senior Secondary School Ghasera , Nuh Mewat
49722	750	ROHIT	Government Middle School Kota Khandewla
49723	750	AASHIK HUSSAIN	Government Middle School Rithoda , Nuh Mewat
49724	750	FARAN	Government Senior Secondary School Salahari
49725	750	MIR AYAN AYAN	Government Girl Middle School Habibia Nuh Mewat , Nuh Mewat
49726	750	MOHDAASHAFKHANDOSAMU N	Government Middle School Ibrahim Bas , Nuh Mewat
49727	750	MASTER IMRAN UNG JAFRUDDIN	Government Middle School Sorikh , Nuh Mewat
49728	750	VANSHIKA	Government Girl Middle School Kota Khandewla , Nuh Mewat
49729	750	MISS HUMERA	Government Girls Middle School Salahari , Nuh Mewat
49730	750	SAMIADOSHAMUDEEN	Government Middle School Chainguri Nuh Mewat , Nuh Mewat
49731	750	MISS MANTASHA MANTASHA	Government Girl Middle School Habibia Nuh Mewat , Nuh Mewat
49732	750	NASIMA	Government Middle School Bhand , Nuh Mewat
49733	750	KHUSHNUMADOUJAWED	Government Middle School Ibrahim Bas
49734	750	SAHISTA	Government Middle School Rithoda , Nuh Mewat
49735	750	WAFANA	Government Girl Senior Secondary School Ghasera , Nuh Mewat
49736	750	FASAL MG JEBUM	Government Middle School Satputiyaka
49737	750	SOFIYA MG SAHRUNA	Government Middle School Satputiyaka , Nuh Mewat
49738	750	SARMA	Government Middle School B A Pur , Nuh Mewat
49739	750	SAYDA	Government Middle School Shekhpur , Nuh Mewat
49740	750	RIFANSOQIBAL	Government Senior Secondary School Fath Khori
49741	750	KHUSNUMA DO SHARIF OF SHARIF	Government Senior Secondary School Fath Khori , Nuh Mewat
49742	750	SAHILA	Government Senior Secondary School Baded , Nuh Mewat
49743	750	ANJALI	Government Middle School Jhammuwas
49744	750	DIPESH	Government Middle School Jhammuwas
49745	750	RAMI S/O ROOP CHAAND RAJESH DEVI	Government Middle School Jhammuwas , Nuh Mewat

Total Students Nuh (Newat) 9th to 12th (2023-24) Secondary Education			
Sr.No.	Credit Amount	Full Name in English	Address Line2
1	1450	AMANAT	Government Girls Senior Secondary School Taoru
2	1450	NIKI	Government Girls Senior Secondary School Taoru
3	1450	HIMANSHI	Government Girls Senior Secondary School Taoru
4	1450	MIRAKSHI	Government Girls Senior Secondary School Taoru
5	1450	POOJA	Government Girls Senior Secondary School Taoru
6	1450	KHUSHBU	Government Girls Senior Secondary School Taoru
7	1450	TANNU	Government Girls Senior Secondary School Taoru
8	1450	REEMA RANI	Government Girls Senior Secondary School Taoru
9	1450	KUSUM	Government Girls Senior Secondary School Taoru
10	1450	MUSKAN	Government Girls Senior Secondary School Taoru
11	1450	PRIYA	Government Girls Senior Secondary School Taoru
12	1450	SHIVANI	Government Girls Senior Secondary School Taoru
13	1450	SILONI	Government Girls Senior Secondary School Taoru
14	1450	VANSHIKA	Government Girls Senior Secondary School Taoru
15	1450	MUSKAN	Government Girls Senior Secondary School Taoru
16	1450	SONYA	Government High School Alduka
17	1450	NAVITA	Government High School Alduka
18	1450	RAMESHWAR	Government High School Alduka
19	1450	RAKHI	Government High School Alduka
20	1450	BANTI	Government Senior Secondary School Feroz Pur Namak
21	1450	WINKU	Government Senior Secondary School Feroz Pur Namak
22	1450	ANKUSH	Government Senior Secondary School Ujina
23	1450	SUMIT	Government Senior Secondary School Ujina
24	1450	SOMAY SINGH	Government Senior Secondary School Ujina
25	1450	MANJEET	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
26	1450	NITIN	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
27	1450	ABHISHER	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
28	1450	PARSHANT	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
29	1450	KRISH	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
30	1450	RANBIR SINGH	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
31	1450	ANIKET	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
32	1450	JEET	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
33	1450	DAVID	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
34	1450	DIPKA	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
35	1450	RAVI KUMAR	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
36	1450	SUMIT	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
37	1450	ROHIT	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
38	1450	RAJULMAR	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
39	1450	SOURAV	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
40	1450	KULDEEP	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
41	1450	DHARA SINGH	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
42	1450	VIKASH	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
43	1450	CHINTU	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
44	1450	HIMANSHU	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
45	1450	ANSHU	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
46	1450	VIKASH	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
47	1450	ROGESH	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
48	1450	SANINA	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
49	1450	SANNI	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
50	1450	SUMIT KUMAR	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Taoru
51	1450	AMIT	Government Senior Secondary School Hasan Pur Taoru
52	1450	GUNJAN	Government Senior Secondary School Hasan Pur Taoru
53	1450	KAPIL	Government Senior Secondary School Hasan Pur Taoru
54	1450	LOKESH	Government Senior Secondary School Hasan Pur Taoru
55	1450	LALIT	Government Senior Secondary School Ghassera
56	1450	ATUL	Government Senior Secondary School Ghassera
57	1450	JATIN	Government Senior Secondary School Chhapera
58	1450	KHUSHI	Government Senior Secondary School Chhapera
59	1450	AJIT	Government Senior Secondary School Chhapera
60	1450	MANISH	Government Senior Secondary School Chhapera
61	1450	KEERTI	Government Senior Secondary School Chhapera
62	1450	PAWAN	Government Senior Secondary School Chhapera
63	1450	NAVYEN	Government Senior Secondary School Chhapera
64	1450	GOURAV	Government Senior Secondary School Singar
65	1450	SHIVAM	Government Senior Secondary School Sakras
66	1450	RITIK	Government Senior Secondary School Sakras
67	1450	SAMBER	Government Senior Secondary School Sakras
68	1450	ANJANI	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Saroli
69	1450	SONAM	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Saroli
70	1450	MONIKA	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Saroli
71	1450	MOHIT KUMAR	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Saroli
72	1450	VEER	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
73	1450	SHIVKUMAR	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
74	1450	SHIVA	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
75	1450	VISHAL	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
76	1450	PRINS	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
77	1450	HIMESH	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
78	1450	HIMANSHU	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
79	1450	PRITHVI	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
80	1450	RAAJ	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
81	1450	FARVEEN KUMAR	Government Model Sanskriti Senior Secondary School Nagina
82	1450	RAASHI	Government Girls Senior Secondary School Phangwan

83	1450	RAMI	Government Girls Senior Secondary School Pinangwan
84	1450	SADHNA	Government Girls Senior Secondary School Pinangwan
85	1450	(YOTI)	Government Girls Senior Secondary School Pinangwan
86	1450	KUMKUM	Government Girls Senior Secondary School Pinangwan
87	1450	LATA	Government Girls Senior Secondary School Pinangwan
88	1450	MONIKA	Government Girls Senior Secondary School Pinangwan
89	1450	MONIKA	Government Girls Senior Secondary School Pinangwan
90	1450	LALITA	Government Girls Senior Secondary School Pinangwan
91	1450	MUSRAAM	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
92	1450	SARJNA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
93	1450	LATIKA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
94	1450	KHUSHI	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
95	1450	POONAM	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
96	1450	KUSUM	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
97	1450	SONIA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
98	1450	MONIKA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
99	1450	MISHA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
100	1450	KAJAL	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
101	1450	SANIYA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
102	1450	PABUJ	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
103	1450	RASHI	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
104	1450	TATISH RAMI	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
105	1450	SONYA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
106	1450	MONIKA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
107	1450	ISHA	Government Girls Senior Secondary School Ferozpur Jharka
108	1450	AMAN	Government Senior Secondary School Bichhor
109	1450	VUETA	Government Senior Secondary School Bichhor
110	1450	ANJU	Government Senior Secondary School Bichhor
111	1450	PARMOD	Government Senior Secondary School Bichhor
112	1450	AJAY	Government Senior Secondary School Bichhor
113	1450	RAKH	Government Senior Secondary School Bichhor
114	1450	DIPANSHU	Government Senior Secondary School Bichhor
115	1450	PARYEEN KUMAR	Government Senior Secondary School Bichhor
116	1450	DUSHYANT	Government Senior Secondary School Bichhor
117	1450	LALIT	Government Senior Secondary School Bichhor
118	1450	RAJMI	Government Senior Secondary School Bichhor
119	1450	GIRNAJ	Government Senior Secondary School Badesi
120	1450	RAJMI	Government Senior Secondary School Badesi
121	1450	SAKSHI	Government Senior Secondary School Indri
122	1450	YOGENDERA	Government Senior Secondary School Ferozpur Jharka
123	1450	MONU	Government Senior Secondary School Ferozpur Jharka
124	1450	PANKAJ	Government Senior Secondary School Ferozpur Jharka
125	1450	NEERAJ	Government Senior Secondary School Ferozpur Jharka
126	1450	AMIT	Government Senior Secondary School Ferozpur Jharka
127	1450	KULVRAJ SINGH	Government Senior Secondary School Ferozpur Jharka
128	1450	ANKIT	Government Senior Secondary School Ferozpur Jharka
129	1450	SURAJ	Government Senior Secondary School Purnana
130	1450	MANISH KUMAR	Government Senior Secondary School Purnana
131	1450	INDREET	Government Senior Secondary School Purnana
132	1450	ROHIT	Government Senior Secondary School Purnana
133	1450	PRINCE	Government Senior Secondary School Purnana
134	1450	JATIN	Government Senior Secondary School Purnana
135	1450	SAGAR	Government Senior Secondary School Purnana
136	1450	GORAV KUMAR	Government Senior Secondary School Purnana
137	1450	MANISH KUMAR	Government Senior Secondary School Purnana
138	1450	VISHNU	Government Senior Secondary School Purnana
139	1450	SUMIT	Government Senior Secondary School Purnana
140	1450	SUMIT	Government Senior Secondary School Purnana
141	1450	AMIT	Government Senior Secondary School Purnana
142	1450	ABKASH	Government Senior Secondary School Purnana
143	1450	SAGAR	Government Senior Secondary School Purnana
144	1450	SUMIT	Government Senior Secondary School Purnana
145	1450	BAJRIK	Government Senior Secondary School Purnana
146	1450	AMIT	Government Senior Secondary School Purnana
147	1450	HARTEL	Government Senior Secondary School Pinangwan
148	1450	SANAM	Government Senior Secondary School Pinangwan
149	1450	ARJUN	Government Senior Secondary School Pinangwan
150	1450	KARAN	Government Senior Secondary School Pinangwan
151	1450	AJAY	Government Senior Secondary School Pinangwan
152	1450	PRADDEEP	Government Senior Secondary School Pinangwan
153	1450	RAGHVEER	Government Senior Secondary School Pinangwan
154	1450	NISHA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
155	1450	SHALINI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
156	1450	NAMRATA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
157	1450	JHALAK	Government Girls Senior Secondary School Purnana
158	1450	KAVITA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
159	1450	SAPNA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
160	1450	RIYA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
161	1450	PRIVA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
162	1450	GARCEMA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
163	1450	PLIJA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
164	1450	ANJU	Government Girls Senior Secondary School Purnana
165	1450	ONI VATI	Government Girls Senior Secondary School Purnana
166	1450	ANSHIKA	Government Girls Senior Secondary School Purnana
167	1450	VANDANA	Government Girls Senior Secondary School Purnana

40079	450	NASIMA	Government Model Sanskriti Primary School F.P. Banarsi
40080	225	NAVED	Government Primary School Bari
40081	75	NAVED	Government Primary School Chhabli Kajan
40082	225	NAVED	Government Model Sanskriti Primary School Singar
40083	500	NAZMA	Government Middle School Nargli Nah Mewat
40084	300	NIDA	Government Primary School Maholi
40085	275	OSAD KHAN	Government Model Sanskriti Primary School Akera
40086	775	QVAISH MOHAMMAD	Government Primary School Banarsi
40087	450	PARI	Government Primary School Aduka
40088	225	PARVEJ	Government Model Sanskriti Primary School Sakras
40089	225	PARVEJ	Government Model Sanskriti Primary School Akbarpur
40090	150	PARVEJ KHAN	Government Model Sanskriti Primary School Akery
40091	450	PARWANA	Government Primary School Dhanu
40092	300	PARWANA	Government Primary School Chilla
40093	225	PRIT	Government Primary School Aitkila
40094	450	PRIYANKA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Singar
40095	450	RAARIYA	Government Primary School Faleindi
40096	200	RAFI	Aarshi Model Senior Secondary School Bawala
40097	225	REHAN	Government Primary School Sunari
40098	225	RIHAN	Government Primary School Amira Bad
40099	200	RIHAN	Government Middle School Jafabad
40100	150	RIHAN	Government Primary School Baharza
40101	225	RIHAN	Government Primary School Ghata Shamshabad
40102	450	RIHANA	Government Primary School Chhara
40103	75	RISAL	Government Model Sanskriti Primary School Namb
40104	225	RIVAZ	Government Primary School Amira Bad
40105	225	RIVAZ	Government Primary School Gulatta
40106	300	ROFIZA	Government Primary School Thek
40107	150	RDHOD	Government Primary School Sarabhas IP Jhina Nah
40108	800	RUBI TARSSUM	Government Primary School Alawatgur
40109	450	RUCHIKA	Government Model Sanskriti Primary School Tauru
40110	150	RUFAN	Government Primary School Chlawal
40111	150	RUFAN	Government Primary School Babalheri
40112	600	RUKAYA	Government Girls Middle School Sultangpur Nah
40113	450	RUKSAR	Government Girls Model Sanskriti Primary School Singar
40114	450	RUKSAR	Government Primary School Ibrahimbas
40115	450	RUKSAR	Government Primary School Chlawal
40116	300	RUMANA	Government Primary School Gulatta
40117	300	RUMIZA	Government Primary School Dhanu
40118	300	SAABRIN	Government Primary School Bhan
40119	150	SAAD	Government Primary School Pipaki
40120	300	SAADIA	Government Primary School Uttar
40121	450	SAARA	Government Primary School Faleindi
40122	450	SAAMEEN	Government Primary School Ragpur
40123	450	SABREEN	Government Primary School Salamba
40124	450	SABRIN	Government Primary School Chhabli Kajan
40125	600	SABRCON	Government Middle School Gadhola
40126	450	SADAF	Government Girls Model Sanskriti Primary School Bichore
40127	150	SADIK	Government Primary School Chandraka
40128	300	SADIKA	Government Primary School Rajal Mee
40129	450	SADIYA	Government Model Sanskriti Primary School Akbarpur
40130	450	SADIYA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Singar
40131	300	SADIYA	Government Primary School Tain
40132	300	SAZIYA	Government Primary School Dhanu
40133	450	SAFANA	Government Primary School Chandraka
40134	450	SAFIYA	Government Primary School Chandraka
40135	450	SAFIYA	Government Primary School Badarpur
40136	150	SAFIYA	Government Primary School Ghata Shamshabad
40137	225	SAHIB	Government Primary School Kharta Puchara
40138	300	SAHIL	Aarshi Model Senior Secondary School Bawala
40139	225	SAHNI	Government Model Sanskriti Primary School Ragpur
40140	300	SAHNA	Government Primary School Dalawan
40141	300	SAHNA	Government Primary School Gulatta
40142	300	SAHISTA	Government Model Sanskriti Primary School Nai Branch
40143	450	SAHMAZ	Government Primary School Chandraka
40144	300	SAHUMA	Government Primary School Gyanvahaan
40145	225	SAHNWAI	Government Primary School Bhaluka
40146	450	SAHRANA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Bichore
40147	450	SAHREEN	Government Primary School Banarsi
40148	300	SAHREEN	Government Primary School Tain
40149	450	SAHREENA	Government Primary School Bajarka
40150	450	SAHRINA	Government Primary School Tundlaka
40151	450	SARBA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Chawli
40152	150	SAID	Government Model Sanskriti Primary School Akera
40153	225	SAIF	Government Primary School Nishara
40154	150	SAIF ALI	Government Primary School Dhanu
40155	225	SAIFAN	Government Primary School Banarsi
40156	150	SAIFAN	Government Primary School Babalheri
40157	450	SAIFANA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Bichore
40158	225	SAPREEN	Government Primary School Sultan Pur Nah
40159	300	SAPREEN	Government Primary School Banarsi
40160	450	SAPREENA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Bichore
40161	300	SARMA	Government Primary School Banarsi
40162	300	SARMEEN	Government Primary School Banarsi
40163	450	SAISTA	Government Primary School Gadhola

40164	225	SAJID KHAN	Government Model Sanskriti Primary School Nal Branch
40165	450	SALIYA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Chanderni
40166	300	SAKIELLA	Government Primary School Chikawal
40167	450	SAKIPA	Government Primary School Ghasera
40168	225	SALMAN KHAN	Government Primary School Dihana
40169	300	SANA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Bichhora
40170	450	SAMAJLA	Government Primary School Balai
40171	300	SAMAR	Government Primary School Ghasera
40172	150	SAMEER	Government Primary School Ustaka
40173	150	SAMIM	Government Primary School Bubalheri
40174	150	SAMIR	Government Primary School Chandraka
40175	225	SAMR	Government Primary School Dewla Negli
40176	450	SAMSH KHAN	Government Primary School Dagar Dham
40177	600	SAMREEN	Government Girls Middle School Sultanpur Nuh
40178	450	SAMREEN	Government Girls Model Sanskriti Primary School Bichhora
40179	225	SAMJUN	Government Primary School Barika
40180	450	SANA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Singar
40181	450	SANA	Government Primary School Kansali
40182	450	SANA	Government Model Sanskriti Primary School Tapra
40183	300	SANA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Chanderni
40184	300	SANA	Government Primary School Utton
40185	300	SANA	Government Primary School Bubalheri
40186	300	SANA	Government Primary School Bubalheri
40187	300	SANA	Government Model Sanskriti Primary School Lahnwari
40188	300	SANA	Government Primary School Rangala Rajpur
40189	300	SANAPA	Government Primary School Ustaka
40190	450	SANIYA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Singar
40191	225	SANIYA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Singar
40192	300	SANDOYA	Government Girls Middle School Sultanpur Nuh
40193	225	SARAN	Government Primary School Adbar
40194	225	SARFRAJ	Government Model Sanskriti Primary School Akbarpur
40195	225	SARHAN HUSSAIN	Government Model Sanskriti Primary School Akara
40196	150	SARIF	Government Primary School Beli
40197	450	SARMEEN	Government Girls Model Sanskriti Primary School Singar
40198	450	SARMEEN	Government Primary School Chikawal
40199	300	SARMEEN	Government Primary School Sikarpur
40200	450	SARMEEN	Government Girls Model Sanskriti Primary School Singar
40201	225	SAVAAN	Government Model Sanskriti Primary School Taoru
40202	450	SAWANA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Singar
40203	450	SAZIA	Government Primary School Bajarka
40204	300	SEFREEN	Government Primary School Baransi
40205	450	SEHANJUM	Government Primary School Balai
40206	450	SEHNUMA	Government Primary School Bajarka
40207	150	SEHNWAI	Government Primary School Dihana
40208	150	SEHWAN	Government Primary School Bubalheri
40209	225	SEHWAN KHAN	Government Primary School Bubalheri
40210	150	SEMA	Government Primary School Ghasera
40211	450	SEVANA	Government Primary School Bawla
40212	300	SEVANA	Government Primary School Tain
40213	150	SEWAN	Government Model Sanskriti Primary School Akara
40214	225	SEWAN	Government Primary School Chikawal
40215	150	SHAD	Government Primary School Chikawal
40216	150	SHAD ALI	Government Primary School Basai Meo
40217	600	SHAGLITA	Government Middle School Godhola
40218	300	SHAIBA	Government Girls Primary School Shikrawa
40219	150	SHANAYAT	Government Primary School Chandraka
40220	225	SHANWAI	Government Primary School Chikawal
40221	225	SHIYAN	Government Primary School Rangala Rajpur
40222	450	SHIFA	Government Primary School Chikawal
40223	450	SHIFA	Government Primary School Allah Bass
40224	225	SHIYAT	Government Primary School Mandarka
40225	600	SIFA	Aarohi Model Senior Secondary School Bawala
40226	450	SIFA	Government Primary School Halandi
40227	450	SIFA	Government Model Sanskriti Primary School Rajpur
40228	450	SIFA	Government Primary School Balai
40229	450	SIFA	Government Primary School Balot Patti
40230	150	SIFAN	Government Primary School Dihana
40231	150	SIFAN	Government Primary School Faleindi
40232	225	SIFAN	Government Primary School Ganduri
40233	150	SIFAN	Government Model Sanskriti Primary School Rajpur
40234	300	SIFANA	Government Primary School Timwara
40235	450	SIFRANA	Government Girls Model Sanskriti Primary School Bara
40236	450	SIHANA	Government Primary School Ghata Shamshabad
40237	450	SIMRAN KHATUN	Government Primary School Balot Patti
40238	300	SIRATAJ	Government Primary School Kuldihara
40239	450	SIZA	Government Primary School Amina Bad
40240	300	SOPIYA	Government Primary School Dihana
40241	450	SORIYA	Government Primary School Noshara
40242	150	SORIYA	Government Primary School Firsozpur Meo
40243	450	SORIYA	Government Primary School Gusbethi
40244	450	SOFIYA KHATUN	Government Primary School Chandraka
40245	300	SOFIYA SAMREEN	Government Primary School Chikawal
40246	300	SOFIYANA	Government Primary School Mahoi

न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करना

78. श्री बलराज कुंडू: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएं कि:

- (क) क्या राज्य में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा
- (ख) क्या किसानों को डी.ए.पी./यूरिया/उर्वरकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है तथा विशेष कीटनाशक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): महोदय,

- (क) न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा तय और अधिसूचित किया जाता है। इसलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के संबंध में कोई भी निर्णय भारत सरकार का शेषाधिकार है। हालाँकि, राज्य सरकार राज्य में धान, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, तिल, उर्द, अरहर, कपास, गेहूं, जौ, सरसों, सूरजमुखी, चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीद का विवरण अनुलग्नक 'ए' में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, खरीफ 2021 से बाजार दरों और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर को प्रदान करने के लिए भावांतर भरपाई योजना बाजरा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। भावांतर भरपाई योजना बाजरा के तहत, 440.02 करोड़ रुपये खरीफ 2021 और 390.20 करोड़ रुपये की राशि खरीफ 2022 के दौरान डीबीटी के माध्यम से क्रमशः 2.43 लाख तथा 2.76 लाख किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।

राज्य सरकार ने 21 नष्ट होने वाली बागवानी फसलों की बाजार में कम कीमत के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 01.01.2018 से भावांतर भरपाई योजना भी शुरू की है। विवरण अनुलग्नक 'बी' में दिया गया है।

- (ख) रबी 2023-24 सीज़न के दौरान राज्य में डीएपी/यूरिया/उर्वरक की कोई कमी नहीं है। दिनांक 15.12.2023 तक 6.70 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 2.04 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मात्रा किसानों को वितरित की जा चुकी है और राज्य में 1.55 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 0.34 लाख मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है। राज्य कृषि विभाग

नियमित रूप से उर्वरकों की उपलब्धता, बिक्री और स्टॉक की स्थिति की निगरानी कर रहा है और कीटनाशकों सहित कृषि सामग्री की किसानों को जबरन बिक्री के मामले में दोषियों के खिलाफ 2023-24 के दौरान 53 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 31 लाइसेंस निलंबित और 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

वर्ष	बन (एकर/घंटे)	क्षेत्र (एकर/घंटे)	बन (एकर/घंटे)	मक (एकर/घंटे)	नुरबगुची (एकर/घंटे)	बरसों (एकर/घंटे)	मूंग (एकर/घंटे)	चना (एकर/घंटे)	चना (एकर/घंटे)	अनुसूचक ए	
										बन (राशि)	बन (राशि)
2015-16	42.70	67.70	5,094		4,164	-	-	-	-	-	-
2016-17	51.48	67.54	6,341		4,784	-	-	-	-	-	-
2017-18	59.57	74.25	31,449		8,459	36,942	-	-	-	-	-
2018-19	58.82	87.57	1,81,009	175	4,926	2,69,196	225	-	-	-	-
2019-20	64.71	93.60	3,18,821		13,196	6,39,622	3,752	380	-	-	6,22,808
2020-21	56.54	74.01	7,78,908	406	16,489	7,47,633	1,089	30,637	648	-	30,57,808
2021-22	55.30	84.93	**	244	4,065	*	1,129	*	*	*	*
2022-23	59.35	41.85	81,213 +**		-	*	-	1,240	*	*	*
2023-24	57.34	62.90	3,61,099		-	5,38,416	-	-	*	*	17,855

* बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक

** बाबासाहेब नरपाई योजना

*** बाजार भाव अधिक होने के कारण बी.आर.ए. उपयुक्त क्षेत्रों में खरीद नहीं हो सकी।

वर्ष	व्यक्ति	पंजीकृत विद्यार्थी	श्रेणियाँ पंजीकृत	बहुसंख्यक जाति		
				संख्या	संख्या	प्रति (वर्ष)
2017-18	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2018 तक	4,435	18,789	उत्तर	565	12.68
2018-19	31 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 तक	17,930	66,301	बहु	3,244	919.34
				पुनर्जाति	169	21.35
2019-20	15 सितंबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक	36,981	94,830	बहु	289	59.24
				उत्तर	5	23.41
2020-21	1 सितंबर 2020 से अक्टूबर 2021	30,170	54,120	-	-	-
2021-22	1 सितंबर 2021 से अक्टूबर 2022	56,089	1,20,666	बिन्दी	1	0.81
				बिन्	1	0.28
				शेक	13	3.65
				शिक्षा बिन्	16	2.84
				बिन्	2	0.70
				उत्तर	92	16.08
				बहु	4	11.74
				पुनर्जाति	92	25.00
				पात्र	3	8.86
				बहु	984	319.41
2022-23	अप्रैल 2022 से 30.11.2023 तक	99,451	1,28,876	शेक	1	2.18
				बिन्	17	16.70
				पात्र	6	0.17
				बहु	4,851	888.19
2023-24	सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024	14,687	31,265		2,981	188.76
	अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024				4,271	362.96
		1,19,793	4,86,725	कुल	16,353	6,389.11

राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कृत शिक्षकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना

79. श्री बलराज कुंडू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएं कि :-

(क) क्या राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कृत शिक्षकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है:-

- नई तबादला नीति में पांच अंक;
- पूर्व प्रथानुसार सेवा काल में दो वर्ष का विस्तार;
- मुफ्त बस यात्रा;
- टोल फ्री सुविधा;
- 3% आरक्षण कोटा;

(vi) सेवा काल में दो इंक्रीमेंट (वेतन वृद्धि); तथा

(ख) यदि हां, तो इन शिक्षकों को उपरोक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) नहीं श्रीमान जी;

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

.....

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मेट के लिए नीति बनाना

80. श्री बलराज कुंडू : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएं कि : -

(क) क्या यह तथ्य है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले मेट अपनी निम्नलिखित मांगों के लिए दिनांक 6.10.2023 से पंचकूला में हड़ताल पर हैं: -

i) पूरे साल काम मिलना चाहिए ;

ii) 600 रूपये की दिहाड़ी ;

iii) काम के दौरान दुर्घटना होने पर ढाई लाख रुपए ; तथा

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए किसी नीति को बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान, (क) और (ख) हां, मनरेगा योजना को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों के तहत काम करने वाले कुछ मेट अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। मेट मजदूर समिति, नरवाना का पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य मंत्री, हरियाणा तथा सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती कमलेश ढांडा, राज्य मंत्री, हरियाणा ने दूरभाष के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उनके भतीजे का आकस्मिक निधन होने के कारण वे दिनांक 18 व 19 दिसंबर, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

इसी प्रकार श्री राकेश दौलताबाद, विधायक ने ई-मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उन्हें कुछ जरूरी परिस्थितियों के कारण चण्डीगढ़ से बादशाहपुर वापिस जाना पड़ा, इसलिए वे आज दिनांक 18 दिसंबर, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

इसी प्रकार श्री भव्य बिश्नोई, विधायक ने ई-मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उनकी व उनके छोटे भाई की शादी समारोह की तैयारियों की व्यवस्था के चलते वे दिनांक 18 व 19 दिसंबर, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: नीरज शर्मा जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष: नीरज शर्मा जी की किसी भी बात को रिकॉर्ड ना किया जाये।

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज जिन माननीय सदस्यों को शून्यकाल में बोलने का अवसर मिलेगा वे इस प्रकार से हैं। श्री बिशन लाल सैनी, विधायक, श्री लीला राम, विधायक, श्री इंदुराज, विधायक, श्री सुभाष गांगोली, विधायक, श्रीमती निर्मल रानी, विधायक, श्री नयन पाल रावत, विधायक, श्री बलबीर सिंह, विधायक, श्री मामन खान, विधायक, श्री विनोद भ्याना, विधायक, श्री सीता राम, विधायक, श्री नरेन्द्र गुप्ता, विधायक, श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री दीपक मंगला, विधायक और श्री धर्मपाल गोंदर, विधायक हैं। सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी बात चार मिनट में रखने का प्रयास करें। अब श्री बिशन लाल सैनी, विधायक शून्यकाल में अपनी बात रखेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा जीन्द के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर दिनांक 15.12.2023 को सदन में उप मुख्यमंत्री और उनके बीच हुए विवाद का मामला उठाना

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी अनुमति से यह कहना है कि हमने दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को शून्यकाल के दौरान बहुत सारे इशूज रोज किये थे उसमें से एक मामला एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के मुताबिक sexual harassment of the girls का मुद्दा उठाया था। मेरा सदन से अनुरोध है और इस समय सदन के नेता भी उपस्थित हैं। मैंने जो इस संबंध में स्टेटमेंट दी थी मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है। उस दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने खड़े होकर कुछ एलिगेशंस लगाने का प्रयास किया था। मैंने उस समय भी उसका खंडन करने का प्रयास किया था। आज मैं लिखित रूप में अपनी स्टेटमेंट दे रही हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, उस मामले के बारे में हाउस में डिसाईड हो गया कि this will be inquired by the sitting Judge of the Hon'ble High Court इसलिए इस मैटर पर अब हाउस में कोई चर्चा नहीं होगी। (विघ्न)

Smt. Geeta Bhukkal: Speaker Sir, definitely it should be inquired.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, सदन की भी कोई गरिमा होती है। क्या हाउस की प्रोसीडिंग्स की इंकवॉयरी माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज साहब से करवायेंगे? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इस बारे में मैंने डिजीजन नहीं लिया बल्कि हाउस ने डिजीजन लिया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, process to submit notice/ procedure regarding raising of matters of urgent public importance during Zero Hour, इस बारे में हाउस ने तय किया था और इसका प्रोसैस आपने तय किया है? उसमें यह लिखा है कि कोई भी झूठा पर्सनल ऐलिंगेशन नहीं लगायेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने बहन गीता भुक्कल पर पर्सनल एलिंगेशन लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह बात तो इंकवॉयरी में ही पता चलेगी कि यह पर्सनल एलिंगेशन है या नहीं है। इस बात का भी पता चलेगा कि क्या यह झूठा ऐलिंगेशन है या नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप इसको विदूढ़ा करे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, जब तक इस मैटर की इंकवॉयरी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं होगा। (विघ्न)

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन का एक फैक्ट करैक्ट करना चाहूंगा कि मैंने उस दिन वर्ष 2011 कहा था उसको प्रोसीडिंग्स में दिसम्बर, 2012 किया जाये। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, अब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय करैक्ट करेंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker: Hooda Sahib, this is a matter of inquiry. हुड्डा साहब यह डिजीजन हाउस का है कि इस मैटर की इंकवॉयरी करवाई जाये। मैंने हाउस का निर्णय मानते हुए डिजीजन लिया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप किस चीज की इंकवॉयरी करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, जो ऐलिंगेशंज एक-दूसरे पर लगे हैं, उनकी इंकवॉयरी होगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे terms of reference बता दीजिए।

Please let me know the terms of reference.

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, terms of reference यह है कि जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कही है, क्या वह सच है या नहीं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, बहन गीता जी ने कहा है कि गलत है, इनके घर कोई मीटिंग नहीं हुई। (विघ्न)

Mr. Speaker: Hooda Sahib, this will be inquired जो गलत होगा वह इंकवॉयरी के दौरान सामने आ जायेगा। चाहे वह उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से गलत हो या फिर बहन गीता जी की तरफ से गलत हो, इंकवॉयरी के दौरान सामने आ जायेगा।। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, दो और दो चार होते हैं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह बात तो इंकवॉयरी में पता चल जायेगी। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात सुनिए। (विघ्न) हमारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, हमारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं और you are not ready to listen.

Mr. Speaker: I am listening. I am listening everything.

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, please listen for a minute.

(Interruptions) Let me finish. I am not yielding.

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरे बीच में बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, सदन के नेता किसी भी समय इंटरवीन कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) He has got every right.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के नेता बीच में इंटरवीन करेंगे तो फिर मैं अपनी बात कब रखूंगा ?

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात सुन लीजिए। मैं उनके बोलने के बाद आपको दोबारा समय दूंगा। फिर आप क्लैरीफाई कर देना। (विघ्न) हमें लीडर ऑफ दि हाउस का सम्मान करना होगा। (शोर एवं व्यवधान) Leader of the House can interrupt at any time.

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, 15.12.2023 को इस विषय पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद चर्चा करने वाले माननीय सदस्यों ने डिमाण्ड की कि इसमें इन्कवायरी करवाई जाए। पहले कहा गया कि एक समिति बनाई जाए और उससे इन्कवायरी करवाई जाए। बाद में यह सुझाव आया कि इसकी इन्कवायरी किसी सिटिंग जज से करवाई जाए। अब सदन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस मामले पर पहले आपके द्वारा निर्णय हो चुका है कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट एक कमेटी बनाकर इसकी इन्कवायरी करें। आज होम डिपार्टमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट को पत्र लिखने वाला है कि आप एक सिटिंग जज की नियुक्ति करें और उसमें 15.12.2023 की चर्चा में जो बिन्दु आये हैं उन सभी बिन्दुओं को टर्मज ऑफ रेफ्रेंस में लिखा जाए। इसके अलावा अगर इस विषय से संबंधित कोई अन्य विषय भी बाकी रहता हो तो नेता प्रतिपक्ष उसे लिखकर दे दें कि टर्मज ऑफ रेफ्रेंस में यह भी जोड़ा जाए। हम इस विषय की खुले मन से एक सिटिंग जज से इन्कवायरी करवाने के लिए तैयार हैं। इसमें हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप 15.12.2023 को लगाए गए हैं अगर हम आपस में इस तरह से लड़ते-झगड़ते रहेंगे तो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अगर इन्कवायरी की रिपोर्ट तथ्य रूप में हमारे सामने आएगी तो उसके अनुसार जिसके खिलाफ जो कार्यवाही करनी होगी वह हम अवश्य करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, 15.12.2023 को हाउस में बहुत-से आरोप-प्रत्यारोप लगे। यह रूलज के अगेंस्ट है क्योंकि जीरो ऑवर में कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह जीरो ऑवर का मामला नहीं है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह जीरो ऑवर का ही मामला है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह निर्णय जीरो ऑवर के बाद हुआ था। यह निर्णय जीरो ऑवर में नहीं हुआ था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं निर्णय की बात नहीं कर रहा हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह निर्णय जीरो ऑवर में नहीं हुआ था। ऐलिंगेशंज, काउंटर ऐलिंगेशंज जीरो ऑवर के बाद लगे थे। यह जीरो ऑवर का मामला नहीं था। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को सुनने से पहले ही जवाब देने लग गये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह मामला जीरो ऑवर का नहीं था। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को सुन लो। अगर मैं गलत बात कहूं तो कह देना। आप मेरी बात को पहले ही क्यों काट रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अगर आप कोई गलत बात कहेंगे तो मुझे बीच में इंटरुप्ट तो करना ही पड़ेगा। यह मामला जीरो ऑवर का नहीं था। इसमें जो निर्णय हुआ था वह बाद में हुआ था। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपका काम सबको प्रोटैक्शन देना और राइट देना है लेकिन आप केवल सरकार की प्रोटैक्शन कर रहे हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं हुड्डा साहब। मैं सरकार की प्रोटैक्शन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं केवल फैक्ट्स को राइट कर रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अब आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बोलिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह जीरो ऑवर का मामला था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह जीरो ऑवर का मामला नहीं था। यह डिसीजन जीरो ऑवर के बाद हुआ था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप फिर से बोल रहे हो। जो हुआ था उसे आप बाद में बता देना। पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हो ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं गलत नहीं बल्कि सही फैक्ट्स रख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, हाउस में जो निर्णय हुआ है वह जीरो ऑवर में नहीं हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह जीरो ऑवर का मामला है। माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय ने इसे जीरो ऑवर में उठाया था। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला जीरो ऑवर की बजाय दोपहर बाद 3:05 बजे आया था। यह विषय जीरो ऑवर के बाद आया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, जीरो ऑवर लंच से पहले हुआ था और यह डिसीजन 3:05 बजे हुआ था। यह तो ऑन रिकॉर्ड है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप बताइये कि उन्होंने जीरो ऑवर में क्या कहा ? सवाल यह है कि माननीय सदस्या पर जो फाल्स ऐलिगेशंज लगाए गए थे वे जीरो ऑवर में लगाए गये थे या नहीं ? (विघ्न) आप इस विषय से संबंधित प्रोसीडिंग्ज निकलवाइये। (विघ्न) I want to see the proceedings of Zero Hour.

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय को जीरो ऑवर के बाद उठाया था। (विघ्न) यह ऑन रिकॉर्ड है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड ही मांग रहा हूँ। I will go by the record. आप जीरो ऑवर की सारी प्रोसीडिंग्ज निकलवाइये। इससे पता चलेगा कि जीरो ऑवर में माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय ने फाल्स ऐलिगेशंज लगाए या नहीं। आप इस पर 'हां' या 'न' में जवाब दीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है हुड्डा साहब, मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दिखवा देता हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे सवाल नोट कर लें और बाद में उनका जवाब दे देना। मेरा सवाल है कि माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय ने जो फाल्स ऐलिगेशंज लगाए वे जीरो ऑवर में लगाये या नहीं ? इसके अलावा माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय ने ऐलिगेशन लगाया कि वर्ष 2005 में भी ऐसा ही हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उस प्रिंसिपल का रिकॉर्ड है। वर्ष 2005 में तो वह सरकारी नौकरी में ही नहीं था। वह तो वर्ष 2008 में सरकारी नौकरी में आया था। यह ऑन रिकॉर्ड है। यह आदमी वर्ष 2005 में सरकारी नौकरी में ही नहीं था। ये ऐलिगेशन लगा रहे हैं कि वर्ष 2005 में यह इंसीडेंस हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मेरा कहना यह है कि हाउस की गरिमा बनाए रखें। आप संबंधित आदमी की इन्कवायरी करवाएं कि इसने शुरू से क्या किया है? लेकिन जो हाउस की प्रोसिडिंग्स हैं उसमें हाउस की गरिमा यह है कि अपनी बात को वापिस करवाएं या जो पर्सनल ऐलिगेशंज लगाए हैं, उनको डिलीट करवाएं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसमें हाउस ने इन्कवायरी मार्क कर दी है और यह हाउस ने तय किया है। यह हाउस का रैजोल्यूशन है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा बनाएं रखें। यह आपकी जिम्मेवारी है। इसमें आपने सदन की गरिमा से कम्परोमाईज किया है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसमें जो निर्णय किया गया है वह हाउस ने किया है। यह निर्णय मैंने नहीं किया है। इसमें जो निर्णय किया है वह हाउस ने किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, अगर लोक सभा में भी कभी ऐसा कोई मामला होता है तो उसमें कभी हाई कोर्ट का जज इन्कवायरी नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, क्या आप यह चाहते हैं कि इस मामले की इन्कवायरी न हो?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्कवायरी हो लेकिन टर्म्ज ऑफ रैफरेंस क्या हो?

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसमें टर्म्ज ऑफ रैफरेंस तो यही है कि जो आपस में एक-दूसरे पर ऐलिगेशंज लगाए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इसमें उस आदमी की टर्मज ऑफ रैफरेंस होनी चाहिए जिसके खिलाफ यह मामला है कि उसने शुरू से क्या किया है? वह टर्मज ऑफ रैफरेंस है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, हमने उसकी इन्कवायरी नहीं करनी है। हमने तो जो काउंटर ऐलिंगेशंज लगे हैं उसकी इन्कवायरी करनी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो एक और हाई कोर्ट के जज से इन्कवायरी करवा लें।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह बात मैं तय नहीं करता बल्कि यह तो सदन तय करता है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा कि वह आदमी वर्ष 2005 में नौकरी में नहीं था। बल्कि मैंने यह कहा था कि वह वर्ष 2005 में जहां पर नौकरी में था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह बात हाउस ने तय की है। हाउस जो तय करेगा मैं वह काम करवाऊंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज उस फैक्ट पर खड़ा हूं कि वह वर्ष 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में था उसकी भी इन्कवायरी होनी चाहिए। उसको इन्होंने ही वर्ष 2008 में प्रिंसिपल भर्ती किया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, वह आदमी वर्ष 2005 में सरकारी नौकरी में नहीं था।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 के बाद वर्ष 2012 में ये इंसिडेंट दोबारा से हुआ। इसमें तथ्य वही है और वैसे ही है और यह सत्य है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इन्कवायरी मांग ली है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इन्कवायरी में सारे तथ्य आएं। ये इन्कवायरी से क्यों डर रहे हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इन्कवायरी से कोई नहीं डर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि इनकी इन्कवायरी करवाएं।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि ये इन्कवायरी करवा लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इसमें पर्सनल ऐलिगेशंस यह लगाया गया है कि माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल के घर पर बैठकर कम्परोमाईज हुआ है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसमें इन्कवायरी में सभी बातें सामने आ जाएंगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को लिखकर दे दें कि घर पर मीटिंग हुई थी।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसमें जज साहब इन्कवायरी करेंगे इसलिए आप सभी चीजें लिखित में दे दें।

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, otherwise withdraw it. That is the grace of the House. False allegation will not be tolerated. Otherwise, we will..... (noise and interruption)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री हुड्डा जी को बताना चाहूंगा कि I still stand with my point कि वर्ष 2005 में सिमिलर नेचर का वाक्या हुआ था और वर्ष 2011 की बजाए वर्ष 2012 में भी हुआ था। I still stand with the same.

श्रीमती गीता भुक्कल: माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बैठ जाना चाहिए। He is not a Parliamentary Minister and not an Education Minister.

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसमें मुझे नहीं लगता कि once the House has decided कि इस मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इन्कवायरी करवा लीजिए उसमें एक-एक चीज क्लीयर हो जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है?

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, हम प्रिविलेज मोशन मूव करते हैं।

श्री अध्यक्ष: गीता जी, आप किस मामले में प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहते हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले में करेंगे। This is our right. We will move privilege motion against him.

Mr. Speaker: You have the right and you can move and the House will decide it.

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, we will move privilege motion because we are forced to do it. ये विदड़ा कर लें तो बात खत्म हो जाएगी और गरिमा बनी रह जाएगी। यह फाल्स ऐलिंगेशन लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष:हुड्डा साहब, आपका जो राईट है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि विदड़ा किस चीज का है? मैं आज भी खड़ा हूँ। क्या ये इन्कवायरी से डर रहे हैं? यह काम इनके राज में हुआ है। इन्होंने उसको बचाया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, यह झूठा ऐलिंगेशन लगाया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, क्या ये इन्कवायरी से डर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये प्रूव हो जाए कि डिप्टी डायरेक्टर इन्कवायरी करने के लिए गयी थी तो फिर क्या कहेंगे?

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह बात मैं डिसाईड नहीं करूँगा कि इसमें कौन झूठा है? इसको मैं डिसाईड नहीं करूँगा। Let the sitting Judge decide it.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, at that time I was not there. अन्यथा मैं यह काम नहीं होने देता।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप एक बात सुन लें कि once the House has decided it....

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि डी.डी.आर. कटी थी तो उसका 2 साल के बाद रिकार्ड ही नहीं रहता है। ये बताएं कि डी.डी.आर. कहां से लाए हैं? अगर डी.डी.आर. कटती है और वह एफ.आई.आर. में कन्वर्ट न हो तो 2 साल के बाद उसका रिकार्ड खत्म हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह बात ठीक है। मेरा यह कहना है कि हाउस ने जो चीज डिसाईड की है क्या उसमें आपको लगता है कि इन्कवायरी नहीं होनी चाहिए या इससे सहमत नहीं हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्क्वायरी होनी चाहिए लेकिन टर्मज ऑफ रफरेंस पर होनी चाहिए और उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप इन्क्वायरी को होने दें। इसमें दिक्कत क्या है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं टर्मज ऑफ रैफरेंस की बात कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप मुझे लिखकर दे दें कि यह टर्मज ऑफ रैफरेंस होनी चाहिए। हम उस पर विचार कर लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एक ही बात होनी चाहिए। उस आदमी के खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, यहां पर उसके खिलाफ इन्क्वायरी का कोई रैफरेंस का मतलब नहीं है। यहां पर उस आदमी के प्रति ऐसी कोई बात नहीं आई है। जो हमने यहां पर इन्क्वायरी मार्क की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ लेकिन आप हमारे हाउस की बात की गरिमा रखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हाई कोर्ट का जज फैसला करेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : House is to decide, I have not decided. House has decided if house feels. अगर आपको लगता है कि ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आप हाउस की सैंस ले लो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आयेंगे।

Mr. Speaker : That is your right. आपका राईट बनता है। House will decide the fate of the(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारा यह राईट बनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आईये। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। House will decide it. (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Geeta Bhukkal : Speaker Sir, I stands by जो मैंने उस दिन बोला था for the terms of reference.

Shri Bhupinder Singh Hooda : On the terms of reference. What are the terms of references. Let the House discuss the terms of reference. अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी प्रोसीडिंग्स पढ़ ली और terms of reference भी पढ़ लिया ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, Terms of reference ये whether the allegation and counter allegation are right or wrong this is to be decided by the sitting judge. यह बात इन्क्वायरी के अंदर आ जायेगी । अगर उनके पास फैक्ट्स हैं तो वे रख देंगे । अगर इनके पास फैक्ट्स हैं तो ये रख देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि Shri Somnath Chatterjee was the Speaker और उनको सुप्रीम कोर्ट ने समन दिया था but he refused. (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bharat Bhushan Batra : Assembly proceedings will be decided by the sitting Judge ? क्या कभी आज तक ऐसा पार्लियामेंट में हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, यह डिसेजन हाउस का है । यह मेरा डिसेजन नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम भी तो हाउस के मैम्बर हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है । (शोर एवं व्यवधान) जो सिटिंग जज से इन्क्वायरी का डिसेजन हुआ, वह हाउस ने किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप करवाओ ।

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस को यह लगता है और मुझे हाउस जो आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि आप सिटिंग जज से इन्क्वायरी करवाओ लेकिन पहले उस प्रिंसीपल के खिलाफ भी इन्क्वायरी करवाओ ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, यहां पर प्रिंसीपल का कोई मैटर नहीं है ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात से और सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2023 तक इस प्रिंसीपल वाले मामले की भी इन्क्वायरी करवा लीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, हां प्रिंसीपल की भी इन्क्वायरी होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये भी चेक करवाईये कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से मिली थी ? क्या उस समय की शिक्षा मंत्री ने एक कमेटी बनाई थी ? (विघ्न)

Mr. Speaker: This can be added in the terms of reference आपका यह सुझाव है कि यह रिफरेंस भी उसमें----- (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर इन्क्वायरी की और वह इन्क्वायरी खत्म हुई। आप चाहें तो सारी चीजों के फैक्ट्स चेक करवा लीजिए। मैं आज भी अपनी बात को लेकर खड़ा हूँ। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : दुष्यंत जी, आप बैठ जाईये। हम माननीय अध्यक्ष महोदय से बात कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं है। I can also make a false allegation against you. (विघ्न)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, मैंने तो हाउस के डिजीजन की रिस्पैक्ट करनी है। When the House takes any decision, I have to respect that decision. (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, terms of reference बताओ।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, terms of reference बताया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, जब हाउस ने पास कर दिया तो Term of reference. (विघ्न)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, terms of reference तो यही है कि allegation and counter-allegation whether they are right or wrong. This is the terms of reference. जो ऐलिगेशंज और काउंटर ऐलिगेशंज दोनों तरफ से लगे हैं वह ठीक हैं या गलत हैं this is to be decided. (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, आपके कहने का मतलब यह है कि हाउस की प्रोसीडिंग की इन्क्वायरी होगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी नहीं। हाउस की प्रोसीडिंग की नहीं बल्कि ऐलिगेशंज की इन्क्वायरी होगी और हाउस ने यह निर्णय किया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, अगर मुझे आज हाउस कहे कि उसको नहीं करना है तो मैं दोबारा कर दूंगा। I have to respect the decision of the House अगर हाउस डिसाइड करता है। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हाउस ने क्या डिसाइड किया।

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, you can say anything. (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, मुझे आप terms of reference बता दो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, मैंने आपको terms of reference बताया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, आपने क्या बताया है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, जो ऐलिगेशंज और काउंटर ऐलिगेशंज लगे हैं this was decided in the House that this should be inquired by the sitting Judge of the High Court. (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, यह सरकार का मामला है। इसके बारे में सरकार इन्क्वायरी करेगी। जो उसने गलत किया है या ठीक किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आप पर false एलीगेशन लगा देता हूँ तो क्या आप इस पर हाई कोर्ट से इन्क्वायरी करवाओगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, यह हाउस ने डिसाइड किया है। मैं इसके हक में नहीं था। I was not in favour of that but when the House has decided, I have to follow it.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, you are protecting...(noise and interruption)

श्री अध्यक्ष :हुड्डा जी, I have to respect the decision of the House. अगर मैं हाउस के डिसेजन की रिस्पैक्ट नहीं करता..... (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव हाउस की गरिमा के खिलाफ है या नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, यह हाउस डिसाइड करेगा कि यह सदन की गरिमा के खिलाफ है या नहीं है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप कुछ नहीं करोगे। आपको स्पीकर किस बात के लिए बनाया है। You are not a party man. You have to save the dignity of the House.

Mr. Speaker: But I have to follow the decision of the House and whatever the House decides, I have to follow that. I am compelled to follow it.

Shri Bhupinder Singh Hooda: Mr. Speaker Sir, you have got ample power.

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, नहीं। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ कि जो हाउस का डिसेजन हो उस पर मैं यह कह दूँ कि यह गलत डिसेजन है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, जहां हाउस की dignity compromise होगी वहां पर , you have to take stand.

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, नहीं। मुझे लगता है कि हाउस ने जो डिसेजन किया है, वह सही है और उसमें इन्कवायरी होने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, यह डिगनिटी नहीं, कोम्प्रोमाइज है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, हाउस की डिगनिटी रहनी चाहिए। अगर हाउस ही डिसाइड करता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ।

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, you inquire about this matter (interruption)

उर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह): स्पीकर सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात रखने के लिए एक मिनट का समय चाहता हूँ।

Mr. Speaker: This decision is taken by the House. If the House decides that this decision should be backed out (interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: मुख्यमंत्री जी, यह ऐसा तमाशा मत करो । आप इन्कवायरी स्पीकर साहब से करवाओ या मैं कहता हूं कि इन्कवायरी आप खुद कर लीजिए । मैं इस पर एग्री हूं ।
Don't compromise the dignity of the House.

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि (शोर एवं व्यवधान)।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष जी, आप मुझे एक मिनट का समय दें ।(शोर एवं व्यवधान)।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष जी, आप हमें अपनी बात रखने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब एवं गीता जी, प्लीज आप बैठ जाएं । सदन में लीडर ऑफ दी हाउस खड़े हैं, प्लीज आप बैठ जाएं ।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जब सदन में कोई विषय चल रहा होता है तो उसमें पक्ष तथा प्रतिपक्ष का कोई भी सदस्य अपनी बात को रख सकता है लेकिन बात रखने में किसी भी सीमा तक जाकर मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए । यह बात ठीक है लेकिन कल थोड़ी तीखी नोंक-झोंक हुई । उस तीखी नोंक-झोंक को वहीं पर रोकने के लिए माननीय सदस्यों को जो सुझाव आया था कि इसके ऊपर कोई एक इन्कवायरी करवा ली जाये और इस इन्कवायरी के बारे में माननीय सदस्यों में से ही यह विषय आया था कि यह इन्कवायरी किसी जज से करवाई जाये, सिटिंग जज से करवाई जाये । यह बात ठीक है कि आज तक हमने किसी सिटिंग जज से कभी भी कोई इन्कवायरी नहीं करवाई । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष जी, इस प्रकार की इन्कवायरी पूरे देश में, डेमोक्रेसी में कहीं पर भी नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, प्लीज आप बैठ जाये ।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि अब चूंकि सदन के हाउस की गरिमा बनाकर रखनी जरूरी है । सिटिंग जज से इन्कवायरी करवाने का निर्णय कल आप दे चुके हैं कि

सिटिंग जज से इन्कवायरी करवाई जाये और उस समय किसी का एतराज नहीं था। उस समय सदन में हमारे प्रतिपक्ष के भी सभी सदस्य बैठे हुए थे। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: मुख्यमंत्री उस समय में सदन में उपस्थित नहीं था।

श्री मनोहर लाल: हुड्डा जी, आप नहीं होंगे लेकिन आपकी जगह सदन में कोई उप नेता रहे होंगे। अगर उस समय कोई आपत्ति करता तो शायद यह विचार हो सकता था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ तो आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस समय सबने स्वीकार किया। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा: मुख्यमंत्री जी, अब इसे रिव्यू करने में क्या एतराज है?

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष जी, उस समय सबने स्वीकार किया। सबने स्वीकार किया तो इसके बाद हमने होम डिपार्टमेंट को यह कहा कि आप जल्दी से Chief Justice of Punjab & Haryana High Court को पत्र लिखिए क्योंकि अब हम नाम भी तय नहीं कर सकते। नाम भी हमको माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अगली बात कह रहा हूँ कि अगर कहीं माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय इसको डिक्लाइन कर देते हैं तो हम उसके ऊपर बाद में विचार कर सकते हैं। एक बार तो हमें वह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा को पत्र लिखें। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, यह मामला अब रिव्यू हो सकता है?

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष जी, पहले तो ये हर समय इन्कवायरी के लिए कहते रहे हैं। यह विषय तो पहली बार आया है कि इन्कवायरी सिटिंग जज से नहीं करवानी चाहिए वरना तो विपक्ष की तरफ से यह विषय कई बार आया कि इन्कवायरी सिटिंग जज से करवाएं। (विघ्न)

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि यह सदन की गरिमा के लिए सही नहीं है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जब आज उसमें कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई न कोई फंस सकता है। उससे विपक्ष के सदस्य इतने उतावले हो गये कि इन्कवायरी बंद करें। इन्कवायरी ना करवायें। या इन्कवायरी कहीं और से करवाये। इन्कवायरी यह करें, इन्कवायरी वह करें। (शोर एवं व्यवधान) जब एक बार इन्कवायरी का फैसला हो गया तो मेरा आपसे

निवदेन है कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम केवल एक ही विषय में रिव्यू करें कि हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें तो हम उस पर विचार करें अन्यथा जो निर्णय हो गया, वह निर्णय है। उसके बाद आगे जो कुछ करना है, वह करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने कहा कि विपक्ष के द्वारा माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इन्कवायरी करवाने की मांग आती रही है, यह मांग आती रही है और अब भी आएगी। यह मांग किसकी आई है। जो वहां पर हुआ है, जो हैडमास्टर प्रिंसिपल ने किया है। जो शराब का घोटाला हुआ है, उसकी इन्कवायरी माननीय हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग आई हो। आप कभी भी ऑन रिकॉर्ड दिखवा दीजिए। अगर विधानसभा की प्रोसिडिंग में मेरी माननीय हाईकोर्ट के जज से इन्कवायरी की मांग आई हो तो आप लिखित में दिखवा दीजिए। आप यह एक दफा दिखवा दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह हो सकता है कि आपकी तरफ से यह मांग न आई हो। (शोर एवं व्यवधान) यह मांग शुक्रवार को आपकी पार्टी के सदस्य द्वारा की गई थी। शुक्रवार को आपकी पार्टी के ही सदस्यों ने यह मांग की थी कि इस मामले की सिटिंग जज से जांच करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान) इस पर मैंने कहा कि ठीक है इस मामले की सिटिंग जज से जांच करवा लेते हैं। (शोर एवं व्यवधान) उस समय बहुत सारे ऑप्शंस थी। (शोर एवं व्यवधान) उस समय बहुत सारे ऑप्शंस भी डिसकस हुए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं चार बार एम.पी. रहा हूं और पांच बार एम.एल.ए. रहा हूं। मैं हाऊस की गरिमा के साथ कम्प्रोमाईज नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान) अब आप फिर उनको डिफेंड कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं हाऊस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) जो हाऊस का निर्णय हुआ है वह सिटिंग जज से इन्कवायरी को लेकर हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उनसे बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां करिए। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उन्होंने कहा कि विपक्ष की आम तौर पर मांग आई है कि हाई कोर्ट से इंकवॉयरी करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान) हाऊस की प्रोसीडिंग का एक इंसीडेंस बता दो जब मैंने कहा हो कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा किसी मामले की जांच करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान) एक दिखा दो। तब मैं मान जाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, हो सकता है कि आपने नहीं कहा लेकिन ये जो डिस्मिशन हुआ। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, सुन लीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसलिए let him clarify. आप क्यों जवाब दे रहे हो?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं नहीं जवाब दे रहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछ रहा हूँ लेकिन जवाब आप दे रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, देखिए मेरा अपना व्यू यह है कि आप ये इंकवॉयरी अपनी आपस की ही सर्वदलीय बैठक करके कर लें। ये अपनी चोटी जजिज के हाथ में देना कोई शोभा की बात नहीं। ये मेरे विचार हैं।

श्री अध्यक्ष : शुक्रवार को ये हाऊस ने डिसाईड किया। (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं था उस फैसले में। (शोर एवं व्यवधान) इससे अच्छा तो आप एक सर्वदलीय कमेटी बना दो। उसका फैसला ले लो। कोई बात नहीं (शोर एवं व्यवधान) लेकिन जजिज के हाथ में अपनी चोटी देना मैं अच्छी बात नहीं समझता। (शोर एवं व्यवधान) यह बात हाऊस की गरिमा के खिलाफ होगी। जजिज हमारी इंकवॉयरी करेंगे? (शोर एवं व्यवधान) इसकी इंकवॉयरी करेंगे, उसकी इंकवॉयरी करेंगे? It will be insult of the House, if I am not wrong.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप कह रहे हैं हाऊस ने किया है। क्या वोटिंग हुई थी हाऊस की? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, हाऊस ने तो यूनानीमसली डिसाईड किया। किसी ने भी ओपोज नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) आप प्रोसीडिंग्स निकालकर देख लो। (शोर एवं व्यवधान) एक मिनट हुड्डा साहब, शुक्रवार की प्रोसीडिंग्स निकलवाकर देख लो। किसी एक विधायक ने इसको ओपोज किया हो। (शोर एवं व्यवधान) किसी एक विधायक ने भी ओपोज नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) आप लोगों ने कहा कि इसकी सिटिंग जज से इंकवॉयरी करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान) मैं इसकी प्रोसीडिंग्स अभी निकलवा लेता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, आप मुझे सिर्फ दो मिनट बोलने दें। मामला आया इस सदन में और आपने यह कहा कि यह इंकवॉयरी शिक्षा विभाग को दे दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने तो ऑप्शंस दी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष जी, उसके बाद बात आई कि पुलिस विभाग को दे दो। 'No' हो गई। फिर मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि one man Speaker Sir आप ही स्पीकर साहब इस कमेटी का फैसला कर दो। साथ में वॉयसज आई। आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सजेशन दिया कि हाई कोर्ट के जज से यह इंकवॉयरी करवा ली जाये। आपने इमीडियेटली हाई कोर्ट जज के लिए हां कर दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, with the sense of the House हाऊस ने कहा कि इसकी इंकवॉयरी सिटिंग जज से कर दो। (शोर एवं व्यवधान) ये गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : हमने कभी हाई कोर्ट नहीं कहा, हम ऐसा कह ही नहीं सकते थे और आज भी विश्वास करते हैं आप सिंगल मैन कमेटी बनाकर आप ही इस मामले की इंकवॉयरी कर दें। बात खत्म हो गई। (शोर एवं व्यवधान) हमने यह कहा था जी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ये शुक्रवार की प्रोसीडिंग्स है मेरे पास। इसमें भारत भूषण बतरा जी कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है कि विधान सभा का मामला विधान सभा में ही रहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि एक ने भी ओपोज नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) वो कह रहे हैं विधान सभा का मामला विधान सभा में ही रहना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) भारत भूषण बतरा

जी की प्रोसीडिंग्स आप भी देख लें। (शोर एवं व्यवधान) फिर आपको वोटिंग करवानी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब कोई ओपोज करेगा तो मैं वोटिंग कराऊंगा। जब सारे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ओपोज किया तो आप वोटिंग करवाते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहां लिखा है कि ओपोज किया? बताओ? प्रोसीडिंग्स मेरे पास है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, बतरा जी ने कहा था कि मेरा अनुरोध है कि विधान सभा का मामला विधान सभा में ही रहना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये सुझाव दिया उन्होंने। उसके बाद कितने सुझाव आये? (शोर एवं व्यवधान)

आप इससे आगे भी पढ़िए उसको। और कितने सुझाव आये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आप क्यों प्रोटैक्ट कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

आपसे मेरा अनुरोध है आप क्यों प्रोटैक्ट कर रहे हैं काइंडली आप मेरी बात सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें। (शोर एवं व्यवधान) मेरी आपसे रिक्वैस्ट है

कि आप मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डैमोक्रेसी में इस बार नाम लिखा जायेगा। इसको मत लिखने दें। (शोर एवं व्यवधान)

नाम क्या लिखा जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए जो हाऊस कहेगा वो मैं लिखूंगा। (शोर एवं व्यवधान) वो चाहे गलत कह

रहा है या ठीक कह रहा है। Because I have to follow the decision of the House अगर

हाऊस ने रिक्मैण्ड किया है तो मैं उसको फोलो करूंगा।

ऊर्जा मंत्री(श्री रणजीत सिंह): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद आधे घंटे से यह मामला

चल रहा है। हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं और 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हाऊस के

कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, नॉर्मज होते हैं। जब कोई मिनिस्टर बोलता है और नेता प्रतिपक्ष खड़े हो

जाते हैं तो मिनिस्टर बैठ जाता है। उसी प्रकार से जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों और लीडर ऑफ

दा हाऊस खड़ा हो जाये तो नेता प्रतिपक्ष बैठ जाते हैं। पहले तो हम इस मार्यादा का पालन करें।

यह आधे घंटे से चला आ रहा है और मैं भी इसमें गुनहगार हूं। इसका कोई फायदा नहीं मिलना, यह विधान सभा लोगों की इन्वैस्टमेंट है। इस घटना को पूरा देश देख रहा है और ये स्कूल के बच्चे आए हैं ये भी देख रहे हैं इसलिए हमें इसको अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। जब हाउस ने डिसाइड कर दिया तो अब उसकी रिपोर्ट आने दें उसके बाद कोई दूसरा फैसला कर लिया जाये। अब इसमें कोई इशू नहीं है कि बार-बार इस पर हंगामा करें। धन्यवाद।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरी बात सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, अगर आप केस प्रस्तुत करेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे फिर धमकाने लग जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, धमकाने की बात नहीं है, 15 दिसम्बर को आपने बहुत कुछ कह दिया था। अब आपको जो कुछ कहना है वह आप सिटिंग जज साहब के सामने ही कहना। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन तो लो। मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रही हूं और आप मुझे धमका रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, मैं आपको धमका नहीं रहा हूं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं...

Smt. Geeta Bhukkal: Sir, I am requesting to you with folded hands. आप उप-मुख्यमंत्री जी को प्रोटैक्ट न करें। मैं हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी बात सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है तो वह आप जो इन्कवायरी ऑफिसर या इन्कवायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर 15 दिसम्बर को हाउस में जो डिसीजन हुआ है उसके बारे में कोई बात रखनी है तो आप जरूर रखिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात को पूरा सुन लें। जैसे ही यह मामला अभी शुरू हुआ तो उप-मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह वर्ष 2011 नहीं था बल्कि वर्ष 2012 था। उसके बाद वर्ष 2005 का जिक्र कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी टेबल पर दो कागज भिजवाए हैं कृपया आप एक बार उनको शांति से पढ़ लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, ये जो आपके फैक्ट्स हैं... (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें, आप उनको क्यों प्रोटैक्ट कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, मैं किसी को प्रोटैक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप ये गलत ऐलीगेशन मुझ पर मत लगाइये। आपके जो फैक्ट्स हैं वे आप इन्वैस्टिगेटिंग एजेन्सी के सामने रखिए। उनका जो भी डिजीजन आयेगा we will follow that. (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, 15 दिसम्बर को मैंने जो बात कही वह आपने एक्सपंज करवा दी और उप-मुख्यमंत्री ने मुझ पर झूठा ऐलीगेशन लगाया वह आपने एक्सपंज क्यों नहीं करवाया? अध्यक्ष महोदय, आप काइंडली मेरी बात सुन लें। मैंने जो जीरो आवर में बात कही वह मैटर इज ओवर, जो भी यौन शोषण की बात कही थी वह मैटर भी ओवर हो चुका था लेकिन उप-मुख्यमंत्री ने खड़े हो कर यह कहा कि वर्ष 2005 में डी.डी.आर. हुई और वर्ष 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पर पंचायत हुई। वर्ष 2011 में मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था और आज उप-मुख्यमंत्री जी वर्ष 2011 की बात से मुकर गये हैं अब वे उसको वर्ष 2012 बता रहे हैं। वर्ष 2005 में वह टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था और उसके बारे में मैंने दो पेज आपको दे दिये हैं। दूसरी बात यह है कि उप-मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से एम.पी. भी रह चुके हैं और वहां से एम.एल.ए. भी हैं यह इनके घर के नजदीक का स्कूल है और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इस मामले को हाई कोर्ट को दें तो हम उसका वैलकम कर देंगे लेकिन point of reference, the only thing is that जैसे ही यह मामला शुरू हुआ तो उप-मुख्यमंत्री जी ने खड़े हो कर यह कहा कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूँ और आपने उनकी बात सुन ली। अध्यक्ष महोदय, मुझ पर झूठा ऐलीगेशन लगाया गया है कि मैंने उस प्रिंसिपल को प्रोटैक्ट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस सरपंच ने कहा है कि जे.जे.पी. के लोग मेरे घर आ कर मुझे गवाह

बना रहे हैं कि आप हां भर दें लेकिन उन्होंने इन्टरव्यू दे दिया है कि हम कभी भी गीता भुक्कल जी के रेजिडेंस पर नहीं गये। मैंने हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज आपकी टेबल पर पहुंचा दिये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, मैंने पहले ही कहा है कि जो फैक्ट्स आपके पास हैं उनको आप जो भी इन्क्वायरी का सिटिंग जज होगा उनके सामने रखिए। उसके बाद अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर आप दोषी पाई जाती हैं तो आपके खिलाफ एज पर रूल्ज कार्रवाई होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहती हूं कि House is over and above the High Court. यहां सदन में लिखा हुआ भी है कि या तो सभा में प्रवेश न किया जाये और अगर प्रवेश किया जाये तो स्पष्ट और सच बात कहें। सर, मैं सच बोल रही हूं और आप उप-मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि उन्होंने झूठ क्यों बोला? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप जहां से शुरू होते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। जब एक-एक चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए हमने तय कर दी तो फिर उससे हम भागते क्यों हैं। हम उससे दूर क्यों जा रहे हैं। हम उससे भाग क्यों रहे हैं। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आप उप मुख्यमंत्री जी से पूछ तो लें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, वे तो इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं। अगर वे इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार न होते तो बोलते। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : सर, इन्क्वायरी तो होनी ही चाहिए परन्तु House is over and above the High Court. (विघ्न)

Mr. Speaker : This is the decision of the House. This is not my decision. (विघ्न)

Smt. Geeta Bhukkal : Hon'ble Speaker Sir, Hon'ble Leader of Opposition is also a part of the House and we are also a part of the House. (विघ्न)

Mr. Speaker : I am saying that every respected Member is a part of this House and the decision taken by the House will be followed. (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरी जो बात है वह यह है कि आप उप मुख्यमंत्री जी से एक बार पूछ लें क्योंकि वर्ष 2005 में वह सरकारी टीचर नहीं था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं पूछूंगा। यह मेरा काम नहीं है। यह इंक्वायरी ऑफिसर पूछेगा। जो भी होगा। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आप कमाल कर रहे हैं। आप इंक्वायरी करवा लें लेकिन जो झूठा ऐलिंगेशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लगाया है उसका क्या? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या झूठ है या क्या सच है सब पता लग जाएगा। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैंने हस्ताक्षर सहित सदन के नेता के पास अपनी स्टेटमेंट भेज दी है। स्पीकर सर, मैंने आपकी टेबल पर भी हस्ताक्षर सहित स्टेटमेंट भेज दी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, मैं तो जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास आपकी स्टेटमेंट भेज दूंगा। मैं आपसे यह प्रोमिस करता हूँ कि आपने जो फैक्ट्स रखे हैं वे मैं इंक्वायरी ऑफिसर के पास भेज दूंगा, I promise that. (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे को कोई एतराज नहीं है। आपने जो कर दिया और हाई कोर्ट भी जो करेगी कर लेगी लेकिन गीता जी ने सदन को लिख कर दे दिया है कि यह झूठ है। आप उप मुख्यमंत्री जी से भी तो लिखित में ले लो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, इन्होंने जो ऐलिंगेशन लगाए हैं वे सब हाऊस की प्रोसिडिंग में लिखे हुए हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, गीता जी ने लिख कर दिया है तो उप मुख्यमंत्री जी भी लिख कर दे दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, वह उनकी मर्जी है। कोई अपने फैक्ट्स देना चाहता है या नहीं देना चाहता है वह तो उनकी मर्जी है।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप इसका ऐफिडेविट तो देंगे ना, आप इसका कोई तो रिकॉर्ड देंगे। गीता जी तो सारा रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं।(विघ्न)

Mr. Speaker : This is sufficient record. This is sufficient record for any inquiry. जो भी प्रोसिडिंग या जो भी बात हाऊस के अन्दर हुई है, वह बिल्कुल पूरी तरह से साफ लिखी हुई है। उस पर हाऊस जो भी डिस्मिशन करेगा वह मैं फोलो करूंगा। If House takes any other decision I will also follow that. (विघ्न)

Shri Ram Kumar Gautam : Speaker Sir, you are the Speaker of all the MLAs. मैं कहता हूँ कि अपनी चोटी किसी और के हाथ में ना दो। Don't not make mockery of this House किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना it will be foolishness of this House. (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, मैं क्या करूँ जब हाऊस कोई चीज डिस्मिड करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कोई डिस्मिशन नहीं किया। This is the decision of the House. (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आप जज से बहुत बड़े हैं। आप ऐसा मत करो। आप एक कमेटी बना दो और आप उसके चीफ बन जाओ और फैसला दे दो। आप इस झगड़े को मिटाओ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, प्लीज एक मिनट। कल जब ये डिस्मिशन हुआ था। बतरा जी, आप हाऊस के अन्दर थे। उस समय आपने एक बार भी नहीं कहा। उस समय आपने यह कहा कि सिटिंग जज से इन्क्वायरी होनी चाहिए। अब जब यह हाऊस ने डिस्मिड किया है तो उसमें मैं क्या करूँ।(विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, जज का डिस्मिशन तो आपका था। हमारा नहीं था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, यह डिजीजन मेरा नहीं था यह हाऊस का डिजीजन था। हाऊस ने कहा कि इसकी सिटिंग जज से इंकवायरी करवाई जाए। This was not my decision. (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको इसके लिए कब कहा। हमने तो यह कहा था कि आप इंकवायरी करवा लो। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं ऐफिडेविट देने को तैयार हूँ। आप उनको खड़ा करके तो पूछ लें कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, यह झूठ सच का फैसला मैं नहीं कर सकता। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2011 को वर्ष 2012 करवा लिया। उप मुख्यमंत्री जी अब आप हंस रहे हैं, आपके पड़ोस में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो गया और आप हंस रहे हैं और आपने उनको प्रोटेक्ट भी नहीं किया। (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं हंस नहीं रहा हूँ। मैं तो इनकी बात पर हंस रहा हूँ। मैं तो आज भी उस बात पर गम्भीर हूँ।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री जसबीर सिंह मलौर, पूर्व विधायक, श्री रामबीर सिंह, पूर्व विधायक, रामफल कुण्डू, पूर्व विधायक एवं श्री धर्मपाल ओबरा, पूर्व विधायक सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। (विघ्न)

गवर्नमेंट कॉलेज पटौदी, जिला गुरूग्राम के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज पटौदी, जिला गुरूग्राम की छात्राएं तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने

के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा जीन्द के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर दिनांक 15.12.2023 को सदन में उप मुख्यमंत्री और उनके बीच हुए विवाद का मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ रैफ्रेंस बता दीजिए।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठ जाइये।(विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, -----(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठ जाइये।(विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आप रैफ्रेंस तो बता दीजिए।(विघ्न)

बैठक का स्थगन

(i)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

*1:04 बजे

(तत्पश्चात् सभा मध्याह्न पश्चात् 1:04 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

(जब सदन समवेत हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की)

बैठक का स्थगन

(ii)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्यवाही दोपहर भोजनावकाश के लिए एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

14:04 बजे

(तत्पश्चात् सभा मध्याह्न पश्चात् 2:04 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की)

शून्यकाल के सम्बन्ध में सूचना देना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, वैसे तो शून्यकाल का समय एक घंटे का था जो बीत चुका है लेकिन मेरा यह मत है कि संबंधित माननीय सदस्यों को बोलने का समय मिलना चाहिये, इसलिए आज का बिजनैस समाप्त होने के बाद एक घंटा शून्यकाल के लिये रख लेते हैं।

आवाजें: ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से सम्बन्धित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा 'राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से संबंधित' ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 प्राप्त हुई है जोकि मैंने स्वीकार कर ली है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-23, जोकि श्री बलराज कुण्डू, विधायक द्वारा दी गई है, को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बलराज कुण्डू, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-29, जोकि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव संख्या-1, जोकि श्री बिशन लाल सैनी, विधायक तथा 12 अन्य विधायकों (सर्वश्री वरूण चौधरी, मेवा सिंह, भारत भूषण बतरा, कुलदीप वत्स, जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती रेनु बाला, शीशपाल सिंह, श्रीमती शैली, श्रीमती शकुन्तला खटक, आफताब अहमद, राव दान सिंह तथा श्रीमती गीता भुक्कल) द्वारा दी गई है, को मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-55 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 के

साथ जोड़ दिया गया है। श्री बिशन लाल सैनी, विधायक भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-44, जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।

अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला को अपनी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 पढ़ने के लिए कह दिया। अब मैं अपनी बात कैसे कहूं ? आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको बोलने के लिए टाइम दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, हम आपको बाद में बोलने के लिए समय दे देंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, अब तो आप भी थोड़ा-सा नरम रूख रखिये क्योंकि सरकार के लास्ट डेज चल रहे हैं। अब चुनाव का भी लास्ट ईयर चल रहा है। आपने मांग का स्टाइल बदल दिया तो अब आप हाउस को चलाने का भी थोड़ा-सा स्टाइल बदलिये।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपका धन्यवाद।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, उस समय बोलने का मेरा राइट था। उस समय आपने मुझसे कहा कि आप बाद में बोल लेना।

श्री अध्यक्ष : ठीक है कादियान साहब, हम आपको बाद में बोलने के लिए समय दे देंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : थैंक यू स्पीकर सर।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हम 13 माननीय सदस्यों ने आपको स्थगन प्रस्ताव संख्या-1 दिया था लेकिन आपने केवल एक ही माननीय सदस्य को बोलने के लिए अलाउ किया है।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, हम इन प्रस्तावों पर हर माननीय सदस्य को बोलने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। नियम के अनुसार एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 5 माननीय सदस्य बोल सकते हैं। अब एक ही स्थगन प्रस्ताव के अंदर 13 माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हुए हैं। (विघ्न)

स्थगन प्रस्ताव पर भी 2, 3 या 4 माननीय सदस्य ही तो बोलेंगे। हम तो 5 माननीय सदस्यों को बुलवा रहे हैं। (विघ्न)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, फिर हमें एडजर्नमेंट मोशन देने का क्या फायदा हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, यह कोई नई चीज नहीं है। इसका तो आपको पहले ही पता है। अगर आपका कोई एडजर्नमेंट मोशन एडमिट करने के योग्य होगा और उसके जैसा कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं आया होगा तो उसे जरूर एडमिट किया जाएगा। (विघ्न) यह विषय ऐसा है कि सबके ध्यान में जरूर आना चाहिए। मैंने इसीलिए इसको एडमिट किया है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, इस एडजर्नमेंट मोशन पर हम 13 विधायकों ने अपने सिग्नेचर किये थे तब यह आपको दिया था।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, आपकी यह बात ठीक है। यह आपका राइट है। अभय जी, आप अपनी सूचना पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं नवम्बर, 2023 में प्रदेश के यमुनानगर और अम्बाला जिले में जहरीली और नकली शराब पीने के कारण लगभग 22 लोगों की मौत बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी हाल ही नवम्बर, 2023 में प्रदेश के यमुनानगर और अम्बाला जिले में जहरीली और नकली शराब पीने के कारण लगभग 22 लोगों की मौत हुई है। गत वर्षों में भी सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद सहित कई जिलों में भी जहरीली और नकली शराब पीने के कारण सैकड़ों मौतें हुई थी। प्रदेश में अवैध नकली शराब के धंधे पर अंकुश न लगाने की वजह से यह धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब घोटाले के बाद विभिन्न जिलों में शराब गोदामों की चैकिंग की गई तो 75,250 पेटी शराब कम पाई गई जिससे स्पष्ट है कि शराब का अवैध कारोबार निरंकुश तौर पर जारी है जोकि सत्ता में बैठे राजनेताओं/अधिकारियों के संरक्षण एवं संलक्षिता के बिना संभव नहीं हो सकता। प्रदेश में खासतौर पर करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिरसा, हिसार, फरीदाबाद आदि जिलों में अवैध और नकली शराब का कारोबार धड़ल्ले से अभी भी चल रहा है। लॉकडाउन के

दौरान हुए शराब घोटाले की जांच के लिए सरकार द्वारा एस.ई.टी. गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट आज तक भी सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ सलंगन

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं इस महान सदन का ध्यान अति लोक हित विषय की ओर दिलवाना चाहता हूँ कि हरियाणा में शराब माफियाओं का जबरदस्त जाल फैला हुआ है। खुलेआम अवैध रूप से शराब बनाई और बेची जा रही है। सम्बंधित विभाग की इस जहरीली शराब काण्ड में मिली भगत होने की सम्भावना दिखती है। हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर/अम्बाला में इस जहरीली शराब का सेवन करने से लगभग 20-22 लोगों की जानें चली गयी हैं। ये जहरीली शराब खुलेआम सरकारी ठेकों पर बेची जा रही है, यह तक खबर आ रही है। यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस गंभीर विषय को लेकर सदन में विस्तार से चर्चा करवायी जाए। इसका पोर्टल पर कोई जवाब भी नहीं डाला गया है।

श्री अध्यक्ष: कुंडू जी, इसका जवाब पोर्टल पर डाल दिया गया है।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, यह अभी डाला गया है। ये घोटाले पिछले दिनों से हुए थे और उसके लिए कमेटी की गठित की गयी थी और उसकी रिपोर्ट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही उस कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री अध्यक्ष: कुंडू जी, एक बार माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ लें और उसके बाद माननीय मंत्री जी रिप्लाई देंगे। आप उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बलराज कुंडू: ठीक है, जी।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ सलंगन

श्री नीरज शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जहरीली शराब से हुई मौत बारे में श्रीमान जी विषयांकित मामले में आपका ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहूंगा कि

हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से लगभग 18 लोगों की मौत हुई। इस पर सरकार इस महान सदन को अवगत करवाए कि सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की और वर्ष 2020 से अब तक जहरीली शराब पीने से कितने लोगो की मौत हुई तथा जहरीली शराब के सदर्थ में सरकार ने कोई कमेटी गठित की थी, अगर गठित की थी तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को क्या बताया और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 में परिवर्तित तथा

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ सलंगन

श्री बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा मैं तथा श्री वरूण चौधरी, विधायक श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक, श्री कुलदीप वत्स, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्रीमती रेणु बाला, विधायक, श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्रीमती शैली, विधायक, श्रीमती शकुन्तला खटक, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, राव दान सिंह, विधायक एवं श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक आपका ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण यमुनानगर में 18 और अंबाला जिले में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जिसकी जांच होनी चाहिए और जो पीडित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा प्रदेश दूध दही के खाने के नाम से जाना जाता है लेकिन आज प्रदेश शराब, चिट्टा, हेरोईन, स्मैक और सिंथेटिक नशे का अड्डा बनकर रह गया है। हरियाणा प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों के मरने का कारण सत्ता में बैठे लोग नशा के कारोबारियों को संरक्षण देना है और नशा के कारोबारी प्रदेश में खुली लूट मचा रहे हैं। पुलिस विभाग के संरक्षण के बिना यह संभव नहीं हो सकता है, यही वजह है कि जहरीली शराब के कारण प्रदेश में लोगों की मृत्यु हुई है। जहरीली शराब की अवैध तस्करी के कारण ही शराब तस्करों के आकाओं की तिजोरियां भर रही हैं और प्रदेश को टैक्स का नुकसान भी हो रहा है। इतना ही नहीं कोरोना काल के दौरान ही करोड़ों रुपये के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था जिस पर कोई उचित कार्यवाही सरकार द्वारा भरोसा देने के बावजूद भी नहीं हुई है। सरकारी संरक्षण के बिना शराब की अवैध तस्करी करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। नवम्बर 2020 और नवम्बर 2022 में भी पानीपत और सोनीपत में 30 से ज्यादा लोगों को जहरीली शराब पीने के कारण अपनी जान गवानी पड़ी थी। एन.सी.आर.बी. के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश में नशा इस कदर बढ़ गया है कि नशे और नशे की ओवर डोज से होने वाली मौतों के मामले में हरियाणा ने पंजाब और हिमाचल को पीछे छोड़ दिया है। आज के दिन लोगों का अवैध नशे के फैलते कारोबार के कारण सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच सी.बी.आई. से करवानी चाहिए ताकि जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उनके बारे में पता लग सके और प्रदेश की जनता को जहरीली शराब से मुक्ति मिल सके। बल्कि मैं तो यह मांग भी करूंगा कि इसकी हरियाणा प्रदेश के किसी हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच होनी चाहिए ताकि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके बारे में पता लग सके।

CALLING ATTENTION NOTICE NO. 44
Clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 15

Smt. Kiran Choudhry: I want to draw the kind attention of this august House towards a matter of great importance that the unabated trade and sale of spurious and Illicit liquor in the State leading to successive hooch tragedies In the year 2020 there were reports of unauthorised sale of liquor from distilleries during lockdown. In the year 2020 about 46 persons had died in Panipat/Sonipat due to consumption of spurious/illicit liquor. In November 2022 four people died in Sonipat/Panipat due to consumption of illicit liquor. The latest tragedy has taken place in November 2023 in Ambala/Yamuna Nagar where about 18 person died due to consumption of spurious liquor supplied by the retail vendors casting its ominous and dark shadow over Diwali celebrations. Such tragedies have been occurring at regular intervals, despite SIT and SET constituted by the State Government at the time of previous incidents. The kingpins of these operations-owners of distilleries, wholesale contractors or senior official are rarely arrested-the Government tending to put the entire blame on small players by netting the small fish. Despite our flagging the concerns the Government has failed to put in place standard operating procedures for affixing of holograms, CCTV Cameras in distilleries and liquor vends. This indicates deep Government nexus warranting a court Monitored CBI probe into the matter This is matter of utmost public import, the same may be taken up for discussion and the Minister concerned may be asked to make a statement on the floor of house as per procedure."

वक्तव्य-

गृहमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना जवाब सदन के पटल पर रखें।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, जहरीली शराब के सेवन से 20 लोगों की मौत के मामले में, पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर और अंबाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन से 20 मौतें हुई हैं, इस संबंध में 05 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इन दोनों जिलों में कुल 52 गिरफ्तारियां की गईं जिनमें 36 आरोपी शामिल पाए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर ने सूचित किया है कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव मंडेवरी, यमुनानगर निवासी एक व्यक्ति को संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच से पता चला कि नकली शराब उसी गांव मंडेवरी निवासी रॉकी नामक व्यक्ति द्वारा संचालित एक अवैध खुर्दा से बेची जा रही थी। जिस संबंध में पुलिस द्वारा एक अपराधिक अभियोग अंकित किया गया, तथा गहनता से जांच की गई। जांच में अंबाला जिले के गांव धनौरा में अवैध रूप से चल रही एक फैक्ट्री का पता चला, जहां नकली शराब का निर्माण और वितरण किया जा रहा था। इस मामले में कुल मिलाकर 05 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:

1. एफ.आई.आर. संख्या 249 दिनांक 08.11.2023 धारा 302/328/120-बी आईपीसी और 72-ए आबकारी अधिनियम थाना फरकपुर, यमुनानगर।
2. एफ.आई.आर. संख्या 387 दिनांक 10.11.2023 धारा 302/328/120-बी आईपीसी और आबकारी अधिनियम 72-ए थाना छप्पर, यमुनानगर।
3. एफ.आई.आर. संख्या 451 दिनांक 11.11.2023 धारा 302/328/120-बी आईपीसी और 72-ए आबकारी अधिनियम थाना बिलासपुर, यमुनानगर।
4. एफ.आई.आर. संख्या 327 दिनांक 09.11.2023 धारा 304, 302 328, 120-बी आईपीसी और 72ए आबकारी अधिनियम थाना बराड़ा, अंबाला।

5. एफ.आई.आर. नं. 410 दिनांक 09.11.2023 धारा 188, 201, 120बी, 272, 308, 328, 420, 468, 471, 473 आईपीसी और 61 और 63ए पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 थाना मुलाना, अंबाला।

यमुनानगर और अंबाला पुलिस द्वारा सभी पहलुओ पर गहनता से जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों सहित 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो दुकानों के मूल आवंटनकर्ता थे।

जहरीली शराब के सेवन से कुल 20 मौतें (यमुनानगर में 18 और अंबाला में 2) हुई हैं, जिसमें गांव धनौरा, अंबाला में अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री में काम करने वाले दो श्रमिकों की मौत भी शामिल है, जिन्होंने संदिग्ध जहरीली शराब का सेवन किया था। इसके अलावा बीमार 5 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गिरफ्तार किए गये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, केवल एक आरोपी को छोड़कर जिसने जहरीली शराब पी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

इसके अलावा, दयालु योजना के तहत अब तक 8 मृतकों के परिवारों/आश्रितों को 32 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है, जबकि अन्य विचाराधीन हैं।

अब तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन मामलों में निष्पक्ष, तरीके से जांच की जा रही है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष, 2023-24 के आबकारी नियमों के उल्लंघन मामले में मैसर्स महेंद्र सिंह, एल-13 लाइसेंसधारी, जिला यमुनानगर के विरुद्ध भी कार्रवाही शुरू की है। कलेक्टर (आबकारी) द्वारा जारी आदेश पृष्ठांकन संख्या 3801/X-VI, पंचकुला दिनांक 20.11.2023, के तहत रुपये 2,51,00,000/- का जुर्माना लगाया गया, पृष्ठांकन संख्या 3853/X-VI, पंचकुला दिनांक 22.11.2023 के तहत एल-13 लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, जिला यमुनानगर में मैसर्स महेंद्र सिंह के 11 जोन के एल-2/एल-14ए लाइसेंस, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 37 के प्रावधानों के अलावा कलेक्टर (आबकारी), हरियाणा के आदेश पृष्ठांकन संख्या 3869/X-VI पंचकुला दिनांक 23.11.2023 के तहत रद्द कर दिए गए। इन 11 जोन को विभाग द्वारा नीलामी में पुनः आवंटित किया गया है।

दिनांक 07.11.2023 को जहरीली शराब की इस घटना से पहले राज्य भर में खुदरा दुकानों से 2193 नमूने लिए गए थे और 07.11.2023 के बाद अब तक कुल 2875 नमूने लिए गए हैं। आबकारी नीति 2023-24 के प्रारंभ (दिनांक 12.06.2023) होने से अब तक राज्य भर में कुल 5068 नमूने खुदरा शराब विक्रेताओं से लिए गए हैं।

अवैध एवं नकली शराब के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन एवं तत्परता से कार्यवाही की जाती रही है। जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	कुल अंकित अभियोग	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	बरामदगी (बोतल/लीटर में)		
			शराब (बोतल/लीटर)	अंग्रेजी शराब (बोतल/लीटर)	बीयर (बोतल/लीटर)
2016	16263	18118	377778	549884	94967.7
2017	14536	15497	922958	761047	73910
2018	11532	12137	862914	702540	36592
2019	10476	10824	907575	923972	48104
2020	11220	13051	676546	567734	57918
2021	10562	11664	397946	355340	31939
2022	13408	13819	535320	320031	54753
2023 (30 नवंबर तक)	9898	9733	642237	135932	25046

नोट:- दर्ज मामलों की संख्या और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित डेटा C.C.T.N.S पोर्टल से लिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रदेश में दिनांक 11.11.2023 से 14.12.2023 तक अवैध खुर्दा के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें कुल पंजीकृत 1466 अभियोगों में 1463 गिरफ्तारियां की गयीं, जिसमें देशी बोतलें-43008, अंग्रेजी बोतलें-25419, बीयर बोतलें-2057, लाहन-7895 लीटर व कच्ची शराब-939 बरामद की गयी। दिनांक 12.12.2023 को अभियान के अन्तर्गत एफआईआर संख्या 407 दिनांक 12.12.2023 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी व 61(1) (सी), 63ए, 72ए-4-20 एक्साइज एक्ट थाना धारूहेड़ा, रेवाडी दर्ज की गई। जिसमें ओल्ड मोंक बोतल-05, देशी शराब के पच्चे-13490, ओल्ड मोंक शराब बोतल कैपिंग मशीन, बोतल 500डीएस-08, कलर बोतल-12 लीटर, एक 65 लीटर ड्रम कास्टिक कारमेल स्प्रींट घुलनशील जिसे मापने पर 10 लीटर पाया गया, केमिकल-10 लीटर,

एक ड्रम में भरा हुआ आदि बरामद किया गया है और मामले की जांच के दौरान 13 ड्रम केमिकल, एक कैंटर, 306 पेटी शराब और 20000/- रुपये भी बरामद किये गये हैं। जहां तक विभिन्न जिलो में एल-1 एल-13 के गोदामों में कुल 75250 पेटियों की कमी का सवाल है, यहां यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग की सामान्य प्रक्रिया के तहत दिनांक 07.11.2023 से लेकर अब तक एस-1 लाइसेंसधारियों के 18 उल्लंघन के मामले और एल-13 लाइसेंसधारियों के 17 आबकारी नियमों के उल्लंघन के मामलों का पता लगाया है, जिसमें क्रमानुसार 9,914 पेटियां और 59,435 पेटियां कम पाए गईं। ऐसे मामलों में, जहां एल-1 और एल-13 लाइसेंसधारी अतिरिक्त आबकारी शुल्क से बचने के लिए आबकारी नीति 2023-24 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, विभाग द्वारा नियमित तौर पर आबकारी नीति के खंड 4.7 (जो एल-13 लाइसेंसधारियों से संबंधित है) व खंड 5.6 (जो एल-1 लाइसेंसधारियों से संबंधित है) के अनुसार सख्ती से जुर्माना लगाया जाता है।

हरियाणा में नशे की ओवर डोज से मौत के मामले बहुत कम हैं। पिछले 5 वर्षों में यानी 2017-2022 तक नशीली दवाओं के अधिक सेवन के कारण 34 मौतें हुई हैं।

जहां तक कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान अनियमितताओं का सवाल है, राज्य सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1.विशेष जांच दल का गठन

इस मामले में अवगत करवाया जाता है कि आदेश संख्या 6/2/2020-2एच.सी. दिनांक 11.05.2020 के तहत, गृह विभाग, हरियाणा ने खरखौदा-महिंदू रोड, सोनीपत, हरियाणा में अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के स्टॉक से चोरी के मामले की जांच करने के लिए श्री टी.सी. गुप्ता, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत, अधिकारिता, नवीकरणीय ऊर्जा एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एस.ई.टी.) का गठन किया। दिनांक 30.07.2020 को, विशेष जांच दल (एस.ई.टी.) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें रिपोर्ट में उल्लिखित चूकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिशें और आबकारी विभाग के कामकाज में व्यवस्थित सुधार के लिए सुझाव अनुशंसित उपाय भी शामिल हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई, जिनका वर्णन नीचे वर्णित पैराग्राफ में किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे मामले की जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जाए।

2.अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन

विशेष जांच दल की रिपोर्ट के अनुवर्ती के रूप में, श्रीमति कला रामचन्द्रन, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी तथा श्री श्रीकांत जाधव, आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अन्य कमेटी का गठन किया गया। 14 मामलों में 27 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

3. आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उठाये गए कदम

यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग द्वारा श्री धीरेन्द्र सिंह, आबकारी निरीक्षक को दिनांक 17.12.2020 को आरोप पत्र जारी किया गया है। इसी मामले में धीरेन्द्र सिंह, आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध जिला सोनीपत में एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 7 ए. ई. टी. ओ. के विरुद्ध भी हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए हैं। इससे आगे भी अगर पढ़वाना हो तो मैं पढ़ देता हूँ अन्यथा इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

आवाजें: ठीक है, जी इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: अब श्री अभय सिंह चौटाला अपनी सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बा चौड़ा जवाब सदन में पढ़ा है। यह जो लम्बा चौड़ा जवाब दिया गया है इसमें इतनी खामियां हैं कि पढ़ते-पढ़ते मंत्री जी परेशान हो गये और इन्होंने स्वयं कहा है कि इस तरह की गलत बात मुझसे हाउस में न पढ़वाई जाये।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कब कही है कि मुझसे गलत बात न पढ़वाई जाये? यहां पर सारा हाउस बैठा हुआ है। मैंने यह बात कब कही है कि मुझे गलत बात न पढ़वाई जाये?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि मुझसे पच्चे के बारे में भी बुलवाया जा रहा है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा था कि मुझसे पच्चे भी कहलवाये जा रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हरियाणा में नशे की ओवरडोज से हुई मौत के मामले बहुत कम हैं। पिछले 5 वर्षों में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक नकली दवाओं की ओवरडोज के कारण 34 मौत हुई हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, नकली दवाओं और नशे की ओवरडोज दो अलग-अलग चीजें हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के एक-एक गांव में चिट्टे की वजह से, कैमिकल नशे तथा नशे की ओवरडोज की वजह से सैंकड़ों मौत हुई हैं। मैं जो मौत हुई हैं उनके बारे में तथा उन गांवों के बारे में बता सकता हूं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं एक जिम्मेदार सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि सरकारी रिकॉर्ड में तो यही 34 मौतों का आंकड़ा है अगर इनके पास अन्य मौतों की कोई जानकारी है तो ये रिपोर्ट दर्ज करवाएं। अपराध छिपाना भी गलत है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर बहुत बार चर्चा हुई है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अपराध को छुपाना भी तो अपराध है। जिन-जिन गांवों में ऐसे युवक हैं आप उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। अब सरकारी रिपोर्ट तो यही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से मंत्री जी कहते हैं कि ओवर डोज की वजह से या जहरीली शराब की वजह से मौत हुई हैं जबकि 20 मौत तो यमुना नगर और अम्बाला में हो गई हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मंत्री जी ने ओवर डोज के बारे में कहा है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उसमें ओवर डोज भी माना जाएगा और जहरीली शराब भी मानी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मंत्री जी ने जहरीली शराब का अलग आंकड़ा दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आदमी नशे की ओवर डोज से ही मरता होगा। अगर आप हर रोज की अखबारों की कटिंग भी निकलवाकर देख लेंगे तो एक साल के अन्दर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबार में एक आधी खबर फतेहाबाद, डबवाली, सिरसा और रानियां में मौत की नहीं होती होगी। ऐसी खबरों से सारा का सारा अखबार भरा रहता है। वहां पर रोज लोग मरते हैं। मंत्री जी को विभाग ने सबसे पहले तो यहीं गुमराह कर दिया और

मंत्री जी भी हाऊस में उसको पढ़कर बता रहे हैं। मंत्री जी कम से कम इस तरह की चीज तो ना पढ़ें जो सार्वजनिक रूप से सभी सांझा हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, अगर आपके पास कोई और तथ्य हैं तो उसकी हाऊस को भी जानकारी दें और मंत्री जी को भी जानकारी दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो रोज अखबार की खबर है इसमें तथ्य की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपके पास जो भी जानकारी है चाहे वह अखबार की ही है तो भी आप उसको बताएं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा के अन्दर इस तरह ओवर डोज से अब तक 400-500 से ज्यादा नौजवान बच्चों की मौत हो चुकी है जिनकी उम्र 18 से 25-30 साल है। आप यहां केवल पढ़वा देते हैं कि केवल इतनी मौत हुई हैं। इससे बड़ा झूठ क्या होगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर इनके पास कोई ऐसी डिटेल है तो ये हमें दे दें हम इंकवायरी करवा देंगे। मैं उसकी जांच करवा दूंगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह डिटेल कल ही मंत्री जी को दे दूंगा कि अब तक कितने बच्चे मर चुके हैं।

श्री अनिल विज : अभय जी, आप मुझे डिटेल दे दीजिए, मैं उसकी जांच करवा दूंगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कल ही अपने हल्के व रानियां हल्के की डिटेल दे दूंगा और बाकी की डिटेल भी मंगवा दूंगा।

श्री अनिल विज : ठीक है, आप मुझे वह डिटेल दे दीजिए मैं उसकी जांच करवा दूंगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं वह सारी डिटेल मंगवा दूंगा। इसके साथ-साथ विषय में पिछले विधान सभा सत्र के दौरान इसी जहरीली शराब का जब सोनीपत में कांड हुआ था और हमने जब सदन में चर्चा की थी और उस वक्त मंत्री जी ने सदन में जो आंकड़े प्रस्तुत

किये थे और जो आंकड़े लोकसभा में भेजे गए थे उसमें एक अन्तर था। उस वक्त मंत्री जी ने हाऊस में एक बात कही थी कि जिन अधिकारियों ने मुझ से गलत पढ़वाया है मैं उन अधिकारियों के खिलाफ मैं 15 दिन के अन्दर-अन्दर कार्यवाही करूंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि उसमें आपने क्या कार्यवाही की है? उस समय कौन अधिकारी था उसका नाम भी बताया जाए। जिसने इस तरह की रिपोर्टिंग यहां विधान सभा में भी और लोक सभा में भी करवाई है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हाल ही में जो शराब घोटाला हुआ है। जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं उसके बाद जो जांच करवाई गई है उस जांच के अन्दर आपके अलग-अलग जो एल-1, एल-13, एल-14 है या जो भी है जहां आपके गोदाम बनाए गये हैं वहां से फिर 75 हजार 250 शराब की पेटी कम पाई गई हैं। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? वे कौन-कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आपने कार्यवाही की है? आप उनके नाम भी बता दीजिए कि इन-इन लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है और ये-ये लोग इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ भी आपकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अलावा मंत्री जी ने स्वयं अभी पढ़ा है कि इसमें दो जांच हुई हैं जिसमें मंत्री जी ने कहा है कि पहली जांच तो टी.सी.गुप्ता जी से करवाई गई है और दूसरी जांच एक आई.पी.एस. अधिकारी से करवाई गई जो एडिशनल डी.जी. था जो आपके विजिलेंस के अन्दर लगा हुआ था। उसमें विजिलेंस वाले की जो रिपोर्ट है जैसा कि आपने कहा है कि जांच करवाई है तो फिर उस जांच की रिपोर्ट कहां है। वह रिपोर्ट आपने क्यों नहीं प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के अनुसार कौन-कौन लोग उसमें शामिल थे और उनके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें यह सब पढ़ा तो है उस समय माननीय सदस्य थोड़ी देर के लिए सो गये थे लेकिन मैं तो पढ़ता रहा था।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी लगातार सुन रहा था। उसके अलावा लोक डाउन के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी उसके ऊपर मंत्री जी समय रहते अगर सख्त कार्यवाही करते तो फिर आज इन सब चीजों के लिए मंत्री जी को फिर से कटघरे में खड़ा नहीं होना पड़ता। फिर

से आज इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। इन सबका कारण मंत्री जी के अपने विभाग के अन्दर पुलिस स्टाफ की कमी की वजह से है जो 21 हजार के करीब हैं। पुलिस कांस्टेबल या दूसरे और पदों के कर्मचारियों की कमी भी एक कारण है कि जिसकी वजह से भी इस किस्म के हादसे रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री जी को हाऊस के अन्दर पूरे विस्तार से इन सारी बातों की जानकारी देनी चाहिए। इसके अलहदा एक चीज और है। आबकारी विभाग की तरफ से यह बताया गया था कि सी.सी.टी.वी. कैमरे लगायेंगे और क्यू.आर. कोड भी लगायेंगे। ट्रेस सिस्टम के तहत सी.सी.टी.वी. कम्पैराज लगाये जायेंगे इनको लगाने का सरकार भी दावा करती है परन्तु कैग की रिपोर्ट 2020-21 में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विभाग के नियमों की पालना न करने की वजह से शराब का व्यापार करने वालों को सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब यह है कि जब समय रहते आपने यह फैसला किया था तो उस वक्त फैक्ट्रियों के अंदर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाते, क्यू.आर. कोड लगाते तो आज इस किस्म के हालात न होते? अध्यक्ष महोदय, खुद डिपार्टमेंट ने यह माना है कि उनमें यह कमी रही है और कमी की वजह से आज तक इस चीज को पूरा नहीं कर पाये हैं। इसके अलहदा शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों के जो स्टोरेज हैं, वहां पर उच्च स्तरीय फ्लो मीटर लगाये जाने चाहिए थे, वे भी नहीं लगाये गए। कैग की रिपोर्ट का कहना कि डिस्टिलरियों द्वारा बनाई गई शराब के अतिरिक्त न्यूट्रल एल्कोहल की मात्रा का निर्धारण और निगरानी के लिए विभाग द्वारा नियमानुसार डिस्टिलरियों में कोई भी फ्लो मीटर नहीं लगाया गया।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा करता हूँ कि ध्यानाकर्षण सूचना का कुछ उत्तर फिर से पढ़ देता हूँ जब मैं ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर पढ़ रहा था तो कुछ माननीय सदस्यों ने कह दिया था कि इसको पढ़ा माना जाये तो इस प्रकार इन्होंने शायद इसको पूरा नहीं पढ़ा है। अब मैं जो बचा हुआ रिप्लाइ है, उसको भी पढ़ देता हूँ, जो इस प्रकार है:-

" तथा 1 ए.ई.टी.ओ. के विरुद्ध नियम 8 का आरोप पत्र जारी किया गया है जिन्होंने 27.03.2020 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान परमिट स्वीकृत किए थे। इस अवधि में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा 15 आबकारी

निरीक्षकों को हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए, जिन्होंने 27.03.2020 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान शराब की दुकानों को परमिट और पास जारी किये गए थे, जबकि कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। आगे यह उल्लेख किया जाता है कि जिला सोनीपत में अनुबंधित चपरासी सुनील कुमार की सेवा को भी समाप्त कर दिया गया है। 15 में से 13 आबकारी निरीक्षकों के आरोप पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किए गए हैं। इन सभी मामलों में उचित दंड लगाए गए हैं जिनमें संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकना, 6% पेंशन राशि को स्थायी रूप से रोकना आदि शामिल है।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी एवं कराधान विभाग ने SET की सिफारिशों पर काम करते हुए व्यवस्थित सुधार के लिए सक्रिय रूप से अनेक गुणात्मक कदम उठाये हैं। विभाग ने अवैध शराब से होने वाले राजस्व नुकसान को रोकने हेतु भी अनेक कदम उठाये हैं।

1. डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों से अवैध शराब की आपूर्ति रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं-

(क). राज्य के सभी डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में अत्याधुनिक सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गए हैं जिनको मुख्यालय स्थित एकीकृत नियंत्रण कक्ष से जोडा गया है। इन कैमरों से लाइव फीड मुख्य कार्यालय के साथ-साथ जिला स्तर पर डी.ई.टी.सी. को भी उपलब्ध कराई जा रही है। आबकारी नीति 2023-24 के खंड 12.3 के प्रावधानों के अनुसार एल-1 और एल-13 लाइसेंसधारियों के परिसर में भी सी.सी.टी.वी. कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा, शहरी दुकानों के प्रवेश, निकास व बिलिंग काउंटरों और अहातों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर भी सी.सी.टी.वी. कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं।

(ख). डिस्टिलरी के साथ-साथ बॉटलिंग प्लांट में भी प्रवाह (फ्लो) मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संदर्भ में डिस्टिलरी नियमों में भी जरूरी बदलाव किये गए हैं और विभाग द्वारा प्रवाह (फ्लो) मीटरों से संबंधित मानक भी तय कर दिये गए हैं।

(ग). यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि स्प्रिट के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जी.पी.एस. युक्त हों और इन वाहनों में ई-लॉक प्रणाली की भी व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्प्रिट ले जाने वाले ऐसे वाहनों के सभी आउटलेट पर टैम्पर प्रूफ सील लगाई जाए। इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

घ. आबकारी नीति 2023-24 के खंड 12.1 के तहत शराब की बोतल पर हॉलोग्राम लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी उत्पादकों के लिए अपने परिसर से अंग्रेजी व देसी शराब आपूर्ति से पूर्व सभी बोतलों पर हॉलोग्राम लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ-साथ विभाग ने 12.12.2023 से पायलट आधार पर राज्य के सभी डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में क्यू. आर. कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि अति सुरक्षा युक्त हॉलोग्राम लगी अंग्रेजी व देसी शराब आपूर्ति की पूरी कड़ी की निगरानी की जाये।

2. विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए नियमित रूप से शराब के ठेकों की जाँच की जाती है। राजस्व हानि को रोकने के लिए आबकारी नीति 2023 में अवैध शराब की बिक्री से 24 संबंधित कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ विभाग द्वारा की गई त्वरित और कड़ी कार्रवाई से शराब लाइसेंसधारियों द्वारा कोटा उठाने में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क अतिरिक्त, आबकारी शुल्क व परमिट शुल्क के रूप में सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। वर्तमान आबकारी नीति वर्ष, 2023-24 में दिनांक 12.06.2023 से 20.11.2023 की अवधि के लिए आबकारी राजस्व पिछले आबकारी नीति वर्ष की

इसी अवधि की तुलना में 22.70% बढ़ गया है जो कि विभाग द्वारा आबकारी नीति को सही ढंग से लागू करने का नतीजा है।

अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए अधिकांश शराब के ठेकों पर बिल जारी करने हेतु प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें लगाई गई हैं। बाकी बचे ठेकों पर मशीनें न लगाने को लेकर आबकारी नीति के तहत जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि वो भी इस प्रावधान का पालन करें।

अवैध और नकली शराब को रोकने के लिए हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। धारा 61 के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाया गया है। इसके अलावा, मार्च, 2020 में संशोधन के माध्यम से धारा 72ए पेश की गई, जिसमें हानिकारक दवा या विदेशी घटक वाली शराब के कारण मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि हॉलोग्राम तथा डिस्टिलरी व ठेकों पर सीसीटीवी कैमरे संबंधी आदर्श प्रणाली (SOP) की पालना नहीं हो रही। जैसा की ऊपर वर्णन किया गया है आबकारी नीति, वर्ष 2023-24 में हॉलोग्राम अनिवार्य किया गया है, तथा डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाये गए हैं जिनको मुख्यालय स्थित एकीकृत नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है, एल-1 और एल-13 लाइसेंसधारियों के परिसर में भी सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। सही मायने में विभाग द्वारा सक्रिय रूप से नये कदम उठाये गए हैं जो कि राज्य के सभी डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में क्यू.आर. कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने से साबित होता है।

4. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई जांच

मुख्य सचिव सरकार कार्यालय के आदेश पत्रांक 33/26/2020-3Vig (1) दिनांक 31.08.2020 के अनुपालन में द्वारा सूचित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा में जांच संख्या 04 दिनांक 01.09.2020 दर्ज की गई है। लॉकडाउन के दौरान शराब

की बड़ी अनधिकृत आवाजाही में कुछ आबकारी एवं कराधन विभाग अधिकारियों के साथ-साथ कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत की जांच की जाएगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

इस राज्यव्यापी जांच के दौरान, एसीबी ने इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अभियोगों के विवरण सहित प्रासंगिक रिकॉर्ड एकत्र किए हैं। इसके अलावा, एसीबी ने अब तक की पूछताछ के दौरान शराब ठेकेदारों, आबकारी एवं कराधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों, पुलिस विभाग के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों और डिस्टिलरी, ब्रुअरीज और बॉटलिंग प्लांट से संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं ताकि इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान पूरे मामले में उनकी विशिष्ट भूमिका के साथ की जा सके।

दिनांक 16.12.2023 के पत्र संख्या 21042/आई-1/एसीबी (एच) पंचकुला द्वारा प्राप्त उपरोक्त जांच की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, एसीबी ने कुछ रिकॉर्ड मांगे हैं जो अभी भी आबकारी एवं कराधन विभाग तथा अन्य विभागों से वांछित हैं। रिकार्ड मिलते ही अंतिम जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

एसीबी द्वारा आगे सूचित किया गया है कि इस मामले में कई सीडब्ल्यूपी माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी लंबित हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के दूसरे कार्यकाल को भी चार वर्ष हो गए हैं और इस कार्यकाल में जहरीली शराब का मामला पहली बार नहीं आया है बल्कि लगातार आ रहा है। सवाल यह है कि यह क्यू.आर. कोड पिछले चार साल से क्यों नहीं लगा है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब दे तो रहा हूँ कि क्यू.आर. कोड अब बोटलों पर लगना शुरू हो गया है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, अब बहस करने का समय नहीं है। आप प्लीज इस विषय पर बहस न करें।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं बहस की कोई बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आपने इस ध्यानाकर्षण सूचना पर 3-4 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिए हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई अलग बात तो नहीं पूछी है।

श्री अध्यक्ष: बात क्यों नहीं पूछी, आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब मंत्री जी ने दिया तो है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, क्या जवाब दे दिया मंत्री जी ने ?

श्री अध्यक्ष: जो भी जवाब दिया, आपके सामने ही दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वयं यह माना है कि अभी क्यू.आर. कोड लगाना शुरू किया है लेकिन मैं यह पूछ रहा हूँ कि अभी चार वर्ष तक क्या सरकार सोई हुई थी? सरकार क्या कर रही थी ? पहले जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी तो उसके बाद से सरकार ने क्या कार्रवाई की है ? अब मैं 2020-21 की राजस्व की जो रिपोर्ट है उसको पढ़कर सुना रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: यह सारी बातें तो पहले ही आ गई हैं। अब अगर आपने कोई और प्रश्न पूछना है तो उसको पूछ लें। आपने अब तक चार प्रश्न पूछ लिए हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए लेकिन बहस मत कीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो आधी बात भी नहीं पूछी गई है। मैं तो प्रश्न ही पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: देखिए, कालिंग अटेंशन नोटिस के संदर्भ में सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, दो-चार प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन बहस नहीं की जाती है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही तो पूछ रहा हूँ और बताओ मैं क्या पूछ रहा हूँ?

श्री अध्यक्ष: आप केवल सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं। जो लिखा हुआ है मंत्री जी वही तो पढ़कर सुना रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसको लिखा किसने है ? लिखा हुआ तो मंत्री जी पढ़कर सुना ही रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो जो इन्होंने लिखा हुआ है, उसका जवाब मांग रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो गलत लिख रखा है, वह मंत्री जी सदन में लेकर आये हैं और इसलिए मंत्री जी गलत ही पढ़ रहे हैं। जो सही और सरकारी आंकड़े हैं, मंत्री जी उनका जवाब क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष: अभय जी, यह प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वही प्रश्न तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैग की 2020-21 की रिपोर्ट है, क्या मंत्री जी ने उस 2020-21 की कैग की रिपोर्ट को पढ़ा है ?

श्री अनिल विज: नहीं पढ़ा है, अब बताओ। (हंसी)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट इनको पढ़नी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, आखिरकार मंत्री जी को सदन में जवाब देना होता है तो मंत्री जी को यह रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। जो सवाल मैंने आपसे किया है उसका जवाब मंत्री जी देंगे या कोई और देगा ? जितना मंत्री जी इस बात को हंसी में टालने की कोशिश कर रहे हैं, जितना किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह मेरी समझ से बाहर है कि इन जैसा सीनियर मंत्री भी क्या इस तरह की बात करेगा?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है कि इस रिपोर्ट को पी.ए.सी. पढ़ती है और फिर वह कंसर्ड डिपार्टमेंट को बुलाकर इन्क्वायरी करती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कैग की रिपोर्ट को सब नहीं पढ़ते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा है उसमें कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि कैग की रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक राजस्व का जो नुकसान बताया गया वह इस प्रकार दिया गया है कि प्रदेश के राजस्व को लगभग 106 करोड़ और 71 लाख रूपये की चपत लगाई गई है और विभाग के अधिकारियों ने आडिट अधिकारियों के बीच में इस बात को स्वीकार भी किया है कि उनसे गलती हुई और उनकी गलती की वजह से इतना

बड़ा नुकसान हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो अधिकारी शामिल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मेरा निवेदन है कि यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, वह जहरीली शराब के कारण जो मृत्यु हुई है, उसको लेकर है। इसलिए पिछली 2020-21 की रिपोर्ट या फलाना-डमकाना पर माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। इसलिए केवल स्पेसिफिक जवाब दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब जो जहरीली शराब की वजह से नुकसान हो रहा है, जो नकली ठेके चल रहे हैं उनका सदन में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जहरीली शराब के बारे में उत्तर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, मंत्री जी ने जहरीली शराब का जवाब देते हुए बताया है कि कितने लोगों पर केस दर्ज हुए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, खरखोदा में इतनी जहरीली शराब पकड़ी गई थी क्या वह जहरीली नहीं थी ? मंत्री जी का जवाब आउट ऑफ कांटेस्ट है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, मंत्री जी ने जहरीली शराब का भी जवाब दिया है और कहा है कि इतनी शराब उन्होंने पकड़ी है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने भी सरकार का पक्ष ले लिया है और कह रहे हैं कि मंत्री जी ने जवाब दिया है, अगर जवाब दिया है तो मंत्री जी बता दें कि मंत्री जी ने जो विजिलेंस की इंक्वायरी करवाई थी, वह रिपोर्ट कहां पर है ?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पढ़कर बताया था कि जो टी.सी.गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसके द्वारा क्या-क्या एक्शन लिए गए , किन-किन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, किसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई । मैंने ये सारी बातें बताई हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बतायें कि क्या उन्होंने श्रीकांत जाधव की तरफ से जांच करवाई ? उस जांच की रिपोर्ट कहां है ? वह रिपोर्ट कहां रखी है, यह बताओ ? आखिरकार सरकार किसको बचाने का काम कर रही है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट भी दे देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हम तो रिपोर्ट ही तो मांग रहे हैं। विज साहब से तो मैंने वह जवाब भी मांगा था कि जहरीली शराब की वजह से कितने लोग मरे तो इस विषय के बारे में लोक सभा में कुछ और जवाब दिया गया था लेकिन विज साहब की तरफ से विधान सभा में कुछ अलग जवाब दिया गया था और इन्होंने तो यह भी कहा था कि 15 दिन में इसकी रिपोर्ट दे दूंगा, बताओ कहां गई वह रिपोर्ट और आपने उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का काम किया ?

श्री अध्यक्ष: बलराज कुंडू, जी अब आप अपनी बात रखिए ? अभय जी आप सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन बहस करना जरूरी नहीं है।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: बलराज जी, आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी बात का जवाब आ जायेगा। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: बलराज जी, आपका समय जा रहा है, आपने कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए ?

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न पूछना है लेकिन उससे पहले अभय जी को कहना चाहूंगा कि उनके बोलने में और मेरे में एक फर्क यह है कि उनको तो सरकार यह मान लेती है कि वे इंटरनेशनली बोल रहे हैं और मैं आपकी बात के साथ जो बोल रहा है, वह इस बात पर मुहर लगाने की बात कर रहा हूँ कि यह पक्की बात है कि घोटाला हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की जहरीली शराब से हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिकों की मृत्यु हो रही है और यह कोई पहली बार नहीं हो रही है बल्कि एक साल पहले पानीपत में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें काफी मौतें हुई थी। इस प्रकार की घटनाओं को कैसे

रोका जाये महत्वपूर्ण बात यह है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का कोई फायदा नहीं है। हम इस तरह की चीजों को रोककर किस प्रकार से अपने प्रदेश के लोगों को सेफ करें यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में 5 वर्षों की जो बात कही है इसके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने करीबन 6-7 महीने पहले उनको लिखित दस्तावेज दिया था। वह मेरे क्षेत्र महम से संबंधित मुद्दा था। अकेले मेरे महम शहर में पिछले चार साल में अनेक मौतें हो चुकी हैं। उसका मैंने माननीय मंत्री जी को लिखित में ब्यौरा दिया था। मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठा बेचने वालों की कम्प्लेंट भी की थी। उसी दौरान तीन-चार घर ऐसे बर्बाद हुए थे जहां इकलौते बच्चों की डैथ हुई थी। वे शायद सरकार के रिकॉर्ड में होंगे भी नहीं। सरकार ने पूरे हरियाणा में शराब की ओवरडोज की वजह से सिर्फ 34 मौतों की बात की है। वह उस टाइम का ताजा डाटा था जिसमें एक से डेढ़ महीने के अंदर हुई मौतों की बात थी। उनमें ऐसे बच्चे थे जो अपने घर के इकलौते बेटे थे। वह रिकॉर्ड मैं माननीय मंत्री जी को रिटन में देकर गया था। अतः पहले तो माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट को दुरूस्त कराएं। ये रिपोर्ट जिस किसी अधिकारी ने माननीय मंत्री जी को दी है यह टोटली गलत है। माननीय सदस्य अभय सिंह जी ने जो बोला है इसमें बिल्कुल सच्चाई है। गांवों में ओवरडोज की वजह से सैंकड़ों-सैंकड़ों बच्चों की मौतें हो चुकी है। यह बहुत गंभीर विषय है। जिस भी अधिकारी ने माननीय मंत्री जी को मिसलीड करने के लिए यह रिपोर्ट भेजी है उसको माननीय मंत्री जी सीरियस लें ताकि कोई गलत रिपोर्ट सदन के समक्ष न आये। यह बहुत गंभीर विषय है। दूसरी बात यह जो शराब की पेटियां कम हो रही हैं इससे आबकारी एवं कराधान विभाग के उपर बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लग रहा है। क्यू.आर. कोड और कैमरे लगाने की बातें हम पिछले तीन साल से सुनते आ रहे हैं कि सरकार लेटेस्ट टेक्नोलोजी लाकर क्यू.आर. कोड लगाने जा रही है। इस समय सदन में माननीय उप-मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। ये बातें हम इसी सदन में साढ़े तीन-चार साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि हम ऐसी पॉलिसी बना देंगे, इतना रिवैन्यू बढ़ाने जा रहे हैं आदि। अब सरकार की जाने की बारी आ गई है तो सरकार कह रही है कि अब सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगेंगे और क्यू.आर. कोड भी लगेगा। यह कैसी बात है? अब तो सरकार

की विदाई का टाइम आ गया है। सरकार की विदाई के लिए जनता इंतजार में बैठी है और अब सरकार इन को लगाने की बात कर रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलराज जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ही है और यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। जिस क्यू.आर. कोड को और कैमरे लगाने की सरकार बातें करती थी वे अभी तक क्यों नहीं लगे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बलराज जी, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कैमरों और क्यू.आर. कोड के संबंध में है। प्लांट के अंदर सरकार कैमरे लगाने और शराब की बोटल के उपर क्यू.आर. कोड लगाने की जो बात करती थी वे कार्य कब पूरे होंगे ? आज शराब की वजह से बहुत ज्यादा मौतें हो चुकी हैं जबकि 4 साल पहले सरकार इतनी बड़ी-बड़ी दावेदारी कर रही थी कि हम इसको रोक कर ऐसा करेंगे लेकिन आज तक इसका कुछ भी समाधान नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दयालु योजना का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने सिर्फ आठ मृतकों के परिवारों/आश्रितों को हैल्प देने की बात की है। प्रदेश में जहरीली शराब से इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं। ऐसे में या तो सरकार इस योजना को हटा ही देती ताकि यह तो नहीं पता चलता कि सरकार ने सिर्फ आठ गरीब लोगों को हैल्प दी है। जब मौतें इतनी ज्यादा हो गईं तो सबको इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जाता ? खरखौदा की बात जो पिछले काफी दिनों से उठ रही है उस मामले में एक गरीब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिज पर चपड़ासी की नौकरी लगा था उसको बलि का बकरा बनाकर रिपोर्ट को खत्म कर दिया गया। वास्तव में जो अधिकारी उसके अंदर सम्मिलित थे, जो मोटी मछलियां थी और जिनको उपर से मोटा संरक्षण प्राप्त था उनका रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है। अतः सरकार इसके उपर गंभीरता से विचार करके एक्शन ले। यह तो माननीय मंत्री जी के क्षेत्र अम्बाला और यमुनानगर का मामला है। माननीय मंत्री जी को तो गब्बर कहा जाता है। अतः गब्बर जी की आंख के नीचे दिये तले अंधेरा कैसे हो रहा है ? माननीय मंत्री जी इसे देखें। माननीय मंत्री जी का बड़ा नाम है और हम इनकी रिस्पैक्ट करते हैं और इनके आश्वासन पर विश्वास भी करते हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है कि हर कनेक्टिड आदमी को अरेस्ट किया गया है चाहे वह शराब बनाने वाला हो, चाहे जगह देने वाला हो, चाहे जगह दिलाने वाला हो, बोतलें सप्लाई करने वाला हो, चाहे स्टीकर सप्लाई करने वाला हो, चाहे ढक्कन सप्लाई करने वाला हो और जो ऑरिजनल ठेकेदार था उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। उस ठेकेदार ने जिसको सब्लैट किया और उस सब्लैट ठेके से जिन कारिंदों ने शराब बेची हमने उनको भी गिरफ्तार किया है। यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी मामले में शामिल एक भी आदमी को नहीं छोड़ा। अभी सिर्फ एक आदमी भागा हुआ है जो हमारे काबू नहीं आ रहा है लेकिन हम उसको भी पकड़ लेंगे। (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला रूक क्यों नहीं रहा है ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमारे संज्ञान में यह मामला आया वैसे ही पुलिस ने बड़ी सख्ती और मुस्तैदी के साथ काम किया है। हमने एक-एक आदमी को डैड एंड तक पकड़ा है। माननीय सदस्य किसी एक भी आदमी का नाम बता दें जिसको हमने न पकड़ा हो। हमने इस मामले में शामिल हर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इतनी गिरफ्तारियां पहले कभी नहीं हुई हैं। पहली बार इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं। (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। दिनांक 15.12.2023 के जिस मुद्दे को सरकार ने हाई कोर्ट में भेजने का निर्णय किया है उसको तो अपने बीच में रहने दीजिए। अगर सरकार को सिटिंग जज से जांच करवानी है तो इस मुद्दे की करवाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुण्डू जी, कल फिर आप लोग ही यह कहेंगे कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से क्यों करवा रहे हो ?

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, आप इस शराब घोटाले, अमृत योजना घोटाले और टैण्डर घोटाले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाइये तब मजा आएगा। हमारे आपसी मुद्दे को हाई कोर्ट में मत लेकर जाइये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुण्डू जी, सदस्य ही पहले मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग करते हैं और फिर कहते हैं कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से क्यों

करवा रहे हो ? कल फिर आप लोग ही यह कहेंगे कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से क्यों करवा रहे हो ?

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारे देहाती में एक कहावत है कि चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो।

श्री अध्यक्ष: नीरज जी: आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। ये जहरीली शराब का घोटाला पिछली बार 26 जनवरी, 2022 में भी सामने आया था और मार्च, 2023 में भी सामने आया है। यह जहरीली शराब कहां से बन रही है? यह सिप्रिट कहां से आ रहा है? ये आपदा को अवसर कौन बना रहा है? मेरा तो बहुत सूक्ष्म सा प्रश्न है बाकी सब साथियों ने भी अपना प्रश्न पूछना है। ये जो आपने 1, 2 और 3 कमेटीज बनायी हैं क्या उनमें किसी कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि डिस्टिलरीज की जांच होनी चाहिए? अगर सिफारिश की थी तो वह जांच किसने रोकी? सरकार ने आज तक डिस्टिलरीज की जांच क्यों नहीं की कि कोरोना काल में सैनेटाइजर बनाने के बहाने से कौन-कौन लोग इस तरीके से अवैध सिप्रिट ले गये और वो सिप्रिट आगे बटती गयी जोकि अंततः आदमियों की मृत्यु का कारण बनी। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कमेटी के बाद ए.सी.बी. को जांच दे दी। स्पीकर साहब, ए.सी.बी. तो वैसे ही पंगू है। वह तो कुछ भी लिख ले उसको आगे जाकर ऊपर से परमीशन ही नहीं मिलती कि इन्वेस्टिगेशन की परमीशन चाहिए या इन्कवायरी की परमीशन चाहिए। इसमें दोनों महकमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही हैं। स्पीकर साहब, तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत ध्यान देने की बात है कि इसमें गरीब घर का बच्चा जा रहा है। ऐसा आदमी जा रहा है, जो किसी भी हालात में नशे की लत में पड़ गया। उसके बाद सरकार उसके परिवार को मुआवजे के नाम पर क्या दे रही है? इसमें सरकार 4-4 लाख रूपये मुआवजे के तौर पर दे रही है। इसको भी बढ़ाने की तरफ सोचें। तीसरी जो कमेटी बनी थी उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करें। जहां तक ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग सिस्टम की बात आ रही है तो ये घोटाले वर्ष 2020 से हो रहे हैं। स्पीकर साहब, यह दिनांक 12.12.2023 को ही लागू किया गया है। जबकि चलो यह शराबबंदी का तो अलग मसला है क्योंकि हम शराब पीने से रोक नहीं सकते। यह क्यू.आर. कोड इतना सिंपल होना चाहिए कि किसी के मोबाईल में भी

एप आ जाए। बहुत पोर्टल और डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है तो जो बोतल ले वह अपना क्यूआर. कोड स्कैन कर ले कि वह ओरिजनल है या नहीं है।

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना विधान सभा में रखी है और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। मेरे बोलने से पहले जितनी भी बहस हुई है वह मैंने सारी की सारी सुनी है और आपने भी सुनी है। अब इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो यह है कि वहां मौके पर नकली शराब कितने दिनों से बन रही थी? यह तो किसी ने नहीं बताया। वह कितने दिनों से वहां पर बन रही थी क्योंकि त्यौहारों के दिनों में आकर कोई ऐसा मसाला गिर गया जिसके कारण शराब जहरीली बन गयी। दूसरी बात यह है कि जो नाम माननीय मंत्री जी ने लिये हैं कि हमने उसको भी पकड़ा, हमने उसको भी पकड़ा, हमने उसको भी पकड़ा, हमने उसको भी पकड़ा और हमने उसको भी पकड़ा। क्या इनके अलावा कोई और पकड़ने के लिए नहीं था और भी लोग थे।

श्री अध्यक्ष: क्या किसी निर्दोष को भी पकड़ लेते?

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। इनके अलावा पकड़ने के लिए और भी लोग थे। आप यह बताएं कि जब कई महीनों से नकली शराब बन रही थी तो एक्साईज डिपार्टमेंट वाले कहां पर थे? वहां की लोकल पुलिस कहां पर थी? ये वहां सिर्फ उनकी दुकानों पर दूध पीने के लिए जाते थे या पैसे लेने के लिए जाते थे। उन्होंने मौके पर चैक क्यों नहीं किया? उन्होंने उसका मार्का क्यों नहीं देखा? मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें ये लोग भी शामिल थे जिनको माननीय मंत्री जी ने पकड़वाया ही नहीं और यह कह दिया कि हमने उसको भी पकड़ा, उसको भी पकड़ा और उसको भी पकड़ा। इतना बड़ा जवाब लेकर के आ गए। इनमें आगे असली को भी पकड़ें। क्या मैं गलत कह रहा हूँ?

श्री अनिल विज: ठीक है, जी।

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न है कि इसमें सारे गरीब घरों के लोग मरे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दयालु योजना के तहत 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रूपये दिये हैं। क्यों नहीं उनके परिवारों को 30-35 लाख रूपये दिये जाते? इन 2-3 लाख रूपये

में क्या बनेगा? आप ये बताएं कि 2-3 लाख रूपये में क्या बनेगा? आप यह कहेंगे कि शराब पीकर मर गये। हम क्या करें?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब श्रीमती किरण चौधरी जी अपनी बात रखेंगी।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इस नोटिस में मेरा नाम भी है, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिय जाए।

श्री अध्यक्ष: वरूण जी, मैंने पहले 5 माननीय सदस्यों के नाम लिए हैं। चूंकि संबंधित नोटिस में

15:00 बजे

तो 14 माननीय सदस्यों के नाम हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, आपने एडजर्नमेंट मोशन को कंवर्ट करके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बना दिया, उसके बावजूद भी इनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हो । मेरा इसमें यह कहना है कि माननीय सदस्य अपना एक-एक सवाल तो पूछेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, मैंने आपकी पार्टी के पांचों माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है । आपने एडजर्नमेंट मोशन को कंवर्ट करके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बना दिया । क्या आपने सिर्फ इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट कर दिया कि इनको बोलने का मौका न मिल सके । मेरा आपसे इसमें यही कहना है कि इनको एक-एक सवाल पूछने के लिए एक-एक मिनट की इजाजत दे दी जाये ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी शराब के विषय को लेकर चर्चा हो रही है और मैं इस चर्चा को सुन भी रही थी । बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि स्टेट के अंदर एक के बाद एक ऐसे वाक्य हो रहे हैं । यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है कि इस तरह spurious liquor के तहत hooch tragedy हो रही है । हरियाणा प्रदेश में यह बात तीसरी बार हुई है, इसके कारण इतने सारे लोग मारे गये हैं लेकिन सरकार द्वारा खानापूति करके इस बात का जवाब दे दिया जाता है कि हम इसकी जांच करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं जो श्री बिशन लाल सैनी जी ने बात कही है कि कौन सा ऐसा पुलिस ऑफिशियल है या एक्साइज का कर्मचारी है, जिनके इलाके में ऐसा होता है और उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि यह क्या हो रहा है? इन्होंने किसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की है । दूसरी बात यह है कि जो Standard Operating

Procedure (S.O.P.) हैं, उनको मैशन किया जाना चाहिए और जिन बातों के बारे में यह कहा जाता है कि हमने यह यह कर दिया है चाहे flow meters हों और चाहे C.C.T.V. Cameras की बात हो तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जब यह शराब distilleries से निकलती है तो जो इसके flow meters बनाये गये हैं, वह सही तरह से लगाकर रखे जाने चाहिए क्योंकि अगर वे सही तरीके से काम कर रहे होंगे तो पता चल जायेगा कि कितनी शराब बाहर निकल रही है ? इसके साथ ही साथ वहां पर जो ट्रक शराब को लेकर जाते हैं, उन पर tracking device G.P.S. लगाकर रखेंगे तो इनको पता लग जायेगा कि कहां पर गलत काम हो रहा है ? हरेक इलाके के अंदर पुलिस को वैसे ही मालूम होता है कि कहां पर उल्ट पुल्ट काम हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि यह कैसे होने दिया गया? इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूं कि इनकी अपनी एस.आई.टी. रिपोर्ट में इस बात को माना गया है कि हरियाणा के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से शराब की तस्करी हो रही है । इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि एस.आई.टी. यह बात कहती है कि जो I.M.F.L. (Indian Made Foreign Liquor) है, वह दूसरी स्टेट से सीज की गई है । बिहार से 1.04 लाख cartons पकड़े गये हैं । उत्तरप्रदेश से 79,650 लाख cartons पकड़े गये हैं । झारखंड से 27,824 लाख लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है । दिल्ली से 59,179 लाख cartons पकड़े गये हैं । छत्तीसगढ़ से 10,537 लाख लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है और गुजरात से 73,131 अवैध बोटल्ज illicit IMFL (Indian Made Foreign Liquor) पकड़ी गई हैं । उसके बाद एस.आई.टी. रिपोर्ट में कहा गया है कि this is the tip of the iceberg. So, if this is the tip of the iceberg then you tell me what is the actual thing. फिर तो पता नहीं अंदर कितना गंद होगा ? क्या-क्या घोटाले होंगे और क्या-क्या हो रहा होगा ? मैं यह बात इनसे पूछना चाहती हूं और मैं इसके साथ ही साथ यह भी पूछना चाहती हूं कि जो इथनॉल की तस्करी हो रही है । जब illicit तरीके से इथनॉल निकाला जाता है तब जाकर के अवैध शराब बनती है । ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त Standard Operating Procedure क्या होगा यानी किस तरह से लेकर जाया जायेगा और पुलिस का Standard Operating Procedure क्या होगा ? एक्साइज विभाग का Standard

Operating Procedure क्या होगा ? That has not been put in place. इसमें इनकी गलती नहीं है। मैं बता रही हूँ। इनको सब कुछ करना चाहिए था। अभी तक केवल यह बात बोलते आ रहे हैं और यह Standard Operating Procedure जो है, इसको प्लेस मेंशन नहीं किया गया है। अगर यह Standard Operating Procedure सही तरीके से डाला जाता तो जो इतने सारे गरीब लोग हैं, जो बिना मिलावट के शराब पीना चाहते हैं वह पी नहीं सकते हैं और जो इल्लीगल शराब पीते हैं, उसके बाद फिर उनकी मौतें हो जाती हैं। उसके बाद परिवार बिखर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बात में सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि distilleries and bottling plants पर सरकार के फ्लो मीटर काम क्यों नहीं कर रहे हैं ? सरकार ने ट्रकों पर जी.पी.एस. सिस्टम क्यों नहीं लगाया है, हमें इसके बारे में भी बताया जाये ? इसके साथ ही साथ यह भी बताया जाये कि इतनी सारी लिटर बाहर कैसे पकड़ी जा रही है ? यह कहीं न कहीं से तो निकल रही होगी। ये कह रहे हैं कि हमने Standard Operating Procedure लगा दिये हैं तो फिर इसकी कैसे तस्करी हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें बहुत बड़ी-बड़ी मछलियों का हाथ है और उन बड़ी मछलियों के ऊपर सरकार हाथ नहीं डाल पा रही है। धन्यवाद।

**पी.एम. श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विद्यार्थीगण
तथा अध्यापकगण का अभिनंदन करना**

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि पी.एम. श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): स्पीकर सर, कॉफी प्रश्न पूछे गये हैं और मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं। स्पीकर सर, यह जो धनौरा में फैक्टरी बनी है यह दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को बनी और यह दिनांक 08 नवम्बर को पकड़ी गई। यह किसी ने गन्ने के खेतों के अन्दर जाकर बनाई हुई थी और उसके बाद हमने इसके हर फैक्ट पर कार्यवाही की है। स्पीकर सर, जहां तक कुंडू जी ने सी.सी.टी.वी. कैमरों की बात कही, ये वर्ष 2021-22 से लग चुके हैं और क्यू आर कोड अब हमने लगाने शुरू कर दिये हैं। स्पीकर सर, जहां तक यह बात कही गई कि है कि जो बड़ी मछलियां है उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। इस पर मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो मुख्य आरोपी है, वह मांगे राम है। वह *** का प्रदेश डेलिगेट है। इसके अलावा जो दूसरा अपराधी है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर सर, अपराधी केवल अपराधी है। चाहे वह इनकी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो अथवा किसी और किसी पार्टी का हो। इसमें मेरा क्या है? Why you are naming me? How can you name me. (विघ्न)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल फैक्ट की बात बता रहा हूं। जब पूछा जा रहा है तो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी नाम नहीं ले सकते। Why he has naming me? अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी नाम नहीं ले सकते।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी से संबंधित जो नाम लिया गया है, वह इन शब्दों में से निकाल दिया जाये।

श्री अनिल विज: ठीक है, चलो वह कांग्रेस पार्टी का है।

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं, मुझे अपनी बोलने के लिए मौका दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुलदीप जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा आरोपी गौरव बुग्गा है। उसके पिताजी राजकुमार ने वर्ष 2014 में इनैलो पार्टी की टिकट से रादौर से चुनाव लड़ा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह भी बताये कि वह आज कौन सी पार्टी में है? (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मुझे यह नहीं पता, मुझे रिकॉर्ड की बात पता है कि वह वर्ष 2014 में इनेलो पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हर बात को अदरवाईज ले जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यह बताये कि वह वर्ष 2014 में इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हर बात को अदरवाईज ले जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यह बताये कि वह इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा। यह काम वही लोग कर रहे हैं और कौन कर रहा है ? (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य यह बताये कि वह इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा ? ये बताये कि इन्होंने टिकट दी थी या नहीं दी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछे थे उनका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, आपके प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बहुत से प्रश्न पूछे थे लेकिन उनका जवाब माननीय मंत्री जी की तरफ से नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, इसमें बहस करने की कोई बात नहीं है। माननीय मंत्री जी के पास जो जवाब था वह उन्होंने दे दिया है। किसी भी माननीय मंत्री जी को कम्पैल नहीं कर सकते। उनके पास जो जवाब था, वह उन्होंने दे दिया है।

वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक मांगों को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक मांगों को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्य किसी भी मांग पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन उनसे अनुरोध है कि वे उस मांग संख्या को इंगित करें, जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

वर्ष 2019-2020 के लिए मांगें

कि मांग संख्या 8 भवन एवं सड़कें के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किये गये खर्च को विनियमित करने के लिए ₹126,99,64,859/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि मांग संख्या 23 खाद्य एवं आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किये गये खर्च को विनियमित करने के लिए ₹26,39,64,601/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

वर्ष 2020-2021 के लिए मांगें

कि मांग संख्या 35 पर्यटन के संबंध में वर्ष 2020-21 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किये गये खर्च को विनियमित करने के लिए ₹21,92,63,603/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

वर्ष 2021-2022 के लिए मांगें

मांग संख्या 7 आयोजना तथा सांख्यिकी के संबंध में वर्ष 2021-22 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किये गये खर्च को विनियमित करने के लिए ₹63,43,10,825/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

मांग संख्या 8 और 23

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2019-2020 के दौरान अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर मांग संख्या 8 और 23 को सदन में मतदान के लिए रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि मांग संख्या 8 भवन एवं सड़कें के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किये गये खर्च को विनियमित करने के लिए ₹126,99,64,859/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि मांग संख्या 23 खाद्य एवं आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किये गये खर्च को विनियमित करने के लिए ₹26,39,64,601/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या 35

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2020-2021 के दौरान अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर मांग संख्या 35 को सदन में मतदान के लिए रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि मांग संख्या 35 पर्यटन के संबंध में वर्ष 2020-21 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किये गये खर्च को विनियमित करने के लिए ₹21,92,63,603/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या 7

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021-2022 के दौरान अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर मांग संख्या 7 को सदन में मतदान के लिए रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

मांग संख्या 7 आयोजना तथा सांख्यिकी के संबंध में वर्ष 2021-22 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किये गये खर्च को विनियमित करने के लिए ₹63,43,10,825/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री, वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान(दूसरी किस्त) नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ।

नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री मोहन लाल बड़ौली, विधायक, चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

प्राक्कलन समिति चेयरपर्सन (श्री मोहन लाल बड़ौली) : श्रीमान जी, मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ।

वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत कर सकते हैं अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हों और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो। उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 51,19,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹6,39,41,268/- से अधिक न हो, मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन / निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 4-राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 5-गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 3,54,82,865/- से अधिक न हो, मांग संख्या 6- वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी (डी.ई.एस.ए.) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 286,61,65,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 59,33,20,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 74,72,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 12- शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/युवा मामले) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 221,89,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 17-लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/परिवहन/नागर विमानन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1126,25,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 19-ऊर्जा विभाग (विद्युत/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/ एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 260,10,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 20- नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय(स्थानीय सरकार)/विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल जी की तरफ से डिमांड संख्या 17 और 20 तथा श्री भारत भूषण बतरा जी की तरफ से डिमांड संख्या 23 और 24 के ऊपर बोलने की रिक्वेस्ट आई है।

श्री वरुण चौधरी: अध्यक्ष जी, मैं भी इन डिमांड्स पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: वरुण जी, आप जिन डिमांड्स पर बोलना चाहते हैं, वे लिखकर के दे दीजिए।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष जी, मैंने वर्ष 2023-2024 की डिमांड्स पर बोलने के लिए लिखा था।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, इसमें आपने लिखा है "I want to speak on demands No. 23 and 24" लिखा है। यह आपने ही लिखकर के दिया है।

डिमांड्स की हार्ड कॉपी सदस्यों को उपलब्ध करवाने के बारे में मामला उठाना

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं वर्ष 2023-24 के लिए डिमाण्ड नम्बर 17 और 20 पर बोलना चाहता हूं और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि सभी सदस्यों को सप्लीमेंट्री डिमांड की एक हार्ड कॉपी भी दे दी जाए क्योंकि वह बहुत जरूरी है और ये सेशन भी इसलिए बुलाया जाता है। इन डिमांड्स की हार्ड कॉपी देने में क्या एजराज है? अब मुख्यमंत्री जी के पास तो हार्ड कॉपी है इसलिए उनके लिए everything is clear to him. लेकिन हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है इसलिए nothing is clear to us.

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, हार्ड कॉपी तो फिर ज्यादा छपवानी पड़ेगी।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, उसमें क्या हो जाएगा केवल 90 कॉपी ही तो छपनी हैं। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। इससे क्लीयर हो जाता है कि किस डिपार्टमेंट की कितने पैसे की डिमांड है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इससे क्लीयर हो जाता है कि किस बात के लिए पैसे मांग रहे हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आगे से प्लीज इसको जारी कर दीजिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, उससे प्रोपर पिक्चर सामने आती है।

श्री अध्यक्ष : आगे से सभी सदस्यों को एक-एक हार्ड कॉपी दे दी जाएगी।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान(पुनरारम्भ)

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर, अनु.जा.) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नम्बर-17 पर बोलना चाहती हूं। यह डिमाण्ड बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स से सम्बन्धित है। इसमें मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे झज्जर हल्के में एक खोरड़ा रोड है जो केवल मात्र 600 मीटर का टुकड़ा है। उस पर काफी बार ट्रक पलट जाते हैं। माननीय हाई कोर्ट द्वारा उसका संज्ञान लेकर उस पर ऑर्डर भी पास कर दिये गये थे लेकिन आज तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इसी प्रकार से एक सड़क बहु गांव में खेड़ा की ओर जाती है जिसके बारे में कई बार सदन में यह बताया गया कि वह मंजूर हो गई है। इस समय उस सड़क में इतना पानी भर गया है कि वह सड़क झील टाईप हो गई है। आज तक उस सड़क

का निर्माण नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, झज्जर शहर को लेकर कई बार चर्चा हुई है मैं आपसे केवल एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमें यह कहा गया था कि गड्डों में कैमरे घुसा घुसाकर आपने सड़कों की फोटोज खींची हैं। अब उन गड्डों को भरने की बजाये पूरे झज्जर शहर की सड़कों को खोद दिया गया है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक मेरा अनुरोध यह है कि हमारी खोरड़ा गांव और गांव बहु की सड़क का नये सिरे से निर्माण करवाया जाये। जो पूरे शहर की सड़कों को खोद दिया गया है उनकी भी मुरम्मत का कार्य जल्दी से जल्दी करवाया जाये। मेरा दूसरा मुद्दा डिमाण्ड नम्बर-20 से सम्बंधित है। लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट को हमने बार-बार पार्क की रेनोवेशन और ब्यूटीफिकेशन करने के लिए कहा। उस समय हमें यह बताया गया कि इसके लिए 25 लाख रुपये की राशि मंजूर हो गई है लेकिन वास्तव में वहां पर पार्कों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया। हमारे श्रीराम स्वतंत्रता सेनानी पार्क को तोड़कर प्राईवेट लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस पार्क की रेनोवेशन और ब्यूटीफिकेशन का कार्य जल्दी से जल्दी करवाया जाये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह भी अनुरोध है कि मेरे झज्जर के हॉस्पिटल में नये सी.सी.टी.वी. कैमराज लगा दिये जायें। कुछ समय पहले जब एक हॉस्पिटल में एक पत्रकार ईलाज के लिए गया था तो उस समय सही ईलाज न मिलने की वजह से उनकी डैथ हो गई थी। बाद में जब सी.सी.टी.वी. कैमराज को चैक किया गया तो सी.सी.टी.वी. कैमराज में इसकी रिकार्डिंग नहीं मिली थी। उस पत्रकार का नाम संजय थरानी था। उसके परिजनों ने बार-बार डॉक्टरों से यह कहा कि उसका चैक-अप कर लें लेकिन डॉक्टरों ने उनकी बात नहीं मानी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि मेरे हल्के के रोड्ज और बस-स्टैण्ड को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाये। खुरड़ा व बहु के रोड की जो स्थिति है उसको भी ठीक किया जाये। विशेष तौर पर झज्जर हॉस्पिटल में नये सी.सी.टी.वी. कैमराज लगाये जायें और उनकी प्रॉपर मँटीनैस का कार्य किया जाये। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा यह कहना है कि लोग रोड जाम कर देते हैं जिससे सही समय पर ईलाज न मिलने के कारण काफी सारी डैथ्स हो जाती हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आफताब अहमद (नूह) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्बन लोकल बॉडी और शिक्षा की दो डिमाण्ड के ऊपर बोलना चाहता हूँ। मैं अपनी डिमाण्ड में यह कहना चाहूंगा कि मेवात मॉडल स्कूल, जय सिंह पुर, नूह की करोड़ों रुपये की लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है लेकिन तीन वर्षों से उसमें न तो स्टॉफ नियुक्त किया गया है और न ही क्लॉसिज लगाई जाती हैं। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी ये मामला सदन में उठाया था। मैंने शिक्षा मंत्री जी से दो मांगे की थी कि उस स्कूल में टीचर्स की जल्दी से जल्दी नियुक्ति करके वहां जल्दी से जल्दी क्लॉसिज शुरू करवाई जायें लेकिन अब फिर से अगला शिक्षा सत्र आ गया है लेकिन वहां पर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसी तरह से मैं अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट

के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूँ। नूंह शहर में पिछले दो साल से जलभराव की समस्या के समाधान के लिए कब्रिस्तान लैवल को ऊपर उठाया गया था इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हमारे नूंह शहर में शहीदी पार्क है वहां पर नैशनल फ्लैग भी लगा हुआ है लेकिन उसके रखरखाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसकी चारदीवारी भी नहीं रही। उसकी हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। प्रशासन द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी को शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प भी चढ़ाये जाते हैं लेकिन उस पार्क के रखरखाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि नूंह शहर के शहीदी पार्क का जल्दी से जल्दी रेनोवेशन और ब्यूटीफिकेशन करके उसके मैटीनैस का पुख्ता इंतजाम किया जाये। सरकार के विभागों के स्तर पर शहीदों के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह तथ्य भी लाना चाहूंगा कि नूंह के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर होने के बावजूद भी वहां पर न तो सड़कों से जल निकासी का कोई प्रावधान है और न ही सड़कों का सही ढंग से रखरखाव ही किया जाता है

श्री भारत भूषण बतरा(रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर-17 पर बोलना चाहता हूँ। यह डिमांड पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट से संबंधित है। पिछले दिनों पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट ने 25 करोड़ रुपये की ग्रांट के साथ सभी शहरों में सभी विधान सभा क्षेत्रों में अपनी-अपनी सड़कें बनवाने के लिए कहा था। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वहां रोहतक में शीला बाई पास के ऊपर फ्लाई ओवर के बाद एक सड़क जाती है। यहां पर मंत्री जी व अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं। उस सड़क का लैवल घरों के लैवल से दो फीट ऊंचा कर दिया गया है जिससे बारिश का सारा पानी विशाल नगर के घरों में जाएगा क्योंकि वहां बारिश के पानी की निकासी के लिए और कहीं कोई साधन नहीं है। मैंने इसके लिए संबंधित ए.सी.एस. साहब से भी रिक्वेस्ट की थी और उनके पास इसका 70 लाख रुपये का बजट भी पैडिंग है। अगर वे इस बजट को सैंशन कर देंगे तो उनको इससे काफी सुविधा होगी। मैं उप मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वे इस 70 लाख रुपये का बजट सैंशन कर दें तो उससे उनको काफी सुविधा मिल जाएगी। दूसरा हमारे वहां एक डी.टी.एम. होटल के साथ में नाला जाता है और उस नाले के अन्दर सारे सीवरेज के कनेक्शन हैं क्योंकि उस एरिया में कैलाश कालोनी है जिसमें सीवरेज की लाईन नहीं डली हुई है इसलिए उसका भी समाधान किया जाए ताकि स्टॉर्म वाटर निकालने का समाधान हो सके। इसी तरह से अभी नियर फ्यूचर में सुखपुरा चौक के ऊपर फ्लाई ओवर बना रहे हैं। यदि वहां सड़क को ऊंचा किया जाता है तो यह स्टॉर्म वाटर पीर बहुदी तक नहीं पहुंचता है इसलिए वहां पर जब बारिश आती है तो फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। इस पानी का पूरा निदान करने के लिए ये स्टॉर्म वाटर के दोनों नाले एग्जास्ट होकर और इनको सुखपुरा चौक से क्रॉस करके पीर बहुदी तक पहुंचाना चाहिए ताकि शहर की इस समस्या

का समाधान हो सके। मैं इसके लिए उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा। इसके साथ ही मुझे यह भी बताया जाए कि तिलियार लेक के सामने वाली सड़क कब तक पूरी हो जाएगी। इस सड़क को लगता है ग्रहण लगा हुआ है कभी इस पर इतने टाईम से इतने गड्ढे थे जिसके बारे में मैंने तीन-चार बार सदन में भी सवाल उठाया था। अब वह सड़क बनी है तो वह ठीक नहीं बनी है। वहां पर लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से वहां मस्त नाथ नगर में एक सड़क जाती है अब यह पता नहीं कि वह सड़क एच.एस.वी.पी. की है या वह पी.डब्ल्यू.डी. की रोड है इसका फैसला डिपार्टमेंट स्वयं कर लेंगे लेकिन पांच साल से वह सड़क टूटी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से यह भी कहना है कि जिन-जिन डिपार्टमेंट्स से संबंधित मांगें हैं, उनके संबंधित मंत्री व विभागीय उच्च अधिकारी जरूर सदन में उपस्थित हों ताकि हमारी मांगों पर विचार हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, तिलियार लेक के सामने व मस्तनाथ नगर के सामने वाली सड़क की पिछले पांच साल से बहुत बुरी हालत है। अब मैं मांग संख्या- 20 जोकि नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी से संबंधित है उस पर बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, डेरी कॉम्प्लेक्स का बहुत बुरा हाल है और इसके लिये हम कई समय से सुन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके लिये 14 करोड़ रुपये की ग्रांट भेज रहे हैं लेकिन इस बात को लगभग 2 साल हो गये हैं अभी तक एजेंडे में होते हुए भी कोई ग्रांट नहीं गई है। इस ग्रांट को जल्दी से जल्दी दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में कच्चा बेरी रोड का भी बहुत बुरा हाल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे क्षेत्र की डेरी फार्मिंग, सामुदायिक केन्द्रों, नालों आदि की हालत भी देखी हुई है। वहां पर फ्लाइओवर तो बना दिया गया लेकिन उसके नीचे वालों की हालत ठीक नहीं है। वहां पर नाले का समाधान होना चाहिये। जहां पर पुराना बस स्टैण्ड हुआ करता था और अब वह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग की जगह है। वहां पर रात को रूकने वाले यात्रियों के लिये जगह छोड़ी हुई है। उसकी जगह पर तो पार्क बन गया और नाला वहां से 90 डिग्री होते हुए पार्क की तरफ मुड़ जाता है और कमेटी ने वहां पर नाले को बंद करके पार्क बना दिया। मैंने इसके लिये स्थानीय प्रशासन से रिक्वेस्ट भी की हुई है कि या तो पार्क को खत्म करके इस नाले को ऑपन करो या फिर वहां नया नाला निकाल दो। यदि वहां

पर नाला चल गया अर्थात् ऑपन ड्रेन चल गई तो डेरियों की समस्या भी खत्म हो जायेगी और कच्चा बेरी रोड की समस्या भी खत्म हो जायेगी। सरकार इसके लिये ग्रांट मंजूर करके शहरी स्थानीय निकाय विभाग को आदेश दे कि वहां नाला आगे थाने तक ले जाये। इस तरह से एरिया का स्लम खत्म हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, रोहतक शहर में पिछले दो महीने से गारबेज नहीं उठ रहा है। सरकार ने पता नहीं इसके लिये किसी ठेकेदार को ठेका दे रखा है या नहीं। इसके लिये शॉर्ट टर्म कंडीशन पर भी ठेका दिया जा सकता है। वहां से गारबेज टाइमली उठाया जाये और सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाये। उपाध्यक्ष महोदय, रोहतक में राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम लगभग 108 एकड़ में बना है, इसलिए इसे बहुत ही सुंदर बनाईये। यह स्टेडियम हमारे प्रांत की धरोहर है। उस स्टेडियम में ट्रैक आदि काफी चीजें ठीक नहीं है और उस स्टेडियम से हरियाणा के गोल्ड मैडल विजेता खिलाड़ी पैदा होकर निकलते हैं। मैं चाहता हूं कि यह स्पोर्ट्स स्टेडियम बहुत ही सुन्दर होना चाहिये। पहले वाली सरकार ने जो इस स्टेडियम पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वह किसी भी कीमत पर वेस्ट नहीं जानी चाहिये। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि यह बात सारे प्रांत के लिये है। प्रांत के प्रत्येक शहर में अनेकों जगह पर और नहरी पुलों आदि पर पोस्टर्ज चिपका दिये जाते हैं जिससे सारे का सारा शहर गंदा दिखाई देता है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के होर्डिंग या फ्लैक्स बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। इनसे शहर इतना गंदा लगता है कि कोई चौराहा आ गया और वहां पर कोई कोचिंग सेंटर हैं तो उसको पोस्टों से भर देते हैं। यदि कोई नई दुकान ऑपन होती है तो उसके नाम के पोस्टर्ज से सारे के सारे चौक को पोस्टर्ज आदि से भर देते हैं। मैं यह केवल रोहतक शहर की बात नहीं कर रहा बल्कि प्रांत के सारे शहरों की बात कर रहा हूं। लोग सरकारी भवनों, प्राईवेट भवनों, सड़कों, पिलर्ज, स्कूलज की बिल्डिंग, नहरी पुलों आदि पर पोस्टर्ज चिपका देते हैं। सरकार मूलर पेंटिंग्स कलाकृतियां तो करवाती हैं लेकिन उसके बाद वहां बहुत बुरा हाल हो जाता है। जो इस तरह के पोस्टर्ज आदि लगाते हैं उनके उपर पैनल एक्शन होना चाहिये और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान होने चाहिये। सरकार को सुन्दरता की तरफ आगे बढ़ना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमाण्ड पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं मांग संख्या -17 जोकि लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/परिवहन/नगर विमानन से संबंधित है, उस पर बोलना चाहता हूँ। प्रदेश में जितनी सड़कें एच.एस.ए.एम.बी. बना रहा है वह ठीक नहीं बना रहा है। जब मैंने अपने क्षेत्र में इस बारे में पूछा कि आप लोग सड़क पर तारकोल क्यों नहीं बिछा रहे हैं तो उनका कहना है कि ये तो टैम्पेरी तौर पर बनाई जाती है। फिर मैंने उनसे कहा कि इस तरह से सड़क बनाने का क्या फायदा है। उनका इस पर कहना है कि फिर आप लोक निर्माण (भवन व सड़कें) विभाग से बनवा लो। हमारे क्षेत्र में 8 या 9 सड़कें इस तरह की हैं जो बनने के लिये तैयार हैं। एक-दो सड़कों पर तो काम शुरू हो चुका है लेकिन बाकियों पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण (भवन व सड़कें) विभाग ने जो सड़कें बनानी शुरू कर रखी हैं उनको भी लगभग दो महीने से बनाने के लिये उखाड़ रखा है। नारनौल में तो सड़कों को बनाने की मंजूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक उन पर काम ही शुरू नहीं हुआ है। जहां पर काम शुरू हो चुका है वहां पर भी कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि संबंधित एक्सियन ने मुझे सूचना दी थी कि जीन्द से हांसी सड़क दोबारा से बनने के लिये मंजूर हो चुकी है। उस काम को भी जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये। हमारी एक महत्वपूर्ण सड़क जीन्द से कैथल के बीच की है और उस सड़क पर निकले हुए हमें लगभग तीन-चार साल हो गये हैं क्योंकि वह सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसी प्रकार से एक सड़क जीन्द से सफीदों तक है उस सड़क की भी बड़ी दुर्दशा है, उस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि सरकार को सड़कों की तरफ विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये। मैं यह भी चाहता हूँ कि एच.एस.ए.एम.बी. में सड़कों के संबंध में स्पेसिफिकेशन लोक निर्माण (भवन व सड़कें) विभाग जैसी होनी चाहिये या फिर सारी की सारी सड़कें लोक निर्माण (भवन व सड़कें) विभाग के अन्तर्गत ही बननी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

धन्यवाद।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या -17 जोकि लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/परिवहन/नगर विमानन से संबंधित है, उस पर बोलना

चाहता हूँ। इस मांग पर आज सदन में मेरा सवाल भी लगा हुआ था लेकिन समय के अभाव के कारण लग नहीं सका लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब तो विभाग से आ गया है। मेरे क्षेत्र में स्टेट पॉलिसी होने के बावजूद भी 13 सड़कें अभी भी कच्ची हैं। जब मैंने इस संबंध में लिखकर भेज दिया तो उसका विभागीय रिप्लाय आया कि तीन सड़कें पहले से पक्की हैं। सबसे बड़ा तो झूठ यही है। इस रिप्लाय में लिखा है कि असंध-कैथल रोड से मर्दानहेड़ी गांव तक सड़क जाती है उसका ऑलरेडी एस्टीमेट्स बनकर आया हुआ है। सभी संबंधित ऑफिसर्स को पता है फिर भी इस बारे में पता नहीं क्यों ऐसा रिप्लाय दिया है। दूसरा, मेरे हल्के में बॉर्डर पर एक गांव रूखसाना है। वहां से हावड़ी गांव की तरफ एक सड़क जाती है जिससे आगे कैथल जिला लगता है। कैथल जिले में वह सड़क बनी हुई है लेकिन करनाल जिले में नहीं बनी है। वह सड़क डीग रोड से निकलती है। उसको भी लिख दिया कि वह बनी हुई है। तीसरी सड़क जुंडला से जाणी की है। उस सड़क में जुंडला से जाणी तक सात मीटर का वाइडनिंग का काम हो गया है। मैंने यह लिखा कि उससे आगे जो सड़क है वह कच्ची नहीं है लेकिन वह सड़क 12 फुट की है। उस सड़क को भी मुनक रोड तक जोकि अढाई-तीन किलोमीटर आगे तक है, वाइडनिंग में शामिल कर दिया जाए। उसको भी लिख दिया गया कि वह सड़क बनी हुई है लेकिन जो आगे नहीं बनी हुई है उसका भी तो कोई माई-बाप होगा। मेरे क्षेत्र के दो बड़े-बड़े गांव हैं। पहला, राहड़ा गांव से डीग की तरफ एक सड़क जाती है जोकि सारी कच्ची है। दूसरा, हांसी-बुटाना नहर पार करने के बाद जैसिंहपुर गांव से उपलाना तक एक सड़क जाती है। वह भी कच्ची है। यह मैं आपको बड़े-बड़े गांव की बात बता रहा हूँ। गंगाटेहड़ी गांव से कोलखेड़ा तक एक सड़क जाती है। इन तीनों सड़कों का मैंने अलग से ए.सी.एस. और अन्य को भी लैटर लिखकर दिया है कि अगर आप मेरी 13 सड़कें नहीं बना सकते तो ये 3 सड़कें ही बना दीजिए। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बड़ी मजेदार बात याद आ रही है। पुराने जमाने/इनके जमाने में क्या चलता था कि मोहन सिंह से सोहन सिंह के घर की गली बना दो। वह गली बन जाती थी। फिर 6 महीने बाद ऑर्डर आता था कि सोहन सिंह से मोहन सिंह के घर की सड़क बना दो। वह भी बन जाती थी। अब हमारे माननीय सदस्य गोगी जी कहते

हैं कि कोलखेड़ा से गंगाहेड़ी की एक सड़क बना दो। फिर ये बाद में लिखते हैं कि गंगाहेड़ी से कोलखेड़ी की सड़क बना दो। इनकी लिस्ट में ये 2 सड़कें आई हुई हैं।

श्री शमशेर सिंह गोगी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़क रिपीट हो गई। यह लिखने में गलती हुई है। अगर मैं सरकार की ऐसी गलतियां निकालने लगूं तो सरकार ने अभी तक जितने जवाब दिए हैं उनमें बहुत गलतियां हैं। सरकार के जवाब झूठे होते हैं। सरकार के पास तो खूब पढ़े-लिखे अधिकारी हैं। मेरे जैसा अनपढ़ व्यक्ति तो गलती कर भी सकता है। मेरा कहना है कि अगर मैंने 2 सड़कें लिखी हैं तो सरकार उनमें से 1 सड़क को तो बना दे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि अगर वे इन सभी सड़कों को नहीं बना सकते तो कम से कम ये 3 सड़कें ही बना दें क्योंकि इनके साथ 6-6, 7-7 हजार वोट के गांव लगते हैं। पता नहीं आज तक इन सड़कों के काम कौन-सी पॉलिसी और कौन-सी नीयत के तहत रूके रहे हैं। जिन लोगों ने इनको नहीं बनवाया यह उनकी गलती रही होगी। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती है कि ये इन सड़कों को बनवा दें। बाकि सड़कों को हम अपनी सरकार आने पर स्वयं ही बनवा देंगे।

श्री मेवा सिंह (लाडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नं. 17 पर बोलना चाहूंगा। एक सड़क की करनाल से लाडवा तक फोरलेनिंग हुई परंतु उसका 2 किलोमीटर का एक टुकड़ा सिंगल छोड़ दिया गया। इससे वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। इनमें कई लोगों ने अपनी जान गवां दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउसमेंट भी की थी लेकिन फिर भी 2 किलोमीटर का वह टुकड़ा नहीं बनाया गया है। दिनांक 26.12.2022 को डिप्टी सी.एम. साहब ने हाउस में आश्वासन दिया था कि पिपली से यमुनानगर रोड का जो 32 किलोमीटर की सड़क का टुकड़ा बकाया है उसको 31 मार्च के बाद स्टेट गवर्नमेंट फोरलेन करने का काम करेगी लेकिन उस पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। लाडवा में एक सड़क पर सारा दिन जाम लगा रहता है। यमुनानगर से माइनिंग के लिए जितने भी व्हीकल्स निकलते हैं जिसमें बड़े-बड़े ट्राले होते हैं वे पूरे हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में जाने के लिए लाडवा के बाजार से होकर निकलते हैं। इनकी वजह से वहां पर कई-कई घंटे तक लोग जाम में फसे रहते हैं। अगर यह 3 किलोमीटर की सड़क बन जाए और लाडवा यमुनानगर रोड को लाडवा के बाहर से लाडवा-इंद्री रोड से मिला दिया जाए तो जाम की समस्या का समाधान हो जायेगा और सारा इलाका जाम से बच

जायेगा। इस समस्या को मैं पिछले चार साल से उठा रहा हूँ लेकिन इस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनाउंसमेंट के बाद भी मात्र दो-दो किलोमीटर के सड़क के टुकड़े अधूरे पड़े हैं। दूसरी बात जो सड़कें 25-25 करोड़ रुपये की लागत से बनी हुई हैं आप उनकी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए क्योंकि उनकी क्वालिटी बड़ी पुअर है। पुअर क्वालिटी की वजह से बनने के केवल 4 महीने के बाद ही वे सड़कें उखड़ जाती हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। सड़क बनाने वाले ठेकेदार की पांच साल की गारंटी होती है। इसके बावजूद कोई भी इस पर दोबारा पैच नहीं लगाता। सड़क के बनने के केवल 6 महीने बाद ही ये खराब होनी शुरू हो जाती हैं। उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री बिशन लाल सैनी जी मांग नं0 8 पर अपनी बात रखेंगे।

डॉ. बिशन लाल सैनी (रादौर): उपाध्यक्ष महोदय, जो सम्मानित सदस्य ने कहा है, मैंने भी वही कहना था। इसके अलावा कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, जी। अब माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी डिमांड नं0 20 पर अपनी बात रखें।

श्री नीरज शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डिमांड नं0 20 पर तो कहना ही है लेकिन मुझे डिमांड नं0 19 पर भी एक बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष: नीरज जी, आपने डिमांड नं0 20 पर ही बोलने के लिए लिखकर दिया है।

श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद, एन.आई.टी.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय इसके बारे में लिखना भूल गया था। अगर आप इस डिमांड पर अपनी बात रखने के लिए आज्ञा दे दें तो सिर्फ एक ही लाईन की बात है। यह डिमांड नं0 19 इरीगेशन विभाग से संबंधित है। वैसे तो यह डिमांड नं0 20 नगर निगम से ही रिलेटिड है। हमारे यहां पर एक 55 फुट की नहर है। पहले कभी नहर होती थी अब उसका वर्क ऑर्डर भी इशू हो गया है और आधा काम भी हो गया है और कम से कम 2 साल से परमीशन मांग रहे हैं। नगर निगम ने चिट्ठी भी लिख दी कि आप हमें जमीन दे दो। इरीगेशन विभाग कह रहा है कि आप इसको खरीद लें। वहां पर नहर चलती नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हुए हैं और वे वित्त मंत्री भी हैं और इस महकमें के मंत्री भी हैं। मैं आपके

माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वहां पर जो आधा काम हो गया है, वह भी वेस्ट हो रहा है। नगर निगम में इतना पैसा नहीं है कि उस नहर के पैसे दे सके। आप कम से कम उसकी टैम्पेरी परमीशन दे दें ताकि वह टैंडर पूरा हो जाए। वह टैंडर खत्म भी नहीं हो सकता। इसमें नगर निगम वालों की कमी है कि बिना इरीगेशन विभाग की परमीशन के क्यों उसका टैंडर किया है और क्यों वर्क ऑर्डर किया है? इससे लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। वह 55 फुट की नहर थी जोकि वार्ड नं0 9, नगला इन्कलेव बालाजी मंदिर के पास है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी डिमांड तो 20 नम्बर से रिलेटिड है। एक तो वही 27 करोड़ 48 लाख रुपये की 7 डिमांड्स हैं। अगर आप कहें तो मैं इनको पढ़ देता हूं या आप इनको पढ़ी हुई मान लें। मैंने दूसरा प्रश्न डिमांड नं0 17 एच.आर.डी.एफ. के लिए लगाया था कि हमारी एन.आई.टी. -86 को कितने पैसे दिये हैं? इसके 39 पेजिज हैं और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 39 पेजिज पढ़ दूं या मैं आपको कागज दे दूंगा और आप उनको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, जी।

श्री नीरज शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब मिला कि हमारी एन.आई.टी.-86 को शून्य मिला है। मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि सबका-साथ, सबका विकास कहां है? हमारे ग्रामीण एरिया के लिए कुछ न कुछ जरूर दे दें। एक चीज और है कि हमारे फरीदाबाद में महाभारत कालीन गांव तिलपत है जिसको तिलपरस्त भी कहा जाता था। डिमांड भी आ रही है कि इसका नाम बदलना चाहिए। उस मेन गांव तक के लिए एक सड़क बनी है जिसकी हालत ठीक है और उसका अभी तक डिफैक्ट लाएब्लिटी पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है और नयी सड़क का टैंडर नहीं हो रहा है। हालांकि यह गांव मेरी विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। हम पिछले दिनों वहां पर गये थे और मैं वहां के लोगों से वायदा करके आया था कि मैं आपकी आवाज जरूर उठाऊंगा। आज के समय में भी वहां पर दो-दो, डेढ़-डेढ़ फुट पानी खड़ा हुआ है क्योंकि डिपार्टमेंट यह कहा रहा है कि ठेकेदार ये काम करवाएगा। ठेकेदार का वहां पर कोई अता-पता नहीं है और उससे वहां के सारे के सारे लोग परेशान हो रहे हैं। शायद, यह सड़क माननीय सदस्य श्री राजेश नागर जी की विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है। इसके लिए सरकार उस ठेकेदार से बात करे क्योंकि सरकार जनता

से टैक्स ले रही है। यह तिलपत गांव तक मेन सड़क है और वहां पर लाखों लोग रहते हैं, इसलिए उस सड़क को बनवाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स जी डिमांड नं० 17 पर अपनी बात रखेंगे।

श्री कुलदीप वत्स (बादली): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। इस समय माननीय उप मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में दो-तीन बातें दिलाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने हर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे बादली हल्के की दो-तीन बातें बताना चाहूंगा जोकि बड़ी गम्भीर बातें हैं। मेरे हल्के की जिन गांवों की सड़कें खराब थी और बुरी हालात में थी उनके लिए हमने सी.एम. साहब, डिप्टी सी.एम. साहब और अधिकारियों को लिखित में दिया था लेकिन उन सड़कों पर काम न होकर दूसरी सड़कों पर काम हुआ है। रिवाड़ी-सिलानी रोड पर हमारा एक मादलपुर गांव है और मादलपुर टू कहाड़ी की सड़क को 4 साल से पाड़कर रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि उस सड़क को 4 साल से पाड़कर रखा हुआ है और वहां से संबंधित तीनों-चारों गांव के अलावा 50 गांवों के लोग निकलते हैं। लेकिन वह सड़क यूं की यूं पड़ी हुई है और अब तक नहीं बनी है। इसके साथ ही साथ हमारे कासनी से ढाकला गांव तक की सड़क के भी यही हालात हैं। पिछले 4 सालों से वह भी ठेकेदार को बनाने के लिए दे रखी है लेकिन उसको भी पाड़कर रखा हुआ है। वह भी अभी तक नहीं बनी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस पर भी संज्ञान लें और तुरंत उसका काम शुरू करवाएं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बादली टू बोहला गांव की सड़क की बुरी हालात है जिसके बारे में मैंने 25 करोड़ के कार्यों में ही लिखित में दिया था। इसका काम नहीं हुआ बल्कि उसके बदले में दूसरा काम हो गया। जो सड़क बिल्कुल ठीक थी, उसका काम हुआ। जिस सड़क की बुरी हालत थी, उसका काम नहीं हुआ। इसके बाद सुरहेती टू किलोहड़ टू दादनपुर सड़क की सबसे बुरी हालत है, लेकिन उसका भी काम नहीं हुआ। मैंने इसके बारे में लिखकर दिया था, लेकिन दूसरी सड़क का काम हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरी सड़क

बावरा टू सिलानी और बावरा टू ढाबला सड़क की सबसे बुरी हालत है और वहां से डेली बहुत से लोग निकलते हैं। उसकी भी बुरी हालत है, लेकिन उसका भी काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका काम भी जल्दी से करवाया जाए। मुख्यमंत्री जी, मैंने सरोला से जेधपुर रोड के बारे में लिखकर दिया था लेकिन उस काम को सरोला से छप्पार होते हुए न्योला तक कर दिया गया। मैंने जिस रोड का नाम लिखकर दिया था उस रोड पर तो काम नहीं किया गया, उस रोड की बहुत ही खस्ताहालत बनी हुई है इसलिए इस रोड को बनाने का भी काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ एक हब है। झज्जर से बहादुरगढ़ की तरफ जो सड़क जाती है, उसकी पिछले 4-5 साल से हालात बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी है। आप चाहें तो जाकर देख लो, उस रोड की इतनी बुरी हालत है कि आप वहां पर पैदल भी नहीं चल सकते हो, गाड़ी का निकलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कहा जाता था कि रोड में गड्ढे हैं लेकिन वहां तो गड्ढों में ही रोड है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि उस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाये। मुख्यमंत्री जी एक ध्यान देने का विषय है। यह बात ठीक है कि सरकार ने 25 करोड़ रुपये के काम करवाये हैं, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ लेकिन जिन गांवों में 25 करोड़ रुपये की लागत से काम हुए हैं, उन गांवों के बीच में जो गांव आये थे, जहां से गांवों के रास्ते शुरू होते हैं और अंत में खत्म होते हैं, वहां पर तो काम करवा दिये गये लेकिन जो गांव के बीच के रोड थे, उनको छोड़ दिया गया जिसके कारण उन रोड्स की बहुत बुरी हालत बनी हुई है। उन गांवों में आर.सी.सी. के नाले बने हुए हैं जो टूटे पड़े हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि आर.सी.सी. के पक्के नाले बनाने का काम किया जाये। हमारे उपमुख्यमंत्री जी सदन में आ गये हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा। मेरे इलाके और झज्जर जिले की काफी ऐसी सड़कें हैं, जिनकी बहुत बुरी हालात बनी हुई है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप विभाग के अधिकारियों को आदेश दें कि इन सड़कों को दोबारा बनाया जाये। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।

श्री शीशपाल सिंह (कालावाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 17 पर बोलना चाहता हूँ। मेरे हल्के में कालावाली से लेकर देशुमलकाना रोड जाती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा

खराब है। उस रोड से पंजाब शुरू होता है क्योंकि यह मेन रोड है इसलिए इस रोड का जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य करवाया जाये। इसके साथ ही साथ छतरिया से रघुवाना रोड है, उसकी भी काफी हालत खराब हो रखी है इसलिए इस रोड का जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य करवाया जाये। इसके साथ ही साथ सिरसा से बरनाला रोड पर बुर्जकर्मगढ़ गांव हैं, वहां की रोड बाढ़ के कारण जमीन में धंस गई थी क्योंकि वह रोड पहले भी काफी नीचे थी। जो रोड बाढ़ के कारण धंस गई हैं, उनके लिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर रखा है तो हम चाहते हैं कि उस रोड की लैवलिंग करवाने का काम किया जाये। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय है कि वर्ष 2014 के अंदर कालावाली सब-डिवीजन बन चुका था लेकिन अभी तक उसकी बिलिडिंग का निर्माण नहीं हुआ है। वहां पर न तो ज्युडिशियल कॉम्प्लैक्स है और न ही वहां पर कोई बिलिडिंग है। वहां के लोगों को सब-डिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहां पर अपना काम करवाने के लिए हजारों लोग आते हैं परन्तु बिलिडिंग न होने के कारण धक्के खाने को मजबूर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां पर सब-डिवीजन की बिलिडिंग को जल्द से जल्द बनाया जाये।

श्री प्रदीप चौधरी (कालका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 17 पर बोलना चाहता हूं। वैसे तो मेरे कालका विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50 ऐसी सड़कें हैं जो गांवों के साथ जुड़ी हुई नहीं है लेकिन मैं कुछ मुख्य सड़कों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा। जैसे रायपुररानी को सीधा श्री गुरु गोविन्द सिंह जी मार्ग से जोड़ा जाये (यह रोड टांगरी से पारवाला रोड पर रायपुररानी से सीधा रोड पड़ता है) क्योंकि रायपुररानी से मानकटबरा गुरुद्वारे में आने वाला पुराना रास्ता जिस पर चलकर श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज मानकटबरा गुरुद्वारा के स्थान पर पधारे थे वो आज भी कच्चा रास्ता है जिसे जल्द से जल्द पक्का करना चाहिए। इस कच्चे रास्ते का नाम गुरु गोविन्द सिंह के नाम से हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वहां के लोगों को 4 किलोमीटर तक घूमकर आना पड़ता है। इसी प्रकार से रहना गोविन्दपुर को जोड़ने के लिए बीच में नदी पड़ती है। इसी तरह से टिककरताल से गजान, कंडेरन से डाबस स्कूल तक की रोड को आपस में जोड़ने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, ओरियां ऐसा गांव हैं जो कालका की जड़ में ही है। अगर वहां पर छोटी सी पुलिया बन जाये तो वहां के लोगों

को 8 किलोमीटर तक घूमकर नहीं आना पड़ेगा इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ओरियां से कालका को जोड़ने का काम किया जाये। इसी तरह से थाना से मरोग तक और हरका घाट से राजी टिक्करी स्कूल और टिक्करताल से गजान स्कूल की ओर जो रोड जाती है है, इन रोडज को भी बनाने का काम किया जाये। इसी तरह से और भी सड़कें ऐसी है जो जुड़ी हुई नहीं है जैसे टिक्करताल से धारवाला, धारवाला से मीरपुर, जे.बी.टी. स्कूल से उत्तरों तक के बहुत से ऐसे रास्ते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इन रास्तों को चिन्हित करके जोड़ने का काम किया जाये ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके।

**पी.एम. श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गंगवा, जिला हिसार के
विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनंदन करना**

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि पी.एम. श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गंगवा, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

**वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदान अनुमान (दूसरी किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा
मतदान
(पुनरारम्भ)**

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय विधायक श्री वरुण चौधरी जी, डिमांड संख्या 3, 6, 10, 12, 17, 19 तथा 20 पर बोलेंगे। विधायक जी, आपने बहुत सारी डिमांड्स पर बोलने के लिए लिखा है इसलिए आप समय के अभाव को देखते हुए अपनी बात थोड़े संक्षेप रूप में कहने की कृपा करें।

श्री वरुण चौधरी(मुलाना): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझदारी की बात करने का प्रयास करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो डिमांड्स हैं इनका कुल योग लगभग 2 हजार 90 करोड़ रुपये है। जब बजट प्रस्ताव फरवरी, 2023 में 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ का आया था, यह उसका लगभग 1.1 प्रतिशत हिस्सा है और यह भी बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें मुख्यतः राजस्व खर्च की बात हो रही है। 86 प्रतिशत, यह जो 2 हजार 90 करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की

डिमांड आ रही है, यह राजस्व खर्च की है। इसके अन्दर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वह मात्र 14 प्रतिशत है। अभी जो चर्चा हो रही है वह किसी विशेष सड़क की, किसी विशेष बिल्डिंग की, किसी विशेष पार्क की तथा किसी विशेष नहर की हो रही है। यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह जो डिमांड्स माननीय वित्त मंत्री जी ने दी हैं उसके साथ यह रिप्लाइ नहीं लिखकर आया कि यह किस कार्य के लिए आई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जब आप लिखकर के दे देंगे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि शिक्षा विभाग किसी कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने के पैसे मांग रहा है और मैं मांग रख रहा हूं कि उस स्कूल की बिल्डिंग बननी थी, उसके अन्दर कमरा वगैरा नहीं था या कहीं कुछ और नहीं था तो उसका यहां पर लाभ नहीं है। अगर वित्त मंत्री जी लिखकर के दे दें, विभाग लिखकर दे दे कि यह जो मांग की जा रही है, वह मांग इस खास कार्य के लिए की जा रही है तो यह जो चर्चा होगी वह उस कार्य तक ही सीमित रहेगी और एक सकारात्मक चर्चा होगी। ऐसे चर्चा हम करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात को समझ रहे होंगे कि उसका लाभ क्या है? जब तक हमें यह नहीं पता कि यह किस चीज की मांग की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिए कि यह जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनकी स्थिति क्या है, यह हमें पता चलना चाहिए कि आज इनकी क्या स्थिति है? क्या हमारी राजस्व प्राप्तियां बढ़ गई हैं जिसमें से हम यह 2 हजार 90 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। या इसके लिए फिर से कोई कर्जा लेंगे। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा होगा कि आगे से सरकार लिखकर के दें कि हम इस कार्य के लिए मांग कर रहे हैं जिससे कि चर्चा वहां हो और उसका लाभ हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब डिमांड सख्या 17 पर माननीय सदस्य श्री इन्दु राज जी बोलेंगे।

श्री इन्दु राज(बरोदा): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। विधानसभा में यह बात कई बार हो चुकी है कि 6 करम के जितने भी कच्चे रास्ते हैं उन सभी को पक्का बनाया जायेगा। यह सरकार सबका साथ-सबका विकास का नारा भी देती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक गढ़वाल से मेहरड़ा का 6 करम का रास्ता है तथा दूसरा रिण्डाणा से अकालगढ़ का 6 करम का रास्ता है। इसे जींद जिले में 6 करम का पक्का रास्ता बना दिया लेकिन मेरी सीमा में आकर

यह बंद कर दिया। यह ऑन रिकॉर्ड है। जहां से सोनीपत की सीमा शुरू होती है, वहां से यह बंद हो गया। यह अकालगढ़ से भी बनता आ गया, मेहरड़ा से भी बनता आ गया लेकिन ज्यों ही सोनीपत की सीमा में आई आगे यह रास्ता बंद हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों 6 करम के कच्चे रास्तों को जरूर पक्का बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकार द्वारा बरोदा मोर से जनता कॉलेज, बुटाना तक 6 करम का जो कच्चा रास्ता है उसको भी पक्का बनवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, गोहाना से जुलाना का जो मेन रास्ता है इस पर मेरा पैतृक गांव रिण्डाणा है, वहां अवैध कब्जा है। इस पर कोर्ट की स्टे हो गई और यह केस चार वर्ष से चल रहा है लेकिन इसके बराबर साइड से पूरा गांव 6 करम का टैम्पेरी रास्ता देने के लिए तैयार है। इसका रैजोल्यूशन बनाकर भी दे दिया गया कि जब तक कोर्ट केस फाइनल ना हो तब तक इसे साइड से टैम्पेरी बना दिया जाये ताकि आने-जाने का रास्ता खुल सके लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहां मौके पर कई बार एस.ई तथा एक्सीयन भी गये लेकिन इसकी कुछ भी प्रक्रिया शुरू नहीं होती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मुख्य रास्ता है इसलिए इस पर साइड से से जो 6 करम का रास्ता है उसको बनवाया जाये और इसी प्रकार से जो एन.एच. 71 पानीपत-रोहतक रोड है वह नया बन गया है लेकिन जो माहरा, रूखी गांवों के बीच के रोड हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इन गांवों के बीच से निकलने वाली सड़कों की भी मरम्मत करवाई जाये। इसी प्रकार से निजामपुर से नंदगढ़ भी ऐसा ही रोड है इसकी भी मरम्मत करवाई जाये। सरकार जो 'सबका साथ और सबका विकास' की बात करती है उसको पूरा करने का काम करे। धन्यवाद।

श्री जगदीश नायर (होडल) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिमाण्ड नं. 20 पर अनुरोध करना चाहूंगा कि महाग्राम योजना के तहत हमारी सरकार ने बड़े-बड़े गांवों में सीवरेज लाईन बिछाई है जिनमें दिघौट, खामी, बिढूकी, सौंध, बंचारी और औरंगाबाद इत्यादि गांव शामिल हैं। इस बारे में मेरा अनुरोध है कि वहां के रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो गये हैं। वहां ग्राम पंचायतों के पास बजट की कमी है इसलिए इन महाग्रामों में उन रास्तों को ठीक करने के लिए कुछ और बजट का आबंटन किया जाये। इसी में जोड़ दिया जाये ताकि इन बड़े गांवों जिनकी आबादी लगभग 20-20 हजार है उनके रास्ते और नालियां ठीक हो जायें। मैं सरकार से

बार-बार अनुरोध करता हूं कि सौंध, बंचारी, बिढूकी, औरंगाबाद और खामी इत्यादि गांवों के समस्त रास्तों को इस मांग नम्बर में जोड़ा जाये।

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑर्डर है। सप्लीमेंट्री डिमाण्डज के ऊपर विपक्ष बोलता है सत्ता पक्ष नहीं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, विपक्ष ही तो बोलने लग रहा है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं तो रूल की बात बता रहा हूं।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नम्बर-17 पर बोलना चाह रहा हूं। (विघ्न)

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बोलना चाहूंगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। अगर है तो ये उसे सदन की रूल बुक में दिखा दें। इनके टेबलेट में रूल बुक है ये उसको खोलकर पढ़ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई रूल है। अगर है तो आप प्लीज उसको दिखा दें।

श्री भारत भूषण बतरा : ठीक है डिप्टी स्पीकर सर, मैं दिखा देता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर भी मुझे आपकी रूलिंग चाहिए कि हर विषय पर प्वायंट ऑफ ऑर्डर और रूल का हवाला इस हाऊस में दे दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि टाईम दे दीजिए मैं पढ़कर बताता हूं। उपाध्यक्ष जी, आप इस विषय पर भी अपनी जजमेंट दीजिए।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ से नारनौल स्टेट हाईवे नम्बर 148 का कंस्ट्रक्शन जारी है लेकिन गांव नांगल सिरोही के पास जाकर के वो रास्ता रोक दिया जाता है क्योंकि वहां पर कुछ बाई पास के ऊपर फॉरेस्ट लैंड है जहां पर पेड़ों की कटाई की परमिशन न होने की वजह से वहां पर काम को आगे नहीं चलाया जा रहा है। इसकी वजह से जो आम ट्रैफिक है वो गांव के अंदर से जहां पर भी सुविधा नजर आती है वहीं से व्हीकल को पास ऑन करने की कोशिश वाहन चालक करते हैं जिससे पूरे गांव के अंदर एक असुविधा की स्थिति है। मेरा निवेदन है कि वहां पर पेड़ कटाई की परमिशन सरकार जल्दी से जल्दी दे ताकि आम आदमी को असुविधा से

बचाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, एक ये हैवी बिल्डिंग मैटीरियल को ले जाने वाला ट्रैफिक है ये जब कनीना से डहीना तक जाता है तो वहां पर इतना जबरदस्त ट्रैफिक लोड है कि वहां पर रोड नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। उस रोड को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये। एक रोड है जो नांगल सिरोही से पांच गांवों को कनेक्ट करता है। वह रोड worst कंडीशन में है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि टैण्डर भी फ्लोट कर दिया और टैण्डर अलॉट भी कर दिया लेकिन जो कांट्रैक्टर है वह उस पर काम शुरू नहीं करना चाहता। यह मामला पिछले दो साल से लम्बित पड़ा हुआ है। एक रोड मेरे हल्के का है जो महेन्द्रगढ़ से बवानिया को कनेक्ट करता है उसकी भी यही कंडीशन है और एक रोड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सतनाली को कनेक्ट करता है उसके लिए बहुत लम्बे समय से हमारी डिमाण्ड चली आ रही है। उसकी जमीन निश्चित है लेकिन सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि उसका संज्ञान लिया जाये ताकि पढ़ाई के उस संस्थान को सतनाली से जोड़ा जा सके। धन्यवाद।

श्री कुलदीप वत्स : डिप्टी स्पीकर सर, मेरी एक बहुत ही अहम डिमाण्ड है। जो पूरा सौदी-

16:00 बजे

फतेहपुर-इस्मालपुर इण्डस्ट्री एरिया है उसकी बहुत बुरी हालत है एक बार उसको जरूर बनाया जाये।

श्री बलराज कुंडू(महम): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड्ज पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डिमांड नं. 17 पर अपनी बात रखना चाहता हूं। अभी हमारे साथी श्री वरूण चौधरी जी इस बारे में विस्तार से बता रहे थे। मेरा भी इस बारे में यही मानना है कि ये डिमांड्ज वे डिमांड्ज हैं जिनको सरकार ने पहले नहीं लिया और बेसिक पब्लिक की जरूरत के हिसाब से हम लोग इनको अब यहां रख रहे हैं। इसको एडिशनल फंड में काउंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इन डिमांड्ज को ऐसे ही रख रहे हैं। हम ये डिमांड्ज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सड़कों की या जो दूसरी प्रोब्लम बता रहे हैं वे दिक्कतें पब्लिक को हैं जो हमारे प्रदेश के लोग हैं उनको दिक्कतें हैं। जब हम उनको यहां सदन में रख रहे हैं तो उसकी एडिशनल डिमांड होनी चाहिए। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र की डिमांड्ज भी बार-बार यहां सदन में रखी हैं।

मुख्यमंत्री(श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, विषय थोड़ा सा डायवर्ट हो रहा है। माननीय सदस्य श्री वरूण चौधरी जी ने जो विषय रखा था वह यह था कि इसके अन्दर केवल वे आंकड़े रखे जाते हैं जो अनुपूरक मांगों के होते हैं लेकिन उसकी डिटेल्स यहां पर नहीं होती है। अगर उसकी डिटेल्स हो तो यह पता लग सकता है कि यह राशि किस मद के लिए है। इसके लिए मेरा जवाब यह है कि जो ऐस्टीमेट्स कमेटी होती है वहां पर डिटेल्स में सभी मदों पर डिस्कशन होता है। ऐस्टीमेट्स कमेटी जिन डिमांड्स को पास करती है उनको ही यहां पर रखा जाता है तथा ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट आप सभी को दी गई है और उसमें यह सारा उल्लेख है। दूसरी बात जो माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू जी बोल रहे हैं उसके बारे में मेरा कहना यह है कि यहां पर जो डिमांड्स डिस्कस हो रही हैं तो जो सभी विभागों के अधिकारी बैठे हुए हैं वे उसका संज्ञान ले रहे हैं। अगर चालू वित्त वर्ष के बजट में ये डिमांड्स पूरी हो सकती होंगी तो उसमें पूरी होंगी और अगर इस बजट में पूरी नहीं हो सकती हैं तो अगली बार फिर जब अनुपूरक डिमांड्स आयेंगी उस समय इसका आंकलन किया जा सकता है। इस समय तो उसमें शामिल करना शायद ठीक नहीं होगा और अगर पहले ही उसमें जोड़ दी गई हैं तो उसमें जुड़ जायेंगी।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये काम ऐसे हैं जो मैं सदन के पटल पर बार-बार रख चुका हूं और वे आपके संज्ञान में रहे हैं। एक तो आपका ही गांव निन्दाना है और निन्दाना तथा फरमाणा का आपस में भाईचारा माना जाता है। आप निन्दाना-फरमाणा रोड की हालत चैक करवा सकते हैं कि उसकी क्या हालत है? उससे बदतर हालत नहीं हो सकती है। उसको देख कर ऐसा लगता है कि गड्ढों में सड़क है। उसको आप अपने स्तर पर किसी से चैक करवा सकते हैं अन्यथा मैं आपको उसकी फोटोज भेज सकता हूं। मैं इस सड़क की बात को पहले भी चार बार उठा चुका हूं और अब फिर इसलिए उठा रहा हूं ताकि अगली बार की अनुपूरक मांगों में आप इसको शामिल करवा दीजिए। इसी प्रकार से बहू अकबरपुर से समरगोपालपुर रोड है उसका गांव का 800 मीटर का पोर्शन है जिसके लिए मैं पिछले डेढ़ साल से आवाज उठा रहा हूं और उप-मुख्यमंत्री जी को लिख कर भी दे चुका हूं। इसकी बहुत बुरी हालत है। इसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं और लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसी प्रकार से बहू अकबरपुर से निडाना रोड की हालत भी इतनी खराब है

कि उसको देख कर लगता ही नहीं है कि यहां पर रोड है। इसी प्रकार से बलम्भा-कलानौर-बेरी रोड की हालत भी बहुत जर्जर है। गुरुग्राम के जिन लोगों को हिसार और सिरसा जाना पड़ता है उनको भी यह रोड प्रभावित करता है क्योंकि उनको यह रास्ता छोटा पड़ता है। इसके अतिरिक्त जीन्द रोड से गांव भगवतीपुर का एक किलोमीटर का रोड है जिसकी हालत इतनी खराब है कि उसको देख कर भी शर्म आती है। इसी प्रकार से महम के अन्दर जो रोहतक रोड है और गोहाना रोड से लेकर कोर्ट तक सड़क के दोनों तरफ आई.टी.आई. तक जो नाला बना है वह ओवरफ्लो हो कर सारा पानी सड़क पर आ जाता है जिसके कारण दुकानों के सामने कीचड़ जमा हो जाता है। उससे पूरे शहर के हालात खराब हो रहे हैं इसलिए उसको ठीक करवाया जाये। अब मैं डिमांड नं. 20 पब्लिक हेल्थ पर बोलना चाहता हूं महम शहर में पीने के पानी और सीवरेज का सिस्टम बहुत खराब है जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार आवाज उठा चुका हूं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसलिए उस पर काम होना चाहिए। वहां पर 8-8 दिन में पानी आता है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अनअर्थॉराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलर करने की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि महम में रोहतक रोड पर दोनों तरफ, सामान रोड पर दोनों तरफ, फरमाणा रोड पर दोनों तरफ तथा भराण रोड पर दोनों तरफ कच्ची कॉलोनियां हैं। गरीब आदमियों ने सस्ते के चक्कर में वहां पर मकान बनाए हुए हैं। आप उनको रेगुलर तो जब करोगे तब करोगे लेकिन उनको बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधायें तो प्रदान करवा दो। रोड तथा सीवरेज तो समय के अनुसार बनते रहेंगे लेकिन उनको बिजली पानी तो मुहैया करवा दो। उन आधे घरों में न तो बिजली की सुविधा और न ही पानी की कोई व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन कॉलोनियों में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधायें मुहैया करवाई जायें। बाकी सुविधायें तो रेगुलर होने के बाद भी हो जायेंगी। और इन सुविधाओं पर तो सबका अधिकार है। मेरा आपसे यही निवेदन है। इसी के साथ महम में जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स बना हुआ है उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। मेरा मानना है कि उस पर लगभग 100 करोड़ रुपये लगा होगा। उसके अन्दर बहुत अच्छी-अच्छी बिल्डिंग हैं लेकिन वहां अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है। वह बिल्डिंग बिल्कुल बर्बाद/खंडहर होने लग रही है। मेरा अनुरोध है कि उन बिल्डिंग को किसी भी यूटिलाइजेशन में लाया जाए। मेरी तो पिछले तीन-चार साल

से वहां होस्पिटल की मांग है। अगर आप वहां सर्वे करवाएंगे तो वह इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि वहां होस्पिटल भी खोला जा सकता है लेकिन वह कबाड़ और जर्जर हो रही है। वे सरकारी संपत्तियां हैं उनको यूज किया जाना चाहिए। उस समय उस बिल्डिंग पर लगभग 100 करोड़ रूपया लगा था और अब वह बिल्कुल खंडहर पड़ी हुई है उसमें कुछ नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी इस बात को सदन में रखा है इसलिए उस पर संज्ञान लिया जाए क्योंकि वह सरकारी सम्पत्ति है जिसको इतना पैसा लगाकर बनाया गया है और उसका मिस यूज हो रहा है और वह बर्बाद हो रही है/खंडहर हो रही है। उसमें चोरी-चकारी करने वाले बच्चे रहते हैं जो वहां पर कई तरह के गलत काम करते हैं इसलिए उसको संज्ञान में लाकर आप उसका सर्वे करवा कर उसमें कोई अच्छी चीज चालू करवाईये।

श्री वरूण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अभी कहा है कि ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होती है। ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट जस्ट अभी आई है जिसको हम देख नहीं पाए और उसके बाद चर्चा होती है। उसके बाद जो बात आ रही थी कि मानलीजिए अर्बन लोकल बोडीज में 260 करोड़ रूपये की डिमांड राजस्व खर्च के लिए है। वित्त मंत्री जी बता दें कि उसके अन्दर कौन सा पार्क बनवा सकते हैं, उसके अन्दर कौन सा सी.सी.टी.वी. लगा सकते हैं, उसके अन्दर कौन सी बिल्डिंग बना सकते हैं। राजस्व खर्च में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होगा ? यही इशू मैं उठा रहा था। जब आप बता देंगे कि आप यह पैसा किस कार्य पर खर्च करने के लिए मांग रहे हैं तो आसानी हो जाएगी और फिर उसी मुद्दे पर चर्चा होगी।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि ये सारे विषय ऐस्टीमेट्स कमेटी में जो सदस्य बैठते हैं ये सारी चर्चाएं होती हैं। उस चर्चा में कमेटी से संबंधित सारे विधायक होते हैं और वे उन पर सारी चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद वहां जो एक निष्कर्ष निकलकर आता है उस पर ये डिमांड बनकर आती है और यहां वे डिमांड्स रखी जाती हैं इसलिए यहां उसकी चर्चा करना न तो अपेक्षित है और न इस प्रकार से कोई संभव है। पहले जो परम्परा रही है वे यही हैं। (विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, यहां ऐस्टीमेट्स कमेटी की डिटेल नहीं रखी जाती और न ही उसमें वर्क का नाम होता है कि किस कार्य के लिए पैसा मांगा गया है। मैं ऐस्टीमेट्स कमेटी का सदस्य हूं वहां ऐसी कोई डिटेल नहीं दी जाती है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जाइये। जयवीर जी, आप अपनी बात रखें। (विघ्न)

श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला): उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। जैसे जो पैसा ऑलरेडी आपकी डिमांड है आप उसके लिए पैसा पास करवा रहे हैं जिसकी आपको पहले से जरूरत है। सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या खोट किया है कि वे भी अपनी नई डिमांड नहीं रख सकते हैं इसलिए उनको भी मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सिहाग जी, उनको मना थोड़ी किया गया है।

श्री जोगी राम सिहाग : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भी डिमांड हैं हम भी चर्चा कर सकते हैं। फिर यह रूल कहां से आ गया। इस तरह तो फिर हम भी चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से इस चर्चा का कोई औचित्य नहीं है और न ही मैं यहां कोई डिमांड रख रहा हूं। हमें जीरो ओवर भी मिलता है, हम प्रश्न भी लगाते हैं। यह तो केवल समय बर्बाद करने वाली बात है। जीरो ओवर में हम अपने हल्के की डिमांड रख सकते हैं। मेरे हिसाब से वरूण जी जो बात कह रहे हैं वह 100 प्रतिशत सही है। जिसके लिए पैसा डिमांड किया गया है केवल उन्हीं के ऊपर चर्चा की जाए कि वह काम सही है या नहीं है। उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब जैसे मेरे हल्के में भी चार सड़कों की जरूरत है। मैं भी लिख कर दे देता हूं ताकि अगले सेशन में मेरी भी डिमांड शामिल हो जाए। इस तरह हम तो रह जाएंगे।

श्री जयवीर सिंह (खरखौदा): उपाध्यक्ष महोदय, यहां सी.एम.साहब भी बैठे हैं मैं पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे वहां सोनीपत में बड़वासनी से लेकर बवाना तक नहरों के बीच सड़क बनी हुई है और जिस पर आए दिन हादसे होते हैं। पिछली बार भी मैंने यह बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई थी। पीछे सांपला के कुछ लोगों की कार उसमें डूब गई थी। वहां आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहां नहरों में कार गिरती है और उसमें आदमी मर जाते हैं। अभी चार-पांच दिन पहले फिर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक आदमी की डैड बॉडी मिली है और एक

आदमी की तो डैड बॉडी आज तक भी नहीं मिली है जोकि सिसाना गांव का अशोक नाम का आदमी था। उस पूरी सड़क पर न तो पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ से कोई सेफ्टी है और न ही नहरी विभाग की तरफ से कोई सेफ्टी है। आये दिन ये हादसे होते है। इस विषय को मुख्यमंत्री महोदय ने प्रायरिटी पर लेकर तुरंत प्रभाव से सुरक्षा के प्रबंध करने की बात कही थी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस विषय पर विशेष ध्यान देकर, यहां पर सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाये ताकि भविष्य में कोई एक्सीडेंट न हों और लोगों के जान माल की रक्षा की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: अब श्री जगबीर सिंह मलिक डिमांड नम्बर 10, 11 तथा 17 पर अपनी बात रखेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जो नहर वाली बात माननीय जयवीर जी ने कही है, मैं भी उस बात का समर्थन करता हूँ क्योंकि नहर के बीच की यह सड़क मेरे हल्के से भी गुजरती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे हरियाणा प्रदेश की सड़कें खराब हो चुकी हैं लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गोहाना बाई पास की एक घोषणा की थी और इस संदर्भ में दो बार विधान सभा के अंदर भी एशोरेंस दिया गया था लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार यह बाई पास बनेगा या नहीं बनेगा ? अगर सरकार इस बाई पास को नहीं बनाना चाहती है तो साफ तौर से इंकार ही कर दे ? इसके साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पहले सरकारी बसें चला करती थी लेकिन अब इनको हटाकर प्राइवेट बसें चलानी शुरू कर दी हैं। इसकी वजह से हमारी बेटियों का खानपुर यूनिवर्सिटी में आना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे यहां भावड़ गांव से कोई भी सरकारी बस नहीं आती है। अतः यहां की हमारी बेटियों को चार-पांच गांव से गुजरकर खानपुर यूनिवर्सिटी में आना जाना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि यहां पर सरकारी बसों का प्रावधान किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, सोनीपत से रोहतक, झज्जर व बहादुरगढ़ के लिए सारी प्राइवेट बसें ही चलती हैं। पता नहीं ये प्राइवेट बसें कहां से आ गईं, पहले ऐसा नहीं होता था।

इसकी वजह से लड़कियों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अतः इन रूटों पर जल्द से जल्द सरकारी बसें चलाई जायें ताकि लड़कियों को आने जाने में सुविधा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे किसानों को एक अलग से टैंशन भी हो रही है। यह टैंशन हाई वोल्टेज वायर्स की है जो उनके खेतों के उपर से गुजरती है। ये हाई टैंशन तार आदमी को अपनी और खींच लेती हैं और इसकी वजह से आये दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक तो जान माल का खतरा और दूसरा जो खेत में पोल लगे होते हैं, वहां पर पैदावार भी नहीं होती। इसकी वजह से छोटी होल्डिंग के किसान बहुत 'सफर' करते हैं क्योंकि उनकी सारी जमीन तो बिजली विभाग के पास चली जाती है तो उनके पास क्या बचेगा ? अतः सरकार को डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे किसानों को मुआवजा देने का प्रबंध करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आउट ऑफ कांटेस्ट, एक बात याद दिलाना चाहता हूँ जोकि वास्तव में इस प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। जुमला मुसतरका मालकान की जमीन के बारे में पिछले सदन में एक एश्योरेंस दिया गया था कि कुछ किसानों की जो कृषि योग्य भूमि है या कुछ वैसी भी है जोकि जुमला मुसतरका मालकान की है और उनकी खेवट के साथ लगती है जिसे कुछ ने बेच दिया है, के संदर्भ में सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि पंजाब कामन लैंड एक्ट में अमेंडमेंट लाकर इसमें इस तरह से सुधार करने का काम किया जायेगा कि यह लैंड पंचायत के नाम न चढ़े बल्कि व्यक्तिगत तौर पर जिनकी है, उनके पास ही रहे तो इस संदर्भ में मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि इस एजेंडे पर जरूर काम करें। अगर सरकार इस विषय को ऐसे ही छोड़कर जाना चाहती है तो आगे जाकर यह किसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब डॉ. रघुवीर सिंह कादियान डिमांड नम्बर 10, 12, 17 व 20 पर अपनी बात रखेंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे तो यह बात कस्टमरी ही है कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेंट्स (सैकिंड इंस्टालमेंट) हर साल आते हैं और एप्रूव होते हैं और इसमें ओरिजनल बजट

से अलग बजट की डिमांड की जाती है। इस संदर्भ में हार्ड कापी प्रोवाइड करवाने की बात पहले भी कही जा चुकी है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यदि हार्ड कापी मिल जाये तो माननीय सदस्य कम से कम यह तो देख सके कि ओरिजनल बजट से अलग जो पैसा मांगा गया है वह आखिरकार किस परपज के लिए मांगा गया है और ऐसे में माननीय सदस्य अपने सुझाव भी दे सकते हैं और इससे स्कॉप ऑफ डिस्कशन का एक तरह से लिमिटेशन हो जाता है जिसकी वजह से सदन का महत्वपूर्ण समय भी बच जाता है। अब जिस तरह से टैब पर सब कुछ डाल दिया गया है उससे हमें स्पेसिफिक तो यह पता ही नहीं चलता कि बजट कहां पर यूटिलाइज होगा। उपाध्यक्ष महोदय, 286 करोड़ रूपये की डिमांड दे रखी है तो इसमें मेरा सबमिशन यह है कि जो यह पैसे मांगे जा रहे हैं तो इस संदर्भ में जो आनरेबल मैम्बरज के सुझाव आ रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए अर्थात् माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि वित्त मंत्री भी है और ओवर आल पावरफुल मैन हैं, वे डिस्कशन के दौरान जो आनरेबल मैम्बरज की डिमांड आ रही हैं, उनकी डिमांड्स को भी उसी तर्ज पर इस बजट के साथ जोड़ लें जिस तरह से ओरिजनल बजट तैयार करते समय आनरेबल मैम्बरज की ओपीनियन ली जाती हैं और बजट के साथ उनको जोड़ लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: कादियान जी, जो आप बता रहे हैं उसको आगे के लिए भी नोट किया जा रहा है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 10 जोकि एनवॉयर्नमेंट से संबंधित है, पर एक सुझाव देना चाहता हूँ। पिछले तीन-चार महीनों से पोल्यूशन-पोल्यूशन-पोल्यूशन और खराब एयर क्वालिटी की बात की जा रही है और इसका कारण बताया जा रहा है कि फलां-फलां जगह से ऐसी हवा आ रही है और इस प्रकार यह बात माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। उपाध्यक्ष महोदय, एनवॉयर्नमेंट पाल्यूशन कंसर्ड विद द क्वालिटी ऑफ द लाइफ और चाहे बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं, यह हर आम और खास की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। हरियाणा प्रदेश दिल्ली की पैरिफरी में आता है। दिल्ली देश की राजधानी है। वहां पर हरियाणा का एनवॉयर्नमेंट का एक अलग विषय है। अगर आप एनवॉयर्नमेंट का एक होली-सोली डिपार्टमेंट बना लें तो चूंकि एनवॉयर्नमेंट के विषय पर सेंटर की विसिनिटी है तो उस ग्राउंड के

आधार पर एनवॉयर्नमेंट के लिए कितना ही बजट सेंटर से मांगा जा सकता है और वह बजट मिल भी जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल पार्टीज भी एनवॉयर्नमेंट के विषय को अपने मैनिफैस्टों में देने की बात कर रही हैं तो उस परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि प्रदूषण का जो अस्पेक्ट है, उस पर आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं क्योंकि यह क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कंसर्ड है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2016 में बेरी में गए थे तो एक कालेज की बात कहकर आए थे लेकिन उस बात को हुए आज सात साल हो गए हैं लेकिन वहां पर आज तक न तो कोई ईंट ही लगाई गई है और न ही वहां के लिए किसी तरह की कोई फाइनेंशियल सेंशन/एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल आई है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के का जो डीघल गांव है उसका भी अस्तित्व अलग से उभरकर सामने आ रहा है। यहां की फाइनेंशियल कैपिटल के हिसाब से सुविधायें उपलब्ध नहीं है। मुझसे मेरे हल्के के 15-20 गांव के आदमी मिले थे और उन्होंने बेरी और डीघल के कालेज के लिए अनुरोध किया है। उस परिपेक्ष्य में सबमिशन है कि सरकार बेरी और डीघल में कालेज बनवाने का काम करे। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड न. 17 पर बोलना चाहूंगा। फतेहाबाद, फाजिल्का, गंगानगर और भिवानी आदि के लोगों को महम से बेरी होते हुए गुड़गांव जाना पड़ता है। हमारे यहां पर एक पैरिफरल रोड की पिछले काफी दिनों से चर्चा हो रही है। यहां बेरी में पैरिफरल रोड बनाने की बहुत जरूरत है क्योंकि यहां पर आए दिन जाम लगा रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ दुलेडा, दाबोदा व मातन का बाई पास तथा छारा का नार्दन बाई पास भी मंजूर हो चुका है। इनको भी इस बजट में शामिल कर लिया जाये तो बहुत अच्छी बात होगी। हम पिछले नो साल से इस विषय को उठाते आ रहे हैं और जिस प्रकार सरकार सबका साथ-सबका विकास की बात करती है, ऐसी बातों की वजह से इस नारे में ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है और मुझे इसमें एक अपोजीशन मैम्बर के साथ डिस्क्रिमिनेशन की ही स्मैल आती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री कुलदीप वत्स जी ने बहादुरगढ़-झज्जर रोड का मामला उठाते हुए बताया था कि 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वह डेढ-दो घंटे में पूरा होता है। जब बाहर का कोई आदमी एन.सी.आर या यू कहें कि दिल्ली की विसिनिटी में आता है तो उसके लिए हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सबमिशन है कि हमारी इस मांग की तरफ ध्यान दिया जाये। अंत में मैं

डिमांड न. 20 पर बात करना चाहूंगा जोकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से संबंधित है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत ही इल्लिगल, हैफाजर्ड और अनप्लांड मैनेर प्रस्तुत किया गया है। इसको अनअथोराइज्ड डिवैल्पमेंट कह लो, कोलोनाइजर कह लो या चाहे इसको विकास कह लो , उपाध्यक्ष महोदय, इसकी वजह से इतने लोग इसके विरोध में खड़े हो गए है कि ऐसी हालत में कस्टमर की भी एक्सप्लायटेशन है, फार्मर्ज की भी एक्सप्लायटेशन है और ऐसी अवस्था में प्रभावित लोग कैसे काम चलाते होंगे यह आप भी समझ सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डिपार्टमेंट भी इंवोल्व हैं । यह कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा नक्शा देकर जाएं जिसमें पूरी तरह से डिवैल्पमेंट हो । देखिये, रोहतक के 18-20 किलोमीटर तक चारों तरफ कॉलोनियां कटी हुई हैं । उन कॉलोनियों को कौन काट रहा है ? अगर मैं किसान को दस लाख रूपये देकर उसकी जमीन खरीदकर प्लॉट काट दूंगा तो प्लॉट बिकते रहेंगे और रजिस्ट्रीज होती रहेंगी । अगर रजिस्ट्री नहीं भी होगी तो भी वे कागज पूरे करवाकर लोगों को प्लॉट दे देते हैं और कब्जा दे देते हैं । जो प्लॉट काटता है वह तो बीच में 20-30 या 50 करोड़ रूपये मुफ्त में लेकर चला जाता है । बाद में वहां पर पानी, बिजली, सीवर और अन्य फैसिलिटी कौन देगा इस बारे में कोई नहीं सोचता । मेरा प्रश्न यह है कि यह सिचुएशन कैसे खड़ी हुई ? यह सब एक गलत पॉलिसी के तहत खड़ी हुई है । पहले के समय मे ड्रॉ ऑफ लॉट होता था जिसमें हर आदमी अपना अलग से फॉर्म भरता था । डिप्टी स्पीकर सर, ड्रॉ ऑफ लॉट में इतना पैसा आता था कि वह दो-तीन साल तक सरकार के पास पड़ा रहता था और उसके केवल ब्याज से ही सैक्टर बन जाता था । वह बहुत जबरदस्त प्रोफिटेबल सिस्टम था और उस ड्रॉ ऑफ लॉट सिस्टम से आम आदमी को प्लॉट मिलता था । ई-ऑक्शन से यह हुआ कि उससे पूंजीपति लोग प्लॉट ले लेते हैं और आम आदमी इधर-उधर देखता रहता है । इसके लिए कॉलोनाइजर ने रास्ता ढूंढ लिया । इस तरह से यह एक ऐसी हैफजर्ड एण्ड मशरूम ग्रोथ हो रही है जोकि सरकार के लिए एक चैलेंजिंग असाइनमेंट साबित होगा । हरियाणा में जिस तरह से ग्रॉथ हो रहा है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही सीरियस होगा । मेरा सरकार से अनुरोध है कि ई-ऑक्शन की पॉलिसी को ड्रॉ ऑफ लॉट से किया जाए । आप

सैक्टर चाहे 50 काटो या 200 काटो लेकिन आप उसकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी देखो ताकि सभी को फायदा मिले। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हरियाणा में प्लॉट काटने का सिस्टम चल रहा है अगर आप इसको डिटेल में देखोगे तो पाओगे कि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। इसमें ऊपर तक पैसा जा रहा है, इसीलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सब्मिशन है कि वे इसे ठीक करें और एक ऐसी पॉलिसी बनायें जिससे दिल्ली के नजदीक हरियाणा में प्लान्ड तरीके से ग्रोथ हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यह कहें कि हमारे पूर्वज अच्छा काम करके गये थे। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह (इसराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नं. 17 पर बोलना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि गांव छिछड़ाणा से दीवाना वाली सड़क बिल्कुल खराब है और गांव भाऊपुर से भिंडारी वाली सड़क भी बिल्कुल खराब है। महोदय, रिफाइनरी फाटक से बोहली तक की सड़क बिल्कुल टूटी हुई है और मैंने इस समस्या का जिक्र हर सत्र में किया है। ऐसा कोई भी सत्र नहीं गया जब मैंने उसकी बात न की हो। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। रिफाइनरी वाली सड़क से हर रोज 8-10 गांव के आदमी रिफाइनरी में काम करने के लिए जाते हैं और वहां से बहुत-सा ट्रैफिक भी जाता है परंतु अब यह रास्ता अत्यंत खराब होने की वजह से उन लोगों को दूसरे गांव से काफी दूरी तय करके आना पड़ता है। अतः सरकार यह सड़क भी बनवाने का कार्य करें। इसके अलावा गांव शाहपुर से परढाणा तक की सड़क भी काफी खराब है। उस पर लोगों का आना जाना भी बंद है। गांव दरियापुर से टीटो तक का 6 करम का रास्ता कच्चा है। उसे पक्का कराया जाए। इसके साथ-साथ गांव भादड़ से सुताना वाला रास्ता भी 6 करम का है और यह भी कच्चा है। उसे भी पक्का कराया जाए। पानीपत से सफीदों तक की सड़क को फॉरलेन करने के पैसे सरकार ने काफी समय से दिए हुए हैं। मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस पर सरकार जल्द-से-जल्द कार्य शुरू करवाने का काम करे। गांव इसराना से रोहतक वाला जो फलाईओवर गुजरता है उसके दोनों तरफ गड्ढे बने हुए हैं। इनकी वजह से वहां से आने-जाने का रास्ता नहीं बचा है। वहां पर अब भी सड़क के दोनों ओर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए मैंने पहले भी कई

बार निवेदन किया है। एक-दो बार उन गड्ढों को मशीन से साफ कराया गया लेकिन उनका सही समाधान नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि फलाईओवर के पास जो सड़कें टूटी हुई हैं सरकार उन्हें बनाने का काम करें क्योंकि वहां से लगभग 50 गांवों के लोगों का आना-जाना है। महोदय, ब्लॉक इसराना और मतलौडा में कोई भी रैस्ट हाउस नहीं है। अतः मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि यह बड़ी भारी समस्या है, इसलिए सरकार दोनों जगह रैस्ट हाउस बनाने की कृपया करे। सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद सर।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री मामन खान जी डिमांड नं० 20 पर अपनी बात रखेंगे।

श्री मामन खान (फिरोजपुर झिरका): अध्यक्ष महोदय, मैंने 3 डिमांड्स पर बोलने के लिए लिखकर भेजा था।

श्री उपाध्यक्ष: मामन खान जी, आपने डिमांड नं० 20 के बारे में लिखकर दिया था।

श्री मामन खान: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चेंज करवाया था कि मुझे डिमांड नं० 12, 17 और 20 के बारे में बोलना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरी बात डिमांड नम्बर 12 से संबंधित है। मैंने इससे पहले विधान सभा में सेशन के दौरान प्रश्न लगाया था कि मेवात के लिए एक स्टेट यूनिवर्सिटी दी जाए। मेरे पास इसका दिनांक 23.5.2022 को जवाब आया था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जवाब मिला है कि आपके मेवात के लिए यूनिवर्सिटी अंडर कंसीड्रेशन है। मेरे पास यह उस चीज का जवाब है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हर जिले में यूनिवर्सिटी है तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मेवात के लिए भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी दी जाए क्योंकि यह गरीब इलाका है। वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। वहां के बच्चों के पैरेंट्स के पास इतने अच्छे इन्कम के रिसोर्सिज नहीं हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हिसार, रोहतक और सिरसा भेज सकें। इसमें यही बात थी कि जो फाईल है, उस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी उस टाइम पर हॉयर एजुकेशन विभाग को देखते थे, मैंने उनको उसका रैजोल्यूशन दिया है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट

भी आ गयी है। इस पर यह लिखा हुआ है कि your file is under consideration. मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस बजट में भी स्टेट यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया जाए। इसके अलावा मैं डिमांड नम्बर 17 पर बोलना चाहूंगा। मेरे हल्के के कुछ रोडज हैं जोकि बहुत ज्यादा खराब हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर दौरा करके आये थे और उन्होंने भी उस रोड की हालत देखी है। होडल से लेकर बड़खली चौक तक निकलना मुश्किल है और वहां के लोग साईड के गांवों में से निकलकर आते हैं। इसको भी इस डिमांड में शामिल किया जाए। निठल बारा से लेकर गुआना तक रोड की भी ऐसी ही हालत है। मैं इसमें गढ़े तो क्या बोलूंगा कि वहां से गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल होती है क्योंकि काफी गाड़ियों के तो रात को जब लाईट नहीं पड़ती है तो चैम्बर टूट जाते हैं। इसको भी इस डिमांड में शामिल किया जाए। अलवर रोड से पाठकोरी रोड की भी हालत बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपको नेशनल हाइवे-248 के बारे में तो पता ही है कि नूंह से लेकर निमूड़ाका बॉर्डर तक क्या हालत है? सुभाष चौक से लेकर नूंह तक इतना अच्छा रोड बना दिया गया कि वहां से मात्र 25 मिनट में आ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब नूंह से निमूड़ाका बॉर्डर तक जाते हैं तो कम से कम 2 घंटे का टाइम लग जाता है। आप पिछले दिनों मेवात का दौरा करके आये थे तो वहां पर आपने देखा भी था। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं तो इसको क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है? क्या ऐसी बात है कि जब हम पिछले 4 सालों से बार-बार इसी बात को उठा रहे हैं? मेरे अलावा मेरे दोनों साथी माननीय विधायकों ने भी इस बात को बार-बार उठाया है कि इस रोड को किसी भी सूरत में कंसीडर कर लें। ईवन, सरकार की और जो प्रपोजल है उसको भी देख लें। इसकी रि-सरफेसिंग तो कर दें जब सुभाष चौक से लेकर नूंह तक हो गयी है तो नूंह से लेकर निमूड़ाका बॉर्डर तक सरफेसिंग हो जाने से लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा मैं डिमांड नम्बर 20 पर अपनी बात रखना चाहूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहले भी यह बात रखी थी कि मेवात जिला अप्रैल, 2004 में घोषित हुआ था और हरियाणा प्रदेश में 22 जिले हैं। इन 22 जिलों में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसमें हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण के सैक्टर्ज न हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हम इस पर एक प्रोजैक्ट तैयार करवा लेते हैं। उन्होंने यह बात

ऑन दा फ्लोर ऑफ दि हाउस कहा था कि एक प्रोजैक्ट तैयार करवा लेते हैं। प्रपोजल बनवाकर जमीन का रेट निकलवा लेते हैं और जितना भी रेट आएगा तो कुछ मेवात के लोग उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मामन खान जी, क्या आप डिमांड नं० 20 पर बोल रहे हैं? आप जल्दी कन्कल्यूड करें।

श्री मामन खान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 20 पर ही बोल रहा हूँ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में आश्वासन दिया था कि इसमें जो प्रोजैक्ट तैयार होकर आएगा उसमें जमीन की कितनी कॉस्ट आती है उसके हिसाब से यहां पर सैक्टरज काटेंगे। जब बगैर जिले बने तावडू, पलवल और दूसरी जगहों पर सैक्टरज कंस्ट्रक्टिड हैं तो मेवात में क्यों नहीं हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस बजट में मेवात में भी ये सैक्टरज दिये जाएं।

श्री लक्ष्मण नापा (रतिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 20 पर बोलना चाहता हूँ। मेरे हल्के में अलीका पिलछियां रोड है जो कि मार्केटिंग बोर्ड से जिला परिषद् को ट्रांसफर हुई है। इस सड़क की हालत बहुत ही खराब है। यह सड़क 30 गांवों को जोड़ने का काम करती है। इन गांवों के बीच में से घग्गर नदी गुजरती है। इस सड़क पर सिर्फ एक ही पुल है। पंजाब राज्य के काफी गांव इस सड़क से जुड़े हुए हैं। इसका एस्टीमेट्स 2 करोड़ 20 लाख रुपये का बन चुका है और जो पूर्व विधायक हैं उनका गांव भी पिलछियां में पड़ता है, उनका मुझे आए हफ्ते फोन भी आता रहता है। यह सड़क बनाना बहुत ही जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में वोटिंग के लिए रखा जाएगा।

मांग संख्या 3 से 6

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है-

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 51,19,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹6,39,41,268/- से अधिक न हो, मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन /

निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 4-राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 5-गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 3,54,82,865/- से अधिक न हो, मांग संख्या 6- वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी (डी.ई.एस.ए.) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या 10

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है-

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 286,61,65,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या 12

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है-

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 59,33,20,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 74,72,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 12- शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या 15

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है-

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/युवा मामले) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या 17

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है-

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 221,89,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 17-लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/परिवहन/नागर विमानन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या 19 से 20

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है-

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1126,25,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 19-ऊर्जा विभाग (विद्युत/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/ एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 260,10,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 20- नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय(स्थानीय सरकार)/विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधायी कार्य-

(क) विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023.

श्री उपाध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक 2023 पर तुरंत विचार किया जाये।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

कि हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है -

कि हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 2

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 3

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है उसमें मेजर रीजन इन्होंने सैटलमेंट ऑफ दी आउटस्टैंडिंग ड्यूज दिया है तो यह सिचुएशन अराइज हुई कि मतलब ये ड्यूज जो बकाया हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, एक कारण यह भी दिया है। मतलब यह है कि इसमें हमारे पास कौन एजेंसी है किसका बकाया है, कौन आदमी है किसका बकाया है? उपाध्यक्ष महोदय, यह एक लिस्ट तो सभी माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए देनी चाहिए थी ताकि उससे सभी को पता लग सके कि कितना पैसा बकाया है जिनकी सैटलमेंट होने के बाद आने की उम्मीद भी है। इस तरह की बात तो होनी ही चाहिए थी। अब आप एक्ट तो हमारे से पास करवा रहे हैं लेकिन उसका मोटिव क्या है? आप कोई स्पैसिफिक पिक एंड चूज का कोई सैटलमेंट करोगे, किस तरह से करोगे? उपाध्यक्ष महोदय, ये कौन लोग हैं, इनका कितना अमाउन्ट बकाया है? इस लाइन पर मेरी सन्निभान है कि इस एक्ट के पास होने से पहले यह इन्फोर्मेशन माननीय सदस्यों को देनी चाहिए।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, इसमें दो अमेंडमेंट्स हैं। पहली अमेंडमेंट यह है कि जब जी.एस.टी. एक्ट आया था तो वैट को

समाप्त करने के लिए 31 मार्च, 2017 की तारीख रखी गई थी। मगर जी.एस.टी. की जो इम्पलीमेंटेशन थी, वह इम्पलीमेंटेशन 01 जुलाई, 2017 से थी और जो दूसरी अमैंडमेंट और प्रोवीजन डाला जा रहा है, वह वन टाइम सैटलमेंट स्कीम के लिए लाया जा रहा है। जिसमें वैट रिजिम के जितने भी ड्यूज सरकार के आज पैडिंग हैं। चाहे कोई विवादित हैं, किसी के ऊपर अभी नोटिस इशू हुए हैं, किसी के ऊपर अलग-अलग प्रकार से क्लेम्स आज बनाये गये हैं और उनमें ऑब्जेक्शंस फाइल करी हुई है और किसी के ऊपर क्लेम्स बनकर ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं है। आज चार तरह के लगभग 32 हजार करोड़ के आज विवादित टैक्स ड्यूज पैडिंग हैं। इसके लिए एक स्कीम लायी जा रही है क्योंकि हमें बीच के गैप को ट्रीट करने के लिए तारीख में परिवर्तन करना पड़ेगा इसीलिए आज यह अमैंडमेंट लायी गई है। ओ.टी.एस. स्कीम तो कैबिनेट की एक स्कीम थी जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी। आज सिर्फ तिथि बदलने के लिए, उसका रैफरेंस इस एक्ट के अन्दर दिया गया है ना कि इस सदन में हम कोई इतनी बड़ी अमैंडमेंट लेकर आ रहे हैं और दूसरी चीज जो ड्यूज, नो ड्यूज हैं। मूल किसी का माफ नहीं किया जा रहा है। जो उसके ऊपर एरियर्स और पैनल्टीज लगेंगी। ओ.टी.एस. स्कीम के माध्यम से जैसे पहले विवाद से विश्वास के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और हमारे से पहले बहुत प्रदेशों ने भी ओ.टी.एस. स्कीम लाने का काम किया। उसी तरह की स्कीम आने वाले भविष्य में प्रदेश सरकार लायेगी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदय, उसका कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। इन्होंने मूल पैसे के लिए कह दिया कि डिफरेंट पर्सन के साथ डिफरेंट क्राइटेरिया होगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज की इस अमैंडमेंट में ओ.टी.एस. स्कीम का कोई लेना-देना नहीं है। यह अमैंडमेंट तो आज सिर्फ तिथि को परिवर्तित करने के लिए लाई गई है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है—

कि विधेयक पारित किया जाये।

(विधेयक पारित हुआ।)

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.12.2023 और 18.12.2023 को सदन में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जवाब देना ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सत्र दो दिन से चल रहा है तो इस दौरान इसमें काफी विषय कल के क्वेश्चन ऑवर के दौरान तथा कुछ विषय आज के क्वेश्चन ऑवर में से हैं। इनमें से मुझे कुछ के जवाब डिपार्टमेंट्स द्वारा दिए गए हैं जिनको मैं सदन में रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हमारे कई माननीय सदस्यों ने नौकरियों का विषय रखा है चाहे ये एच.पी.एस.सी. की हों अथवा स्टाफ सलैक्शन कमीशन की हों। इसके अलावा बेरोजगारी की बात कही गई, एच.के.आर.एन. की बात कही गयी। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती गीता भुक्कल जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री रामकुमार गौतम जी, श्री अभय सिंह चौटाला जी, राव दान सिंह जी के अलावा भी कई माननीय सदस्यों के बहुत से प्रश्न थे जिनके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हम लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियों में तुलना जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि आखिर तुलना से ही पता लगता है कि कितनी-कितनी भर्तियां, कैसे-कैसे की गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां स्टाफ सलैक्शन कमीशन तथा एच.पी.एस.सी. की जो भर्तियां हुई हैं उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो एच.पी.एस.सी. की भर्तियां कुल 8700 हुईं और अभी लगभग हमारे नौ सवा नौ साल ही हुए हैं। अभी हमारी सरकार का समय और शेष है। उसमें भी जो और भर्तियां होंगी उनकी भी अलग से डिटेल है। अभी 11,500 भर्तियां हमारी हो गई हैं। एक प्रश्न श्री बलराज कुण्डु जी ने पूछा हुआ था उसको भी साथ में ही शामिल करके मैं उत्तर बता रहा हूं कि क्लास- I और क्लास -II की 3200 भर्तियों की अभी बहुत जल्दी एडवरटाईजमेंट होने वाली है। ऐसे कुल मिलाकर के 15,000 के आस-पास ये भर्तियां एच.पी.एस.सी. की हो जायेंगी। ऐसे ही स्टाफ सलैक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्षों में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां कर दी हैं। इसके अलावा 45,973 ग्रुप सी की भर्तियों में कैंडीडेट्स का सी.ई.टी. टैस्ट हो गया है, यह अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं। सोशियो इकोनोमिक क्राईटेरिया के माध्यम से पांच अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी, गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं

है या जो अन्य कुछ क्लॉसिज हैं उसको लेकर कुछ एप्लीकैंट्स ने कुछ आपत्ति लगाई हुई है मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही उसका फैसला हो जायेगा। तो 48,573 तो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी और ऐसे ही ग्रुप डी का अलग से सी.ई.टी. टैस्ट हुआ है। ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि रिजल्ट आयेगा वह भी लगातार तीन साल के लिए निकालकर रखा जाता है। साढ़े तीन लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं जो भी उसमें क्वालीफाई करके मैरिट पर आयेंगे उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी नियुक्तियां हो जायेंगी। उसमें यह प्रावधान है कि जब रिजल्ट निकालना होगा उस समय हमारे पास जितनी रिक्वीजिशन आएंगी उसके हिसाब से वे भर्तियां होंगी। चीफ सैक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वीजिशन देनी हैं। अभी तक चीफ सैक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13,657 भर्तियों की रिक्वीजिशन तो जा चुकी है लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आयेगा तब तक 500 या 1000 और भी रिक्वीजिशन आ सकती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 15000 हजार भर्तियां आने वाले 6 महीने में ये और हो जायेंगी। ऐसे 15000 ये होंगी और 1,06,000 हम पहले कर चुके हैं। 15,000 ये और 45,000 पहले थी तो कुल मिलाकर 60,000 भर्तियां ये हो जायेंगी। इस प्रकार से इस 10 साल में हमारा अनुमान है 1,67,000 भर्तियां ये ग्रुप सी और डी की हमारी कम्पलीट हो जायेंगी। इसके अलावा एच.के.आर.एन. का जो विषय आया है। इस एच.के.आर.एन. के बारे में भी तरह-तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं। मैं जरूर सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि एच.के.आर.एन. का मुख्य कारण यह था कि बहुत सी जगहों से डिमाण्ड आती थी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाये। ठेकेदारों के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट्स भर्तियां करवाते थे। जहां कहीं आऊटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती भी आऊटसोर्सिंग पार्ट- I और पार्ट -II की लेकिन उसमें बहुत सी अनियमिततायें हमको ध्यान में आती थी क्योंकि जितनी संख्या वे मंजूर करवा लेते थे इतने लोग भी कई बार होते नहीं थे लेकिन सैलरी उतने की ही निकलती थी। अपनी मर्जी से रखना और जितने लोगों को रखते थे उसमें कहीं न कहीं उनकी कमीशन तय होती थी। उसकी बहुत सी शिकायतें आने के बाद हमने उन सभी को

समाप्त करके एच.के.आर.एन. एक सरकारी प्लेटफार्म बनाया है। चीफ सैक्रेटरी की देखरेख में ये सब चलता है जितने पुराने लोग थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि अगर वे उसी व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं तो बने रहें। अगर एच.के.आर.एन. में आना चाहें तो हम उनको पोर्ट करेंगे तो ऐसे अधिकांश लोगों ने अपनी सहमति दी थी। 1,05,728 ऐसी मैन पॉवर है जो दूसरे विभागों से पोर्ट की गई है और अलग से जो डिमाण्ड आई थी 12,885 ऐसे नये लोगों को भी एच.के.आर.एन. में रखा गया है। जो नये लोग रखे जाते हैं उसके अंदर पारदर्शिता से बाकायदा जो सभी कैंडीडेट्स होते हैं उनका पैरामीटर क्या है मेनली परिवार की इनकम जिसकी कम होती है उसको हम अंक ज्यादा देते हैं ताकि गरीब लोगों को ये आऊटसोर्सिंग की प्राइवेट नौकरी मिल सके। ऐसे ही उनकी शिक्षा उनका दूसरा पैरामीटर होता था। अगर परिवार का स्पैशल स्टेटस है हमारी कोई बहन विडो है, विडो का बेटा है या कोई दिव्यांग है तो इस नाते से एज का भी क्राईटेरिया उसमें रखा था कि अगर एज 28 वर्ष से 35 वर्ष के अंदर है वह एक आयु ऐसी होती है जिसमें तुरन्त कुछ न कुछ काम उसको मिलना चाहिए। इस एज वर्ग को वरीयता दी जाती थी। जिस ब्लॉक में नौकरी करनी है उसी ब्लॉक का व्यक्ति होता था तो उसको भी वरीयता दी जाती है ताकि ग्रुप डी का व्यक्ति थोड़ी सैलरी में अगर बहुत दूर चला जायेगा तो उसको कठिनाई होगी। कुछ ऐसे उदाहरण आये हैं कि रहने वाला यहां का है और उसको नौकरी शायद 150 से 200 किलोमीटर दूर मिल गई। कारण यह है कि जब ऑप्शन की बात आती है तो उस समय उसको यही लगता है कि नौकरी मिल रही है और वह दूर की नौकरी भी सिलैक्ट कर लेता है। बाद में जब वह ज्वाइन करता है तो उसकी शिकायत आती है कि मुझे तो 200 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। हालांकि स्टेशन की ऑप्शन भी उसी को दी जाती है कि यह नौकरी है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। आगे से हम इस दूरी के अंक ज्यादा रखना चाहते हैं ताकि जो निकट का व्यक्ति है उसको सिलैक्शन में अंक ज्यादा मिल जायें और दूर जाने वाले को ऑप्शनिंग कम हो जाये ताकि व्यक्ति को जैसी उसको ऑप्शन मिले वह उसमें भर सकता है। इसी प्रकार से अगर बेरोजगारी की बात की जाये तो बेरोजगारी के अलग-अलग ऐजेन्सीज के अलग-अलग आंकड़े आते हैं। उन आंकड़ों के बारे

में हम अपनी आंकड़ों की पुस्तक खोल कर बैठते हैं और हमारे विपक्ष के साथियों की वह आंकड़ों की पुस्तक अलग होती है। इसी क्रम में सी.एम.आई.ई.(सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी) एक संस्था है जिसकी आंकड़ों की स्थिति समय-समय पर बदलती रहती है। यह अलग बात है कि उन्होंने एक बार सितम्बर महीने में कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत है और बाद में बढ़ा कर उन्होंने 28 प्रतिशत और 34 प्रतिशत कर दी और उसके बाद फिर 28 प्रतिशत आ गई। मैंने देखा नहीं है और यह कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, मुझे किसी ने बताया है कि पिछले महीने नवम्बर, में सी.एम.आई.ई.ने हरियाणा में बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत बताई है। हालांकि मेरा सी.एम.आई.ई. की पुस्तिका पर कोई भरोसा नहीं है लेकिन मैं तो उनको बताना चाहता हूँ जो उस संस्था के आंकड़ों पर खेलते हैं। हमारे पास एक-एक व्यक्ति का बेरोजगारी का सैल्फ डिक्लेयर्ड डाटा उपलब्ध है। परिवार पहचान पत्र में हम सामने वाले को कहते हैं कि आप क्या काम करते हैं, अगर वह बेरोजगार होता है तो लिखवाता है कि मैं बेरोजगार हूँ। 18 साल से लेकर 58 साल तक की उम्र के लोग जो अपने आपको बेरोजगार कहते हैं उनका आंकड़ा हमारे पास 7 प्रतिशत के आसपास रहता है। वह कभी आधा प्रतिशत कम होता है कभी आधा प्रतिशत अधिक हो जाता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि नीति आयोग के आंकड़े भी बता दिये जायें। साथ ही साथ यह भी बता दिया जाये कि राष्ट्रीय बेरोजगारी के आंकड़ों से हरियाणा के आंकड़े कितने अधिक हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, आई.एल.ओ. ने भी पिछला आंकड़ा 9 प्रतिशत का ही बताया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी की नैशनल ऐवरेज भी बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ा नैशनल ऐवरेज के आसपास चलता रहता है लेकिन 9 प्रतिशत से ऊपर वे भी नहीं बताते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बताया जाये कि 9 प्रतिशत से अधिक किन-किन राज्यों के आंकड़े हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह विषय पहले आता तो मैं वह भी पता करके आता और मैं वह भी बता दूंगा। जहां तक आई.एल.ओ. के आंकड़ों की बात है तो वह भी सैम्पल बेस्ड होता है और सैम्पल के आधार पर ही सारे निष्कर्ष होते हैं। लेकिन हम सैम्पल के आधार पर नहीं बल्कि हरियाणा की कुल जनसंख्या के आधार पर बता रहे हैं। आज हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख है और 71 लाख परिवार हैं। हमारे पास सभी का डाटा उपलब्ध है कि कौन व्यक्ति क्या करता है। उसमें कोई भी कॉलम खाली नहीं बचता है। अगर कोई औरत हाउस वाइफ है तो उसके कॉलम में लिखा जाता है कि वह हाउस वाइफ है। इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा ऑरफन है तो उसके आगे भी लिखा जाता है जबकि वहां तो कई आंकड़े ऐसे हैं जिसमें 15 साल के बच्चे को भी बेरोजगार दिखाया गया है। 18 साल के बच्चे को हम मानते हैं कि शिक्षा उसका दायित्व है और 0 ड्रॉपआउट हमारी पॉलिसी है। आज के समय में 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के लगभग 2 से अढ़ाई लाख बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूलों में नहीं जाते हैं। यह अलग बात है कि कुछ अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जिनमें जाने वाले बच्चों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। जैसे हमारे गुरुकुल हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं तथा मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और हो सकता है उनमें भी कुछ बच्चे पढ़ते हों या न भी पढ़ते हों और घर में रहते हों या माता-पिता उनको नहीं पढ़ा पाए हों। हम स्कूल ऐजुकेशन के माध्यम से ऐसे 6 साल से लेकर 18 साल तक के एक-एक बच्चे को ट्रेक करवायेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे स्कूल में आ जायें। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है तो वह सीमित है। सरकारी नौकरी सालाना 20 हजार के आसपास रहती है। अगर 2-3 साल की इकट्टी हो जायेंगी तो वे 50-60 हजार हो जायेंगी और अगर सालाना भर्ती होती रहेगी तो वह 20 हजार के आसपास ही रहती है। हमारे कुल गवर्नमेंट इम्पलाइज की संख्या लगभग 4 लाख है। इस बारे में एक बात बार-बार पूछी जाती है कि सैंकशन्ड पोस्ट्स कितनी हैं। यह अलग बात है कि सैंकशन्ड पोस्ट्स सभी डिपार्टमेंट हायर साइड सैंकशन करवा लेते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि भर्ती होने में समय लगता है। उनको यह भी रहता है कि दोबारा पोस्ट सैंकशन करवाने में भी समय लग जाता है इसलिए एंटीसिपेशन करके उनकी संख्या इनफ्लेटिड बढ़ाई जाती है। उदाहरण के लिए जे.बी.टी. की सैंकशन्ड पोस्ट्स 45 हजार हैं जबकि नैशनल ऐजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 30 बच्चों पर एक टीचर के हिसाब से हमें 36

हजार जे.बी.टी. चाहिएं। इस प्रकार से हमारी जे.बी.टी. की 9 हजार पोस्ट्स ज्यादा सैंक्शनड हैं। फिर भी जब हमारे पास ज्यादा टीचर आ जाते हैं तो 1/25 करके हमने उनकी नौकरियों को रखा हुआ है। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कोई खर्ची-पर्ची का विषय आ जाता होगा।(विघ्न)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कोई खर्ची-पर्ची का विषय नहीं है और यही बातें मुझे आपको कहनी हैं कि जो चीजें जब कभी चलती थी वह बातें आपको याद आती हैं।

‘जुबान सही और दिल साफ रखता हूं,
कौन कब कैसे बदलेगा सबका हिसाब रखता हूं।’

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, इसमें क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर हो गया। आप इसके बाद बोल लेना। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने खर्ची-पर्ची की बात की है। इसमें जब डिप्टी सैक्रेटरी के पास तीन करोड़ रूपये पाए गये थे उसमें खर्ची भी थी और पर्ची भी थी और उसमें एक टेलिफोन भी था। उस टेलिफोन में दो ऑफिसर्स का जो वार्तालाप है उसमें रिजल्ट बदलवाने के लिए बात कही गई है।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमारे पास एक भी बात की जानकारी नहीं आई है लेकिन हमने उसका संज्ञान लिया है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : सी.एम. साहब, मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाऊस एक बात कह रहा हूं कि मैं भी आपका प्रशंसक हो जाऊंगा। उसमें जो टेलिफोन मिला था और जिसमें उन दो अधिकारियों का डिस्कशन था कि किसके रिजल्ट बदले जाएंगे, किसके नम्बर दिये जाएंगे, किसके कम दिये जाएंगे। उसको आप कर दीजिए क्योंकि आप गीता के भी स्पोर्टर हो। आप अर्जुन बनकर तीर चलाईये। उसमें आपके अपने आदमी हैं आप उनको निकालिये। उसमें कौन अधिकारी थे ?

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाता हूँ कि अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा तो उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा।
(विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, सी.एम. साहब ने तो हमें गीता जयंती पर भी इन्वार्ड नहीं किया है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमने सभी को उसमें इन्वार्ड किया है लेकिन फिर भी कंवर पाल जी हमारे संसदीय मंत्री हैं मैं उनको कहूंगा कि आज ही सभी विधायकों को गीता जयंती के इनविटेशन चले जाने चाहिए। आज ही सभी विधायकों के पास इनविटेशन पहुंच जाएगा।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, अब कहने के बाद इनविटेशन भेजा गया है। इससे पहले तो नहीं भेजा गया।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, अभी सभी के पास इनविटेशन भिजवा रहे हैं।(विघ्न)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनको हमेशा जहां जाएं वहां कुछ चाहिए और ये कितनी ही लालसा रखें इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। ये चाहे उधर की बात करें, चाहे इधर की बात करें। मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि

‘भंडारे में गये तो पूरी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.एम. साहब को कहना चाहता हूँ कि –

“जब दिल में इतना दर्द है तो हंसते क्यों हो,
अरे, हर रोज दिन-रात मेरा नाम जपते क्यों हो।
कभी पुराने अखबार उठाकर पढ़ना,
पता चलेगा सारे मुजरिम मेरे नाम से डरते क्यों हैं।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय,

हसरतें पूरी न हों तो न सही,

पर ख्वाब देखना कोई आपके लिए गुनाह तो नहीं ।

ख्वाब देखते रहो । (विघ्न) जैसा करोगे, वैसा भरोगे । मित्रों, इस नाते से मैंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में बताया है । (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : सी.एम. साहब, आप हुड्डा साहब को कोई जलजला मत दिखना ।

श्री मनोहर लाल : गौतम जी, हम कोई जलजला नहीं दिखाएंगे । हुड्डा साहब, हमारे मित्र हैं । विपक्षी मित्र हमारे मित्र हैं । सब मिलकर इस प्रदेश के भले के लिए इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे । इसमें कोई दिक्कत नहीं है । मित्रो, जहां तक कल एक विषय हमारे जयवीर सिंह जी ने उठाया था कि फतेहपुर गांव की 40 एकड़ जमीन ली गई है । देखिये जो प्रावधान हैं हम उनसे बाहर कभी जाते नहीं हैं । आखिर किसी भी सामाजिक काम के लिए खासकर गौ-रक्षा आदि के लिए हमारा एक प्रावधान है कि जो गौचरान की जमीनें हैं उनको किसी गौ संवर्धन के काम के लिए लीज पर दिया जा सकता है । हम जमीन बेचते नहीं हैं । (श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, आज भी हमने एक स्पेशल नीति बनाई है कि कोई भी नई गऊशाला बनाने के लिए पंचायत प्रस्ताव पास करा दें या कोई संस्था करे । वहां गऊशाला बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करके दें, फिर हमारा गऊसेवा आयोग और ऐनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट उनके लिए एक एग्रीमेंट करते हैं और बाद में उनको जो भी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए चाहे चार दीवारी हो, शैड हो या साल भर का जो गऊ चारा उनको चाहिए उसका पैसा हम उनको तुरंत देते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष गौ संवर्धन व गौरक्षा आदि के लिये 40 करोड़ रूपये के आस-पास का बजट था । पिछले वर्ष से जो बेसहारा गौवंश बाहर घूमते हैं इनकी व्यवस्था ठीक करने के लिये कुछ आगे कदम बढ़ाते हुए हमने उस बजट को 40 करोड़ रूपये से 10 गुणा बढ़ाकर 400 करोड़ रूपये किया है । (इस समय मेजें थपथपाई गईं) जो 40 करोड़ रूपया एक वर्ष का बजट होता था उसको तो एक किस्त में भेज भी दिया है । बहुत ही जल्दी एक किस्त 40 करोड़ रूपये की वर्तमान गौशालाएं गौ चरान की हैं उनको भी भेजने वाले हैं । इसके साथ-साथ जो नई गऊशालाएं बन रही हैं जिनका प्रस्ताव स्थानीय

उपायुक्त महोदय के माध्यम से आये हैं उनको भी आश्वस्त किया गया है कि इस संबंध में जितना पैसा उनको चाहिये वो देंगे। फतेहपुर गांव की 32 एकड़ पंचायत की जमीन है, गउशाला को देने के लिये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है और उसको संबंधित उपायुक्त के पास कार्यवाही हेतु भेजा हुआ है, विचाराधीन है। इस प्रकार से यदि और भी कोई इस प्रकार की संस्थाएं गउशालाओं के संबंध में आगे आयेगीं हम उनको भी बजट देने के लिये तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के संबंध में एक बात यह आई थी कि उनकी लिमिट खत्म करके विकास कार्यों के लिये अधिकार दिये जायें। यह बात ठीक है कि सारे विकास के काम लगभग 20 लाख रूपये तक के कुटेशन के आधार पर होते थे। इस संबंध में हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई थी। हमने पंचायत चुनाव से पहले उसके अंदर एक लिमिट फिक्स की थी कि जो छोटे काम हैं उनको कुटेशन के आधार पर करें और बड़े विकास के कार्य ई-टैंडरिंग के माध्यम से होने चाहिये अर्थात् 5 लाख रूपये से उपर के विकास के कार्य ई-टैंडरिंग के माध्यम से होने चाहिये और 5 लाख रूपये से नीचे के विकास के कार्य चाहे वे 2, 4, या साढ़े चार लाख रूपये के हों वे कुटेशज के आधार पर हों। इसमें प्रारंभिक कठिनाइयां जरूर आई थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो भी कोई नया सिस्टम बनता है उसके लिये प्रारंभिक कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। ई-टैंडरिंग सिस्टम में सरपंचों को शुरू में कठिनाइयां आई थी। हमने उनको संबंधित डिपार्टमेंट्स में भेज कर सभी की ट्रेनिंग करवा दी है। ट्रेनिंग करवाने के बाद हजारों की संख्या में ई-टैंडरिंग के माध्यम से गांवों में विकास के काम होने शुरू हो गये हैं। जहां कहीं कठिनाई दिखती है अभी भी उसको दूर कर रहे हैं। जहां तक 5 लाख रूपये के लिमिट की बात है उसमें हमने कहा है कि काम करवाने के लिये जो टोटल राशि है उस बजट की 50 परसेंट राशि छोटे काम पर खर्च कर सकते हैं और 50 परसेंट राशि बड़े कामों के लिये रख सकते हैं। उसके बाद एक विषय यह आया कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां छोटे-छोटे विकास के काम हैं उनमें बड़े काम नहीं है। हम उसमें भी प्रावधान कर रहे हैं और उसका भी इस संबंध में एक पत्र संबंधित विभाग की तरफ से चला जायेगा। अब हम उसमें भी छूट दे रहे हैं कि यदि किसी गांव में 5 लाख रूपये से बड़े काम नहीं है अर्थात् ज्यादा विकास के काम 5 लाख रूपये से कम हैं तो हर पंचायत, बी.डी.पी.ओ., पंचायत समिति के सी.ई.ओ., जिला परिषद् और डिप्टी कमिश्नर से अनुमति लेकर अगर ज्यादा काम भी छोटे हों

तो वे करवा सकते हैं। उनको स्पेशली वे कुटेशंज जिन पर उनकी डिमांड पूरी होती है उसके आधार पर काम करवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर रेट्स तय करने की भी कुछ कठिनाई आई थी। डिप्टी कमिश्नर साहब की इस संबंध जो कमेटी होती है वह रेट तय करती है और कहीं रेट कम और ज्यादा तय हो जाते हैं। कई बार यह बंधन होता है कि इसी रेट पर काम करना है तो बहुत से ठेकेदार इसी वजह से काम नहीं करते हैं। अब हमने उसमें भी छूट दे दी है कि जो एच.एस.आर. है उसको स्टिक करने की जरूरत नहीं है। जो स्थानीय तौर पर रेट्स हैं उसके लिये एक कमेटी बनेगी उसके हिसाब से रेट तय होगा। एक जिले में कम से कम एक रेट हो ताकि कहीं भी इस प्रकार की मिस-मैनेजमेंट ना हो जाये कि कहीं इंटें 6 हजार रूपये प्रति हजार मिल रही हैं और कहीं पर इंटें 8-10 हजार रूपये प्रति हजार मिल रही हैं तो उस जिले के जो रेट हैं उसको फिक्स करके अपने हिसाब से उस रेट को तय कर सकते हैं ताकि कोई कठिनाई ना आये। यह ठीक है कि पंचायती राज विभाग और अर्बन लोकल बॉडीज विभाग दोनों का ऑटोनॉमस सिस्टम होता है, हम इनको ज्यादा से ज्यादा ताकत देना चाहते हैं। जहां तक इसके फाइनेंस का विषय है उसके उपर ऑडिटिंग और कंट्रोल इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रदेश 7 परसेंट पैसा देता है। अगर कोई ऐसी पंचायत हो जिसकी सेल्फ इंकम ही इतनी ज्यादा हों और वे स्टेट से अपेक्षा न रखते हों तब उसको छूट दे सकते हैं कि जैसे मर्जी कमाओ और जैसे मर्जी खर्च करो लेकिन ऐसी पंचायतें और अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है कि उनकी पर्याप्त इंकम हो जाये जिससे उनका काम चल सके। अध्यक्ष महोदय, एक विषय श्री सोमवीर सांगवान, माननीय सदस्य ने चरखी दादरी के मैडिकल कॉलेज के बारे में कहा था। वर्ष 2015 में हमने घोषणा की थी कि हर जिले में कम से कम एक सरकारी अथवा प्राइवेट मैडिकल कॉलेज जरूर हो। इस घोषणा को हम अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे और इस विषय को आगे बढ़ायेंगे। पिछले डेढ़ या दो साल पहले केवल चार जिले इस संबंध में बचे थे उसमें पलवल, चरखी दादरी, फतेहाबाद और कैथल था। इनमें से कैथल का मैडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है। जमीन सब जगह चयनित हो गई है। आखिर में चरखी दादरी जिला बचा था और चरखी दादरी की भी मेरे पास दो दिन पहले फाइल आई थी और गांव घसोला की जमीन को मैडिकल कॉलेज के लिये उपयुक्त माना गया है। उसको स्वीकृति देते हुए निर्णय ले लिया गया है कि वहां मैडिकल कॉलेज बनेगा।

अध्यक्ष महोदय, संबंधित जिलों में मैडिकल कॉलेज के लिये जमीनें फिक्स हो गई हैं लेकिन तीन जिलों में मैडिकल कॉलेज का शिलान्यास बाकी है। बहुत ही जल्दी उनके शिलान्यास करने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति आदि की सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे। (विघ्न) मुझे मालूम है कि नलहड़ मैडिकल कॉलेज की व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, कहीं भी रेगुलर डॉयरेक्टर नहीं है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी चार रेगुलर डॉयरेक्टर लगाये हैं और नलहड़, रोहतक, करनाल, खानपुर में मैडिकल कॉलेज में भी रेगुलर डॉयरेक्टर लग चुके हैं। हम बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और जनहित में काम कर रहे हैं। जनहित में सारी योजनाएं बना रहे हैं, इन योजनाओं का भविष्य क्या होगा इसकी भी हम निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। वर्तमान में किसी भी कमी को छोड़ते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी जो समस्याएं विपक्ष ने बताई हैं अर्थात् कुछ डिमाण्ड्स रखी हैं हमारा प्रयास रहेगा कि इन डिमाण्ड्स को इस समय में पूरा कर दें या फिर उनको फाइनल बजट के रखते समय पूरा करेंगे। समाज के अंदर कोई भी समस्या को नहीं रहने देंगे। अब तो विधायकों के साथ-साथ आम जनता से भी कोई डिमाण्ड आती है तो उनको भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस समय सरकार का एक कार्यक्रम 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' चल रहा है। वहां पर विषय यही है कि कोई भी आम आदमी अपनी डिमाण्ड बता सकता है। जनहित में जारी सारे भारत वर्ष में चलने वाला यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से उनकी डिमाण्ड पूछते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसको खत्म करते हैं। सरकार की योजनाओं का जो लाभ आम आदमी को नहीं मिला उनको देते हैं। मेरा तो केवल यही कहना है कि-

“आप लोग अपना महल रेत का बनवाते हैं
लेकिन पता बारिश को देकर आते हैं।”

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को वापिस लेना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर विचार के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 जिसे आज की कार्यसूची में दर्शाया गया है, प्रशासनिक कारणों से इसको वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि हाउस की अनुमति हो तो इस विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दे दी जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, इस विधेयक को प्रशासनिक कारणों से वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(विधेयक वापिस लिया गया।)

3. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय उच्चतर मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

उच्चतर शिक्षा मंत्री (पं. मूल चंद शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उच्चतर शिक्षा मंत्री (पं. मूल चंद शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इन्कवायरी करवाने के मामले पर पुनर्विचार करने का मामला उठाना ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर जीरो आवर में आपकी बोलने की इच्छा हो तो शुरू करें ?

आवाजें : हां जी, हम जीरो आवर में बोलना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण आधे मन से बोल रहे हैं ।

श्री भारत भूषण बतरा : नहीं अध्यक्ष महोदय, हम पूरे मन से बोल रहे हैं । जब तक आप कहेंगे हम तब तक हाउस में बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बतरा जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप ही सदन का समय अपराह्न 5:00 बजे तक करने की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे यह बात पूछी है ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हम हाउस में बैठेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से एक बड़े ही रैलीवेंट प्वायंट के बारे में बोलना चाहता हूँ । मैं Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly के रूल-112 (1) के बारे में बोलना चाहता हूँ ।

“112. (1) A point of order shall relate to the Interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker.”

सर, इस विषय पर 15.12.2023 से चर्चा चल रही है लेकिन आज मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता । मैं आपको आर्टिकल-194 ऑफ दि कांस्टीट्यूशन को रैफर करना चाहता हूँ । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में रिक्वैस्ट करूंगा कि यह आर्टिकल पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है । Clause (2) of Article 194 is very important. I am not defending anybody, I am not asking whether you go to the High Court or not लेकिन मैं लीगल पॉजीशन के बारे में अप्राइज करना चाहता हूँ ।

“194. Powers, privileges, etc., of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof. —

“(2) No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said . . . ”

सदन में जो कुछ भी बोला जाता है उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। यह हमारा कांस्टीट्यूशन कहता है। इसमें इसी बात को दर्शाया गया है कि लैजिसलेचर्स के पास पावर्स होती हैं, पार्लियामेंट के पास पावर्स होती हैं। इनकी कमेटीज होती हैं, इनके पास प्रिविलेज की पावर होती है, एक्सपेंस की पावर होती है आदि। अगर यह रैफरेंस हाई कोर्ट में जाएगा और वहां से जो फाइंडिंग्स/इंडिक्टमेंट आएंगी, वे इंडिक्टमेंट इस सदन की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। मैं इससे आगे और पढता हूँ। इसमें लिखा है-

“ . . . said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication . . . ”

अतः आप इसका भी अवलोकन कर लें। इसके बाद आर्टिकल-105 का क्लॉज-4 है जो इसको रैफर कर रहा है। Rule 4 of the Article of Constitution of India. It says-

“The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of Parliament or any committee thereof as they apply in relation to members of Parliament.”

This is very important. This is to be seen by the Hon'ble Speaker. This is to be seen that High Court is a judicial authority, which is not an authority within the cognizance of the Constitution of India. This is to be seen whether we can send the proceedings and matter which we are referring to the High Court or not? आपने रैफरेंस की बात भी पूछी है। मेरा इस सदन की गरिमा को बचाने के लिए, सदन में इस बात को बचाने के लिए कहना चाहूंगा कि इन्कवायरी से कोई नहीं डरता है। किसी भी हालत में कोई नहीं डरता है। इस बात को रिव्यू करें क्योंकि

हिन्दुस्तान के ऑर्टिकल 194 में हमें बोलने के लिए राईट्स मिले हैं। चाहे हम झूठ बोलते हैं या चाहे कुछ भी बोलते हैं या किसी को अभद्र भाषा भी कहते हैं तो वह भी राईट है और उसके बारे में कोर्ट में कोई प्रोसिडिंग नहीं जा सकती। हमारे विद्ईन सर्कल यहां पर प्रोसिडिंग जा सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं और इतना ही निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। इसको भेजने से पहले इस ऑर्टिकल को एग्जॉमिन करके एल.आर. से ओपिनियन जरूर लेना कि इसकी क्या रैलिवेंसी है या जो एल.आर. बैठते हैं, उसकी क्या रैलिवेंसी है? This is the only thing.

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य द्वारा कांस्टीच्यूशन ऑफ इंडिया का रफरेंस दिया गया है। माननीय सदस्य बहुत ही लर्नड सदस्य हैं और साथ ही वकील भी हैं। मैं इनकी बात को महत्व देते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस विषय पर जरूर विचार करके ही काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कल हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए 15 मिनट का समय निकाल लें। फिर चाहे उसके लिए सेशन शुरू होने से पहले बैठक कर लें या सेशन की कार्यवाही के बीच में बी.ए.सी. की एक 15 मिनट की बैठक बुला लें। अभी माननीय सदस्य ने कांस्टीच्यूशन ऑफ इंडिया के जिस ऑर्टिकल के बारे में बताया है, उसके बारे में अध्ययन नहीं किया है। इस पर कल तक विचार कर लेंगे और इसके लिए सभी पक्षों की बी.ए.सी. की 15 मिनट के लिए मीटिंग रखकर संबंधित विषय पर जो भी आगे करना होगा, वह कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी, इस संबंध में कल तक एल.आर. की ओपिनियन भी आ जाएगी।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, इसमें एल.आर. की ओपिनियन की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: गौतम जी, इसमें अगर हाउस चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूं?

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है।

डॉ. बिशन लाल सैनी (रादौर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

से सदन को यह बताना चाहूंगा कि जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिक्र कर रहे थे कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने गांवों में एक प्रोग्राम चला रखा है। जिसको भारत विकास संकल्प यात्रा या सद्भावना यात्रा कुछ ऐसा नाम दे रखा है।

शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ० कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसका नाम विकसित भारत यात्रा है।

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही कोई नाम दिया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, हम भारत देश को विकसित करना चाहते हैं।

डॉ० कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, इनको मेरी बात आराम से सुननी चाहिए। माननीय मंत्री जी बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सैनी साहब, आप हाउस में मर्यादा से बात करें।

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष: सैनी साहब, हाउस में रिस्पैक्टफुली बात करें।

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैंने गलत क्या बोला है? मैंने सद्भावना ही बोला है। क्या यह गलत बोला है?

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक टारगेट रखा है कि वर्ष 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बना देंगे। इसमें विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी सहयोग करना चाहिए। यह भारत देश हम सबका है।

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय मंत्री जी मेरी बात तो सुन लें।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, हमारे गोहाना हल्के में जाने से किसने रोका है?

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, इस तरह से बीच में बोलने से आपकी पार्टी के माननीय सदस्य का ही समय खराब हो रहा है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, उस प्रोग्राम में गांव के अन्दर जाकर चाहे बी.जे.पी. का कोई खंड प्रधान है, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट प्रैजिडेंट है, चाहे कोई वार्ड्स प्रैजिडेंट है या चाहे कोई हारा हुआ एम.एल.ए. है या कोई हारा हुआ मंत्री है। ये सारे अधिकारियों को बुलाते हैं और वहां

पर सारे अधिकारियों को बुलाकर गांव के लोगों से समस्याएं पूछते हैं। यह तो अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह कहना है कि जीते हुए एम.एल.ए. को तो जनता की समस्या सुनने की पावर नहीं है क्योंकि कोई अधिकारी हमारी बात सुनता ही नहीं है ? मैं पूछना चाहता हूं कि खंड प्रधान, जिला प्रधान या कोई वाइस प्रधान हैं वे किस अथॉरिटी से विभाग के अधिकारियों को बुलाते हैं ? अध्यक्ष महोदय, वे किसलिए ऑफिसरज को बुलाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो एम.एल.ए. हारा हुआ है, वह जनता की समस्याएं सुनेगा, जबकि जीता हुआ एम.एल.ए. समस्याएं नहीं सुनेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, विषय कहीं दांय बांय जा रहा है। देखिये, यह जो कार्यक्रम है, इसका नोडल अधिकारी डिप्टी कमिश्नर है और डिप्टी कमिश्नर के पास लिखित में हिदायते हैं कि वो चुने हुए प्रतिनिधियों को सूचना देंगे और उनका सूचना देने का काम है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि आप डिप्टी कमिश्नर से सम्पर्क करे और उनको कहें कि आप हमें सूचना क्यों नहीं देते हो ?

श्रीमती गीता भुक्कल : मुख्यमंत्री जी, क्या आपने उनको शिकायत दी है।

श्री मनोहर लाल : गीता जी, हमने उनको शिकायत दी हुई है। अगर आप हमें लिखित में शिकायत देंगे तो हम उनको दोबारा से शिकायत दे देंगे लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर के अलावा वहां पर जो मंत्री जायेंगे तो उनके नाते से एग्जैक्टिव के रूप में अपनी बात कह सकते हैं लेकिन अगर विधायक जायेंगे तो वहां पर अपनी चर्चा कर सकते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, क्या हम कार्यक्रम के दौरान मीटिंग में अन-इनवाइटिड जायेंगे ?

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, अब वहां पर सरपंच पर प्रेशर है क्योंकि लोगों के लिए पकौड़े भी बनाने हैं, उनके लिए चाय भी बनानी है, उनके लिए तम्बू भी लगाने हैं और उनके लिए कुर्सियों का भी इंतजाम करना है। अब इसके लिए सरकार ने सरपंच को 20 हजार रूपये देने की बात कही है। इस सरकार के अंदर एक सरपंच 20 ईंट लगाने की अथॉरिटी नहीं रखता

तो वह कैसे इन चीजों पर 20 हजार रुपये खर्च करेगा ? यह बड़े ही मजाक की बात है । लोगों के काम होना ठीक बात है लेकिन आज तक तो आप लोगों से लोगों के काम तो हुए नहीं । सभी काम मंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी नहीं होते । हां यह बात ठीक है कि मंत्री जी उस कार्यक्रम के दौरान मीटिंग में जायें । मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी जायें और विभाग के सभी अधिकारियों को बुलायें । इसमें बेशक एम.एल.एज. भी जायें सभी अधिकारियों को बुलायें लेकिन जो एम.एल.ए. हारा हुआ है उसको इसके अंदर बुलाने का क्या मतलब बनता है ? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है और इसके अलावा कुछ नहीं है ।

श्री लीला राम (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । मैंने आज सवेरे दैनिक ट्रिब्यून अखबार पढ़ा और उस अखबार को पढ़कर मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय बिजली मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं । सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले एक साल तक सरकार बिजली के किसी भी प्रकार के रेट नहीं बढ़ायेगी । अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मुद्दा है जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना जरूरी है । हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल पहले सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का होता था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार्यकुशलता से इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया जिसके लिए हरियाणा प्रदेश में आज तक भी बिजली को लेकर धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी बल्कि लोगों को सुचारू रूप से 24 घंटे बिजली मिल रही है । अध्यक्ष महोदय, सरकार बिजली के रेट न बढ़ाये तो वह इसके लिए बधाई की पात्र होगी । मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, अतिथि अध्यापक या दूसरे कर्मचारियों का डैलीगेशन हर विधायक के पास मिलने के लिए आता है । मुझे भी अतिथि अध्यापक या दूसरे कर्मचारियों का डैलीगेशन मिला था । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने मांग की थी कि उनके जिलों में अतिथि अध्यापकों की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है । उनकी बदली जैसे कैथल वालों की फतेहाबाद में हो गई है और किसी की फरीदाबाद में हो गई है तो उनका सरकार से अनुरोध है कि उनको नजदीक कहीं भी डेप्यूट किया जाये । यह कांग्रेस पार्टी के समय में भर्ती हुई थी । आज तक भी उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई है । उस समय की हमारी शिक्षा मंत्री जी बड़ी-बड़ी बातें करती थी परन्तु यह

कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल का किया हुआ काम है लेकिन हमारी सरकार ने उनको राहत देते हुए उनकी सैलरी दुगुनी करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की बात सदन में रखना चाहूंगा। मैंने ये मांगे पिछले सेशन के दौरान भी सदन में रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मेरे कैथल शहर से एक ट्रेन जाती है। मेरे हल्के का एक बड़ा गांव सजुमा है। यह ट्रेन कैथल शहर से वाया कुतेपुर, वाया सिलाखेड़ा, वाया धुंधरेड़ी-सजुमा तक जाती है। यह बहुत बड़ी ट्रेन है इसलिए इस ट्रेन की पटरी को सड़क का रूप दिया जाये ताकि सजुमा जैसे बड़े गांव के लोगों को इसका फायदा हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैंने पिछले विधानसभा सेशन के दौरान सदन में यह बात रखी थी कि मेरे हल्के कैथल शहर का बाईपास जो कैथल-अम्बाला रोड से लेकर कैथल-जींद रोड पर जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह कैथल शहर की मुख्य सड़क है। इस सड़क से सैक्टर 18 तथा सैक्टर 20 लगते हैं। इस पर सिविल हॉस्पिटल है, चौधरी देवीलाल पार्क है, 6 पेट्रोल पम्प हैं। इसके अलावा इस पर धन-धन सतगुरू डेरे का भी भवन है इसलिए इस सड़क को फोरलेन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी तथा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इस सड़क को चौड़ा करने के लिए प्रिमिक्सिंग की तो परमीशन दे कर इसको मंजूर कर दिया गया परन्तु जब तक यह सड़क फोरलेन नहीं बनती तब तक कैथल का सुधार नहीं हो सकता। (घंटी) अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे शिक्षा मंत्री जी से संबंधित बात रखने के लिए केवल दो मिनट का समय और दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: लीला राम जी, आपका समय पूरा हो गया है प्लीज आप बैठ जायें।

श्री लीला राम: नहीं अध्यक्ष जी, मेरी कुछ बातें और भी कहने से रह गई हैं लेकिन यदि समय की कमी है तो आप इनको प्रोसिडिंग का पार्ट बनवा देना।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आप इनको टेबल कर दीजिए। इनको प्रोसिडिंग का पार्ट बनवा दिया जायेगा।

- * श्री लीला राम: अध्यक्ष महोदय, 1. कैथल शहर में सब्जी मण्डी बनाई जाये ।
2. कैथल शहर में ग्योंग ड्रेन को पक्का किया जाये ।
3. कैथल शहर में लड़कियों के 10+2 स्कूल की बिल्डिंग का नवनिर्माण किया जाये ।
4. हल्का कैथल के गांव सजुमा के 6 करोड़ रुपये, गांव पाड़ला के 6 करोड़ रुपये तथा गांव क्योड़क के 6 करोड़ रुपये जो सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है उस बजट को रीलिज किया जाये ।
5. हल्का कैथल के गांव दयोरा के स्कूल की तालाब की तरफ रिटेनिंग वॉल बनाई जाये।
6. गांव क्योड़क में निर्माणाधीन लुवास संस्था को चालू किया जाये ।
7. हल्का कैथल के गांव मानस में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाये ।
8. गांव उलाना में पूर्व सरपंच मदन के मकान से हाकम सरपंच के मकान तक गली का निर्माण करवाया जाये । इसके अतिरिक्त पार्क निर्माण व शिवधाम में बरामदा व शैड बनाये जाये।
9. हल्का कैथल के गांव दयोरा, मुन्दड़ी, कौल, गुहणा, साधन, मानस, खुराना, ग्योंग, सिरटा, बालदाना, पाड़सा तथा सजुमा में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाया जाये ।
10. गांव बलवंती में जरनल चौपाल का निर्माण करवाया जाये ।
11. कैथल शहर में लड़कियों के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया जाये।
12. हल्का कैथल के गांव नौच से गांव रामगढ़ तक की कच्ची सड़कों को पक्का किया जाये।
13. गांव दयोरा में 2 शिवधाम का निर्माण करवाया जाये ।
14. गांव क्योड़क को सब-तहसील बनाया जाये ।

* चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसिडिंग का पार्ट बनाया गया ।

श्री इंदु राज(बरोदा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से खेल और खिलाड़ियों के बारे में कहना चाहूंगा कि अभी जो एशियाड खेल हुए हैं, इनमें हमारे प्रदेश के लगभग 80 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इनमें से करीब 44 खिलाड़ियों ने गोल्ड मैडल लाने का काम किया। इन खिलाड़ियों को हरियाणा प्रदेश की सरकार ने करनाल में सम्मानित करने के साथ ही अवार्ड देने का भी काम किया लेकिन इनमें से सरकार ने ऐसे कई खिलाड़ी छोड़ दिये जिन्हें ना तो अवार्ड दिया गया और ना ही इस कार्यक्रम में बुलाया गया। इन खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा एक बहाना बनाया गया कि ना तो आप हरियाणा प्रदेश में नौकरी करते हो और ना ही आप हरियाणा प्रदेश से खेले हो। इसमें इन खिलाड़ियों का क्या कसूर था। जबकि ये खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश में ही जन्में, पढ़े और खेलें। जब इन्हें हरियाणा प्रदेश में रोजगार नहीं मिला तो इन्होंने मजबूरी में आकर किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इसमें इन खिलाड़ियों का तो कोई कसूर नहीं है, अगर इसमें कसूर है तो वह हरियाणा प्रदेश की सरकार का है, सरकार को इन खिलाड़ियों को प्रदेश में रोजगार देना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मेरे हल्के की तीन बेटियां जो कबड्डी में गोल्ड मैडल लेकर आयी हैं, चाहे इनमें साक्षी पूनिया हो, मुस्कान मलिक हो या आशिमा हो। इनके अलावा भी हमारे प्रदेश के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें ना तो सरकार द्वारा कोई अवार्ड दिया गया और ना ही नौकरी का ऑफर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारी सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी नौकरियां दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं खिलाड़ियों के बारे में कहना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में इस सरकार द्वारा खेल नीति बदली गई। यह खेल नीति हुड्डा साहब की सरकार की थी, हमारी 10 साल की सरकार के दौरान की थी। यह 'पदक लाओ-पद पाओ की नीति थी लेकिन इस नीति को इस सरकार ने बदलने का काम किया। इस नीति के द्वारा हमारी सरकार में हमने लगभग एक दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों को डी.एस.पी., करीब दो दर्जन खिलाड़ियों को इंस्पेक्टर तथा 40 खिलाड़ियों को सब-इंस्पेक्टर लगाने का काम किया लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार ने यह नीति वर्ष 2018 में बदल दी। उस नीति के तहत स्पोर्ट्स के एशियाड गोल्ड मैडलिस्ट तथा ओलम्पिक मैडलिस्ट के जो खिलाड़ी थे सरकार द्वारा उनसे

एप्लीकेशन मांगी गई कि हम आपको नौकरी देना चाहते हैं। इन खिलाड़ियों ने उस नीति के तहत फार्म भरे और क्वॉलीफाई करने का काम भी किया लेकिन सरकार द्वारा इन खिलाड़ियों को भी भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद इन खिलाड़ियों द्वारा मजबूरी में आकर कोर्ट का रास्ता देखा गया। माननीय कोर्ट ने दिनांक 09.10.2023 को हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि आप इन खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम करें लेकिन सरकार द्वारा आज तक इन खिलाड़ियों को भी नौकरी देने का काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जहां पर भी बैठे होंगे वहां से मेरी बात को सुन रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खेल मंत्री भी हैं इसलिए आप इन खिलाड़ियों का जो हक है वह इन्हें देने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन में अपने हल्के की बात रखना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव बुटाना में एक न्यू सब माईनर निकाली गई और इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपये का खर्च भी हो गया लेकिन इसमें केवल बिजली का कनेक्शन होना बाकी है। अगर यह कनेक्शन हो जाये तो किसानों की हजारों एकड़ फसल को पानी मिल जाए। दो वर्ष हो गए लेकिन इस माईनर में बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा जिसके कारण किसानों की फसल में नहरी पानी नहीं जाता। सरकार ने इसे मंजूर भी कर रखा है चाहे तो सरकार द्वारा इसे चैक करवा लिया जाये। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि हमने प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान किये। हम सभी ने देखा कि 6-7 महीने पहले जितनी भी भर्ती निकाली गई वो सारे मामले आज कोर्ट में चले गए। अब और कह दिया कि सरकार 60 हजार नौकरियां देगी। इस समय सरकार के 6 महीने बाकी हैं। क्या सरकार के पास एशोर्मेंस है कि सरकार ने जो 60 हजार वैकेंसीज निकाली हैं क्या सरकार उनको नियुक्ति प्रदान कर पायेगी? इस पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से नशे की तरफ जा चुका है। कोई अपराधी बन गया है। आज यहां पर नशे के बारे भी बात हुई। आज हर गांव में और हर गली में सिर्फ रोजगार न होने के कारण प्रदेश का युवा नशे की तरफ जा रहा है।

श्री दुड़ा राम (फतेहाबाद) : धन्यवाद स्पीकर महोदय जी। स्पीकर महोदय जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अभी लाल डोरा की सम्पत्तियों का मालिकाना हक दिया। यह हमारी सरकार का एक बहुत ही बढ़िया फैसला है। मेरे हल्के के एक गांव भट्टू का मामला मैंने पिछली बार उठाया

था। वह गांव लाल डोरे के बजाये पंचायत समिति में बसा हुआ है। उसमें स्कूलों की बिल्डिंग्स के साथ-साथ और भी बहुत कुछ है। पंचायत समिति में होने के कारण उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। उनको अब हर चीज में बड़ी भारी दिक्कतें आ रही हैं। मीटर लेने में भी और लोन लेने में भी उनको दिक्कत आ रही है। इस सब को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के हित में मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि जिस तरह से लाल डोरे में सम्पत्तियों का मालिकाना हक दिया गया उसी प्रकार से उस गांव को भी मालिकाना हक दिया जाये। अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद शहर पहले सब-डिवीजन था लेकिन अब जिला हैडक्वार्टर है। अब फतेहाबाद जिला बन गया है। वहां पर बहुत पुराना वॉटर वर्क्स बना हुआ है। फतेहाबाद जिले में नई आबादी भी आई है और शहर का एरिया भी बढ़ा है इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि नया वॉटर वर्क्स बनाया जाये। ताकि लोगों को दिक्कत न हो और वहां पर नहरी पानी पहुंच सके। मेरे हल्के में तीसरी बात यह है कि वहां पर सेम का एरिया बहुत है। वहां पर मोहम्मदपुर, गोरखपुर, दहमन, बनावाली, शेखूपुर, दड़ौली, बन मंधौरी, पीली मंधौरी, डाबीकलां और भट्टू इत्यादि गांवों में सेम की ज्यादा समस्या है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर सोलर ट्यूबवैल्ज लगाये जायें ताकि भूमिगत जलस्तर नीचे चला जाये और किसानों को दिक्कत न हो। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद का एक रजबाहा है जो टोहाना से आता है टेल पर फतेहाबाद पड़ता है। यह बहुत लम्बा एरिया है। मेरी प्रार्थना है कि उसको नया बनाया जाये ताकि आगे टेल पर पानी पहुंच सके। इसी प्रकार से भूना शहर बहुत बड़ा शहर बन गया है लेकिन अभी तक वहां पर बाई-पास नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि भूना शहर में बाई-पास बनाया जाये। इसी तरह भूना में अनाज मण्डी बहुत पुरानी है जोकि प्राइवेट तौर पर कटी हुई है। वहां पर सरकारी अनाज मण्डी नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना है कि भूना में नई अनाज मण्डी बनाई जाये। इसी प्रकार धांगड़ के पुल से लेकर फतेहाबाद दरियापुर रोड के पुल तक पुराना हाईवे नम्बर-9 पर डिवाइडर बनाकर लाईट्स लगाई जायें। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले विधान सभा सेशन में भी यह बात रखी थी अब फिर से रख रहा हूं कि मेरे एरिया में जो खाले हैं उनको नया बनाने के लिए 20 साल की समय सीमा तय की गई थी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है इस समय सीमा को 20 साल से घटाकर

10 साल किया जाये। ताकि किसानों को दिक्कत न हो। इसी तरह पीछे बड़ी भारी बारिश हुई। कुछ मेरे एरिया में सेम की समस्या बहुत ज्यादा है। इस कारण से उस एरिया में वॉटर वर्क्स लगभग सारे खराब हो गये। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि जो भी वॉटर वर्क्स खराब हुए हैं। उनको नया बनाया जाये ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। इसी तरह फतेहाबाद शहर के अंदर पुराना एस.डी.एम. निवास है उसको नगर परिषद् का कार्यालय बनाया जाये क्योंकि पुराना नगर परिषद् कार्यालय बहुत पुराना है और उसमें कमरों की व्यवस्था भी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में कोई उद्योग नहीं है। औद्योगिक रूप से हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि फतेहाबाद में एच.एस.आई.आई.डी.सी. के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लगाये जायें ताकि मेरे जिले के लोगों को रोजगार मिल सके क्योंकि वहां पर पहले कोई भी इण्डस्ट्रियल एरिया नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से बार-बार यही प्रार्थना है कि वहां पर किसी न किसी तरीके से एच.एस.आई.आई.डी.सी. के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाये ताकि वहां के बच्चों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुभाष गांगोली(सफीदों): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जीन्द-पानीपत सड़क को फोरलेन बनाने के लिए हर सेशन में आवाज उठाता हूँ लेकिन आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसके लिए 184 करोड़ रुपये का बजट भी आया हुआ है और वन विभाग की एन.ओ.सी. की जरूरत है इसलिए वह एन.ओ.सी. जारी करवा कर जल्दी से जल्दी इस सड़क को फोरलेन बनवाया जाये। वहां पर हर रोज बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं जिसके कारण मुझे भी और सरकार को भी बहुत गालियां मिलती हैं, अतः इस सड़क को यथाशीघ्र बनवाया जाये। इसी तरह से सफीदों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2 साल पहले पैरा मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी लेकिन उसको भी जीन्द ले गये। उस समय मुख्यमंत्री जी ने यह बात विशेष रूप से कोट की थी कि जो पॉलिसी में भी नहीं आया तो भी पॉलिसी में ढील देते हुए हम सफीदों में पैरा मेडिकल कॉलेज बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले के सत्रों में भी इस बात को उठाता रहा हूँ और आज फिर आपके माध्यम से सरकार से निवेदन

करना चाहता हूँ कि कोई तो काम सफीदों में ऐसा कर दो जिससे जब आप वहां जाओ तो यह कह सकें कि हमने सफीदों में यह काम किया है। इसी प्रकार से सफीदों में वर्ष 2019 में चुनावों से कुछ दिन पहले 100 ईंटों के साथ एक नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी, आज 2023 जा रहा है लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उसकी जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन आज तक उसके ऐस्टीमेट्स भी नहीं बने हैं इसलिए यथाशीघ्र इसको बनवाया जाये। इसी तरह से पिल्लूखेड़ा में पिछली प्लान में एक गर्ल्स कॉलेज बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन उसकी बिल्डिंग आज तक नहीं बनी है। आज उसकी क्लासिज एक स्कूल में लगती हैं। मैंने और विभाग के अधिकारियों ने एक बहुत अच्छी लोकेशन की जमीन तलाश की है जिसका ऐस्टीमेट सरकार के पास आया हुआ है। अभी पिछले दिनों विधान सभा की शिक्षा समिति में मैंने विभाग के अधिकारियों से जब इस बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट की शॉर्टेज है और हमने इसके लिए सरकार से बजट की मांग की हुई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन तीन कामों में से कोई काम तो करवा दिया जाये। एक को तो जीन्द में ले गये और दो सी.एम. अनाउंसमेंट हैं जिनकी जमीनें भी ट्रांसफर हो चुकी हैं लेकिन उन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं जिनको बनाना बहुत जरूरी है जिनमें कालवा से रझाना खुर्द, बाघडू खुर्द से मालश्री खेड़ा, गांव मुआना से बाहरी वाला रास्ता जो कि कच्चे हैं इनको पक्का करवाया जाये। इसी प्रकार पिल्लू खेड़ा मण्डी जो 1957-58 में बनी थी जो तीन ग्राम पंचायतों के अधीन आती है और यहां की 80 प्रतिशत आबादी रजिस्ट्री की समस्या से परेशान है। इनकी पुरानी जमीन के इन्तकाल न हो पाने की वजह से उनकी किसी भी जमीन की सेल व परचेज नहीं हो पाती है इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाये ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी पी.एच.सीज., सी.एच.सीज. और सफीदों का जनरल हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टर्स की बहुत अधिक कमी है और मैं हर सत्र में इस बात को उठाता हूँ इसलिए वहां पर डॉक्टर्स भेज कर हमारी डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाये। अब मैं माइनिंग के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे माननीय सदस्य दादा गौतम जी ने भी इस विषय को उठाया था। किसान को अपने खेत को ऊंचे से नीचा भी करना पड़ता है और उसको एक जगह से मिट्टी उठा कर दूसरी जगह लेकर

जानी पड़ती है लेकिन माइनिंग विभाग द्वारा उनके चालान काट दिये जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति डम्पर या ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपना काम करता है तो उसको केवल 45 दिन का माइनिंग का समय दिया जाता है और विभाग के कर्मचारी उनसे मोटी रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत का आलम यह है कि विभाग में एच.के.आर.एन. के माध्यम से लगे हुए कर्मचारियों ने भी रिश्वत से बड़ी-बड़ी कोठियां बना ली हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान किया जाये।

श्री आफताब अहमद, विधायक द्वारा सदन की अधिकारी दीर्घा में शून्य काल के दौरान किसी भी सीनियर अधिकारी के न बैठे होने बारे मामला उठाना

Shri Aftab Ahmed(Nuh): Speaker Sir, we are thankful to you that you have introduced Zero Hour for the benefit of the Members and for the State. But we are sorry to say that the seriousness of the Zero Hour is becoming insignificant. You had said that Zero Hour would be recorded and the problem which the Members would raise, they would be addressed to. I don't think any problem has been discussed, addressed to. The state of affairs in the Zero Hour is that no official, no senior official seems to be present during Zero Hour. We are thankful to two Ministers who are present here. Sir, in the Zero Hour we are raising the issues of the public importance and the Government is not serious about it.

संसदीय कार्य मंत्री(श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य श्री सुभाष गांगोली जी की जीन्द-पानीपत रोड के लिए एन.ओ.सी. का विषय नोट कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : आफताब अहमद जी, आपने जो प्रश्न उठाया है और जो बात आपने ध्यान में लाई है उसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा।

श्री आफताब अहमद : धन्यवाद सर।

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

श्रीमती निर्मल रानी (गन्नौर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि उसकी अच्छी नियत हो, उसकी नियती अच्छी हो और उसका कुशल नेतृत्व हो। मोदी और मनोहर लाल जी की जो गारंटी वाली गाड़ी है वह लोगों को ढूँढकर सभी योजनाओं को वहां तक पहुंचा रही है। इनसे पहले जो केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाएं बनती रही हैं उनको ढूँढने के लिए लोग इधर-उधर घूमते रहते थे लेकिन अब जब ये गाड़ी गांवों में जाती है तो लोगों के चेहरे विश्वास और खुशी से खिल उठते हैं। यह गारंटी इसी कुशल नेतृत्व का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में एक जीतता है और एक हारता है लेकिन मध्यस्थता से दोनों की जीत होती है। न्याय और समाधान में सिर्फ यही अन्तर है जोकि मुख्यमंत्री जी ने कर दिखाया है। अब लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। हमारी सरकार ने जिनकी फैमिली आई.डी. में सालाना इंकम एक लाख रूपये थी या साल का 1800 यूनिट यानि 150 यूनिट प्रति महीना बिजली खर्च होती थी उनके 3600 रूपये बिजली के बिल माफ कर दिये हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि जिनकी फैमिली आई.डी. में सालाना एक लाख अस्सी हजार रूपये इंकम है उनको भी आगे लाया जाए और अगर ये 200 यूनिट प्रति महीना हो जाए तो इससे कुछ और लोगों को भी फायदा होगा। इस प्रकार कुछ और लोग भी कर्ज मुक्त होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। बाकी मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि जो कोलोनी बची हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी रेगुलर करने का काम करें। हमारे गन्नौर की कुछ सड़कें हैं जोकि जी.टी.रोड से सनपेड़ा रोड-राम नगर होते हुए जा रही है। वह रोड जल्दी से जल्दी बनाई जाए क्योंकि फ्री जोन होने की वजह से वहां फैक्ट्रियां बहुत आ गई हैं और उस रोड का बहुत बुरा हाल है और वहां गांव के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ हमारी पुरखास व धतूरी रोड भी बहुत बुरी हालात में हैं। इन पर भी जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए। इसके साथ ही गन्नौर में कॉलेज की जो लम्बे समय से मांग थी अब तो उसके लिए जगह भी निश्चित हो गई है और सब डिविजनल होस्पिटल की जगह भी चिन्हित हो गई है। इन दोनों का काम भी जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। गन्नौर में एक सैक्टर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की

तरफ से मंजूर करवाया जाए। इसके साथ ही गन्नौर की नगर पलिका की पॉपुलेशन अब 50 हजार से ज्यादा हो चुकी है इसलिए इसको भी नगर परिषद बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर में एक राजपुरा माईनर आती है जिसमें काफी महीनों से पानी नहीं आ रहा है जोकि लोगों की काफी बड़ी समस्या है। अतः राजपुरा माईनर में पानी छोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, हमसे कुछ एक्स सरपंच मिले थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे थे उन्होंने यह कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक हजार रूपये महीना पेंशन की है और उन्हें 32 महीने की पेंशन एक बार इक्की मिली है तथा 16 महीने की एक बार मिली थी। उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया लेकिन अब कुछ महीनों से वह पेंशन नहीं आ रही है। उसका क्या कारण है इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया धनवान और शक्तिशाली को मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारी मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में अन्त्योदय योजना के तहत अन्तिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी ओर ध्यान दिया गया है। आज हर गरीब व्यक्ति अन्त्योदय योजना का लाभ उठा रहा है जिससे वह बहुत खुश है। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री नयन पाल रावत (पृथला): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी दोनों ही योजना के साथ प्रदेश की दो करोड़ अस्सी लाख जनता को 'सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास' के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले के जो माननीय मुख्यमंत्री जी होते थे वे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी विधान सभा में या अपनी सिटी तक सीमित रह जाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे हरियाणा की जनता को अपने साथ लेकर सभी विधान सभा क्षेत्रों में बराबर के काम कर रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : हमारी विधान सभा क्षेत्र में तो कुछ काम हुआ नहीं है।

श्री नयन पाल रावत : बहन जी, आपकी विधान सभा क्षेत्र में तो न कभी आपके समय में काम हुआ है और न अब होगा और न कभी आगे होगा। आपकी विधान सभा में तो कभी काम होगा ही नहीं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हम तो पहली बार चुनकर आये हैं लेकिन ये मेरे सामने जो कई माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, ये तो कई-कई बार चुनकर आये सीनियर सदस्य हैं लेकिन मैं

देख रहा हूँ कि सदन का एक तिहाई समय तो इन तीन-चार माननीय सदस्यों की लाइन ही ले जाती है और नए सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ये सदस्य हर बात में इंटरुप्ट करते हैं और जो ये बहनें बैठी हुई हैं, इन बहनों को यह भी तकलीफ होती है कि सरकार का एक नारा जो हरियाणा की बेटियों के लिए दिया गया है अर्थात् बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जब भी कोई घटना घटती है तो ये बहनें उस नारे को लेकर सबसे आगे आकर सदन का समय खराब करने लगती हैं। इनको यह नहीं पता कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद हमारी बेटियों को कितना सम्मान मिला है। आज हर जिले में महिला थाना बने हुए हैं, वहां पर हमारी बहन बेटियां तन्मयता के साथ तथा बिना झिझक के अपनी बात कह सकती हैं जबकि सामान्य थानों में यह बात कही नहीं जा सकती थी। जो उचाना का मामला है वह ठीक है छोटी घटना थी लेकिन एक बड़ा मामला भी था लेकिन उस मामले को लेकर जिस तरह से सदन को इंटरुप्ट किया गया, वह ठीक नहीं था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, वहां पर 142 लड़कियों के साथ सैक्सुअल हारासमेंट हुई है, क्या उन बच्चियों की आवाज उठाना गलत बात है ?

श्री नयन पाल रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं बहन गीता जी को कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से वह मामला बढ़ा था लेकिन जिस तरह की बात उनकी तरफ से की गई, वह उनकी छोटी सोच को ही दर्शाता है। इस सरकार ने उस प्रिंसिपल को 10 दिन के अंदर टर्मिनेट करके जेल में डालने का काम किया है। जबकि ये लोग तो अपराधियों को बचाते रहे हैं लेकिन मनोहर लाल जी ने तो अगर किसी ने गलत काम किया है तो नीचे क्लर्क लैवल से लेकर आई.ए.एस. आफिसर तक को जेल में भेजने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह बात भी जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हजारों-हजार करोड़ रुपये के काम किए हैं। 950 करोड़ रुपये की लागत से एक स्किल डिवैल्पमेंट यूनिवर्सिटी को मेरे क्षेत्र में देने का काम किया गया है। 400 करोड़ रुपये का एक प्राइवेट होस्पिटल जिसको पहले गोल्ड फील्ड का नाम दिया गया था लेकिन अब उसे अटल बिहारी वाजपेयी कालेज के नाम से जाना जाता है, उस पर भी काम चल रहा है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय हमारे यहां 'जेवर'

एयरपोर्ट के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया गया है। वहां पर लोग तीन महीने से धरने पर बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद घोषणा करके आये थे, उसी परिपेक्ष्य में मेरा अनुरोध है कि इस एक्सप्रेस-वे की मोहना गांव से कनेक्टिविटी करवा दी जाये तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि जो 'वेगी' अर्थात् विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत पैसा विधायकों को मिलता था और इसी प्रकार डि-प्लान का पैसा विधायकों को मिलता था, के तहत विभिन्न कामों के टेंडर प्रोसेस में कर दिए गए हैं। पहले ऐसा होता था कि जैसे कोई घोषणा होती थी तो हमें निर्माण कार्य की दृष्टि से एक्सियन आफिस में जाकर हमें उस काम को कंप्लीट करवाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बात भी जरूर कहना चाहूंगा कि पंचायतों के संदर्भ में जो एक छोटा सा संशोधन किया गया है, उसकी तरफ भी जरूर ध्यान दिया जाये। पंचायतों को कम से कम 10 लाख रुपये की पावर दी जाये क्योंकि 5 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपये में कोई गली का निर्माण नहीं होता है और उनको अगर 10 लाख रुपये की पावर दे दी जायेगी तो हमारे गांवों का उद्धार हो जायेगा क्योंकि मेरे जैसा विधान सभा क्षेत्र तो 104 गांवों से बना है, उसका तो निश्चित रूप से कल्याण ही हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह (इसराना)(एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भाजपा व जजपा गठबंधन की सरकार ने जब से ग्राम पंचायतों के उपर ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू की है तब से ही ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों व ब्लॉक समितियों के विकास कार्य ठप्प के बराबर हो गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी तो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। उस समय सरपंचों को 20 लाख रुपये तक के काम करवाने का अधिकार था। अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि ठीक उसी तर्ज पर सरपंचों को वापिस उसी तरह काम करने का अधिकार दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस गठबंधन की सरकार ने सरपंचों के अधिकार छीनने का ही काम किया है। सरकार से अनुरोध है कि हमारे सरपंचों को काम करने के जो अधिकार पहले थे, वे फिर से लागू होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 7.8.2021 को जापान के अंदर ओलम्पिक गेम्ज हुए थे जिसमें भारत देश के खिलाड़ी श्री नीरज चोपड़ा जी जिला पानीपत, हल्का इसराना, गांव खंडरा ने गोल्ड मैडल जीतकर देश

का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने गांव खंडरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी परन्तु अढ़ाई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस स्टेडियम का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस विषय पर मेरा 15 दिसम्बर, 2023 को सदन में एक प्रश्न भी लगा था और उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उत्तर दिया गया था कि जो जमीन ग्राम पंचायत खंडरा ने दी है, उस पर कोर्ट केस है जिसकी दिनांक 10.1.2024 को कोर्ट में सुनवाई है और साथ ही उपायुक्त, पानीपत से ग्राम खंडरा व इसके आस-पास के गांव में उपयुक्त/वैकल्पिक भूमि की पहचान करने का अनुरोध किया गया है तथा भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की बात कही गई। अध्यक्ष महोदय, यह अनुरोध डी.सी. से जब किया गया जब मैंने सदन में अपना प्रश्न लगा दिया था। यदि सरकार की नीति उस खेल स्टेडियम को बनाने की थी तो जो काम सरकार ने अब किया है, वह काम पहले भी तो हो सकता था ? मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस स्टेडियम को बनाने का काम जल्द से जल्द किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हल्का इसराना के ब्लॉक मतलोडा में तहसील की बिल्डिंग व बी.डी.पी.ओ. आफिस की नई बिल्डिंग बनाने की बात मेरे द्वारा सदन में कई बार-बार कही गई है। हर बार विश्वास दिलाया गया कि यह बिल्डिंग जल्द से जल्द बनाई जायेगी परन्तु आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हल्का इसराना के गांव कुराना में लगभग 525 एकड़ भूमि में जंगल है जिसमें काफी जंगली जानवर हैं जो गांव कुराना के आस-पास के किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं। इस जंगल के दो साइड में सड़क लगती है जिस पर जंगली जानवर आ जाते हैं और इस वजह से काफी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। मेरी सदन के माध्यम से सरकार से विनती है कि इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य किया जाये। एक मेरा निवेदन यह भी है कि राजकीय महाविद्यालय, इसराना की बिल्डिंग के निर्माण के लिए सरकार ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले 28 करोड़ रुपये दिए थे परन्तु आज तक भी सरकार ने उस महाविद्यालय की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू नहीं किया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसराना महाविद्यालय की बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनावाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। (घंटी) मेरे हल्का इसराना में मैंने जो सड़कों का जिक्र किया है, आप उसको चैक कराएंगे तो पायेंगे कि ये सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। आज मेरे हल्के में यह मुख्य

मुद्दा बना हुआ है। (घंटी) मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इन सड़कों को बनाने का काम जल्द से जल्द किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मामन खान (फिरोजपुर झिरका): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं बहुत स्लोगन सुनता हूँ कि सबका साथ-सबका विकास या फिर डबल इंजन की सरकार। मगर वास्तव में देखा जाये तो यह सरकार धरातल पर बिल्कुल 'जीरो' है। खासकर जो मेवात के साथ दोगलापन इस सरकार ने किया है, आज तक किसी सरकार ने इस तरह का दोगलापन नहीं किया था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जब सी.एम. थे तो वे मेवात के लिए जो काम कर गए थे, उन कामों की गाड़ी उससे आगे नहीं बढ़ सकी है। मैं यह बात किस लिए बोल रहा हूँ वह बताता हूँ। स्पीकर सर, आपकी अनुमति से मैंने काफी बार विधान सभा में क्वेश्चन उठाये हैं और यही नहीं जीरो आवर में भी अपनी बात रखी है लेकिन इसके लिए केवल झूठे आश्वासन ही मिलते हैं। पेपरों में रिटन में यैस सर- यैस सर- यैस सर लिखकर आ जाता है और बाद में जाकर ये एश्योरेंस जीरो हो जाते हैं। स्पीकर सर, हमारा नैशनल हाइवे नम्बर 248 का जो रोड है, उस पर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि रोजाना एक-दो बंदे एक्सीडेंट में एक्सपायर हो ही जाते हैं। वहां के लिए मैंने ट्रामा सेंटर मांगा था तो हमारे हैल्थ मिनिस्टर विज साहब ने इसके लिए 'यैस' किया था। इस संदर्भ में मेरा क्वेश्चन नम्बर 113 था और यह दिनांक 28.2.2020 को लगा था लेकिन दिनांक 7.2.2022 को एश्योरेंस कमेटी के अंदर इसका जवाब दिया गया कि वहां पर ट्रामा सेंटर की जरूरत नहीं है क्योंकि गर्वनमेंट नार्म्ज के अनुसार दो ट्रामा सेंटर की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर की होनी चाहिए जबकि सिविल होस्पिटल मांडी खेड़ा और नलहड़ की दूरी 26 किलोमीटर है, जहां पहले से ही ट्रामा सेंटर के मरीजों को देखा जा रहा है। स्पीकर सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार वहां कहां पर ट्रामा सेंटर है ? वहां पर कहां पर न्यूरो सर्जन है ? वहां पर कौन डाक्टर मरीजों को देखता है ? स्पीकर सर, इतने बड़े झूठे आश्वासन इस हाउस में दिए जाते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि इस पर गौर फरमाया जाये। इसी तरह से हमारे यहां पर सी.आर्म मशीन की मैंने एक डिमांड रखी थी। चार साल से इसकी मांग कर रहा हूँ। मैंने इस बारे में क्वेश्चन नम्बर 1509 दिनांक 14.3.2022 को लगाया था और

डाक्टर कमल गुप्ता जी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि दो महीने के अन्दर सी.आर्म मशीन भेज दी जायेगी लेकिन यह आश्वासन दिए हुए एक साल का समय बीत चुका है परन्तु आज तक सी.आर्म मशीन नहीं भेजी है। स्पीकर सर, जब हड्डी टूट जाती है तो हमारे यहां के लोगों को पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक जाना पड़ता है। हमारे यहां के लोग बहुत गरीब हैं लेकिन वहां पर उनका जो इलाज होता है वह बहुत एक्सपेंसिव होता है। अतः सरकार को झूठ पर झूठ न बोलकर इस दिशा में काम करने की जरूरत है। स्पीकर सर, इसी तरह से सी.एम. साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि सभी एम.एल.एज. को 5-5 करोड़ रूपये दिए जायेंगे। इस बात को हुए चार साल हो गए है लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक उस अमाउंट के फिफ्टी परसेंट टैंडर भी नहीं करवाये जा सके हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है ? आज हम अफसरों के पास जाते हैं। जे.ई., एस.डी.ओ., एक्सियन वगैरह मीटिंग कर लेंगे और पूछ भी लेंगे कि क्या काम है लेकिन वे सरकार से इतना डरते हैं कि वे अपोजीशन के एम.एल.ए. के साथ बैठ गए तो कहीं सस्पेंड न हो जायें। स्पीकर सर, हमारे साथ बैठें या न बैठे लेकिन काम तो जरूर करें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो जिला परिषद है, सी.एम. अनाउंसमेंट है, एच.आर.डी.एफ. प्लान है इनकी ग्रांट से हम 5 लाख रूपये तक के काम कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 लाख रूपये के काम तो हम बिना टैण्डर भी कर सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि हम वैगी में इस तरह से काम क्यों नहीं कर सकते ? सरकार ने वैगी को इनसे अलग क्यों रोक रखा है ? काम चाहे 50 हजार रूपये का हो या 1 लाख रूपये का हो इसमें सभी कामों का टैण्डर लगाना पड़ता है। अतः आप इसे वैगी में भी लागू करवाइये और इसका एक सर्कुलर जारी करवाइये। अध्यक्ष महोदय, हमारे बुबलहेड़ी और डोंडल सब-स्टेशन में 33 के.वी.ए. के सब-स्टेशंज हैं। दोनों सब-स्टेशनों की बिजली रंगाना राजपुरा के 220 के.वी.ए. से यानि केवल 1 लाइन पर चल रही है। यह लाइन डबल होनी चाहिए। अतः रात के समय जब लोड ज्यादा हो जाता है और 2 सब-स्टेशंज सिंगल लाइन पर होते हैं तो रात को उनके फ्यूज उड़ जाते हैं। ऐसे में 40-45 गांवों को अंधेरे में रहना पड़ता है। अतः सरकार से मेरी विनती है कि वहां पर जल्दी-से-जल्दी डबल लाइन की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने फिरोजपुर-झिरका में एक गवर्नमेंट कॉलेज

बनाने की घोषणा की थी। क्या कारण है कि वह कॉलेज आज तक नहीं बनाया गया है ? इस समय सदन में माननीय ऐजुकेशन मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं। उसके लिए सरकार ने फण्ड भी जमा करवा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर उसे क्यों नहीं बनाया जा रहा है ? सरकार से मेरी विनती है कि वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज को बना दिया जाए ताकि हमारे वहां की बहन-बेटियां पढ़ाई कर लें। थैंक यू सर।

श्री विनोद भ्याना (हांसी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन का जो कार्य किया है उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। हमारी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के मैरिट के आधार पर नौकरी देकर व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। आज पोर्टल के माध्यम से गरीब आदमी का घर बैठे बिना सरकारी दफ्तर जाये राशन कार्ड बन रहा है। गरीब आदमी का आयुष्मान कार्ड बनाकर और उसको 5 लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त में कराने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। आज पोर्टल के माध्यम से बुजुर्गों का सम्मान/बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बन रही है। हमारी सरकार ने किसान को भावान्तर भरपाई योजना देकर और 14 फसलों को एम.एस.पी. पर खरीदकर किसान कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। मैं इस सारी व्यवस्था परिवर्तन के लिए मनोहर सरकार को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से सरकार को अलग-अलग विषयों पर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमने अभी हाल ही में अखबारों में पढ़ा कि विभाग ने सब्जी मण्डी में सब्जी की सेल पर मार्केट फी एकमुश्त कर दी है। यह एकमुश्त फी भी इस तरह से की है कि आढ़ती जितनी मार्केट फीस पिछले साल देता था उससे 40 परसैंट बढ़ाकर अगले साल देनी है और उसके अगले साल से हर वर्ष मार्केट फीस 10 परसैंट बढ़ाकर देनी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि अनाज के रेट में तो हर वर्ष थोड़ा-बहुत ही फर्क पड़ता है मगर सब्जी के भाव निश्चित नहीं होते कि कितने बढ़ जाएंगे या कितने घट जाएंगे। मान लीजिए कि पिछले साल टमाटर 200 रूपये प्रति किलोग्राम मिल रहा हो लेकिन इस साल वह 20 रूपये प्रति किलोग्राम के भाव पर भी बिक सकता है। ऐसे में कहां तो आढ़ती को 4 रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मार्केट फीस देनी थी और कहां अब 40 पैसे देनी है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि हर साल आढ़ती को 10

परसैंट मार्केट फी बढ़ाकर देना बहुत मुश्किल काम है। अतः इस पर विभाग को दोबारा जरूर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी उठाई है कि मिट्टी के उठान को खनन श्रेणी से बाहर निकालना चाहिए। आज अगर किसी छोटे-से किसान ने अपना घर बनाने के लिए प्लॉट में मिट्टी डालनी है या पशुओं के लिए मिट्टी डालनी है या अपने खेत को समतल करना है तो जब वह अपने खेत से मिट्टी उठाकर लाता है तो उस पर खनन विभाग बड़ी भारी पैनल्टी लगाता है। किसान पर रोड़ी, बजरी, रेत आदि की किस्म की खनन की पैनल्टी लगाई जाती है। इसके लिए आम आदमी/किसान को वह पैनल्टी पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कारणवश उसके काफी कार्य रूक जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे क्षेत्र हांसी के चारों ओर आज सड़कें बहुत बढ़िया बन गई हैं या बन रही हैं। अंत में मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हांसी से जीन्द रोड बहुत बुरी हालत में है, इसलिए सरकार इसका भी संज्ञान ले और जल्दी-से-जल्दी इसको बनाने का कार्य करे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मेरा क्षेत्र हांसी पुलिस जिला है। लेकिन यहां पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के रहने के लिए आवास नहीं हैं। इस कारण अधिकारी और कर्मचारी शाम को हिसार चले जाते हैं। अगर वे आवास उनको हांसी में उपलब्ध हो जाएं तो उनको हिसार न जाना पड़े और कानून एवं व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सीता राम यादव (अटेली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा के दौरान हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा लगभग 70 वैन गांवों में जा रही हैं और वे हर गांव और हर शहर में जाकर के पात्र लोगों को सेवाएं दे रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत हर गांव में तीन घंटे लगाकर सेवाएं दी जा रही हैं। इस दौरान लगातार सभी कर्मचारी मौके पर ही मौजूद रहते हैं फिर चाहे आधार कार्ड बनाने की बात हो या चाहे पहचान पत्र बनाने की बात हो या चाहे बुढ़ापा पेंशन बनाने की बात हो। इसके अलावा चाहे मेरी बेटी, मेरा धन योजना के तहत 21,000 रुपये तीन

बेटियों के जन्म पर देने की बात हो या चाहे कन्यादान योजना के तहत 71,000 रूपये प्रत्येक गरीब परिवार की लड़की की शादी में देने की बात हो। इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की हरियाणा एक, हरियाणवी एक योजना से सभी पात्र लोगों के घर जाकर योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी योजना से वंचित न रहे। हरियाणा प्रदेश में ऐसी स्कीम 30 नवम्बर, 2023 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी तरह से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अटेली तहसील बहुत पुरानी तहसील है और लोगों की कई दिनों से डिमांड भी है कि इस तहसील को उप मंडल का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे दौंगड़ा अहीर गांव में उप तहसील की बहुत पुरानी मांग है। इसके लिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह दौंगड़ा अहीर उप तहसील बनायी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे अटेली विधान सभा क्षेत्र में 9 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी लगभग 10,000 है जिसमें बाघोत, सेहलंग, खेड़ी, धनौंदा, पाथेड़ा, भोजावास, दौंगड़ा अहीर, कांटी व मिर्जापुर बाछौद हैं। इन गांवों में पानी की निकासी न होने के कारण बहुत बुरे हालात हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन 9 गांवों में एस.टी.पी. लगाकर सीवरेज सिस्टम डाला जाए। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी है यह वास्तव में सारे हरियाणा प्रदेश के लोगों के काम आता है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के बाघोत और सेहलंग गांवों के बीच में एक एग्जिट और एक एन्ट्री प्वायंट बनाने की लोगों की मांग है। वहां पर संबंधित लोग लगभग 10 महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी ने दिनांक 9.03.2022 को वहां पर एग्जिट और एन्ट्री प्वायंट की घोषणा भी की थी और मंजूर भी किया था। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और इन्होंने उसके बाद उनको लैटर भी लिखा था। लेकिन अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन लोगों को आश्वासन देकर धरने से उठाया जाए। चूंकि उनको वहां धरने पर बैठे हुए लगभग

10 महीनों का टाईम हो चुका है। (इस समय घंटी बजायी गयी) अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने 5 करम और 6 करम के रास्तों को पक्का करने की घोषणा की है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से रास्ते कच्चे हैं, इसलिए इन 5 करम और 6 करम के रास्तों को पक्का करवाने का काम किया जाए। हमारे अटेली में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और उसमें लगभग पिछले 5 सालों से ऑडिटोरियम बन रहा है। लेकिन अभी उसका काम आधा भी नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको पूरा करवाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए?

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठना (पुनरारम्भ)

श्री नरेन्द्र गुप्ता (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। अनेकों अनेक योजनाएं अंत्योदय के लिए लागू की गईं। मैं आज आपके माध्यम से एक ऐसा काम जो उन्होंने किया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एच.ई.डब्ल्यू. नाम का पोर्टल बनाकर पूरे हरियाणा के सभी डिवैल्पमेंट के काम करवाने का काम किया गया और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने भी आये हैं। सभी डिपार्टमेंट्स का काम उस एच.ई.डब्ल्यू. पोर्टल पर अपलोड करना होता है और विभाग के अधिकारी उससे वर्क ऑर्डर करते हैं। सदन में विभाग के अधिकारी बैठे हुए नहीं हैं लेकिन डॉ. कमल गुप्ता जी बैठे हुए हैं। जो हमारे अर्बन लोकल

बॉडीज के मिनिस्टर हैं। वे इस बात का जरूर संज्ञान लेंगे कि जो एच.ई.डब्ल्यू. पोर्टल है, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब डिवाइलपमेंट का काम कोई ठेकेदार अपने हाथ में लेता है तो ठेकेदार उस काम को समय पर पूरा नहीं करता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के सभी अधिकारियों को सुझाव है कि अगर कोई ठेकेदार उस काम को समय पर पूरा नहीं करता तो उस पोर्टल पर उस डिपार्टमेंट के अधिकारी उसको ब्लॉक कर दें ताकि वह नया टेंडर न ले पायें क्योंकि ऐसी एक परिपाटी चल गई है कि वह ठेकेदार बार-बार काम का टेंडर भरते हैं और अपना काम अलॉट करवा लेते हैं लेकिन कामों को शुरू नहीं करते हैं। हमें जनता की बातें मजबूरी में सुननी पड़ती है और साथ में जनता की ग्रीवेंसिज भी झेलनी पड़ती है। इस बात को लेकर सरकार के खिलाफ भी जनता में रोष उत्पन्न होता है। ठेकेदार को काम के बदले पैसे भी दिये जा चुके होते हैं इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस बात पर जरूर संज्ञान लें ताकि हरियाणा के लोगों को फायदा मिल सके। मैंने इस बारे में पहले भी सरकार से प्रार्थना की थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुडियर चौक है और वहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है। वहां से सैक्टर 8, सैक्टर 3, बल्लभगढ़ विधान सभा और तिगांव विधान सभा क्षेत्र के लोग भी दिल्ली की तरफ जाते हैं। वह एन.एच.ए.आई. बनने से जो वहां पर कट बना हुआ है वह बंद हो गया है। मैंने पिछले सत्र में भी उपरगामी यू टर्न बनाने के लिए डिमांड रखी थी। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसकी डी.पी.आर. बनवा ली है और डी.पी.आर. बनवाने के बाद मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि एन.एच.ए.आई. से एन.ओ.सी. लेकर इसको जल्दी से जल्दी बनाने का काम करेंगे तो बहुत से लोगों को इसका फायदा होगा। जो बल्लभगढ़ में यू टर्न अंडरपास से जाम लगता है और वहां से हमारे विधान सभा क्षेत्र के लोग आते जाते हैं जिससे उनका समय बहुत खराब होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस काम को जल्दी से जल्दी करवाने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में बहुत पहले बड़े-बड़े जिलों में सर्किट हाउस बनाकर सरकार ने अच्छा काम किया है। सर्किट हाउस बनाकर इसे सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी समर्पित करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश की जनता उसको बुक करके इसकी सुविधा का लाभ उठा सकती है। आदरणीय मुख्यमंत्री

श्री मनोहर लाल जी ने खुद हमारे यहां का डिजाइन अप्रूव किया है और अप्रूव होने के बाद फाइनेंस विभाग से पैसे अलॉट न होने के कारण वर्क्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ए.सी.एस. श्री अनुराग रस्तोगी जी बैठे हुए हैं। वे मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैंने पीछे भी उनसे रिक्वेस्ट की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक वह फाइल जरूर निकल जायेगी। अभी अनुदान मांगों में हमने उनकी कोई कटौती नहीं की और सारी की सारी अनुदान मांगें पूरी कर दी हैं। आज आप इसके पैसे भी अलॉट कर दें जिससे कि जल्दी से जल्दी टैंडर प्रक्रिया पूरी हो सके। इसी तरह से एक डिस्पेंसरी और सी.एम.ओ. ऑफिस जो सैक्टर 7 में बनाने का डिजाइन बहुत पहले पास हो चुका है। वह भी मुझे लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इसके लिए जल्दी से जल्दी पैसे देंगे ताकि 30 बैडिड डिस्पेंसरी और सी.एम.ओ. ऑफिस बनाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। (घंटी) मेरे विधान सभा क्षेत्र की स्लम एरिया की बहुत सारी डिमांड हैं उनको भी सरकार पूरा करने का काम करे।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बड़ी ही ब्रीफ में रखूंगा क्योंकि सदन का काफी समय हो गया है। हरियाणा सिविल मैडीकल सर्विसेज के अंदर डॉक्टर पी.जी. में एडमिशन लेते हैं और उनसे 1 करोड़ रुपये का बॉण्ड भरवाया जाता है। यहां पर सरकार का कोई मंत्री बैठा हुआ नहीं है इसलिए इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि 1 करोड़ रुपये का बॉण्ड डॉक्टर देने का तैयार हैं परन्तु साथ में यह कंडीशन है कि वह न तो अपनी प्रोपर्टी दे सकता, न अपने बाप की प्रोपर्टी दे सकता, न ही अपनी माता की प्रोपर्टी दे सकता और न ही अपने किसी रिलेटिव की प्रोपर्टी दे सकता है। उसको थर्ड पर्सन की प्रोपर्टी देनी पड़ती है। एक साधारण परिवार का व्यक्ति अपनी गारंटी तो दे देगा इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार को अपने रूल अमैंड करने चाहिए। इसमें सीधी सी बात तो यह है कि क्या इसमें सरकार को बॉण्ड की गारंटी ही चाहिए? मेरा अनुरोध है कि इस बात का अवलोकन करके इस अमाउंट को कम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्वाइंट वेटरनरी सर्जन की भर्ती के बारे में है। दिनांक 15 जनवरी को एच.पी.एस.सी. द्वारा वेटरनरी सर्जन

का एक एग्जाम लिया गया लेकिन उसके बाद इस एग्जाम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया कि इस भर्ती का पेपर लीक हो गया है। उसके बाद इसे एडमिट कर लिया गया लेकिन सरकार द्वारा इस पेपर लीक की ना तो कोई इन्क्वायरी हुई और ना ही कोई प्रोसिडिंग हुई, इसका कुछ नहीं हुआ। इस पेपर के लीक होने के बाद दिनांक 17 नवम्बर को इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। सरकार ने इस भर्ती को कैंसिल करने में 10 महीने का समय लगा दिया। इसके बाद अब आने वाली 28 जनवरी को इस भर्ती का एग्जाम है। इन वेटरनरी स्टूडेंट्स जो अब तो सर्जन हैं। जो इस एग्जाम में आते हैं उनके सिलैक्शन में उनका मेन ग्रज यह है कि इस पेपर लीक का हमारे ऊपर जो असर पड़ा उसको लेकर सरकार को कोई इन्क्वायरी करवानी चाहिए थी लेकिन सरकार ने इसकी कोई इन्क्वायरी नहीं करवाई। अध्यक्ष महोदय, मैं चाह रहा था कि सदन में अपना तीसरा प्वाइंट नहीं उठाऊं लेकिन अब माननीय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता जी सदन में आ गये हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आनन्द विहार के अन्दर एक 502 गज का प्लॉट है। मैं माननीय मंत्री जी को इसके सारे डॉक्यूमेंट दे दूंगा। इस प्लॉट की आई.डी. अन्नॉन पर्सन के नाम है। इस 500 गज प्लॉट में से एक व्यक्ति ने 100 गज का प्लॉट खरीद लिया। सर, इस 100 गज के प्लॉट की वर्ष 1991 में रजिस्ट्री हुई, वर्ष 2001 में रजिस्ट्री हुई, वर्ष 2006 में रजिस्ट्री हुई तथा 2008 में भी रजिस्ट्री हुई और ये चारों की चारों रजिस्ट्रियां मेरे पास हैं। विभाग कहता है कि आप अन्नॉन पर्सन को ढूँढकर लाओ। हम आपकी आई.डी. नहीं बना सकते। उस व्यक्ति को 100 गज प्लॉट की आई.डी. चाहिए। विभाग इसके साथ ही उस व्यक्ति को यह बात भी कहता है कि आप इस 502 गज के पूरे प्लॉट का टैक्स भरो। फिर उस अन्नॉन आदमी के नाम वह आई.डी. आएगी उसके बाद हम 100 गज के प्लॉट को आपके नाम करेंगे। वह गरीब आदमी कहां जाएगा। उसने आनन्द विहार कॉलोनी के अन्दर 100 गज का प्लॉट लिया हुआ है लेकिन वह दर-दर के धक्के खा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह पत्र है जिसे मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देता हूँ। माननीय मंत्री जी इस मामले को एग्जामिन करवाकर सुलझाये। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दीपक मंगला (पलवल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारे सारे प्रदेश के अन्दर मैडिकल कॉलेज होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ-सबका विकास की बात करते हैं लेकिन मेरे विपक्ष के बहुत से साथी यह बात कहते हैं कि सबका साथ-सबका विकास कहां है? मैं विपक्ष के सभी साथियों को यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेश के अन्दर मैडिकल कॉलेज होने की घोषणा सदन में भी की है और इन सभी मैडिकल कॉलेजों की जगह चिन्हित भी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पलवल में भी पेलक गांव के अन्दर मैडिकल कॉलेज के लिए जगह चिन्हित हुई है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें देश की पहली विश्वकर्मा स्किल डिवैल्पमेंट, यूनिवर्सिटी की सौगात दी है। यह यूनिवर्सिटी ना केवल हमारे पलवल क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए बल्कि नूहं तथा आसपास के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के बेरोजगार युवकों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही पलवल के दुधोला गांव के अन्दर किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पलवल के गांव असावटा के अन्दर एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। इस रेलवे ट्रैक पर बहुत बड़ी संख्या में रेलें आती-जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस रेलवे क्रॉसिंग पर एक आर.ओ.बी. का निर्माण करवाया जाये। वैसे तो पलवल जिले में लगभग सभी रेलवे क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण हो चुका है लेकिन सरकार द्वारा गांव असावटा के रेलवे क्रॉसिंग पर भी आर.ओ.बी. का निर्माण करवाया जाये ताकि यहां के लोगों को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे पलवल में कृष्णा कॉलोनी के अन्दर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का एक गोदाम है। यह गोदाम आज से 50 वर्ष पहले बनाया गया था। जब हमारी रबी एवं खरीफ की फसल की आवक रहती है तो यहां पर बड़ी संख्या में बड़े-बड़े ट्रकों के माध्यम से माल आता है। यह एरिया अब विभिन्न

कॉलोनीज से घिर चुका है जिसके कारण अब यह एरिया भीड़-भाड़ वाला एरिया हो गया है। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इस गोदाम को कहीं बाहर शहर से दूर शिफ्ट करवाया जाये और इसमें एक पार्क बनाया जाये ताकि वहां पर जाम की समस्या से भी निजात मिल सके और शहर से बाहर बनने से इस गोदाम का भी प्रॉपर यूज हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पलवल के अंदर जो हमारा नगर परिषद् का एरिया है माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। उस नगर परिषद् के एरिया में हमारी कुछ दुकानें जो हमारे पलवल रैस्ट हाऊस के बाहर थी वहां बनी हुई थी उनका किराया नगर परिषद् लेती थी। वे दुकानें पी.डब्ल्यू.डी. की थी। जब वे दुकाने पी.डब्ल्यू.डी. ने हटा दी तो जो हमारे वे 27 दुकानदार हैं उनको कहीं न कहीं दूसरी जगह दुकानें दिलवाने का काम सरकार करे। वे सारे के सारे गरीब दुकानदार हैं। ऐसे ही डी.सी. रैजीडेंस के सामने वहां पर जिला योजना बोर्ड की दुकानें थी। उन दुकानदारों को भी दुकानें दिलवाई जायें। अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि असाप्ता से छजू नगर, घोड़ी से रामपुर और जो हमारा अलीगढ़ दिल्ली रोड है इन सभी की रिपेयर का कार्य करवाया जाये।

श्री धर्मपाल गोंदर (नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष जी, सरकार ने 07 अक्टूबर, 2023 को एस.सी. ग्रुप ए और ग्रुप बी में प्रमोशन देने की नोटिफिकेशन की थी। उसके तहत अब तक कितने अधिकारियों को प्रमोट किया गया और कितनों को और करना है? एक वर्ष पहले हरियाणा सरकार ने नीलोखेड़ी को उप मण्डल बनाने की घोषणा की थी। अब इस बारे में नोटिफिकेशन भी हो गई है। एस.डी.एम. साहब व स्टॉफ कब तक नीलोखेड़ी में बैठेंगे। हमारे पास नीलोखेड़ी तहसील में काफी जगह है वहां पर ऑफिस बनाया जा सकता है। अध्यक्ष जी, सभी गांवों में विकास कार्य रूके हुए हैं इसलिए ठेकेदारों के बजाये 20 लाख रूपये तक के कार्य पंचायत के माध्यम से करवा दिये जायें तो इससे गांवों का काफी विकास हो सकता है। अध्यक्ष जी, आशा वर्करों को पांच महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। उनका वेतन शीघ्र दिलवाया जाये ताकि वे अपने घर का गुजारा कर सकें। अध्यक्ष जी, हरियाणा राज्य आजीविका मिशन है उसके कर्मचारियों की आधी तनख्वाह काटने के बारे में विचार किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यह आधी तनख्वाह काटने का काम न किया जाये क्योंकि इस मिशन में लगभग

पांच लाख महिलायें काम कर रही हैं। सरकार के स्तर पर इस बारे में जरूर विचार किया जाये। अध्यक्ष जी, जिन विधायकों को फ्लैट्स देने के बारे में सरकार ने कहा था वह फ्लैट्स का कार्य अधूरा है। उस पर शीघ्र विचार करके विधायकों को शीघ्र फ्लैट्स दिलवाये जायें। अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी विधान सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई वर्ष पहले कई अनाऊंसमेंट्स की थी। उन पर अभी तक भी यानि कई वर्ष बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि इन सभी अनाऊंसमेंट्स को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये। ये अनाऊंसमेंट्स हैं – तरावड़ी में पृथ्वी राज चौहान का शोध सेंटर, असतली झाल से बुड़ेड़ा हैड तक नहर के साथ-साथ सड़क बनाना लेकिन इन पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, जमीन को लोगों के कब्जे से छुड़वाकर पंचायतों को देने का काम था वह काम भी करवाया जाये। पंचायती जमीनों पर लोगों के कब्जे बहुत ज्यादा संख्या में हैं। इसी प्रकार से निसिंग एक बहुत बड़ा शहर है। वहां पर काफी मात्रा में राईस सैलर्ज हैं। वहां पर काफी इण्डस्ट्रीज हैं। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण दिन प्रतिदिन बहुत से हादसे होते हैं। वहां पर हफ्ते में एक डैथ जरूर हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि निसिंग में जल्दी से जल्दी एक बाई-पास का निर्माण करवाया जाये। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास के काम करवाये हैं। खास करके मेरे हल्के नीलोखेड़ी में तो पूरे हरियाणा से सबसे ज्यादा विकास के काम हुए हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विशेष रूप से यह प्रार्थना है कि एजुकेशन और हैल्थ की सेवाओं को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया जाये क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्ज और प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से जनता को लूट रहे हैं। विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटल्ज जनता को बड़ी बुरी तरह से लूट रहे हैं। जो 5/- रुपये की दवाई होती है वह 50/- रुपये से कम नहीं मिलती। कोई भी ऑपरेशन 2.5 और तीन लाख रुपये से कम नहीं होता। इसलिए अगर हैल्थ और एजुकेशन को फ्री कर दिया जाये तो इससे प्रदेश का बहुत विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ विकास करवाया है। नीलोखेड़ी में तो बहुत अधिक विकास करवाया है इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हैल्थ और एजुकेशन को अवश्य फ्री किया जाये। इसके अलावा मेरा एक निवेदन यह है कि करनाल जिले की जमीनों के अन्दर से बहुत अधिक नहरें निकली हुई हैं लेकिन करनाल

जिले के लोगों को उनका पानी नहीं मिल पाता है इसलिए उनके लिए नहरी पानी की व्यवस्था अवश्य करवाई जाए। धन्यवाद।

आर्ट ऑफ लिविंग के सत्र में भाग लेने के सम्बन्ध में सूचना देना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से कल प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक हरियाणा निवास, सैक्टर-3, चण्डीगढ़ में एक कैम्प का आयोजन किया जा रहा है अतः आप सभी से निवेदन है कि वहां पहुंच कर आध्यात्मिक और मानसिक शान्ति प्राप्त करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*18:16 बजे

(तत्पश्चात् सभा मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)